छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा सप्तम् सत्र

मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025
(अग्रहायण 25, शक सम्वत् 1947)

[अंक 04]

Webcopy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

(अग्रहायण 25, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय, (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है कि आज भूपेश बघेल जी को जरूरत से ज्यादा ठंड लग रही है । ऐसे ड्रेस में मुख्यमंत्री थे, तब नहीं दिखते थे ।

श्री भूपेश बघेल :- ज्यादा ठंड लगी तो ...।

श्री सुनील सोनी :- अजय, उस समय भी ध्यान देते थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ज्यादा जड़ा गे हस, कुछ मामला हे ऐसे लगथे ?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 1, प्रणव कुमार मरपच्ची ।

जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में स्वीकृत उच्च शिक्षण संस्थान

[उच्च शिक्षा]

1. (*क्र. 435) श्री प्रणव कुमार मरपची : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में कितने एवं कौन-कौन से उच्च शिक्षण संस्थान संचालित हैं एवं कौन-कौन से शिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं? भविष्य में कौन-कौन से संस्थानों की स्वीकृति दी जाना प्रस्तावित है ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 04 उच्च शिक्षण संस्थान (1) डॉ. भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय, पेण्ड्रा, (2) शासकीय पं. माधवराव सप्रे महाविद्यालय, पेण्ड्रारोड, (3) शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही एवं (4) नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही संचालित एवं स्वीकृत है। प्रस्तावित नहीं है।

श्री प्रवीण कुमार मरपच्ची :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में कौन-कौन से उच्च शिक्षण संस्थान हैं तथा कौन-कौन से शिक्षण संस्थान स्वीकृत है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 4 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं । गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में डॉ.भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय पेंड्रा, शासकीय पंडित माधवराव सप्रे महाविद्यालय पेंड्रा रोड, शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, यह 4 संस्थानें शासकीय रूप से संचालित है और वहां पर 4 अशासकीय महाविद्यालय भी संचालित है । वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय सेखवाकोड, कोटमीकला, जिला पेंड्रा मरवाही, कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेड़ुका, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, एस.एस.कॉलेज ऑफ एजुकेशन सारबाहरा, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, डॉ.भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय, मरवाही । यह 4 शासकीय और 4 अशासकीय महाविद्यालय संचालित है ।

श्री प्रणव कुमार मरपच्ची :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल सा ही लग पाया है, मैं नया सदस्य हूँ । मैं अपने क्षेत्र के महाविद्यालय से जुड़ी हुई समस्यायें सदन में रखना चाहता हूँ । मैं आपके माध्यम से शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही की समस्याओं को रखना चाहूँगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय में 1029 छात्र-छात्रायें अध्ययनरत है, जहां स्नातक में 800 और स्नातकोत्तर में 229 छात्र-छात्रायें हैं । वहॉं पर अभी और कुछ विषयों का संचालन होना है, जिससे महाविद्यालयों में दर्ज संख्या बढ़ेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय में सिर्फ 14 क्लासरूम है, बाकी आफिस है । यह दर्ज संख्या के अनुसार काफी कम है । कई क्लासरूम को प्लाईवुड से पार्टिशन करके उसका संचालन किया जा रहा है, जिससे काफी समस्यायें आती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महाविद्यालय से संबंधित कुछ मांग रखना चाहूँगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये, मांग नहीं । प्रश्न करिये ना ?

श्री प्रणव कुमार मरपच्ची :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहूँगा कि इस महाविद्यालय में जो असुविधायें हैं, उन असुविधाओं को क्या दूर करने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । मंत्री जी, असुविधा दूर करेंगे क्या ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के दो महाविद्यालय डॉ. भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय पेंड्रा, यहां पर विद्यार्थियों की संख्या 1690 है। दूसरे नंबर पर शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही, यहां बच्चों की संख्या 1029 है, यहां पर अभी अध्यापन के दृष्टिकोण से स्वीकृत पद भरे गए हैं, रानी दुर्गावती महाविद्यालय में 21 पद स्वीकृत हैं जिसमें 7 रेगुलर पद में हैं और बाकी 14 रिक्त पद में अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति की गई है। ये

महाविद्यालय अच्छा है, यहां पर मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, उसका एक बार परीक्षण और उसकी समीक्षा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, क्या मांग है आप बता दीजिए। मांग ही बता दीजिए, आप क्या चाहते हो?

श्री प्रणव कुमार मरपची :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हुए 20 कमरे, 4 शौचालय युक्त, सभाकक्ष, अतिरिक्त कॉलेज बिल्डिंग की स्वीकृति प्रदान करने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए ठीक है। मंत्री जी बताईए कुछ कर रहे हैं ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक के द्वारा जो मांग की गई है, एक मांगपत्र सौंप दें और हमारे पास जो साधन की उपलब्धता और मांग है, दोनों की समीक्षा करके एक अच्छा निर्णय लेंगे। सरकार की मंशा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो और सभी साधन सुविधाएं उपलब्ध हो, इस दिशा में जरूर काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- पहला प्रश्न कर रहे हैं कुछ तो बोल दीजिए। उनका पहला प्रश्न है। आप थोड़ा सा दिल बड़ा करके बोलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- पहला प्रश्न में कुछ नहीं कर सकते तो सीमांकन करा दीजिए। (हंसी)

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय में जो कमरे और शौचालय की कमियां हैं, उसे PM USHA के तहत बजट में लेकर स्वीकृति की प्रक्रिया करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बस ठीक है। प्रश्न संख्या 2. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी।

डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य

[लोक निर्माण]

2. (*क्र. 110) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनांदगांव व खैरागढ़ जिले के लोक निर्माण विभाग की कितनी सड़कें मरम्मत योग्य हैं? वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक निर्मित की गयी नयी सड़कों में कितने मुआवजा की राशि लंबित है? जानकारी देवें ? **(ख)** मरम्मत योग्य सड़कों के संधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितनी राशि स्वीकृत हुई, कितने कार्य पूर्ण या अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यो की टेण्डर प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर मरम्मत कार्य कब तक पूर्ण हो जायेंगे ? **(ग)** बजट में शामिल उक्त कार्यो की निविदा उपरांत भी रूके ग्राम पंचायत ढ़ारा से भण्डारपुर होते हुए खैरागढ़ मार्ग ग्राम पंचायत छपारा मार्ग, ग्राम पंचायत कातलवाही मार्ग, ग्राम पंचायत मोहारा से सुकुलदैहान मार्ग, घुमका से

गोपालपुर मार्ग, कलडबरी से मुढ़ीपार मार्ग, बोटेपार से खजरी मार्ग व बढाईटोला से होते हुए बलदेव टोला कलकस्सा मार्ग कार्यों की स्वीकृति राशि कब तक जारी की जावेगी एवं कार्य कब तक पूर्ण करा लिए जावेंगे ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ'**[1] अनुसार है। 48 सड़के मरम्मत योग्य है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 02 नग निर्मित सड़क पर राशि रू. 23.94 लाख की मुआवजा राशि लंबित है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'स'** अनुसार है :- 03 सड़के-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कोरनेट में शामिल। 03 सड़के-वितीय निर्देश 42/2023 के परिपालन में निविदा लंबित। 02 सड़के-बजट में शामिल प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूं और आज आपका पूरा संरक्षण चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा संरक्षण यानी की सरंक्षण नहीं मिलता क्या ? (हंसी)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, संरक्षण मिलता है, क्योंकि इन सड़कों का निर्माण मेरे विधान सभा से आपके विधान सभा की ओर भी जाता है। इसलिए मैं चाहूंगी की आप पूरा संरक्षण दें।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल आप मेरी पड़ोसी हैं, इसलिए चिंता करेंगे, आप चिंता मत करिए, आप प्रश्न करिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न था जिसमें उत्तर दिया है, दो नग निर्मित सड़कों पर 23.94 लाख की मुआवजा राशि लंबित है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दो सड़कें कौन सी हैं और वे लंबित कैंसे हैं ? उसको विस्तार से बताईएगा।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2023-24 से 2025-26 तक कितने सड़क मरम्मत योग्य पाए गए, उसके संबंध में पूछा है, 48 सड़क मरम्मत योग्य पाए गए और उसके लिए 7 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय मंत्री जी, मैंने दो सड़कों के बारे में ही पहला प्रश्न किया है, उसी को बता दीजिए।

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैं वह भी बता दे रहा हूं। मुढ़ीपार से टेकापार लंबाई 2.3 किलोमीटर मार्ग के निर्माण के लिए 16 लाख 62 हजार रूपये की मुआवजा प्रक्रियाधीन है, इसी तरह से भोरमपुर से चिचगामार्ग 2.5 किलोमीटर निर्माण हेतु 7 लाख 32 हजार का मुआवजा प्रकरण लंबित है, इस प्रकार कुल दो सड़कों का 23 लाख 94 हजार मुआवजा प्रकरण वर्ष 2023-24 का प्रक्रियाधीन है।

[11] परिशिष्ट "एक"

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- ये प्रकरण कहां लंबित है और क्यों लंबित है ? आपके विभाग में या वित्त विभाग में लंबित है ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, भू अर्जन की कार्रवाई सब डिवीजनल ऑफिसर के यहां होती है, वहां प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- चलिए ठीक है। मेरे दूसरे प्रश्न के उत्तर (ख) में आपने बताया है, उसकी पूरी सूची भेजी है। 48 जगहों पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिसका निश्चित तिथि या कार्य आप नहीं बता सकते, आपने यह कहा है। ये सारे कार्य जो कि निश्चित तिथि में बताया जाना असंभव है, ये कार्य कहां-कहां पर कौन-कौन सी जगह पर प्रगतिरत हैं, क्या ये बताएंगे ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैं शुरूआत में आपको वही बता रहा था। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 48 सड़कें आपकी विधान सभा में मरम्मत योग्य पाई गई, उसके लिए 7 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। 43 सड़कों की मरम्मत की निविदा पूर्ण हो गई है और 5 सड़कों के मरम्मत की प्रक्रिया निविदा स्वीकृत की गई है, वह प्रक्रियाधीन है, 4 सड़क का मरम्मत पूर्ण हो गया है, 39 सड़कों के मरम्मत का काम प्रगतिरत है, 5 सड़कों का काम अभी अप्रारंभ है क्योंकि वह निविदा की प्रक्रिया में है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगी कि प्रगति पर है, मतलब उसमें काम शुरू हो चुका होगा। यदि वह कार्य प्रगति पर है तो उसकी शुरूआत हो चुकी होगी। यदि वह प्रक्रियाधीन है, मतलब कार्य चालू हो गया होगा। हमने इनमें से किसी भी सड़क में प्रगति नहीं देखी है। आप अपने कार्यकर्ताओं को भी भेजकर दिखवा सकते हैं और रही बात, जैसे कि मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि यह मोतीपुर, सुकुलदैहान, मुसरा, अछोली, डोंगरगढ़ वाली रोड है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जब भी दिखवाएंगे तो कार्यकर्ताओं से नहीं, अपने अधिकारियों से दिखवाएंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जी। अध्यक्ष महोदय, आप अधिकारियों से भी दिखवा सकते हैं। यह जो रोड है, यह आपके विधान सभा और मेरे विधान सभा के बीच की है। जहां से हमारा हमेशा आना-जाना होता है। यह मोतीपुर, सुकुलदैहान, मुसरा, अछोली, डोंगरगढ़ रोड है। जहां एक कंकड़ तक नहीं डला है, मिट्टी तक नहीं डली है तो उसकी मरम्मत कैसे हुई और वह प्रक्रियाधीन कैसे हुई? आपने यहां पर ऐसे कितने सारे कार्यों को प्रक्रियाधीन बताया है। जैसे-डूमरडीह, सेन्हारा, दैहान, विष्णुपुर, चैतुखपरी मार्ग है। वहां पर भी वही व्यवस्था है। आपने जितनी भी लगभग 48 सड़कें बताई हैं, उनमें से ऐसी किसी भी जगह मैंने कार्य को प्रक्रियाधीन नहीं देखा है। मतलब, आपके विभाग ने हमको पूरी तरह गलत जवाब दिया है। वह कार्य लंबित कैसे रहा, कार्य कैसे हुआ, स्वीकृति कैसे हुई, कहां रहा, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। कृपया आप मुझे इसके बारे में बताएंगे।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि 4 सड़कों का मरम्मत का काम पूर्ण हो चुका है। इस पर माननीय सदस्य का कोई विषय होगा कि ये कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं तो वह मुझे उसकी जानकारी दे देंगे, मैं उसको अलग से दिखवा लूंगा। 39 सड़कों का टेण्डर हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। कहां पर काम शुरू नहीं हुआ है, यदि आप यह बता देंगे तो मैं उसको दिखवा लूंगा। मैंने 5 सड़कों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया कि ये कार्य अप्रारंभ हैं और निविदा की प्रक्रिया में हैं। हमने तय किया है और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि दिसम्बर तक मरम्मत के सारे काम आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिए जाएं और आज पूरे प्रदेश भर में सड़कों की मरम्मत का काम द्रुत गति से जारी है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- आदरणीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। अभी मेरा पूरा प्रश्न नहीं हुआ है। मंत्री जी जो 4 सड़कें बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जो आखिरी प्रश्न पूछना चाहती हैं, वह पूछ लीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष जी, मैं जो जानना चाहती हूं, वही प्रश्न पूछ रही हूं। आपने 4 सड़कें कहा तो वह 4 सड़कें कौन सी हैं ?

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देता हूं। ढारा ठेलकाडीह मार्ग, लंबाई 6 किलोमीटर का 18 लाख रूपये का बी.टी. पेच मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने कार्य पूर्ण होने की बात कही है, वह वर्ष 2022-23 का है। मैंने वर्ष 2024-25-26 का प्रश्न पूछा है। जिसमें आप यह जो जानकारी दे रहे हैं, वह पूरी तरह से [xx][2] देने वाली बात है क्योंकि इसमें से एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। (शेम-शेम की आवाज)

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, [xx] शब्द। आप नयी सदस्य तो नहीं रह गई हैं। आप पुरानी सदस्य हो गई हैं। इन शब्दों का उपयोग विधान सभा में नहीं होता है। इसको हम विलोपित तो कर रहे हैं, मगर उसकी जगह और भी दूसरे शब्द हैं, जिनका आप यूज कर सकती हैं।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको विलोपित करना चाहूंगी। लेकिन ये आपके विभाग के द्वारा [xx] देने वाले शब्द हैं, जो यहां पर उल्लेखित किये गये हैं क्योंकि मैंने 48 सड़कों में एक भी जगह मरम्मत कार्य नहीं देखा है। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगी कि इसमें मेरे 3 और भी प्रश्न हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले ही संरक्षण मांगा था कि आपने 3 जगहों में कहा है कि इसके टेण्डर हो चुके थे, फिर भी ये कार्य रूके हुए हैं और प्रगति पर हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत छपारा मार्ग।

---

[2] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये, आप लिखकर मंत्री जी को जानकारी दे दीजिए।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह इसी प्रश्न के उत्तर में है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप लिखकर मंत्री जी को दे दीजिए। मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट जवाब नहीं है, इसीलिए मैं इस विषय में अपनी बात रख रही हूं। घुमका से गोपालपुर मार्ग और गोटेपार से खजरी मार्ग। यह बजट में शामिल था, इसकी स्वीकृति हुई और टेण्डर होने के बाद आज यह राशि कहां लंबित है और क्यों लंबित है ?

अध्यक्ष महोदय :- उप मुख्यमंत्री जी, आप आखिरी जवाब दे दीजिए।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जिन 3 सड़कों का उल्लेख किया है, ग्राम पंचायत छपारा, घुमका से गोपालपुर और गोटेपार से खजरी। इसकी निविदा हो गई थी और अभी निविदा की प्रक्रिया लंबित है। सड़कों की मरम्मत की गई है और ये सड़कें चलने योग्य हैं। आने वाले समय में यदि सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह जो चौड़ीकरण के लिए स्वीकृति मिली थी तो इसकी स्वीकृति होने के बाद, राशि जारी होने के बाद इसको रोक दिया गया है या तो फिर आप इसको आपके विभाग से निरस्त कर दीजिए। अगर विभाग में राशि है तो फिर वह काम चालू होना चाहिए। इस तरह से उस काम को क्यों रोका गया है ?

अध्यक्ष महोदय :- क्या कोई काम रोका गया है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है कि वह सड़क चलने योग्य है और उसकी मरम्मत भी करायी गयी है। आने वाले समय में यदि उसके नवीनीकरण की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से सड़कों को दुरूस्त करने की और उन्हें अच्छा बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है। हम उसे पूरा करेंगे।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जो स्वीकृति हुई है वह सिर्फ चलने योग्य के लिए नहीं बल्कि चौड़ीकरण के लिये और मजबूतीकरण के लिए हुई है। वहां पर असुविधा है।

अध्यक्ष महोदय :- वे बता दिये हैं कि नवीनीकरण के लिये आगे कार्य किया जायेगा। इतना पर्याप्त है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संरक्षण में चाहती हूं कि इस कार्य को प्रारंभ किया जाये। उस कार्य को सेंक्शन होने के बाद भी रोका गया है। मैं यह विषय कई बार सदन में रख चुकी हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आप लिखकर दे दीजिये।

एपीएल. राशन कार्ड से बी.पी.एल. राशन कार्ड में परिवर्तन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 239) श्री सुशांत शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बिलासपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2023 से नवम्बर, 2025 की अवधि तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु ए.पी.एल. राशनकार्डधारियों को परिवर्तित कर बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी किया गया है? यदि हां तो कितने राशनकार्ड परिवर्तित किए गए हैं ? विकासखण्डवार वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या ए.पी.एल. राशन कार्ड से बी.पी.एल. राशन कार्ड परिवर्तित करने के लिए हितग्राहियों से सहमति ली गई ? यदि नहीं तो कारण बतावें ? इस हेतु दोषी अधिकारियों पर क्या-क्या कार्रवाई की गई ? **(ग)** क्या उक्त कार्य में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां तो क्या कार्रवाई की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जी नहीं । शेषांश के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के संबंध में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हां । जांच करायी है। प्राप्त जांच रिपार्ट पर कार्रवाई विचाराधीन है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज मैंने आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक गंभीर प्रश्न पूछा है कि बिलासपुर जिले में ए.पी.एल. कार्ड को।

अध्यक्ष महोदय :- आज गंभीर प्रश्न पूछा है इसका मतलब इसके पहले गंभीर प्रश्न करते ही नहीं थे।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, मैंने किया था। इसमें आपको इसलिए गंभीरता का अवसर करा दूं क्योंकि पिछली बार भी।

अध्यक्ष महोदय :- हम आपके हर प्रश्न को गंभीरता से लेते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, आपने पिछली बार भी इसी प्रश्न पर कुछ पूछने का अवसर दिया था और इस बार भी आपने अवसर दिया है इसके लिये आपको धन्यवाद। क्या ए.पी.एल. कार्ड डिलीट करके बी.पी.एल. कार्ड में परिवर्तित किये गये हैं ? इसमें माननीय मंत्री जी की ओर से जो जवाब आया है, वह पूर्णत: तथ्यात्मक तौर पर गलत है। मैं इसलिए आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि एक भी कार्ड डिलीट नहीं हुए हैं। जिला प्रशासन बिलासपुर के द्वारा 2024 में एक एफ.आई.आर. करायी गयी, जिसमें 4 राशनकार्ड डिलीट पाये गये और फर्जी तरीके से ए.पी.एल. को बी.पी.एल. में परिवर्तित किया गया। अब यह जवाब देते हैं कि जी नहीं, कोई भी कार्ड डिलीट कर परिवर्तित नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या जिला प्रशासन ने गलत एफ.आई.आर. करायी है ? क्या इनके प्रशासन के अधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं और इनको [xx] में रख रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले बजट सत्र की बैठक में भी आया था और मैंने उसका जवाब दिया था। उसमें जांच के संबंध में भी चर्चा हुई थी। विधायक महोदय के द्वारा जो पूछा गया है, उसमें जांच हुई है। इसमें कलेक्टर के निर्देशानुसार समिति बनी है और समिति के द्वारा जांच की गयी है। समिति के द्वारा जांच में दोनों जांच दल द्वारा प्रकाशित खबर में उल्लेखित 19 राशनकार्ड, जिनके हितग्राहियों की जानकारी के बिना ए.पी.एल. से बी.पी.एल. में परिवर्तित हुआ, के संबंध में जांच की गयी है। जांच में पाया गया है कि उक्त 19 राशनकार्डों में से 15 राशनकार्ड हितग्राहियों की सहमित से बी.पी.एल. में परिवर्तित हुए एवं 4 राशनकार्ड के क्रमांक एवं नाम भी है, द्वारा हितग्राहियों की जानकारी के बिना उन्हें बी.पी.एल. प्राथमिकता श्रेणी राशनकार्ड जारी होना प्रतिवेदित किया गया है। उपरोक्त 4 राशनकार्ड नगरपालिका निगम बिलासपुर क्षेत्र के जोन क्रमांक-4 से संबंधित है। जांच में 4 राशनकार्ड के बिना हितग्राहियों की जानकारी के बी.पी.एल. राशनकार्ड जारी होने के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज का परीक्षण किया गया और परीक्षण उपरांत पाया गया कि उक्त 4 राशनकार्ड जोन कमिश्नर जोन क्रमांक-4 नगरपालिका निगम बिलासपुर की अनुशंसा के आधार पर बनाया गया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, जवाब पूर्णत: गलत है। एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी है कि किसी भी प्रकार की प्रमाणिकता नहीं पायी गई है, तब जिला प्रशासन द्वारा अपराध दर्ज कराया गया है और यह कह रहे हैं कि जोन क्रमांक-4 के जोन कमिश्नर के द्वारा सत्यापित किया गया है और उसके आधार पर डिलीट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप इनके प्रश्न का जवाब देख लीजिए, वह आपकी आसंदी पर होगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से स्थापित करता हूं कि आज सदन में मेरे पास सूची है। यदि आप कहे तो मैं पटल पर रख देना चाहता हूं। 250 ऐसे राशनकार्ड हैं जो आज भी प्रासंगिक है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। हम आपके साथ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकंड। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के राशनकार्ड में एस.आई.आर. की जरूरत है। (हंसी)

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि यह गंभीर प्रश्न है। आपने पी.डी.एस. सिस्टम को विश्व स्तर पर स्थापित किया था और उसमें कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और आज उस पी.डी.एस. सिस्टम पर, गरीबों के राशन पर [xx] डाला जा रहा है और ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उस अधिकारी को निलंबित करने की मांग कर रहा हूं और एक बार पुन: मंत्री जी जो जांच की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने

ही प्रश्न उठाया और मेरे ही प्रश्न पर जांच कमेटी बनी और उस जांच कमेटी ने आज दिनांक तक मुझसे कोई तथ्य ही नहीं लिए हैं। ऐसी कौन-सी जांच हो गयी, आप मुझे बता दें ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी जांच को अस्वीकार कर रहे हैं। मेरे पास यह जांच की रिपोर्ट है, जिसमें समिति के जो 5 अधिकारी थे, उन पांचों के दस्तखत हैं। उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी है और उसमें स्पष्ट है कि वह कार्ड जोन कमिश्नर की अनुशंसा पर बनाये गये हैं। लेकिन उसके आगे और है, दोनों जांच में अनुशंसा के आधार पर राशन कार्ड की जानकारी बिना उन्हें बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी होने के संबंध में तत्कालीन जोन कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर सुश्री दीपिका भगत एवं तत्कालीन राशन कार्ड प्रभारी प्रदीप तिवारी के कार्यालय क्षेत्र 66/68 दिनांक 14.07.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग से एफ.आई.आर. नहीं हुई है, यह जोन कमिश्नर के द्वारा किया गया होगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपके अधिकरियों के द्वारा एफ.आई.आर. की गई है, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं पटल पर रख देना चाहता हूं। मेरे पास दस्तावेज हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो मैं पटल रख देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि शासकीय उचित मूल्य 401001121 जय माता दी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार विनोबानगर बिलासपुर, इसके लिये रवि पर्याणी जो उसके विक्रेता हैं, उस पर तीन अधिकारियों ने अपराध दर्ज कराया। तीनों खाद्य अधिकारियों द्वारा पालनार्थ हुआ है, खाद्य नियंत्रक श्री धीरेन्द्र कश्यप द्वारा ये अपराध दर्ज कराया गया है। ये एफ.आई.आर. की कापी मेरे हाथ में है, अगर आप अनुमति दें तो मैं पटल पर रख देना चाहता हूं। विक्रेता रवि पर्याणी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज कर पेश करने हेतु उपरोक्त के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया। दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने का ज्ञापन जांच के उपरांत दिया गया। मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जो तथ्य हैं, आप माननीय मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बड़ी जवाबदारी से एफ.आई.आर. को पढ़ रहे हैं और उसी तरीके से माननीय मंत्री जी नकार रहे हैं तो बड़ा विरोधाभास है और विरोधाभास है तो आप उसमें कल के लिये आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दीजिए। चूंकि इतना बड़ा विरोधाभास सदन में जब आ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें चर्चा होनी चाहिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी।

श्री रामकुमार यादव :- आप मन गा गरीब के राशन कार्ड ला काट देव।

अध्यक्ष महोदय :- पहले इनके प्रश्न हो जाये।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपकी अनुमति से मेरा एक एक पूरक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आपके साथ में एक प्रश्न और भी कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुशांत शुक्ला जी ने पिछले सत्र में भी पुरानी विधान सभा में इस मामले को उठाया था। उनके संज्ञान में कोई जांच होनी चाहिए थी या उनसे कोई तथ्य मांगे जाने चाहिए थे। जो भी जांच हुई, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये मामला गंभीर है। अगर एक बार आपकी आसंदी से दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है या तो आप इसकी आधे घंटे की चर्चा बाद में करा लीजिए या सदन की हाईपावर कमेटी से इसकी जांच करा लीजिए। अगर गलत नहीं हुआ है तो वह भी आ जायेगा, गलत हुआ है तो वह भी आयेगा। अगर गलत हुआ है तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। क्योंकि यह गरीबों के राशन का मामला है। ए.पी.एल. से बी.पी.एल. अचानक हो जाना, ये बहुत गंभीर बात है। अध्यक्ष महोदय, आप उसमें आदेश कर दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधायकों की समिति से या प्रश्न संदर्भ समिति से।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाईपावर कमेटी या विधायकों की समिति, प्रश्न संदर्भ समिति से जांच करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिये।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय उचित मूल्य दुकान जय माता दी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार विनोबानगर के विक्रेता रवि पर्याणी के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्रमांक 0511 दिनांक 09.06.2024 दर्ज कराई गई है। अध्यक्ष महोदय, अधिक दर पर खाद्यान्न वितरण के लिये एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

अध्यक्ष महोदय :- अब और कोई अतिरिक्त जानकारी है तो आप माननीय मंत्री जी को दे दें।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर गलत जवाब आया है। ए.पी.एल. को बी.पी.एल. कन्वर्ट करने के नाम पर यहां पर अपराध दर्ज हुआ है। वह खुद जवाब दिये हैं। मैं आपके माध्यम से पुन: स्थापित कर रहा हूं कि इस विषय पर विधान सभा की एक हाईपावर कमेटी गठित की जाये ताकि सच सामने आ सके।

अध्यक्ष महोदय :- आपको मालूम है कि यदि प्रश्न से संतुष्टि नहीं होती है तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जायेंगे तो उसका रास्ता हम निकालेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उस पर कहां से आ गये? हमने प्रक्रिया तय कर दिये न। कुछ अतिरिक्त है तो वह प्रक्रिया में आयेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने की अनुमति दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह कर रहा हूं कि प्रक्रिया के अनुसार इसमें आधे घंटे की चर्चा रख लें तो मैं तथ्य प्रस्तुत कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपका आग्रह आयेगा तो देख लेंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लिखकर दे देता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने सारी बातों को इंकार कर दिया, प्रश्न उपस्थित नहीं होता, नहीं हुआ है। आप अपना जवाब देख लीजिए और आखिरी में आपने कहा कि हां, जांच करायी तो आपके किस अधिकारी ने यह जवाब बनाया ? और जो विधानसभा में गलत जवाब दे रहे हैं उनके खिलाफ में आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी । आप अच्छे हैं, आप मंत्री ठीक हैं लेकिन जो अधिकारी आपसे गलत करवा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी । आप उसको स्वयं पढ़िए, जब आपने सारी बातों को इंकार कर लिया तो फिर जांच को क्यों स्वीकार कर लिया? इसका मतलब है कि आपको शुरू लाईन में स्वीकार करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, तो क्या आप उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वहां जो गड़बड़ियां हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल जी, आप जितनी बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही उसका समाधान बता दिया । प्रक्रिया में आयेंगे, आगे उसको देखेंगे । प्रश्न क्रमांक-4, इंद्र कुमार साहू जी ।

शुभकामना

अध्यक्ष महोदय :- श्री राजेश अग्रवाल जी मंत्री बनने के पश्चात् आज सदन में पटल पर पहली बार उत्तर दे रहे हैं, बहुत-बहुत शुभकामना । (मेजों की थपथपाहट) चलिये, प्रश्न करिये ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोक न्यासों की भूमि का बिना अनुमति के विक्रय

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

4. (*क्र. 409) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या पर्यटन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोक न्यास की भूमि को विक्रय/लीज किए जाने के पूर्व

"पंजीयक लोक न्यास" से, छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 14 के तहत अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होता है? (ख) क्या पंजीयक लोक न्यास को, छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 14 के तहत, बिना अनुमति के विक्रय/लीज की गयी लोक न्यास भूमि के पंजीयन को शून्य/निरस्त घोषित किये जाने का अधिकार है? (ग) वर्ष 2022 से 2024 के मध्य, पंजीयक लोक न्यास/कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर को कौन-कौन से ट्रस्ट की भूमि को बिना अनुमति के विक्रय/लीज किये जाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? कृपया दर्ज शिकायत प्रकरणों की ट्रस्टवार तथा वर्षवार जानकारी देवें ? (घ) उपरोक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों पर पंजीयक लोक न्यास/कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर द्वारा क्या किसी तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक/पटवारी से किसी प्रकार की जाँच कराई गयी है? यदि जाँच कराई गयी है तो जाँच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं? (ड.) क्या किसी प्रकरण में छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 14 के तहत रजिस्ट्री शून्य/निरस्त घोषित कर धार्मिक लोक न्यास की भूमि को वापस न्यास के नाम पर दर्ज करने की कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल) : (क) जी हॉ। **(ख)** लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 में निम्नानुसार प्रावधान दिया गया हैः- 14 लोक न्यास से संबंद्ध संपत्ति के विक्रय आदि के लिए पंजीयक की पूर्व स्वीकृति- (1) न्यास विलेख में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन अथवा किसी न्यायालय द्वारा इस या अन्य किसी विधि के अधीन दिए गए निर्देश के अध्यधीन (क) किसी अचल संपत्ति का विक्रय बंधक विनिमय अथवा दान नहीं किया जाएगा।(ख) कृषक भूमि के मामले में सात वर्ष से अधिक की कालावधि या अकृषक भूमि अथवा भवन के मामले में तीन वर्ष से अधिक की कालावधि का कोई पट्टा जो लोक न्यास द्वारा धारित हो, पंजीयक की पूर्व स्वीकृति के बीना विधि मान्य नहीं होगा। (2) पंजीयक उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी संव्यवहार के संबंध में अपनी मंजूरी देने से इंकार नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में ऐसा संव्यवहार लोक न्यास के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला न हो।**(ग)** वर्ष 2022 से 2024 के मध्य कुल 03 ट्रस्टों के विरूद्ध 10 शिकायतें प्राप्त हुई है। वर्षवार एवं ट्रस्टवार की विस्तृत जानकारी ‘‘प्रपत्र”[3] में संलग्न है। **(घ)** उपरोक्त अवधि में प्राप्त शिकायतों पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रहीं है जिसमें जॉच प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रकरण विचाराधीन है। **(ड.)**‘‘निरंक”।

[3] परिशिष्ट "दो"

श्री इन्द्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी द्वारा वर्ष 2022 से 2024 के मध्य रायपुर जिलांतर्गत ट्रस्टों की संपत्ति के अवैध विक्रय की 10 शिकायतों के प्राप्त होने की बात स्वीकार की गयी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक न्यास की जमीनों का प्रबंधक कलेक्टर होता है किंतु प्राय: देखा गया है कि ट्रस्ट की जमीनों के रिकॉर्ड के कैफियत खण्ड के जानबूझकर प्रबंधक कलेक्टर दर्ज नहीं किया जा रहा है जिससे भूमाफियाओं द्वारा जमीनों को अवैध रूप से बेचना आसान हो जाता है साथ ही प्राय: यह देखा गया है कि जिला के कलेक्टर व एस.डी.एम. तथा पंजीयक लोक न्यास द्वारा ट्रस्टों का वार्षिक ऑडिट कराने में लापरवाही के कारण जमीनों तथा धन कोष व निधि में अनियमितता व भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आते जबकि जिले अंतर्गत सभी ट्रस्टों का प्रतिवर्ष ऑडिट कराया जाना कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि रायपुर जिले के 468 पंजीकृत ट्रस्टों में से किन-किन ट्रस्टों का कितने वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है ? दूसरा ऑडिट में अनियमितता व देरी के लिये कौन-कौन से अधिकारी व ट्रस्टी जिम्मेदार हैं ? और तीसरा जिन ट्रस्टों की ...।

अध्यक्ष महोदय :- 3 प्रश्न नहीं होते, आप एक-एक प्रश्न करते जाईए । मंत्री जी, एक-एक करके जवाब देंगे । चलिये, मंत्री जी ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । आज मुझे पहली बार उत्तर देने का अवसर मिला है । न्यास का जो एक्ट है वह वर्ष 1951 का है । यह काफी पुराना है और न्यास की संपत्ति काफी जीर्ण-शीर्ण हो गयी हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इसके ऊपर कभी देखरेख नहीं की गयी है, वास्तविकता है और जो बिक्री की गयी है । चूंकि 10 शिकायतें आयी हैं, जिसकी जांच, 2 में हाईकोर्ट से स्थगन है और 8 में पंजीयक जी के यहां इसका प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है । जहां तक माननीय सदस्य महोदय ने ऑडिट की जानकारी पूछी है तो चूंकि प्रश्न में यह नहीं मांगा गया था, मैं इसके बारे में जानकारी लेकर माननीय सदस्य जी को अवगत करा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, और कोई प्रश्न ।

श्री इन्द्र कुमार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न बाकी है। जिन ट्रस्टों के ऑडिट में विलम्ब हुआ है, क्या वहां जमीनों व धनकोषों में कोई अनियमितता व भ्रष्टाचार पाया गया है ? माननीय मंत्री जी, मंदिरों तथा धार्मिक न्यास की जमीनों तथा धनकोषों को संरक्षित करने के लिये क्या सचिव स्तरीय जांच समिति गठित कराकर यह जांच करायेंगे ?

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 3 ट्रस्ट की शिकायत आयी थी । जो प्रकरण चल रहा है और विगत् एक माह से लगातार सभी न्यास की जमीनों के पूरे रिकॉर्ड मंगवाये जा रहे हैं और उनको सुरक्षित व संरक्षित करने की कार्रवाई चल रही है ।

श्री इन्द्र कुमार साहू :- ठीक ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न संख्या 5 ।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा एक प्रश्न था ।

अध्यक्ष महोदय :- इसी में है ? प्रश्न संख्या 4 नंबर में ?

श्री मोतीलाल साहू :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जवाब आया है इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पूछिए । आप भी पूछिए ।

श्री मोतीलाल साहू :- इसलिए माननीय मंत्री जी से कुछ जानकारी चाहूंगा कि रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट जिसको हम (जैतूसाव मठ) के नाम से जानते हैं। उसकी जमीन बड़ी पैमाने पर बेची गयी और उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की आशंका है। यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस जमीन को बेचने के लिए विधिवत् तौर पर परमिशन ली गयी थी? यदि परमिशन ली गयी थी तो उसे किस खसरे से, कितने रकबे की और किसको बेचने के लिए परमिशन ली गयी थी? मुझे यह जानकारी देने की कृपा करेंगे।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रामचन्द्र जी स्वामी ट्रस्ट (जैतूसाव मठ) की जो भी जमीन बिक्री हुई है उसमें 8 शिकायतें आयी हैं, जिसका कि पंजीयक लोक न्यास के यहां प्रकरण चल रहा है, इसका बहुत जल्दी निराकरण किया जायेगा और आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाही थी कि उस जमीन की बिक्री तो हुई है, लेकिन उसे किस खसरे से, कितना रकबा और किसको बेचा गया। क्योंकि अगर परमिशन ली गयी होगी तो इसकी जानकारी परमिशन में आयी ही होगी। मैं यही जानकारी चाह रहा था कि उसे किस खसरे से, कितना रकबा और किसको बेचा गया? कोई प्रकरण होना अलग विषय है। चूंकि उस जमीन को बेचा गया है इसलिए मुझे इसकी जानकारी चाहिए थी।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न में नहीं था। मैं इसकी जानकारी लेकर उपलब्ध करवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे प्रश्न जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न में यह स्पष्ट पूछा गया है कि इस जमीन की बिक्री को लेकर कितनी शिकायतें की गई हैं ? इस प्रश्न के जवाब में आया है कि इस जमीन की बिक्री को लेकर 08 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मेरे पास उसकी जानकारी है। जब इस प्रश्न के उत्तर को देखा तो मैंने पता किया । इसमें स्पष्ट तौर पर यह है कि इसमें अपर कलेक्टर के यहां शिकायत होने के बाद, इस पर अपर कलेक्टर ने निर्णय भी दिया है कि लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत नियम का उल्लंघन पाये जाने पर इसका निर्णय पंजीयक लोक न्यास कर

सकता है। उन्होंने इतना मार्गदर्शन दिया है। चूंकि अधिकार पंजीयक लोक न्यास को है, लेकिन एक साल बीतने के बाद...।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक इसमें पंजीयक लोक न्यास ने कोई कार्यवाही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय :- इस विषय को लेकर इतनी विस्तृत जानकारी है तो अगली बार आप प्रश्न में आ जाईये। अगले सत्र में इसमें आपका प्रश्न रहेगा तो इस पर पूरा स्पष्ट जवाब आ जायेगा।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद्।

महारानी अस्पताल जगदलपुर में निर्माण कार्यो की स्वीकृति

[चिकित्सा शिक्षा]

5. (*क्र. 448) श्री किरण देव : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या महारानी अस्पताल, जगदलपुर में एमआरडी एवं हिमोडायलिसिस, पेलिएटिव केयर तथा कैंसर क्लिनिक का निर्माण किया जाना है ? यदि हां तो निर्माण हेतु स्वीकृति कब प्रदान की गई ? निर्माण में कितनी-कितनी राशि का व्यय संभावित है ? किस योजना अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य किस मद से किया जाना है ? **(ख)** क्या प्रश्नांश 'क' के निर्माण कार्यो हेतु प्रशासकीय स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ? यदि हां तो निर्माण कार्यो की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें ? **(ग)** यदि निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तो निर्माण प्रारंभ नहीं किये जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है ? कब तक कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :(क) जी हॉ। जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला बस्तर के पत्र क्रमांक 4907, 4909/जि.पं./प्रशा./स्वी./DMFT/ 2025-26 जगदलपुर दिनांक 12.6.2025 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त प्रशासकीयस्वीकृति अनुसार एमआरडी भवन निर्माण में रू. 411.99 लाख एवं हिमोडायलिसिस, पेलिएटिव केयर तथा कैंसर क्लिनिक निर्माण में रू. 436.82 लाख लगभग व्यय संभावित है। जिला खनिज संस्थान न्यास DMFT योजना अंतर्गत निर्माण कार्य, निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग जिला बस्तर द्वारा किया जाना है।**(ख)** जी हॉ। वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा खोलने की तिथि 24.12.2025 निर्धारित है। **(ग)** वर्तमान में निविदा प्रक्रियाधीन होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर एक प्रश्न यह है कि महारानी अस्पताल, जगदलपुर में जिला अस्पताल में एमआरडी एवं हिमोडायलिसिस, पेलिएटिव केयर तथा कैंसर क्लिनिक का निर्माण किया जाना है। कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगर इसका निर्माण किया जाना है तो इसकी स्वीकृति कब प्रदान की गयी ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति 12 जून, 2025 को प्रदान की गयी।

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय यही था कि एमआरडी बिल्डिंग और कैंसर क्लिनिक का निर्माण किया जाना, यह बस्तर के स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ मामला है और अगर इसकी स्वीकृति 12 जून, 2025 को प्रदान की गयी है तो आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि 6 माह पश्चात् अभी तक यह कार्ययोजना किस-किस प्रक्रियाओं से होकर गुजरी है, जिसमें कि उसकी स्वीकृति के पश्चात् टेण्डर की क्या स्थिति है ? अगर यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो इतनी लम्बी अवधि सिर्फ टेण्डर प्रक्रिया में चले जाना और बस्तर को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय स्वागतेय है, सम्माननीय मंत्री जी का धन्यवाद् है। लेकिन 6-6 महीने तक टेण्डर प्रक्रिया में क्या स्थिति है ? यह स्पष्ट कर दें ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय का जो जगदलपुर क्षेत्र है, पिछले 7-8 महीने पहले हम लोग उधर प्रवास में गये थे तो माननीय सदस्य महोदय ने अपने विधान सभा का जो जगदलपुर क्षेत्र है, उसमें 3 लोक महत्व के जो डिलीवरी से संबंधित जो माताओं के लिए एमआरडी है, डायलिसिस के लिए वहां पर जो वेटिंग होता था, उसके लिए भी इन्होंने मांग की थी और कैंसर यूनिट जो पेलिएटिव केयर है, उसकी भी मांग की थी । उसको देखते हुए एमआरडी भवन निर्माण के लिए 411.99 लाख एवं हिमोडायलिसिस एवं पेलिएटिव केयर निर्माण के लिए 436.82 लाख रूपए की स्वीकृति की घोषणा माननीय सदस्य की मांग के अनुरूप की गई थी और उस राशि को डीएमएफ फंड से कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया था तथा उसकी निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बना दिया गया । चूंकि वह टेक्निकली भवन होता है, उसमें एनएमसी की जो गाईड लाईन है, उसके अनुरूप इस भवन को बनाना होता है इसलिए जो विशेषज्ञ टीम टेक्निकली कार्य देखती हैं, उनके माध्यम से प्राईवेट एजेंसी हायर करके कंसलटेंट के माध्यम से उसकी पूरी डीपीआर बनवाई गई और डीपीआर बनवाकर पीडब्ल्यूडी को दिया गया । चूंकि 2 करोड़ से ऊपर का निर्माण है, ऐसी पीडब्ल्यूडी विभाग में शायद ऐसा नियम है कि 2 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत करने का उनको अधिकार जिला को नहीं होता है, वह राज्य में भेजते हैं और ई.इन.सी. के माध्यम से स्वीकृति के पश्चात् जो एस्टीमेट है, फिर से उसका टेण्डर जारी होता है । उसकी टेंडर प्रक्रिया जारी है और मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा कि वह सुखद क्षण आ रहा है, जब बस्तर के लोगों को बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी । 24

दिसम्बर को उसका टेण्डर खुलेगा । चूंकि अभी आप यह पूछेंगे कि निर्माण कार्य कब तक चालू करेंगे ? तो मुझे लगता है कि जनवरी में हम लोग भूमि पूजन कर पाएंगे और जल्द ही उसका निर्माण पूर्ण होगा ।

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो विषय है, वह विषय इतना ही है कि अगर 6-6, 8-8 महीने में टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, निर्माण कार्य की शुरूआत नहीं होगी तो वह निर्माण कार्य कब तक समाप्त होगा ? स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला है इसलिए मैं चिंतित हूं । इससे संबंधित एक और विषय है, उसको मैं सदन में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं । यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बस्तर क्षेत्र में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल प्रारंभ होना है, उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । जो मुझे जानकारी है, उसके अनुसार उसका एमओयू तक पूर्ण हो चुका है । अब यह भी शीघ्रताशीघ्र चालू हो तो ये सब काम कब तक पूर्ण हो जाएंगे ? चूंकि बस्तर का विषय जब भी आता है तो वह स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा रहता है । बस्तर से बार-बार विशाखापट्टनम या रायपुर रिफर करना पड़ता है । अगर निश्चित समयावधि में ये सारी चीजें हो जाएंगी तो मैं माननीय मंत्री जी से यही चाहता हूं कि यह सारी प्रक्रिया शीघ्रताशीघ्र हो, इसका समय निर्धारित होना चाहिए । कृपया यह बताएं कि निर्माण कार्य भी और सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भी कब तक प्रारंभ हो जाएंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है क्योंकि बस्तर क्षेत्र में अब तो नक्सल ऑपरेशन के माध्यम से नक्सल मुक्त बस्तर बन रहा है । लेकिन अक्सर झड़प में हमारे जवान घायल होते हैं या वहां के नागरिक गंभीर रूप से घायल होते हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके लाना पड़ता था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम बस्तर के लोगों को एयरलिफ्ट करके नहीं लाने देंगे, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करेंगे और सदन में बड़ी जिम्मेदारी से मैं माननीय सदस्य महोदय को आश्वस्त करता हूं कि अगले महीने जनवरी माह में ही हम सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ कर देंगे और जनवरी में भूमि पूजन होकर आपके ये तीनों कार्य प्रारंभ हो जाएंगे । (मेजों की थपथपाहट)

श्री किरण देव :- धन्यवाद ।

<u>बिल्हा वि.स. क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत कराये जा रहे कार्यो की अद्यतन स्थिति</u>

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

6. (*क्र. 231) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 25.11.2025 की स्थिति में जल जीवन

मिशन के तहत कराये जा रहे ग्रामवार कुल कितने कार्य के लक्ष्य के विरूद्ध कितने पूर्ण, अपूर्ण व अप्रारंभ कार्य हैं तथा अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यो को कब तक पूर्ण/प्रारंभ किया जावेगा ? इन कार्यो की कितनी राशि भुगतान की गयी व कितना भुगतान शेष है ? एजेंसीवार जानकारी देवें ? **(ख)** दिनांक 15 जुलाई, 2025 के तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्रमांक 222) के उत्तर के तहत राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (शीर्ष-समिति) उच्च पावर समिति के सदस्य कौन-कौन हैं? इस समिति की अनुशंसा पर 1 फर्म पर एफआईआर किन आरोप व अनियमितता के आधार पर की गयी एवं अन्य फर्मो पर एफआईआर नहीं करने के क्या कारण हैं ? निविदा स्वीकृत करने के समय उक्त फर्मो के दस्तावेजों की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई और उनके विरूद्व क्या कार्यवाही की गई ? इन संस्थाओं को 17 फरवरी, 2025 के बाद कितना-कितना भुगतान किया गया है और किनकी अनुमति से किया गया है ? **(ग)** प्रश्नांश-ख अनुसार प्रश्न के उत्तर अनुसार क्या कुल 11 जल प्रदाय योजनाओं में अनुभव प्रमाण पत्र कूटरचित पाये गए? तो क्या इनकी अमानती राशि राजसात की गई ? यदि नहीं तो कब की जावेगी? इनके अनुबंध निरस्त करने के पूर्व कितनी राशि का भुगतान किया गया है और भुगतान की गई राशि की वसूली कब तक की जावेगी?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दिनांक 25.11.2025 की स्थिति में जल जीवन मिशन के तहत् कराये जा रहे 199 ग्रामों में 211 कार्य लक्षित है, इसके विरुद्ध 92 कार्य पूर्ण, 119 कार्य अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्य निरंक है तथा अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नही है। इन कार्यों हेतु रू. 11315.34 लाख राशि का भुगतान किया गया है व रू. 316.94 लाख का भुगतान शेष है। ग्रामवार, एजेंसीवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[4] अनुसार है। **(ख)** राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन शीर्ष समिति के सदस्य निम्नलिखित है :- (1) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन-अध्यक्ष (2) भारसाधक सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य (3) भारसाधक सचिव स्कूल विभाग - सदस्य (4) भारसाधक सचिव जनसंपर्क विभाग - सदस्य (5) भारसाधक सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग - सदस्य (6) भारसाधक सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य सचिव (7) भारसाधक सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य (8) भारसाधक सचिव वित्त विभाग - सदस्य (9) भारसाधक सचिव जल संसाधन विभाग - सदस्य (10) मिशन संचालक, जल जीवन मिशन - सदस्य (11) प्रतिनिधि, भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग - सदस्य (12) 03 विशेषज्ञ (ग्रामीण पेयजल योजना/लोक सेवा/प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन/सामुदायिक विकास) से - सदस्य, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (शीर्ष समिति) उच्च पॉवर समिति द्वारा दिनांक 17.02.2025 की बैठक में की गई अनुशंसानुसार तथा कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के कारण 01 फर्म (मेसर्स विजय वी. सालुंखे) पर

---

[4] परिशिष्ट "तीन"

एफआईआर की गयी एवं अन्य 06 फ़र्मों (मेसर्स ए.के. कंस्ट्रक्शन, मेसर्स विक्रम टेली इन्फ्रा, मेसर्स, श्री गणपती कंस्ट्रक्शन, मेसर्स आनंद कंस्ट्रक्शन रायपुर, मेसर्स धर्मेश कुमार रायपुर एवं मेसर्स सोमबंसी इनवायरो) के द्वारा मेसर्स विजय वी. सालुंखे के द्वारा प्रस्तुत कूटरचित अनुभव प्रमाण-पत्र का ही उपयोग जॉइंट वेंचर में किया गया है। अतः इनके विरुद्ध अनुबंध के प्रावधान अनुसार अनुबंध निरस्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पारित निर्णय 27.11.2025 के परिपालन में पुन: कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निविदा स्वीकृत करने के समय सभी 07 फर्मों के दस्तावेजों की जांच खंड स्तर-कार्यपालन अभियन्ता, मंडल स्तर-अधीक्षण अभियंता, परिक्षेत्र स्तर-मुख्य अभियंता एवं तत्पश्चात मिशन संचालक कार्यालय स्तर पर जांच के पश्चात् अनुमोदन किया गया है। सम्बंधित फ़र्मों के द्वारा प्रस्तुत 100 रु. के स्टाम्प में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेजों को सही मानते हुए अभिलेखों की जांच की गयी है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है। इन संस्थाओं को 17 फरवरी 2025 के बाद भुगतान नहीं किया गया है। अतः अनुमति लेने का प्रश्न ही उपस्थित नही होता है। **(ग)** माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2025 के पालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से कूटरचित पाये गये अनुभव प्रमाण पत्र के कारण 11 समूह जल प्रदाय योजनाओं में फ़र्मों के विरुद्ध अमानत राशि राजसात करने की कार्यवाही लंबित रखा गया है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पारित निर्णय का पालन करते हुए कार्यवाही किया जायेगा। इनके अनुबंध निरस्त करने के पूर्व किये गए कार्य के मूल्यांकन के आधार पर मेसर्स ए.के. कंस्ट्रक्शन को रू. 80.80 लाख का भुगतान किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पारित निर्णय के पालन के पश्चात् ही भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन केन्द्र सरकार की एक महती योजना है और इसका उद्देश्य लोगों के घरों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था उपलब्ध कराना है । मैंने इस विषय में माननीय उप मुख्यमंत्री जी से केवल बिल्हा विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न पूछा है और उन्होंने जवाब दिया है कि 211 कार्य लक्षित हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- इतना लंबा उत्तर है, आपको समझ में आ गया न ?

श्री धरम लाल कौशिक :- आपको अभी पता लग जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- एक पेज का उत्तर है तो समय लगता है न ।

श्री धरम लाल कौशिक :- समय नहीं लगेगा । अध्यक्ष महोदय, उसमें 211 कार्य लक्षित हैं, उसके विरूद्ध में 92 कार्य पूर्ण और 119 कार्य अपूण हैं । मंत्री जी ने जवाब दिया है कि समय-सीमा बताना संभव नहीं है कि कब तक पूरा कराएंगे ? इस विषय में मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसके भुगतान की प्रक्रिया क्या है ? इसमें अपूर्ण है, वह कब तक पूरा होगा, बताना संभव नहीं है,

लेकिन उनको पूर्ण रूप से 11,315 लाख रूपए का भुगतान कर दिया गया है । आप परिशिष्ट में देख लीजिये, मैं आपको बता देता हूं। ग्राम झलपा के काम का 167 लाख रूपये का भुगतान कर दिया है और कार्य अपूर्ण है। भुगतान हेतु शेष राशि कुछ नहीं है, आपको देने की जरूरत नहीं है। 119 नलजल योजना का पूरा पैसा दे दिया है और कार्य अपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उसको कैसे पूरा करायेंगे ? जब कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य सत्यापित नहीं हुआ है तो उसको कैसे पूरा भुगतान कर दिया गया है ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य ने बिल्हा विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न किया है। 92 कार्य पूर्ण हुए हैं 199 कार्य अपूर्ण हैं। भुगतान की प्रक्रिया ऐसी है कि ठेकेदार काम करता है, बिल प्रस्तुत करता है। उसके बाद सब इंजीनियर उसका मूल्यांकन करता है, एस.डी.ओ. मूल्यांकन करता है, फिर कार्यपालन अभियंता भी नियमानुसार मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने के बाद बिल आता है, फिर जल जीवन मिशन कार्यालय से एलाटमेंट जारी होता है और उस एलाटमेंट के आधार पर भुगतान होता है। जितना काम हुआ है, जितना मूल्यांकन हुआ है, केवल उतनी राशि का भुगतान सामान्यत: होता है। तो जो भुगतान हुए हैं, वह मूल्यांकन के आधार पर हुए हैं। संपूर्ण कार्य का भुगतान नहीं हुआ है। हमने भुगतान के मामले में बहुत सारे निर्देश जारी किए हैं। हमने निर्देश जारी किया है कि जब तक काम पूरी तरह से पूर्ण नहीं होगा, हर घर तक पानी नहीं आयेगा, 70 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान नहीं करेंगे। इसलिए अतिरिक्त भुगतान का विषय नहीं है। जितना काम किया गया है, उतनी ही राशि का भुगतान हुआ है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप परिशिष्ट देख लीजये। मंत्री जी, आप भी परिशिष्ट देख लीजिये। पहले कार्य पूर्ण होने के बाद ठेकेदार भुगतान प्राप्त करने के लिए घूमते थे। लेकिन अभी यह स्थिति है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और उसको पैसा दे दिया गया है और हम कार्य पूर्ण कराने के लिए ठेकेदार के पीछे घूम रहे हैं, यह स्थिति है। आपने परिशिष्ट के कालम में लिखा है कि भुगतान हेतु शेष राशि कुछ नहीं है। आपने भुगतान कर दिया और आपने यह भी स्वीकार किया कि काम अपूर्ण है। आप एक गांव झलपा का ही बता दीजिये। इसकी कुल स्वीकृति राशि कितनी है और कितना भुगतान हुआ है ? यह कार्य अपूर्ण है तो कब तक पूर्ण किया जायेगा ? कुल 119 अपूर्ण कार्य है, आप केवल एक गांव का ही बता दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- मोला लागथे कि 2047 मा पूरा होही। (हंसी)

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भुगतान के विषय में फिर से स्पष्ट करूंगा कि कार्य अपूर्ण है, इसका मतलब वह योजना पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। परन्तु पूर्ण नहीं हुआ है, इसका मतलब काम कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। काम हुआ है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, काम अपूर्ण है। जितना काम हुआ है, ठेकेदार ने जितना काम किया है उसका मूल्यांकन हुआ है। उस मूल्यांकन के

आधार पर, क्योंकि सब इंजीनियर, एस.डी.ओ., ई.ई. तीन स्तरों पर मूल्यांकन की प्रक्रिया है, नियम है, उसके आधार पर मूल्यांकन हुआ है और भुगतान हुआ है। तो काम अधूरा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 119 अपूर्ण कार्य में सिर्फ एक गांव का प्रश्न किया हूं, एक योजना का प्रश्न किया हूं। उस योजना की कुल कितनी राशि की स्वीकृति है, उसकी लागत क्या है आपने कितना भुगतान किया है ? मैं तो सिर्फ एक गांव का पूछ रहा हूं, 119 गांवों का नहीं पूछ रहा हूं। आज जो स्थिति है, उसमें 2 साल निकल गया है, 92 कार्य पूर्ण होने की बात कह रहे हैं। जो काम की गति चल रही है, उससे इन 119 गांवों का काम आने वाले 3 साल में भी पूरा होने वाला नहीं है। यह बहुत गंभीर मामला है। आपने परिशिष्ट में सारा कालम दिया है, मैं उसमें से केवल एक गांव का ही पूछ रहा हूं, उससे आपको भी पता लग जायेगा। इसलिए उस काम की स्वीकृति राशि कितनी है और कितना भुगतान हुआ है और उसका कितना कार्य अपूर्ण है और कब पूरा करायेंगे ? मैं केवल एक गांव का ही प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- तुम्हर विजन याद है न विजन? (हंसी)

श्री अरूण साव :- माननीय सदस्य जी, बिल्हा विकासखंड का है या पथरिया विकासखंड का गांव है?

श्री धरमलाल कौशिक :- झल्फा है।

श्री अरूण साव :- हां हां जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- झल्फा जो है, वह बिल्हा का है।

श्री अरूण साव :- माननीय सदस्य जी झल्फा का पूछे?

अध्यक्ष महोदय :- गांव का नाम बताइए न, आप क्या पूछ रहे हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- झल्फा, झल्फा, झल्फा ।

अध्यक्ष महोदय :- झल्फा या झलका ?

श्री धरमलाल कौशिक :- बिलासपुर जिला, पथरिया बिलासपुर।

श्री रामकुमार यादव :- खुद पूछने वाला खुद भुला गए हे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- वही बताही।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी लागत का वह टेंडर हुआ है, कितने का काम है, वह मैं अलग से माननीय सदस्य को दे दूंगा। जो उत्तर पूछा है कि कितने पूर्ण और कितने अपूर्ण, वह उत्तर दिया है फिर से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं फिर से मैं बहुत..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ एक के बारे में बात किया है, 111 के बारे में नहीं पूछा हूं, केवल एक।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आप भुगतान की प्रक्रिया बता रहे हैं। भुगतान में अनियमितता के विषय में है।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल जी अपना प्रश्न पूछने में सक्षम हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप खुद बोल रहे हैं। मैंने इसीलिए पूछा है। मैं उस ओर जा नहीं रहा था। आपने कहा कि उतना ही दिया है तो स्वीकृति कितनी है? कितना भुगतान हुआ है। केवल एक का पूछा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, पूछिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- तो स्वीकृति नहीं बताएंगे तो फिर कैसे होगा? आधा अधूरा है, पैसा उनको दिए हैं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न में कितने लागत का वह काम है, यह पूछा नहीं गया है, मैं उनको अलग से जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। कितना काम हुआ है, कितना भुगतान हुआ है, यह पूछा गया है। यह बहुत स्पष्ट रूप से बताया है और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भुगतान करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। सब-इंजीनियर उसका मूल्यांकन करते हैं। ठेकेदार के बिल प्रस्तुत करने के बाद जितना वह काम करता है, उसके आधार पर वह बिल सबमिट करते हैं उस बिल का वेरिफिकेशन होता है । सब-इंजीनियर करते हैं, एस.डी.ओ. करते हैं, कुछ पैमाने में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करते हैं, उसके बाद वह बिल सबमिट होता है, फिर अलॉटमेंट होता है तब भुगतान होता है। बिना काम के भुगतान का कोई विषय नहीं है। भुगतान को लेकर बहुत कठोर निर्देश हमारी सरकार बनने के बाद हमने जारी किया है कि जब तक हर घर में पानी नहीं आएगा तब तक किसी भी ठेकेदार को 70 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं करना है, यह निर्देश दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपका और कोई प्रश्न है? झल्फा से आगे बढिए न।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको भुगतान होना नहीं होना अलग विषय है, शुद्ध पेय जल कब तक मिलेगा, मंत्री जी यह बता दें।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपकी नीयत पर पर भी बात नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो केवल असल में कि 111 अपूर्ण हैं और उसमें लिखा है कि कब तक पूरा करेंगे, वह बताना संभव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वह पूरा नहीं होगा, क्योंकि पैसा हम दे चुके हैं और हम ठेकेदार के पीछे घूम रहे हैं और अधिकारियों के कहने से ठेकेदार काम नहीं कर रहा है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अधिकारी उधर बैठे हुए हैं, जवाब दे देना।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अगले प्रश्न में आइए।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं आ रहा हूं न। तीन प्रश्न करना है।

अध्यक्ष महोदय :- झल्फा से आगे बढिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपकी एक कमेटी बनी। उस कमेटी के द्वारा दिनांक 17/02/2025 को बैठक की गई। अनुशंसा की गई और उसमें जो कूट रचित दस्तावेज है, उसकी जांच करें, उसके आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई करें। 7 लोगों में आपने एक विजय वी. सालुंखे के खिलाफ में एफ.आई.आर. कराया। सेम दस्तावेज बाकी लोगों ने उपयोग किया, उसके खिलाफ में आपने कोई एफ.आई.आर. नहीं कराया। ठीक है। उसी दस्तावेज का उपयोग करके उन्होंने कूट रचित फर्जी दस्तावेज के आधार पर अरबों रुपए के काम ले लिये। दूसरी बात, फिर उसमें खंड स्तर पर कार्यपालन अभियंता, मंडल स्तर अधीक्षण अभियंता, इनकी जांच करने के लिए एक आदेशित हुआ जो 100 रूपये के स्टाम्प उन्होंने ऑनलाइन किया था, उन्हीं को उन्होंने सही मान लिया। उनको आपने कहा कि इनके दस्तावेज की जांच करो। उन्होंने दस्तावेज की जांच नहीं की। वह 100 रूपये का एक एफिडेविट दिया, उसकी जांच कर ली। अब इतने जवाबदार अधिकारी हैं कि कूट रचित दस्तावेज की जांच करनी है या एफिडेविट की जांच करनी है और उसमें बहुत अच्छा लिखा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उसको बता रहा हूं। मैं जो चाहता हूं, वह उसको नहीं करेंगे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, संबंधित फर्मों के द्वारा प्रस्तुत 100 रूपये के स्टाम्प में दिए गए शपथ-पत्र के आधार पर ऑनलाईन प्रस्तुत दस्तावेजों को सही मानते हुए अभिलेखों की जांच की गई।

अध्यक्ष महोदय :- आप छोटा-सा प्रश्न कर लीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपने एक के खिलाफ में एफ.आई.आर. दर्ज किया, उसी दस्तावेज का उपयोग करके दूसरे ने लाखों-करोड़ों रूपये का टेण्डर ले लिया। उनके खिलाफ में आपने एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं कराया? अधिकारी उनको क्यों बचाना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मंत्री जी, बता दीजिये।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजनाओं में 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई, जिसमें से 12 जल समूह योजनाएं ज्वाइंट बेंचर बनाकर उसका आवंटन किया गया। आवंटन करने के बाद मेसर्स विजय सालुंखे के अनुभव प्रमाण-पत्र को लेकर शिकायत हुई कि यह फर्जी है, फोर्ज है, सही नहीं है। जैसे ही शिकायत मिली, जहां नगरपालिका करार महाराष्ट्र से वह जारी हुआ था, हमने तुरंत वहां से उसका सत्यापन कराया। सत्यापन में यह पाया कि यह सर्टिफिकेट वहां से जारी नहीं हुआ है। उसके आधार पर फिर कार्यवाही प्रारंभ हुई है।

जल जीवन मिशन की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो अपेक्स कमेटी होती है, उस कमेटी ने निर्णय किया कि सभी को ब्लैक लिस्ट करेंगे, टेण्डर निरस्त करेंगे और मेसर्स विजय सालुंखे का जो डाक्युमेंट फोर्ज है, उसके खिलाफ में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। एफ.आई.आर. किया गया है। वह मामला पुलिस के सामने विवेचनाधीन है। जो अन्य 6 फर्म थे, जिन्होंने ज्वाइंट वेंचर बनाया, इन्होंने ने भी मेसर्स विजय सालुंखे के खिलाफ शिकायत की थी कि इन्होंने हमारे साथ चीट किया, हमको फर्जी दस्तावेज दिया। अभी पुलिस Investigation कर रही है। उसमें जिनकी-जिनकी संलिप्पतता मिलेगी, उन सब पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। बहुत बढ़िया। अजय जी, आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। इनका कोई प्रश्न है। वह आपके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत लंबा हो गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कुल तीन प्रश्न पर बात की है। मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया और आपने कहा कि अब उसमें कार्रवाई करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बात को मैं वर्ष 2024 से उठा रहा हूं। यह प्रश्न सदन में दो-तीन बार आ गये हैं। वह उस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है, जिस बात को हम उठा रहे हैं। अब उसमें बोल रहे हैं कि हम कार्यवाही करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हो चुका है। उन्होंने क्या आदेश किया है और आप उस पर कब तक कार्यवाही करेंगे?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अपेक्स कमेटी का निर्णय हुआ, उस आधार पर जिला जल स्वच्छता समिति के सचिव के नाते Executive engineer ने कारण बताओ नोटिस जारी किया तो जो अन्य 6 फर्म हैं, वह कारण बताओ नोटिस और अपेक्स कमेटी के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में गये। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.03.2025 को शो कॉज नोटिस और अपेक्स कमेटी के निर्णय को निरस्त किया और सुनवाई देकर फिर से आदेश करने के लिए कहा। माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश किया तो स्पेशिफिक रूप से डायरेक्शन हुआ कि इसका निराकरण मुख्य सचिव करें। लेकिन जो जल जीवन मिशन के गाईडलाईन है, उसमें हाई पॉवर कमेटी अपेक्स कमेटी है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं एवं अन्य नौ-दस सदस्य हैं। उसका clarification के लिए शासन की ओर से Review petition पेश हुआ। Review petition का आदेश दिनांक 27.11.2025 को हुआ। उसके आधार पर यह मामला अपेक्स कमेटी में फिर से विचाराधीन हुआ। अभी अपेक्स कमेटी ने दिनांक 20.12.2025 को उस पर निर्णय किया है। उसके आधार पर पूर्व में जो ब्लैक

लिस्टिंग और एफ.आई.आर. का लिये गये थे, उसे यथावत् रखा है। अब उसके अनुरूप आवश्यक निर्देश जारी हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया। आप दोनों बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील रहे हैं। इतनी लंबी बहस चलाने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि आप दोनों बड़े अधिवक्ता हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत समय दिया। अब मेरे ख्याल से आप दोनों संतुष्ट होंगे। आपको इसी में कुछ छोटा प्रश्न पूछना है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का एक उत्तर आया कि 70 परशेंट भुगतान किया जायेगा और उससे ज्यादा नहीं किया जायेगा । आज इतनी मोटी परिशिष्ट आई है, इस पूरे जल जीवन मिशन में जॉच करें, एफ.आई.आर. करें, 70 परशेंट भुगतान करें, यह विषय नहीं है । विषय यह है कि जो गांव समस्याग्रस्त है, जहॉ बिना जलस्त्रोत के निर्माण किया गया, वहां आप जल स्त्रोत कितने दिनों में उपलब्ध करवा देंगे । चाहे उसको बिलासपुर के संदर्भ में लें, चाहे धमतरी के संदर्भ में लें लें, चाहे रामानुजगंज के संदर्भ में ले लें । जहां जलस्त्रोत नहीं है, वहां बना दिया गया तो उन गांवों में आप कितने दिनों में जल स्त्रोत उपलब्ध करवायेंगे और यह परियोजना पूरी तरह चालू हो ? यदि नहीं करवा सकते हैं तो ऐसा निर्माण कार्य कहीं पर भी किया गया है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे क्या ? 70 प्रतिशत भुगतान से किसी समस्या का हल नहीं हो रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- सब पैसा ला वापस करवावव ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर किये धरे हरे, तोर । बोल दूंहू तो गड़बड़ हो जही ।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, अब बैठिये । मंत्री जी के उत्तर में संदर्भ आया है, 20-12-2025 का उल्लेख किया । यह तिथि में भ्रम है या आपके उत्तर में तिथि गलत है...।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आप मेरे को बैठा दिये, 20-12 आया ही नहीं है । अधिकारी कुछ भी लिखकर भेजते हैं । 20-12 तो आया नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- उस तिथि का संशोधन कर लें ।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहूँगा । यह 2-12-2025 है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 7, विक्रम मंडावी जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरा उत्तर नहीं दिलवाया है ।

श्री रामकुमार यादव :- तोला 2047 में मिलही ।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण कर दिया, वह बहुत बड़ी बात है । चलिये ।

बस्तर संभाग में बाढ़ से हुई क्षति हेतु मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

7. (*क्र.381) श्री विक्रम मंडावी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** अगस्त,2025 में बस्तर संभाग में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति का आंकलन करने हेतु शासन के विभागों द्वारा कब से कब तक सर्वेक्षण कार्य किया गया? कितनी सार्वजनिक शासकीय सम्पत्ति का नुकसान हुआ? कितनी निजी सम्पत्ति/जानमाल की क्षति हुई? कितनी फसलों का नुकसान हुआ? जानकारी जिलावार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण पश्चात कितने पीड़ितों के मुआवजे का निर्धारण कितना-कितना निर्धारित किया गया? कितने पीड़ित परिवारों को मुआवजा वितरण किया गया? कितनी राशि बाढ़ आपदा मद से स्वीकृति हुई? **(ग)** बस्तर संभाग अधिसूचित होने के कारण शासन द्वारा अन्य कितनी व कौन-कौन सी योजनाओं से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य कियाजा रहा है ? राशि सहित विस्तृत जानकारी देवें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) :(क) अगस्त 2025 में बस्तर संभाग में आई बाढ़ से हुई क्षति का आंकलन करने हेतु दिनांक 26.08.2025 से 30.08.2025 तक सर्वेक्षण कराया गया। क्षति की जिलेवार **जानकारी संलग्न पुनरीक्षित प्रपत्र- "अ" अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश ''क'' के अनुसार दी गई अनुदान सहायता की **जानकारी संलग्न पुनरीक्षित प्रपत्र-"ब" अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।**

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को संशोधित उत्तर जस्ट 5 मिनट पहले मिल रहा है, यह पहले मिलना चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आरबीसी 6/4 के तहत नदी में डूबने या बाढ़ में बहने, प्राकृतिक आपदा से जो जनहानि होती है, उसमें 4-4 लाख मुआवजा की पात्रता है, आपने कितना-कितना दिया ?

अध्यक्ष महोदय :- समय कम है, जल्दी-जल्दी जवाब दीजिए ।

श्री टंकराम वर्मा :-माननीय अध्यक्ष महोदय, अगस्त महीने में 26,27,28,29 को जो भारी वर्षा हुई और उस भारी बारिश से बस्तर संभाग के 4 जिले प्रभावित हुये हैं । इन 4 जिलों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दौरा किय हैं और वहां पर शासकीय एवं निजी संपत्ति की जो क्षति हुई है, उसमें तत्काल राहत एवं सहायता के निर्देश उनकी भरपाई के लिये दिये हैं । माननीय विधायक जी जानकारी चाह रहे हैं कि वहां पर जो जनहानि हुई है..।

श्री विक्रम मंडावी :- 4-4 लाख रूपये जो देने का नियम है, आपने उसमें कितना-कितना दिया है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.बी.सी. के तहत वहां पर जनहानि में 4 लाख रूपये देने का प्रावधान है, बस्तर संभाग में कुल 12 लोग मारे गये हैं, उनको 4 लाख रूपये के हिसाब से पूरा भुगतान कर दिया गया है ।

श्री विक्रम मंडावी :- आपने जो जानकारी मुझे दिया है, उसमें अंतर है । नियम जो है उसमें अंतर है । जो राशि आपने बताया है, दोनों में अंतर आ रहा है ।

श्री टंकराम वर्मा :- नहीं, 4-4 लाख रूपये का ही प्रावधान है ।

श्री विक्रम मंडावी :- यह जो जानकारी है, उसमें अंतर है । दूसरा, आपने बीजापुर जिले में 6 कार्यों के लिये 1 करोड़ 2 लाख 44 हजार देना बताया है, उन 6 कामों का नाम बतायेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- आप आराम से, धीरे से पूछिये । ऐसा पूछेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा ।

श्री विक्रम मंडावी :- 6 काम कौन-कौनसे हैं जो मरम्मत चल रहा है, उसका नाम बताईये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके पास मंत्र है, इधर-उधर पूछिये, सीमांकन करवाके ।

श्री विक्रम मंडावी :- 6 कामों का नाम बताईये ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पूरा ब्यौरा देना चाह रहा था ।

अध्यक्ष महोदय :- आप 6 नाम बता दो ना, 6 नाम पूछ रहे हैं ?

श्री विक्रम मंडावी :- 6 काम मरम्मत के हुये हैं, उसे बता दीजिए । नाम नहीं बतायें तो आप राशि बतायें ?

श्री टंकराम वर्मा :- देखिये, जिला बस्तर से 7 लोग हैं...।

श्री विक्रम मंडावी :- जिला बीजापुर ?

श्री टंकराम वर्मा :- बीजापुर से दो लोग हैं । इनको आर.बी.सी. के तहत 4 लाख रूपये का पूरा भुगतान हो चुका है ।

श्री विक्रम मंडावी :- जो मरम्मत कार्य हैं, मैंने उनका नाम पूछा था । आपने जो सूची दिया है, उसमें नाम बताया था ।

श्री टंकराम वर्मा :- हमारे पास मरम्मत कार्य के लिये 187 करोड़ 34 लाख रूपये का प्रक्रियाधीन है...।

श्री विक्रम मंडावी :- आपने बीजापुर जिले के लिये 6 काम बताया है, उस 6 काम के लिये राशि नहीं पूछ रहा हूँ, काम का नाम पूछ रहा हूँ. वह कौन से 6 काम है, कहां-कहां का 6 काम है, उसका नाम पूछ रहा हूँ ?

श्री टंकराम वर्मा :- बता रहा हूँ, बता रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशनार्थ नहीं

समय :

12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगए शासन वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या (वाणिज्यिक)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 5 (वाणिज्यिक) पटल पर रखता हूँ।

(2) कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 28202/रूल 503/16/एजी.एसईसी.(टेक), दिनांक 03 नवंबर, 2025

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना कमांक 28202/रूल-503/16/एजी. एसईसी. (टेक.), दिनांक 03 नवम्बर, 2025 पटल पर रखता हूँ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2024-2025

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2024-25 पटल पर रखता हूँ।

(4) विश्वविद्यालयों के प्रतिवेदन

(i) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024-2025

(ii) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का दशम वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025)

(iii) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025

(iv) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(1) शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर, का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024-2025,

(2) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2024-2025 (01 जुलाई 2024 से 30 जून 2025),

(3) अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 तथा

(4) शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025) पटल पर रखता हूँ।

(5) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 (1 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 (01 जुलाई, 2024 से 30 जून, 2025 तक) पटल पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- शून्यकाल की सूचनाएं।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आज एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। माननीय धर्मजीत जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने एक अशासकीय संकल्प 26 जुलाई, 2022 को लाया था, छत्तीसगढ़ विधान सभा ने ये प्रस्ताव पारित किया था कि हसदेव क्षेत्र में खनन बंद कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हसदेव अरण्य में जिस ढंग से पेड़ों को कांट करके तबाही मचाई हुई है, तमनार में जिस ढंग से पेड़ों की कटाई से तबाही मची है, बस्तर में जिस ढंग से पेड़ों की कटाई चल रही है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारे अशासकीय संकल्प को केन्द्र वालों ने कूड़े में फेंक दिया है, मैं

आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी जगह में था तो मैंने इस प्रस्ताव को भेजा था। वह हसदेव जहां की पानी जांजगीर, कोरबा, रायगढ़ जिले में आती है, वह हसदेव अरण्य जहां लगभग 170 प्रकार की दवाईयां और जड़ीबूटी हैं, जो अलुप्त हो जाएंगे। तमनार में 61 ग्राम पंचायतों के लोगों ने जाकर जिलाध्यक्ष से यह मांग की है कि हमारे यहां किसी भी प्रकार की जनसभाएं नहीं हुई हैं। यहां पर जिस ढंग से पुलिस की छावनी लगा दी गई है, वहां जिस ढंग से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, जिस ढंग से तमनार के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है। इसके कारण छत्तीसगढ़ में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि लोग अब सरकार और पुलिस से डरने लगे हैं। इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप इस स्थगन को स्वीकार करें, ताकि हम सभी स्थितियों को आपके सामने रख सके और आप हमको इस पर चर्चा करने का अवसर देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- उमेश पटेल जी।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैं इसी मामले में तमनार गया था और जिस तरह से।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष स्थगन लाने के चक्कर में सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की अवमानना कर रहा है। नियमत: विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष जी यदि विषय उठा दे तो उस विषय को दूसरा कोई नहीं उठाता है। यदि इनको नहीं आता है तो पहले सब सदस्य बोल ले, फिर आखिरी में नेता प्रतिपक्ष जी को बोलवाये। ये सब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के बोलने के बाद बोलते हैं। यह उनकी अवमानना हो रही है। इसको रोका जाना चाहिए। इनको सिखाया जाना चाहिए कि स्थगन कैसे लाया जाता है और कैसे बोलवाया जाता है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- शून्यकाल में बोलने के लिए कोई नियम नहीं है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- हमारे नेता जी इस मामले को लेकर लीड कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- वह लीड नहीं कर रहे हैं। जो परंपरा है, उसका आपको पालन करना चाहिए। उनका मौजूद होना ही लीड है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- हमारे नेता लीड कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में हम अपने क्षेत्र की बात रख सकते हैं। हमारी जो समस्या है, उसको रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप हमें विषय से विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह हमको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी नेता प्रतिपक्ष जी का जानबूझकर अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप कई बार इसी विधान सभा में बोले हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- शून्यकाल में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। हम अपने क्षेत्र की बात रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह नेता प्रतिपक्ष जी का जानबूझकर अपमान कर रहे हैं। कोई उनका अपमान नहीं सहेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 2 साल पहले कई अवसरों में आप इससे ज्यादा बोले थे। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- नहीं, यह गलत बात है। शून्यकाल में सबको अधिकार है। सभी बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में सभी अपनी बातों को रख सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को आखिरी में बोलवा सकते हैं। इस परंपरा को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, आप इनको प्रताड़ित कीजिये। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि मैं जो बोल रहा हूं, क्या वह गलत है? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम शून्यकाल में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। हम नेता प्रतिपक्ष जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- हमर नेता हे। हमन एमन ला सम्मान करे बर दिखाए बर थोड़ी न आए हन। (व्यवधान)

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता जी बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- हमन ला सम्मान करे बर तुंहर ले सीखेल लागही का?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री भूपेश बघेल :- आपका दूध-भात है। आप रहने दीजिए। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- एला तो जंगल के हाथी हा खोजत हे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि मैंने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है, लेकिन यह एक परंपरा है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह वास्तव में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सुनियोजित अपमान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- वह आपका इशारा समझ गये हैं। बस, उतना पर्याप्त है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह उतना समझते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- वह विषय को खुद ही उठाना चाहते हैं तो आप कैसे करोगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तमनार में अभी जिस तरह से परिस्थिति बनी है, उसको देखने के लिए मैं खुद वहां पर गया था। इसी विषय में यह स्थगन आया है। वहां पुलिस की छावनी बना दी गई है और लोगों को वहां से बिल्कुल दूर रख दिया गया है। यह पेसा कानून के अंतर्गत आता है। बिना उनकी अनुमति के लगातार पेड़ को काटा जा रहा है। अभी आपने जन सुनवाई में सुना होगा। यदि हम धरमजयगढ़ की बात करे तो लोग कलेक्टर के सामने दिन-रात मुर्रा खाकर वहां पर बैठे रहे, लेकिन कलेक्टर उनसे बात करने तक के लिए तैयार नहीं था। अभी तमनार में जो जन सुनवाई हुई है, उसमें मुझे फर्जी तरीके से जन सुनवाई में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि लोग जो तय जगह है, जहां पर जन सुनवाई होनी है, उससे दूर अपना विरोध-प्रदर्शन करने के लिए वहां पर बैठे हैं और उससे दूर ले जाकर अलग जगह में 15 मिनट की जन सुनवाई कर दी गई। (शेम-शेम की आवाज) यह फर्जी तरीके से काम किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस स्थगन को ग्राह्य कर लीजिए, हम इस पर वृहद चर्चा करेंगे। धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से पूरा जंगल ला काटे जात हे तो मैं हर दिल्ली के समाचार ला देखत रेहेव। आज दिल्ली में जिस प्रकार से पूदषण हे, उसी प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में देखे जात हे कि गर्मी के मौसम आवत हे तो 45 डिग्री से ऊपर गर्मी आ जात हे। सब जंगल के कटाई के कारण मौसम सही समय में नहीं आत हे। आज हम सब ला भविष्य के ध्यान रखना चासहिए। आज हम हन कल नहीं रहिबो। लेकिन ये धरती रहिन और कोई ला फायदा पहुंचाये बर पूरा जंगल ला काट देत हव। मोर आपसे निवेदन हे कि ऐसे विषय में चर्चा होना चाहिए। आज जंगल उजाड़ने वाले मन के खिलाफ पूरा प्रदेश ला जानना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप एक ही विषय को रिपीट कर रहे हैं। यदि कोई अलग तथ्य रखेंगे तो ठीक है। हां, आप बोलिये।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- जिनके आस-पास का क्षेत्र है। बस्तर वालों को और अवसर है। हां, लालजीत जी, आप बोलिये।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल, जमीन उनके आय का मुख्य साधन है और वे उसी पर आश्रित हैं। जल, जंगल, जमीन के साथ उनकी निजी भूमि भी है और वह उस जमीन को देना नहीं चाहते। आज किसान संपन्न होते जा रहे हैं और खेती-बाड़ी करके अपने खुद के वजूद को बचाना चाह रहे हैं। यदि वह जमीन नहीं देना चाह रहे हैं तो ऐसी जबर्दस्ती क्यों है ? अध्यक्ष महोदय, वहां पर 5वीं अनुसूची लागू है। ग्राम सभा से कोई

प्रस्ताव नहीं है। ग्राम सभा सहमत नहीं है फिर भी वहां जबर्दस्ती जनसुनवाई करके उनके जंगल की कटाई क्यों की जा रही है ? अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों हैं ? हम सब को इसमें विचार करना चाहिए। वह हमारी जनता है, पूरे शासन-प्रशासन को इस पर विचार करना चाहिए। वहां पर वह अपनी बात रखने जा रहे हैं तो अधिकारी उनसे मिल नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से आप उस पर विचार करिये। किसी तरह से उनकी जमीन सुरक्षित हो, वह नहीं देना चाहते हैं तो जबर्दस्ती उनकी जमीन को न लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। दो मिनट।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जबसे प्रदेश में भाजपा की सरकार आयी है तब से लगातार आदिवासी क्षेत्रों की स्थिति बहुत ही विकराल रूप धारण कर रही है। हम चाहे सरगुजा से लेकर बस्तर की बात करें। हर जगह, हर क्षेत्रों में और पूरे प्रदेश में स्थिति खतरनाक होते जा रही है। खासकर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब होते जा रही है। यदि हम जशपुर जिले की बात करें, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। उस जिले में भी खदानों को आवंटित करने के लिये हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। न जनसुनवाई हो रही है, न ही जनता की बातों की सुनवाई हो रही है। मैं बस्तर के भानुप्रतापपुर के आरी डोंगरी की बात करना चाहता हूं, वहां 5 हजार पेड़ काट दिये गये हैं। वहां और पेड़ काटने की बात चल रही है। ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। उनकी बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीजापुर में भी सुनवाई नहीं हो रही है, वहां भी यही स्थिति है, पेड़ काटे जा रहे हैं। बस्तर से सरगुजा तक हर क्षेत्र में, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में खदान के नाम से माइंस के नाम से पेड़ काटा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपकी बात आ गई।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष जो मामला उठा रही हूं, यह बहुत ही गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- मामला गंभीर है लेकिन संक्षिप्त में बोल दीजिये, दो मिनट में।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, जी। यह आरंग जिले के कुरूद गांव का मामला है। एक 15 साल की बच्ची है, उसको एक बदमाश स्कूल से कार में बिठाकर अपहरण कर लेता है और जब उसके पिताजी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने जाते हैं तो टी.आई साहब उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। उसके पिताजी रिपोर्ट लिखवाने के लिये लगातार थाने में टी.आई. के पास चक्कर लगाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने तो पूरा ट्रैक बदल दिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसमें कार्रवाई चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- यह स्थगन का विषय नहीं है। यह चर्चा का विषय नहीं है। सिदार जी, आप बोलिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह शून्यकाल चल रहा है न ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठ जाईये। सावित्री जी, आप बोलिये।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार आयी है, तब से राज्य का और आदिवासियों के दुर्भाग्य के दिन प्रारंभ हो गये हैं। लगातार वनों की कटाई हो रही है। जैसे अभी विक्रम भैया ने कहा है कि मेरे भानुप्रतापपुर क्षेत्र का जो आरी डोंगरी क्षेत्र है, वहां 5 हजार पेड़ काटे गये हैं। वहां न किसी की जनसुनवाई हुई है, न वहां गांव के लोगो को मालूम है। हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। वहां लगातार वनों की कटाई हो रही है। मैं चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन ग्राह्य करके चर्चा कराई जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। चलिये, आप बोलिये।

श्रीमती विद्यावती सिदार (लैलूंगा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लैलूंगा विधान सभा के तमनार ब्लॉक के सेक्टर-1 में जिंदल के द्वारा जनसुनवाई की गयी और उसमें जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है और जिस तरह से वहां के आम नागरिक 5 तारीख से लगातार जन आंदोलन कर रहे हैं कि जन सुनवाई स्थगित की जाये, निरस्त की जाये लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। आपको हो गया।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे ही रायगढ़ जिले में हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी जी हैं लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहां जनता को कोई देख नहीं रहा है । मैं लगातार उस स्थल में बैठी हूं और वहां पर उनकी घटना को देख रही हूं कि वहां आम नागरिक का कोई महत्व नहीं है। आमजनों का कोई महत्व नहीं है न ही आदिवासियों का कोई महत्व है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आपकी बात आ गई।

श्रीमती विद्यावती सिदार :- आदिवासी 5वीं अनुसूचि में आते हैं लेकिन जिस तरह से ठंड में वहां पर जनता बैठी हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां के लोग चाह रहे हैं कि यहां जनसुनवाई न हो। आगामी यहां पर कोई कोल माइंस न खुले, वे उसके विरोध में बैठे हैं लेकिन आज शासन और प्रशासन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। मैं इसको चर्चा के लिये इस विधान सभा में लाना चाह रही हूं।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय जहां पर 21 वर्षीय छात्र असलान अंसारी जो बी.एस.सी. थर्ड ईयर का छात्र था, उसकी हत्या हो जाती है। 21 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी के छात्रावास से गायब होता है, 23 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी के कैंपस के

तालाब में उसका शव प्राप्त होता है। दो दिन बाद असलान छात्रावास से लापता था, यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दो दिन बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र की लाश मिलती है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्र की मौत को केवल हादसा बताती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्र के सिर में अंदरूनी चोट का मामला आता है और पानी में डूबने से पूर्व उसकी मौत का मामला आता है। आज 27 दिन हो गये, उस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी हत्या की एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई और न किसी के ऊपर कार्रवाई ही हुई। इस तरीके से पुलिस प्रशासन और केन्द्रीय विश्वविद्यालय काम कर रहा है। जहां पर एक छात्र की हत्या होने के बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

समय :

12:16 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में कोल उत्खनन से उत्पन्न परिस्थिति

अध्यक्ष महोदय :- मेरी पास प्रदेश में कोल उत्खनन से उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में 33 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। चूंकि डॉ. चरणदास महंत, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में न तो आदिवासी, न वनवासी चैन से जीवनयापन कर पा रहे हैं, न हाथी, न ही वन्य प्राणी और न ही पक्षी। सरगुजा, हसदेव अरण्य कोल फील्ड, तमनार, बस्तार में चहुंओर फर्जी जनसुनवाई, जन आंदोलन, लाठीचार्ज, धरना-प्रदर्शन, चक्काजाम का नजारा देखने में आ रहा है। यह समझना अत्यधिक कठिन हो गया है कि सरकार छत्तीसगढ़ियों के कल्याण ओर प्रदेश के विकास के लिये काम कर रही है या इन को बर्बाद करके उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के कल्याण के लिये कार्य कर रही है। प्रकृति की ऐसी बर्बादी न तो राज्य विभाजन के पहीले हमने कभी देखी और न ही राज्य बनने के बाद देखी। जिला रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में वन भूमि तथा राजस्व भूमि पर बड़े पैमाने पर हरे भरे वृक्षों की कटाई की जा रही है। तमनार के 61 ग्राम पंचायतों के सरपंच रायगढ़ कलेक्टर के पास पहुंच कर ग्राम सभा के फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों क मांग है कि जंगल कटाई पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषी अधिकारियों व कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। सभी पर्यावरणविदों का मत है कि तमनार क्षेत्र की जैव विविधता पहले से ही बड़े पैमाने पर कोयला खनन के कारण खतरे में है। जंगल कटाई से और अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार का यह कृत्य वन अधिकार अधिनियम (FRA) और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के आदेशों का भी उल्लंघन है। विरोध करने वाले जन प्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों पर पुलिस एवं उद्योगपतियों के नुमाइंदों द्वारा लाठी डंडे बरसाए जाते हैं और गिरफ्तार कर के जेल में डाल दिया जाता

है। जंगल कटाई वाले स्थानों को पुलिस छावनी बना दिया जाता है। स्थल तक जन प्रतिनिधियों को जाने नहीं दिया जाता है। आज भी हजारों की तादाद में ग्रामीण सरकार के इस कृत्य के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव क्षेत्र को उजाड़ा जा रहा है। अब तक लाखों वृक्ष रिकार्ड पर तथा लाखों वृक्ष रिकार्ड के बाहर काट डाले गए हैं। इस सरकार को वन पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु, वन्य प्राणी रहवास से कोई सरोकार नहीं है। हसदेस अरण्य कोलफील्ड के लिए NGT और उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRAI) तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा संपूर्ण जैव विविधता का अध्ययन करके प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मध्य भारत का सबसे बड़ा अखंडित वन जैव विविधता और जल संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। इस वन में दुर्लभ प्रजाति के पक्षी और दुर्लभ प्रजातियों के 170 प्रकार के पौधे संरक्षित हैं। यह वन हाथी विचरण का महत्वपूर्ण गलियारा है। इस जंगल की कटाई से हाथी मानव संघर्ष बढ़ेगा, जल संकट की स्थिति एवं मिनीमाता बांध सूखने का खतरा बढ़ेगा। इसी प्रकार बस्तर के भानुप्रतापपुर में आरी डोंगरी क्षेत्र में अनेक घने वृक्षों को काटा दिया गया। सरकार को न तो विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत संकल्प के पालन की परवाह है, न पर्यावरण की परवाह है, न सिंचाई के लिये पानी की परवाह है, न जनविरोध की परवाह है, न विशेषज्ञों के चेतावनियों की परवाह है और न ही उन वन्य प्राणियों की परवाह है जिन के रहवास क्षेत्र उजाड़े जा रहे हैं। चारो ओर अराजकता की स्थिति विद्यमान है और यह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सैकडों गांवों को उजाड़ने के लिये यह सरकार दृढ़ संकल्पित है, हजारों हेक्टेयर के वन क्षेत्र के करोड़ों वृक्षों को काटने का लक्ष्य है, राज्य की नदियां, बांध, जैव विविधता और भूगर्भ जल खतरे में है। प्रदेश के वन क्षेत्रों की निर्मम कटाई से उत्पन्न खतरों को अनदेखा करते हुए सरकार की कार्यवाही से प्रदेश में उपजे व्यापक जन आक्रोश को देखते हुए एवं विषय की गंभीरता को देखते हुए सदन की आज की अन्य कार्यवाही रोककर प्रस्तुत स्थगन पर चर्चा की अनुमति दी जाए।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार वन, वन्य जीव, आदिवासी, पर्यावरण सभी के लिये संवेदनशील है और इनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तत्परतापूर्वक कार्यरत् है । बस्तर में नक्सलवाद पर निर्णायक चोट पहुंचाते हुए सरकार ने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया है जिसमें रिकॉर्ड 03 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है । राज्य शासन द्वारा गुरू घासीदास तमोर पिंगला टाईगर रिजर्व स्थापित किया गया है जो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाईगर रिजर्व है । जो बिलासपुर के समीप कोपरा जलाशय को रामसर साईट घोषित किया गया है । यह प्रदेश की पहली रामसर साईट है । बेमेतरा जिला के गिधवा परसदा में पक्षी बिहार की स्थापना की गयी है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कोई गलत उत्तर तो नहीं पढ़ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, ठीक है ।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, इसमें हम लोगों ने जो सवाल उठाये थे । इसमें तो बस्तर...।

अध्यक्ष महोदय :- वह शुरूआत में संवेदनशीलता बता रहे हैं, वे बाद में पूरी भूमिका में आयेंगे ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- यह आपके प्रिय विषय हैं। चूंकि आपने इसे पहले उठाया है, आपने स्थगन में यह विषय लाया है तो आपको रिअल चीज ही परोसा जा रहा है ।

डॉ. चरणदास महंत :- उस सारे विषय में पक्षी की बात कहां से आ गयी ?

अध्यक्ष महोदय :- वह भूमिका में बात कर रहे हैं । चलिये, आप पूरा पढ़ दीजिये । पढ़ने के बाद आपको कोई शंका होगी तो चर्चा करेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को कांफिडेंस नहीं है कि वे कहीं गलत स्थगन तो नहीं लगा दिये हैं । यह मामला ऐसा है । उत्तर गलत नहीं है ।

श्री भूपेश बघेल :- हम लोगों ने सही लगाया है, उत्तर गलत आ रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं । आपका कांफिडेंस लूज है इसलिये ।

अध्यक्ष महोदय :- आज काम्बिनेशन गड़बड़ा रहा है ।

श्री रामकुमार यादव :- आंय-बांय-सांय हो गे हे ।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि स्थगन में भी अलग-अलग सदस्यों ने अलग-अलग विषय को लगातार उठाया है, मैंने उसके बाद भी अनुमति दी ।

श्री अजय चंद्राकर :- स्थगन की गंभीरता खत्म हो गयी ।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि बहुत सारे सदस्य पहली बार हैं इसलिये बहुत सारी बातों को इग्नोर किया जाता है तो उस बात की चिंता छोड़िए क्योंकि जो प्रक्रिया होती है, मान्य प्रक्रिया से आगे बढ़कर भी विधानसभा में बात आ जाती है तो पहली बार जो विधानसभा में आये हैं, उनकी बात को सुनना मेरा कर्तव्य है इसलिये मंत्री जी का जवाब आ जाये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जब गांव में भागवत और रामायण की कथा होती है तो पहले थोड़ा भजन-कीर्तन, श्री राम नाम की चर्चा भी करनी पड़ती है ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, होता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो थोड़ा कुछ कर लें फिर भागवत के विषय में आ जायेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने आपसे कल भी आग्रह किया था कि प्रेक्टिस करवाने के लिये एक स्थगन लगवा दीजिये करके । यह बेचारे 51 नये लोग भूल गये हैं करके ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, धीरे-धीरे स्थगन के ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने सही कहा कि इधर-उधर की बात करके स्थगन जैसे मोशन की गंभीरता इन लोगों ने खत्म कर दी भई । यह मानना पड़ेगा ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूरे छत्तीसगढ़ के वनों का, आदिवासियों का और पर्यावरण सभी के बारे में पूछा है तो मैंने उसके बारे में पूरा बनाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ठीक है । आप भूमिका में ले लीजिये, अब पढ़ दीजिये, चलिये ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हाथियों, बाघों तथा महत्वपूर्ण वन्यजीवों की संख्या में भी विगत् 02 वर्षों में भी वृद्धि रिकॉर्ड की गयी है । फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन आवरण में 94.75 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है साथ ही वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों वाले क्षेत्र (Tree outside forest) में 702 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है तो देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रदेश के वन क्षेत्र में विगत् 2 वर्षों में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम अंतर्गत कुल 05 खनन प्रकरण हेतु 1300.869 हे.वन भूमि नियमानुसार व्यपवर्तित की गई है । यह सही नहीं है कि सरगुजा, हसदेव अरण्य कोल फील्ड, तमनार, बस्तर आदि क्षेत्र में फर्जी जनसुनवाई जन आंदोलन, लाठीचार्ज, धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम का नजारा देखने में आ रहा है । राज्य सरकार द्वारा नियमों के अधीन भारत सरकार की स्वीकृति उपरांत ही वन भूमि व्यपवर्तित की गई है एवं व्यपवर्तन की शर्तों के तहत् आवेदक संस्थान के आवेदन अनुसार न्यूनतम वृक्षों की कटाई की गई है । यहां यह उल्लेखनीय है कि वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में व्यपवर्तित वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाता है । विगत् 02 वर्षों में व्यपवर्तित वन क्षेत्र के एवज में 1780.109 हे.क्षेत्र में 1000 पौधे प्रति हे. के मान से 17,80,000 पौधे रोपित किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रकरण में वन्यप्राणी संरक्षण योजना पृथक से तैयार की जाती है जिसके तहत खनन से प्रभावित क्षेत्र के आसपास के वन क्षेत्रों में वन्यप्राणी संरक्षण हेतु कार्य किये जाते हैं।

यह भी सही नहीं है कि जिला रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में वन भूमि तथा राजस्व भूमि पर बड़े पैमाने पर हरे भरे वृक्षों की कटाई की जा रही है। बल्कि सही यह है कि जिला रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम अंतर्गत स्वीकृत 02 प्रकरणों में 6650 वृक्षों की कटाई नियमानुसार की गई है। रायगढ़ जिले में खनन के प्रकरणों में तमनार क्षेत्र में ग्राम सभा का आयोजन नियमानुसार किया गया है। तमनार क्षेत्र में स्वीकृत 02 प्रकरणों में 18 ग्राम प्रभावित है जिसमें महाराष्ट्र स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को वन(संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत गारेपेलमा सेक्टर -2 कोल माईन्स हेतु कुल क्षेत्र 214.869 हे.वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.01.2023 को दी गई, वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार आवेदक संस्थान द्वारा आवेदन दिये जाने पर कुल 3684 नग वृक्षों के विदोहन की अनुमति प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(उत्पादन) द्वारा दिनांक 19.02.2025 को दी गई थी जिसमें से सिर्फ 1124 वृक्षों की कटाई की गई है तथा गारे पेलमा कोल ब्लॉक 4/1 जे.एस.पी.एल. को स्वीकृत वन भूमि 91.179 हे. में 5526 वृक्षों की कटाई हुई है। अत: यह सही नहीं है कि सरकार का यह कृत्य वन अधिकार अधिनियम (FRA) जन सुनवाई और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के आदेशों का भी उल्लंघन है। कलेक्टर द्वारा एफ.आर.ए. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही की गई है एवं नियमानुसार वृक्ष कटाई की अनुमति दी गई है। विरोध करने वाले जन प्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों पर पुलिस एवं उद्योगपतियों के नुमान्दों पर कोई भी बल पूर्वक अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गयी है। यह सही नहीं है कि आज भी हजारों की तादाद में ग्रामीण सरकार के इस कृत्य के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, बल्कि सही यह है कि मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही संबंधित विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में नियमों का पालन करते हुए किया गया।

यह सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव क्षेत्र को उजाड़ा जा रहा है। अब तक लाखों वृक्ष रिकॉर्ड पर तथा लाखों वृक्ष रिकॉर्ड के बाहर काट डाले गये हैं। यह सही नहीं है कि इस सरकार को वन पर्यावरण, जैवविविधता, जलवायु, वन्य प्राणी रहवास से कोई सरोकार नहीं है। सही यह है कि हसदेव अरण्य कोल फील्ड के लिए NGT और उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (ICFRE) तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के द्वारा सम्पूर्ण जैव विविधता का अध्ययन करके प्रस्तुत रिपोर्ट के परसा ईस्ट केते बासेन एवं परसा कोल ब्लॉक को विचार किया जा सकता है। (Can be considered) की श्रेणी में रखा गया है। यह सही नहीं है कि रिपोर्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर कार्यवाही की गयी है। यह सत्य नहीं है कि बस्तर के भानुप्रतापपुर में आरीडोंगरी क्षेत्र में अनेक घन वृक्षों को काट दिया गया। बल्कि सही यह है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम अंतर्गत 138.960 हे. वन भूमि व्यपवर्तन गोदावी पॉवर एण्ड इस्पात के पक्ष में 2008 एवं 2015 में स्वीकृति पश्चात् अधिनियम के निहित प्रावधानों एवं स्वीकृत माईनिंग प्लान अनुसार आवेदक संस्थान से प्राप्त आवेदन के आधार पर 28,922 वृक्ष नियमानुसार काटे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा यही प्रश्न है और लगातार यही प्रश्न उठा रहा है कि वहां फर्जी जन सुनवाई हो रही है, फर्जी तरीके से ग्राम सभा का प्रस्ताव किया जा रहा है । सरपंच वहां पर जाकर शिकायत कर रहे हैं। (व्यवधान) बिलासपुर जिले, सरगुजा जिले में भी इस प्रकार की अवैध पेड़ कटाई हो रही है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- पेड़ कटैया के संरक्षण हे । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- अडानी के इशारे पर ये सारे पेड़ कट रहे हैं । (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए गर्भगृह में आये)

समय :-
12:32 बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपना स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं :-

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

1. माननीय डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल
3. श्रीमती अनिला भेंडिया
4. श्री उमेश पटेल
5. श्री लखेश्वर बघेल
6. श्री दलेश्वर साहू
7. श्री लालजीत सिंह राठिया
8. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
9. श्री दिलीप लहरिया
10. श्री रामकुमार यादव
11. श्री द्वारिकाधीश यादव
12. श्रीमती अंबिका मरकाम
13. श्रीमती संगीता सिन्हा
14. श्री कुंवर सिंह निषाद
15. श्री देवेन्द्र यादव
16. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा
17. श्री इन्द्रशाह मण्डावी
18. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
19. श्री विक्रम मण्डावी
20. श्रीमती विद्यावती सिदार
21. श्रीमती फूलसिंह राठिया
22. श्री अटल श्रीवास्तव

23. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
24. श्री ब्यास कश्यप
25. श्री बालेश्वर साहू
26. श्रीमती शेषराज हरवंश
27. श्रीमती चातुरी नंद
28. श्रीमती कविता प्राण लहरे
29. श्री संदीप साहू
30. श्री इंद्र साव
31. श्री जनक ध्रुव
32. श्री ओंकार साहू
33. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं । मैं निलंबन की अवधि बाद में निर्धारित करूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको एक गाईड दे दीजिए यह बताने के लिए कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा कहां पर लगी है, नया विधान सभा भवन बना है । उधर उनकी प्रतिमा बनी है, खोजते हुए महात्मा गांधी जी के पास जाईए ।

समय :-
12:34 बजे

निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 250 (1) के तहत निम्न सदस्य अपना स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए थे, अत: मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे।

समय
12.35 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश में संचालित औद्योगिक ईकाईयों में व्याप्त अव्यवस्था, कुप्रबंध एवं सुरक्षा व्यवस्था का अभाव होना।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद), नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) एवं श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

प्रदेश में कारखाना अंतर्गत बढ़ती दुर्घटनाओं तथा सुरक्षा की उपेक्षा से होने वाली जनहानियां निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश खनिज संपदा और औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण केन्द्र है। लेकिन लगातार औद्योगिक सुरक्षा में लापरवाही के कारण जनहानि से जूझ रहा है। कारखानों में विस्फोट, गैस रिसाव, लिफ्ट टूटना और संरचनाओं का ढेर हो जाना जनहानि का कारण बनते जा रहा है। हाल ही में दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 को जांजगीर-चांपा के डभरा में स्थित आर. के. पावर प्लांट में चलती लिफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण 40 मीटर की ऊँचाई से अचानक नीचे गिरने के कारण 4 श्रमिकों की मृत्यु हो गयी साथ ही 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुये। इसके पूर्व भी दिनांक 26 सितंबर, 2025 को रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में गोदावरी इस्पात फैक्ट्री में निर्माण कार्य के दौरान छत ढह जाने के कारण 6 मजदूरों की मौत और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए तथा दिनांक 6 अगस्त, 2025 को बिलासपुर के एन.टी.पी.सी. प्लांट में भारी भरकम स्लैब गिर जाने के कारण 1 मजदूर की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल हो गये। पिछले 13 माह के अन्दर 17 हादसे हो चुके है जिसमे 40 से अधिक श्रमिक असमय अपनी जान गवां चुके हैं। वहीं राज्य की औद्योगिक इकाईयों में लगातार हो रही इस तरह की दुर्घटनाएं गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं, जिसमें ऐसी दुर्घटनायें स्पष्ट करती हैं कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो सुरक्षा नियमों को सिर्फ कागजी कार्यवाही तक सीमित रख दिया गया हैं तथा संबंधित विभागों की ढीली निगरानी इस समस्या को और भी बढ़ावा दे रही है। ना तो समय पर निरीक्षण किया जाता है और ना ही ऑडिट किया जाता है। आज स्थिति ऐसी बन चुकी है की श्रमिक वर्ग की जान की कीमत एक दिन की रोजी-रोटी के बराबर हो चुकी हैं जो रोजगार के लिये अपने जान जोखिम में डालकर काम करने के लिये मजबूर हो चुके हैं, जिसके कारण प्रदेश के श्रमिक वर्ग में प्रशासन के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश में कारखाना अन्तर्गत बढ़ती दुर्घटनाओं तथा सुरक्षा की उपेक्षा से होने वाली जनहानियां निरंतर बढ़ती जा रही है। यह कहना सही है कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा और औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण केन्द्र है। किन्तु यह कहना सही नहीं है कि लगातार औद्योगिक सुरक्षा में लापरवाही के कारण जनहानि से जूझ रहा है। विभाग द्वारा कारखानों में औद्योगिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में कारखानों में घटित दुर्घटनाओं की संख्या में तथा मृतक श्रमिकों की संख्या में कमी आयी है।

समय :
12.40 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेंडी) पीठासीन हुए)

यह कहना सही नहीं है कि, जांजगीर-चांपा के डभरा में स्थित आर. के. पावर प्लांट में दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 को दुर्घटना घटित हुई थी। अपितु राज्य के सक्ती जिले में स्थापित मेसर्स-आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, के बॉयलर क्रमांक-02 में दिनांक 07 अक्टूबर, 2025 को मरम्मत कार्य के दौरान लिफ्ट का उपयोग कर बॉयलर में ऊपर जाने के दौरान वायर रोप के टूट जाने पर लगभग 40 मीटर की ऊंचाई से लिफ्ट अचानक नीचे गिरने के फलस्वरूप लिफ्ट में उपस्थित 10 श्रमिकों में से 04 श्रमिकों की मृत्यु हुई तथा 06 श्रमिक घायल हुए। इस दुर्घटना की अविलंब जांच कर कारखाने में स्थापित समस्त लिफ्ट के उपयोग तथा बॉयलर क्रमांक 2 में मेन्टेनेंस कार्य को प्रतिबंधित करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया तथा कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध माननीय श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दायर किया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि, दिनांक 26 सितंबर, 2025 को रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड में निर्माण कार्य के दौरान छत ढह जाने के कारण 6 मजदूरों की मौत और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। अपितु मेसर्स-गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड में स्थापित 1.8 MTPA पैलेट प्लांट के ट्रैवलिंग ग्रेट बिल्डिंग के फर्नेस चैम्बर PH-02 में जमा हुए एक्रेशन को तोड़कर निकालने के कार्य के दौरान गर्म एक्रेशन की परत कास्टेबल वॉल सहित अंदर कार्यरत श्रमिकों के ऊपर अचानक गिरने से घटी दुर्घटना के परिणामस्वरुप 06 श्रमिकों की मृत्यु हुई तथा 06 श्रमिक घायल हुए। इस दुर्घटना की अविलंब जांच कर कारखाने में 1.8 MTPA पैलेट प्लांट में विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन एवं मेन्टेनेंस सहित समस्त कार्यों को प्रतिबंधित करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया तथा कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध माननीय श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दायर किया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि, दिनांक 6 अगस्त, 2025 को बिलासपुर के एन.टी.पी.सी. प्लांट में भारी भरकम स्लैब गिर जाने के कारण 1 मजदूर की मौत और 4 गंभीर रूप से घायल हो गयें। अपितु कारखाना मेसर्स-एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ग्राम- सीपत, पोस्ट-उज्जवल नगर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) में स्थापित यूनिट क्रमांक-5 के बॉयलर के एयर प्री हीटर में मरम्मत के लिए लगभग 22 मीटर ऊंचाई पर निर्मित लोहे के प्लेटफार्म पर खड़े होकर एयर प्री-हीटर केज की सफाई करने के दौरान उक्त प्लेटफार्म के अचानक टूटकर नीचे गिर जाने के परिणामस्वरूप प्लेटफार्म पर उपस्थित 05 श्रमिकों में से 02 श्रमिक की मृत्यु हुई तथा 03 श्रमिक घायल हुए। इस दुर्घटना की अविलंब जांच कर कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए कारखाना प्रबंधन के विरूद्ध माननीय श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दायर किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि, राज्य की औद्योगिक इकाइयों में लगातार हो रही इस तरह की दुर्घटनाएं गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं जिसमें ऐसी दुर्घटनायें स्पष्ट करती

हैं कि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। अपितु कुछ कारखानों में प्रबंधन द्वारा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन नहीं किये जाने के कारण दुर्घटनाएं घटी हैं। जिनमें विभाग द्वारा अविलंब कड़ी कार्यवाही की गयी है।

यह कहना सही नहीं है कि, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो सुरक्षा नियमों को सिर्फ कागजी कार्यवाही तक सीमित रख दिया गया है तथा संबंधित विभागों की ढीली निगरानी इस समस्या को और भी बढ़ावा दे रही है, ना तो समय में निरीक्षण किया जाता है और ना ही ऑडिट किया जाता हैं। उल्लेखनीय है कि, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के तहत समस्त खतरनाक कारखानों का वर्ष में एक बार रेण्डम पद्धति के माध्यम से निरीक्षण किया जाकर कारखानों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की जाती है। साथ ही कारखानों में दुर्घटना घटित होने पर विभाग के अधिकारियों द्वारा त्वरित रूप से दुर्घटना जांच कर आपराधिक प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय में दायर करने की कार्यवाही की जाती है तथा खतरनाक कार्यस्थलों हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया जाता है। राज्य में संचालित अति खतरनाक कारखानों में सेफ्टी ऑडिट प्रति दो वर्ष में एवं आंतरिक रूप से प्रतिवर्ष कराया जाना निर्धारित है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है, साथ ही अन्य खतरनाक कारखानों में भी आवश्यकतानुसार कारखाना प्रबंधन द्वारा सेफ्टी ऑडिट कराया जाता है।

वर्ष 2024 में विभाग द्वारा राज्य में स्थापित कारखानों में कुल 1266 निरीक्षण कर कारखाना प्रबंधनों के विरूद्ध 373 आपराधिक प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय में दायर किये गये। इस अवधि में माननीय श्रम न्यायालय द्वारा कारखाना प्रबधनों को रूपये 97,13,500/-(97 लाख, 13 हजार, 500 रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। वर्ष 2025 में नवम्बर 2025 तक कारखानों में कुल 916 निरीक्षण कर 266 आपराधिक प्रकरण माननीय श्रम न्यायालय में दायर किये गये है। इस अवधि में माननीय न्यायालय द्वारा कारखाना प्रबधनों को रु. 5,66,85,500/-(5 करोड़, 66 लाख, 85 हजार, 500 रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विभाग द्वारा राज्य में संचालित कारखानों में समय-समय पर मॉकड्रिल एवं सुरक्षा प्रशिक्षण इत्यादि का आयोजन कराया जाकर नियोजित श्रमिकों में कार्य के दौरान सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ायी जाती है।

अतः यह कहना सही नहीं है कि श्रमिक वर्ग की जान की कीमत एक दिन की रोजी-रोटी के बराबर हो चुकी हैं। जो रोजगार के लिये अपने जान जोखिम में डालकर काम करने के लिये मजबूर हो चुके हैं, जिसके कारण प्रदेश के श्रमिक वर्ग में प्रशासन के प्रति काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त हैं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर दो-तीन पन्नों का है। उसको कम किया जा सकता था। इस पर आप भविष्य में ध्यान दीजियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, कृत्य कहूं या क्या कहूं। इतने लंबे-लंबे उत्तर है कि यह नियम से भी मोटा है। जो कारखाना अधिनियम है, उससे ज्यादा मोटा इसका उत्तर है। उत्तर में कितनी

संवेदनशीलता है? मेरे ख्याल से दुर्घटना को लेकर विभाग संवेदनहीन हो चुका है। सभापति महोदय, उत्तर में क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, आप उसको पढ़िये। परिणामस्वरूप वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में कारखानों में घटित दुर्घटनाओं की संख्या में तथा मृतक श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। मतलब श्रमिकों की मृत्यु कम हो रही है, वह आपके लिए संतोषप्रद है? आप भाषा तो ठीक से लीखिये। आप जो लिखते हैं, उसमें संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। कम मृत्यु हुई है, वह ठीक है। दूसरा, इन्होंने स्वीकार किया है। मैं प्रश्न करता हूं। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधता हूं। राज्य में संचालित अति खतरनाक कारखानों में सेफ्टी ऑटिड प्रति दो वर्ष में एवं आंतरिक रूप से प्रतिवर्ष कराया जाना निर्धारित है। यह फैक्ट्री एक्ट में है। मैं आपको फैक्ट्री एक्ट की कॉपी दे देता हूं। लेकिन आप कैसे चला रहे हैं, आप उसको आगे सुनिये। जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। मतलब अब तक अनुपालन नहीं हो रहा है। आप अभी अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। मैंने नाम दिया है, वह एक उदाहरण है। मुझे किसी व्यक्ति या कारखाने से कोई मतलब नहीं है। मुझे असली मतलब है कि कारखानों में दुघर्टना बढ़ रही है। मैंने इसमें भिलाई कारखाने का उल्लेख नहीं किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फैक्ट्री एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ में कितने कारखाने पंजीकृत हैं और आपने उसमें कितने कारखाने का दो साल में निरीक्षण करवाया है? दुर्घटना न हो, इसके लिए निरीक्षण के बाद आपने क्या-क्या सुझाव दिया है?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदय पूरे प्रदेश में पंजीकृत कारखानों की संख्या पूछ रहे हैं। जबकि उन्होंने तीन प्लांटों की जानकारी मांगी है। मेरे पास तीन प्लांटों की पूर्ण रूप से जानकारी है। तीनों प्लांटों में जो-जो जांच हुई है कि उसमें कैसे दुर्घटना घटित हुई है। मैं इसके बारे में जानकारी दे दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मुझे पूरा जानकारी से मतलब नहीं है। मंत्री जी, आपने उत्तर में लिखा है कि संचालित अति खतरनाक कारखानों में सेफ्टी ऑडिट प्रति दो वर्ष में एवं आंतरिक रूप से प्रतिवर्ष कराया जाना निर्धारित है, जिसका अनुपानल सुनिश्चित किया जा रहा है। यदि माननीय मंत्री के पास पंजीकृत कारखानों की संख्या नहीं है। वह मुझे मत बताये कि उन्होंने कितने बार निरीक्षण किया है। यह बहुत खेदजनक है। यह तो मुखाग्र रखने वाली चीज है कि दो हजार, पांच हजार कारखाने पंजीकृत हैं। मैंने यह कहा कि मैंने इसमें तीन-चार कारखाने उदाहरण के तौर पर लिखा है। मेरा असली उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में दुर्घटना बढ़ रही है। आप इन तीन कारखानों में ही मुझे बता दीजिए कि आपने दो वर्ष में उनका कितनी बार निरीक्षण किया है? निरीक्षण के पश्चात् क्या-क्या कमी पायी गयी है? निरीक्षण दल में कौन-कौन थे? उसमें किस स्तर के अधिकारी थे और उसके बाद निरीक्षण के पश्चात् आपने क्या-क्या सुझाव दिया?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पूरे प्रदेश में स्थापित कारखाने की जानकारी पूछा था...।

श्री अजय चन्द्राकर :- रहने दीजिए, अब उसके आगे बढ़ गये ।

श्री लखनलाल देवांगन :-उसको भी बता देता हूँ । 7489 कारखाना स्थापित है, जिसमें अति खतरनाक कारखाना 32 है, खतरनाक कारखाना 1006 है, गैर खतरनाक 6451 है, जिसमें लगभग 4 लाख 37 हजार 659 श्रमिक नियोजित हैं । आपने जो 3 प्लाण्ट का पूछे हैं, उसमें से पहले कौन सा बता दूँ ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, चूँकि आपने मुझे निर्धारित किया कि 3 प्लाण्ट के बारे में ही बात कीजिए । मैं जानता था कि ये बोलेंगे, इसीलिए कहा कि मेरा उद्येश्य 3 की संख्या नहीं है । मेरा उद्येश्य प्रदेश में बढ़ती हुई औद्योगिक दुर्घटनायें है । मैंने बीएसपी को भी कहा, लेकिन मैं उसको नहीं लिख पाया । जब आप मुझे तीन में सीमित किये हैं, आप 3 में ही बताईये कि 2 साल में किस स्तर के कौन-कौन अधिकारियों ने कितने बार निरीक्षण किया ? वह कारखाना अति खतरनाक है, खतरनाक है, आडिट या निरीक्षण में क्या कमियॉ पाई गई और उसमें ठीक करने के लिये आपने क्या-क्या सुझाव दिये और वह ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, आर.के.जैन पॉवर प्रायवेट लिमिटेड कारखाना के विरूद्ध कार्यवाही अधिनियम 1948 के 40 बी के तहत समस्त लिफ्ट उपयोग, बायलर के कराये जा रहे मैंटेनेंस कार्य को पुन: तत्काल प्रभाव से रोके जाने हेतु कारखाना प्रबंधन 8-10-2025 दिनांक को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है । कारखाना में घटित जांच के उपरांत ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अब जब मुझे 3 में ही निर्धारित किया गया है तो मुझे वही उत्तर चाहिये । मुझे इधर-उधर की जानकारी चाहिये ही नहीं ? मैंने 2 साल में इन तीन कारखाने में पूछा है कि कितनी बार, कौन-कौन स्तर के अधिकारियों ने निरीक्षण किया ? मेरा प्रश्न पूरा हो जाने दीजिए, मैं दोहरा रहा हूँ और उसमें क्या-क्या कमियॉ पाई गई तथा उसको सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं, विभाग की इसके पास जानकारी आई है कि नहीं आई है, मैंने यह पूछा है ? वह कारखाने जो आपने अति खतरनाक, खतरनाक सहित तीन श्रेणी में बतायें हैं, वह कौन सी श्रेणी के हैं ? इतने में ही मेरा पाईंटेड प्रश्न है और मैं पाईंटेड उत्तर ही चाहता हूँ ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, आर.के.पॉवर जैन प्रायवेट लिमिटेड ग्राम उजबिंडा, पोस्ट ध्रुवकोट, तहसील डभरा के सक्ती में वार्षिक निरीक्षण की कार्यवाही जो है, इसमें 15-03-2024 के शिकायत के आधार पर निरीक्षण ओव्हर टाईम भुगतान में 12 घण्टा कालावधि विश्राम सहित कार्य कराया जाना पाया गया । श्रम न्यायालय द्वारा 4/2025 को 5 हजार अर्थदण्ड आरोपित किया गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह तो मैंने पूछा ही नहीं है ?

सभापति महोदय :- उसी में तो है ना ?

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये साब, माननीय सभापति जी । आपने मुझे लिमिट किया है तो मेरी लिमिट में आप भी रहिये ।

सभापति महोदय :- नहीं मैं ऐसा लिमिटेशन...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किसी की शिकायत में जांच किये हैं । यह बता रहे हैं कि मैंने कहा है कि आप दो साल में स्वमोटो, विभाग का जो दायित्व है दो साल में, फैक्ट्री एक्ट इस बात को बोलता है कि साल में दो बार निरीक्षण होगा । आपने इन तीनों फैक्ट्रियों का जो ध्यानाकर्षण में उल्लेख है, दो साल में कितनी बार कौन-कौन अधिकारियों ने कितनी बार निरीक्षण किया, क्या-क्या कमी पाई, उस कमी को सुधारने के लिये क्या-क्या कदम उठाये, विभाग को सूचना दी है कि नहीं दी है, कमी को ठीक करके वह कारखाना कौन सी श्रेणी का कारखाना है ? यह मेरा पहला प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, जो सदस्य पूछ रहे हैं, कौन अधिकारी हैं, कब गये, आप उसका पाईंटेड उत्तर दीजिए ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, कारखाना अधिनियम के रेण्डम जांच की प्रक्रिया है, इसमें साल में एक बार रेण्डम जांच होती है, शिकायत मिलने पर अलग से जांच होती है, कोई दुर्घटना घटित होती है तो अलग जांच होती है, इस तरह से जांच की प्रक्रिया है । कंपनी में निरंतर रूप से जांच हो रही है, ऑनलाईन रेण्डम की पद्धति है, उसके तहत् एक साल में एक बार जांच की जाती है, अगर किसी उद्योग के बारे में शिकायत मिलती है तो उसकी तत्काल जांच कराई जाती है, कभी-कभी माननीय न्यायालय में भी याचिका दायर होती है कि जांच कराई जाए तो कोर्ट से भी निर्देश होता है, उसके लिए भी जांच कराई जाती है। इस तरह से जैसे आर.के.एम. पॉवर प्लांट में ही अलग-अलग शिकायत और दुर्घटना के आधार पर 2 साल में 9 बार जांच कराई गई है, इस तरह से पूरी जांच की प्रक्रिया है।

सभापति महोदय :- जांच में कौन-कौन गए, वह भी बताईए।

श्री लखन लाल देवांगन :- सभापति महोदय, जांच में औद्योगिक सुरक्षा के अधिकारी जाते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, जब तक मेरे पहले प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आएगा मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। क्या नियम है, क्या कानून है, मंत्री जी जाने, वे विभाग चलाते हैं। आपने शिकायत में 9 बार जांच की, मैंने तीनों के बारे में पूछा है, आपने मुझे तीन के बारे में कहा है। मेरे तीन प्रश्नों का पहला प्रश्न है, सीनियर अधिकारी जांच किए हैं, जूनियर अधिकारी जांच किए हैं, मेरे को मतलब नहीं है, कौन-कौन अधिकारी जांच किए हैं ? उसका पदनाम बताईए। सीधी सी बात है, एक लाईन में बताईए।

समय :

12.56 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

उसके बाद मैंने तीनों कारखाने के बारे में पूछा है, आर.के.एम. भर का नहीं पूछा है, उसमें कितनी बार जांच हुई है ? क्या-क्या कमी पाई गई ? उस कमी को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए है ? विभाग को सूचना है या नहीं है ? चौथी बात, वह कारखाना कौन सी श्रेणी का है ? मैं बार-बार वही बात पूछ रहा हूं। आप उतने में ही सीमित रहिए, बाकी मेरे पास फैक्ट्रियों की जानकारी है।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, NTPC अति खतरनाक श्रेणी में आता है, आर.के.एम. और गोदावरी है, वह खतरनाक श्रेणी के कारखानों में आते हैं। जैसे माननीय वरिष्ठ सदस्य पूछ रहे हैं कि किस अधिकारी द्वारा जांच की गई तो मैंने पहले ही बताया कि हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकारी जांच किए हैं, अब मैं उसका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, आपको नाम चाहिए तो मैं नाम दे दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत प्रश्न हो गए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन से ज्यादा ध्यानाकर्षण थोड़ी होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- एक आखिरी प्रश्न छोटा सा करिए। तीन-तीन महारथी हो, आप अकेले नहीं हो, चरण दास जी भी हैं, धर्मजीत जी भी हैं, वे प्रश्न कर लेंगे, आप आखिरी में एक छोटा सा प्रश्न कर लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण इस बात के लिए चाहूंगा, आप नहीं बोलेंगे मैं नहीं करूंगा, मैं आपकी अवहेलना नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने औद्योगिक दुर्घटना से संबंधित प्रश्न पूछा तो आपने उत्तर दिया कि मेरे पास तीन कारखानों की ही जानकारी है। मैंने तीन कारखानों के बारे में पहला प्रश्न किया उसका पूरा उत्तर नहीं आया, NTPC और दो कारखानें खतरनाक और गैर खतरनाक हैं, आप अधिकारियों का नाम भी मत बताईए, मैं इसमें भी सहमत हूं। लेकिन उसके और पार्ट हैं, हमने तीन बार निरीक्षण किया, दो बार निरीक्षण किया, ये बता दीजिए, ये-ये कमी पाई गई और उन्होंने उसको सुधार करके आपको रिपोर्ट दी या नहीं दी, ये बता दीजिए, फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं आपका प्रश्न हो गया। चलिए।

श्री अजय चंद्रकार :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न का ही उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय :- आधा घंटा हो गया चलिए।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब दे दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- रहने दीजिए मत दीजिए। जवाब नई चाहिए।

श्री लखन लाल देवांगन :- आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो ? जवाब नहीं चाहिए तो मत लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- जब मुझे जवाब नहीं चाहिए तो आप क्यों जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। महंत जी।

नेता प्रतिप्रक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मामला पूरा गरम हो चुका है। एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ आग सुलग रही है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप हथौड़ा मत मारिए गरम हो गया है।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं नहीं मारूंगा, मैं बहुत सीधा सादा आदमी हूं, दोनों मेरे क्षेत्र के हैं, इसलिए मैं आपको तीन प्रश्न शामिल करके बहुत छोटा सा एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय चंद्राकर जी ने बताया, जैसे आपके यहां जांच के निर्देश हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी तीनों फैक्ट्री में सरप्राईज इंस्पेक्शन किया है ? जैसा कि आपको पता है, मरने वाले जितने लोग हैं, वे ठेके श्रमिक होते हैं, गरीब श्रमिक होते हैं, क्या आपने इनको पर्याप्त मुआवजा दिया ? तीनों श्रेणी के अलग-अलग फैक्ट्री में कितना-कितना मुआवजा दिया है ? यह मुझे बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए मुआवजा के बारे में बता दीजिए।

समय :
1.00 बजे

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बड़ी गंभीरता के साथ मुआवजा के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं उसके संबंध में आपको बताना चाहूंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- मैंने मुआवजा के बारे में गंभीरता से नहीं पूछा है। मैंने गंभीरता से यह पूछा है कि क्या पिछले 1 साल में कभी भी कहीं भी surprise inspection हुआ है? आप बाकी को मत बताइये।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, लगातार inspection हो रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- क्या surprise inspection हुआ है? बताकर जाने और बिना बताए जाने में अंतर है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, हम बिना बताए जाते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- आप बिना बताए तो कई जगहों में जाते हैं। मुझे पता है।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको मुआवजा के बारे में अलग-अलग फैक्ट्रीवार बता देता हूं। गोदावरी एण्ड पॉवर लिमिटेड में मृतकों के आश्रितों को प्राप्त मुआवजा आर्थिक सहायता राशि में हमारे कुल 6 श्रमिकों की मृत्यु हुई। जिसमें श्री जे.एन. प्रसन्ना को 46 लाख रूपये का मुआवजा और जब तक उनकी नौकरी की डेट बची है, उतनी तक उनके आश्रितों को प्रतिमाह उनकी तन्ख्वाह 1,38,908 रूपये दी जा रही है। उसी तरह से घनश्याम घोरमारे, उम्र 46 वर्ष को 46 लाख रूपये का मुआवजा और उनके आश्रित व्यक्ति को प्रतिमाह उनकी तन्ख्वाह 61,567 रूपये दी जा रही है। उसी तरह से निराकार मालिक को 46 लाख रूपये का मुआवजा और उनके आश्रितों को प्रतिमाह उनकी तन्ख्वाह 73,753 रूपये दी जा रही है। साथ ही कलियागोटाला कुमार को 46 लाख रूपये का मुआवजा और उनके परिवारजनों को 69,936 रूपये दिया जा रहा है। साथ ही तुलसीराम भट्ट जी को 46 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया। उनकी उम्र 31 वर्ष थी। उनका एस.आई में पंजीयन है तो वह एस.आई. के तहत अभी विचाराधीन है, उसको भी कंपनी अधिनियम के तहत राशि मिलेगी। उसी तरह से नारायण साहू, उम्र 39 वर्ष को 46 लाख रूपये का मुआवजा और उसका एस.आई. के तहत पंजीयन है तो उनकी मासिक पेंशन का निर्धारण अभी प्रक्रियाधीन है। उसी तरह से हमारे आर.के.एम. पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के 4 श्रमिकों की मृत्यु हुई है। श्री मिश्रीलाल जी को 15 लाख रूपये मुआवजा और कारखाना प्रबंधन कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम के तहत मुआवजा राशि 11 लाख 48 हजार रूपये तथा श्रम न्यायालय का जो भी आदेश होगा, उसके अनुसार उनको और मुआवजा मिलेगा। उसी के साथ श्री अंजनी कुमार को 15 लाख रूपये का मुआवजा और कारखाना अधिनियम के तहत उनको भी 13 लाख 81 हजार 275 रूपये प्राप्त होगा। उसी तरह से श्री रविन्द्र कुमार जी को भी कारखाना प्रबंधन कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम के तहत 15 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया है और कारखाना अधिनियम के तहत 14 लाख 95 हजार 500 रूपये का और मुआवजा मिलेगा। बबलू प्रसाद जी को 15 लाख रूपये मुआवजा और कारखाना प्रबंधन के तहत 15 लाख 74 हजार 400 रूपये और मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- यह बहुत हो गया। आप एक प्रश्न और कर लीजिए। यह सब तो बता चुके हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मृतकों के बारे में तो बता दिया, लेकिन घायलों के बारे में नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय :- वह सब तो पढ़ रहे हैं। आप उनको और कितना पढ़वाएंगे?

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, उन्होंने घायलों के बारे में नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप घायलों की भी जानकारी पढ़ दीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप कहां आ गये। मंत्री जी, आप घायलों का पढ़िये।

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, जैसे गोदावरी इस्पात में 6 कर्मचारी घायल हुए थे तो वह सभी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गये हैं। 5 स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनका एक कर्मचारी उपस्थित हो गया है और बाकी जो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनको उनकी पूरी मासिक तन्ख्वाह दी जा रही है। उसी तरह से सभी कंपनियों में किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी, क्या आपका कोई प्रश्न बचा है?

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण श्रमिकों की सुरक्षा के लिए लगा है और आपने कृपापूर्वक यहां पर उसको स्थान दिया। मैं घायल, मरे, कम हुए, ज्यादा हुए, इस पर नहीं पूछता। मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें पूछना चाहता हूं। आप पहला तो यह बताईये कि भिलाई स्टील प्लांट, एस.ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी. कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर और कोल इंडिया में आपको सेफ्टी, लेबर की सेफ्टी और फायर ऑडिट करने का अधिकार है या नहीं है ? दूसरा, क्या आप इस प्रदेश में दुर्घटना न हो, इसके लिए पूरे जनवरी के महीने में अति खतरनाक और खतरनाक संयंत्रों पर योजनाबद्ध तरीके से और उसको एक टास्क के रूप में लेबर सेफ्टी और फायर ऑडिट दोनों की जाचं करायेंगे ? क्या पूरे एक महीने में पूरे प्रदेश के हर संयंत्र की आपके विभाग के द्वारा जांच की जायेगी ? आप तो लेबर डिपार्टमेंट के भी हैं तो जरा देखिये कि गोवा सरीखे यहां भी आग न लग जाये। वहां 15 लेबर मर गये। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उस दिशा में भी जहां-जहां फायर ऑडिट हो सकता है, क्या आप करायेंगे ? आप यह बताईये कि आपको भिलाई स्टील प्लांट, एन.टी.पी.सी., एस.ई.सी.एल. और रेलवे की सेफ्टी के लिए जांच करने का पॉवर है या नहीं है ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को एस.ई.सी.एल. का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त आपने और जिन कारखानों के नाम बताये हैं उनका अधिकार है। उसी तरह से आप जो पूछ रहे हैं कि औद्योगिक सुरक्षा, श्रम विभाग के द्वारा दुर्घटना में कमी लाने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रयास नहीं पूछ रहा हूं। आपका प्रयास बहुत बढ़िया हैं। आपका जवाब भी ठीक है। मैं तो सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि जो 2026 का जनवरी लगेगा, क्या उस जनवरी के पूरे महीने में पूरे प्रदेश के हर उद्योग का आपके विभाग के द्वारा सेफ्टी, फायर ऑडिट और लेबर सेफ्टी की जांच करायेंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, Random पद्धति से जांच कराने की प्रक्रिया है और माननीय सदस्य विधान सभा में बोल रहे हैं कि क्या जांच करायेंगे तो हम निश्चित तौर पर जांच करायेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, एक प्रश्न आप भी कर लीजिये।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भिलाई स्टील प्लांट में यह महसूस करते हैं और लगातार देखते हैं कि हर महीने कोई न कोई श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मैं अगर पिछले दो सालों की बात कहूं तो पिछले दो सालों में भिलाई स्टील प्लांट में हादसे में दो दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इसको लेकर पिछले समय में क्या विभाग ने कोई कार्रवाई की है ? क्या आगामी समय में उसमें कोई निरीक्षण करके और जो सुरक्षा मानक है, उसको लेकर कोई विशेष कदम उठायेंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में कहा है। वह ध्यानाकर्षण में नहीं है। अगर वह अलग से कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं उनको जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। अनुज जी, पूछ लीजिये।

श्री अनुज शर्मा (धरसीवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने अवसर दिया। मैं इंडस्ट्रियल एरिया का जनप्रतिनिधि हूं और मैं आपको जमीनी सच्चाई बताना चाह रहा हूं। इस प्रश्न का जो मूल उद्देश्य है, सच यह है कि ऐसे सैकड़ों कारखाने हैं, जहां पर 12 घण्टे की शिफ्ट चलती है और 8 घण्टे का पेमेंट दिया जाता है, यह सच है। सुरक्षा उपकरणों की तो व्यवस्था ज्यादातर फैक्ट्रियों में नहीं है, जो ज्यादातर दुर्घटनाओं के कारण हैं। उसके प्रति मैं समय-समय पर लगातार सवाल भी पूछता रहा हूं। इस पर एक विषय लेबर के स्वास्थ्य जांच की बात का था । उस पर भी बहुत अनियमितताएं पाई गई थीं। इन सभी विषयों में मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाले समय के लिये क्या कोई योजना है, जिससे इन सारी बातों का निराकरण हो सके और हमारे श्रमिक बंधुओं की समस्या का उपाय सुनिश्चित हो सके ? क्या इन्होंने उस पर कोई कार्ययोजना बनाई है कि आगे उनका जीवन सुरक्षित हो सके ? लगातार दुर्घटनाएं होती रहती है।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा लगातार प्रयास भी किया जा रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कारखनों की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे जांच अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करायी जानी है। साथ ही Random पद्धति के कारखानों का कारखाना अधिनियम अंतर्गत सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण किया जाता है।

कारखाना के विस्तृत जांच उपरांत किये गये उल्लंघनों पर वैधानिक कार्रवाई कर प्रकरण माननीय न्यायालय में दायर की जाती है। इस तरह से बहुत सारे उपाय अभी आने वाले समय में और अच्छा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष मैं कोई विशेष अभियान की बात कर रहा हूं, यह तो करते आ रहे हैं, यह पर्याप्त नहीं है। यह लगातार घटनाएं हो रही हैं। मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या कोई विशेष अभियान चलायेंगे?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसे पूछा कि श्रमिकों को 8 घंटे की जगह ज्यादा काम समय काम कराते हैं। अगर इस प्रकार का कोई काम कराते हैं, उनको ओवरटाइम का प्रावधान है। अगर ओवरटाइम नहीं देता है तो शिकायत करें। मैंने पहले ही बताया कि जांच की पद्धति रेंडम पद्धति से होती है। अगर किसी उद्योग में आपको लगता है तो आप लिखित में दें, निश्चित तौर पर जांच करायेंगे।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय ओ.पी. चौधरी वित्त मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लाबी स्थित कक्ष में, पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन की व्यवस्था भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) सिहावा विधान सभा क्षेत्र में नगरी विकासखण्ड की 18 शालाओं के भवनों की जर्जर स्थिति होना।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड नगरी में 18 प्राथमिक व माध्यमिक शालायें यथा अमलीपारा, खडपथरा, सरईटोला, ठेनही, बासीन, प्रेमनगर, बनोरा, नवागांव, जोगीबिरदो, बुडरापारा, गाताबाहरा, मादागिरी, अमलीपार, गिधावा, खमनापारा, खरका व पूर्व माध्यमिक शाला सिहावा, छिपली के भवन जर्जर व अति जर्जर हो गये हैं जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। भवन की दीवारें टूटने लगी हैं और प्लास्टर लगातार गिर रहा है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पालकों ने अपने बच्चों को पुराने भवन में पढ़ाने से मना कर दिया है। मजबूरी में अब स्कूल की कक्षायें खुले मैदान या अन्य सामाजिक भवन में संचालित करने को मजबूर हो रहे हैं। पालकों के द्वारा

स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जल्द ही नये भवन के निर्माण की व्यवस्था नहीं किये जाने पर स्कूल में तालाबंदी कर आंदोलन करेंगे। पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों के मरम्मत हेतु करोडों रुपये जारी किये गये तथा दर्शित 18 स्कूलों में नवीन भवन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी भेजा गया है। किन्तु आज पर्यनत उल्लेखित विद्यालयों की मरम्मत नहीं कराई गई है और ना ही नवीन भवन की स्वीकृति मिली है। मरम्मत व नवीन भवन की स्वीकृति नहीं मिलने से पालकों में प्रशासन के प्रति जन आक्रोश व्याप्त है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगरी में संचालित 16 प्राथमिक शाला क्रमशः शासकीय प्राथमिक शाला अमलीपारा,

शासकीय प्राथमिक शाला खडपथरा, शासकीय प्राथमिक शाला सराईटोला, शासकीय प्राथमिक शाला ठेनही, शासकीय प्राथमिक शाला बासीन, शासकीय प्राथमिक शाला प्रेमनगर, शासकीय प्राथमिक शाला बनोरा, शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव, शासकीय प्राथमिक शाला जोगीबिरदो, शासकीय प्राथमिक शाला बुडरापारा, शासकीय प्राथमिक शाला गाताबाहरा, शासकीय प्राथमिक शाला मादागिरी, शासकीय प्राथमिक शाला अमलीपारा, शासकीय प्राथमिक शाला गिधावा, शासकीय प्राथमिक शाला खमनापारा, शासकीय प्राथमिक शाला खरका एवं 02 पूर्व माध्यमिक शाला क्रमशः शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिहावा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला छिपली सहित कुल 18 प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला जर्जर है। अपितु सही यह है कि इसमें से 14 प्राथमिक एवं 02 पूर्व माध्यमिक शाला जर्जर है जो मरम्मत योग्य नहीं होने के कारण कक्षायें नहीं लगाई जाती है और उन्हें कलेक्टर धमतरी के द्वारा डिस्मेंटल करने की कार्यवाही की जा रही हे। 02 विद्यालय के भवन अच्छी स्थिति में है। शाला भवन अति जर्जर होने के कारण शाला प्रबंधन समिति की सहमति से छात्रहित में शालाएं वैकल्पिक रूप से सामुदायिक भवन, अतिरिक्त कक्ष, सामाजिक भवन आदि में संचालित की जा रही है। अति आवश्यक मद में मरम्मत कार्य हेतु जिला धमतरी को लगभग 74 लाख रुपये जारी किया गया है। यह भी सही नहीं कि शाला का संचालन खुले मैदान में हो रहा है तथा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अपितु सही सही यह है कि शाला का संचालन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सुचारू रूप से किया जा रहा है। पालकों के द्वारा उक्त के संबंध में तालाबंदी व आंदोलन की स्थिति नहीं है तथा इस संबंध में पालकों में प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का जन आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में सिहावा कितने स्कूलों की मरम्मत एवं भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है ? शाला भवनों की स्थिति बहुत जर्जर है। यदि बजट में शामिल नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि अभी तक सिहावा विधान सभा में 87 शालाओं के लिये 56 लाख 21,199 रूपये जारी किये जा चुके हैं और आपने जो 14 स्कूलों की बात कही है, मैं उसमें बता रहा हूं कि शासकीय प्राथमिक शाला अमलीपारा में नयी बिल्डिंग के लिये राशि जारी की जा चुकी है ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय मंत्री जी, आपने बताया है कि जिला धमतरी में 74 लाख रूपये मरम्मत कार्य हेतु जारी किया गया है ।

श्री गजेंद्र यादव :- नहीं-नहीं, मैंने आपको यह केवल सिहावा की जानकारी दी है । सिहावा विधानसभा में 87 शालाओं के लिये 56 लाख 21,199 रूपये जारी किये हैं ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- 56 लाख ?

श्री गजेंद्र यादव :- 56 लाख 21,199 रूपये ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- यह सिहावा विधानसभा का है ?

श्री गजेंद्र यादव :- सिहावा विधानसभा के लिये जारी किये हैं ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- यह कब तक चालू होगा ?

श्री गजेंद्र यादव :- यह दिनांक 12.09.2025 को जारी हुआ है ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- 12.09. को ?

श्री गजेंद्र यादव :- जी, 2025 को ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- 2025 को जारी हुआ है ।

श्री गजेंद्र यादव :- जी ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- तो यह कब तक पूर्ण होंगे ?

श्री गजेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो जानकारी बता रहा हूं, जिला कलेक्टर ने जारी किया है, जिला शिक्षा विभाग ने और संबंधित ग्राम पंचायतों को वह सारी राशि जारी हो चुकी है ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय मंत्री जी, अभी आपने अपने जवाब में दिया है कि स्कूल कहीं बाहर नहीं लग रहा है लेकिन मेरे क्षेत्र में कई स्कूल हैं जो रंगमंच में ऐसे कपड़े का घेरा लगाकर स्कूल को संचालित किया जा रहा है तो आप मुझे यह बता दें कि वहां पर कितने दिन में स्कूल का निर्माण करवा देंगे ?

श्री गजेंद्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 प्राथमिक शालाएं ऐसी हैं और 2 पूर्व माध्यमिक शाला जो बहुत जर्जर स्थिति में हैं । उसको माननीय कलेक्टर महोदय को डिस्मेंटल के लिये कहा गया है, डिस्मेंटल होने के बाद चूंकि राशि जारी हो रही है और मरम्मत और यह निर्माण जो है, यह सतत् प्रक्रिया है । हम लोग हर साल राज्य शासन से राशि जारी करते हैं और जैसे ही राशि जारी होगी संबंधित ग्राम पंचायत उसका निर्माण करेगा ।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय , मेरे सिहावा विधानसभा में जो सरईटोला है वहां रंगमंच पर लग रहा है और 2 साल से वहां पर शाला भवन डिस्मेंटल हो चुका है तो इसलिये मैं चाहती हूं कि वहां जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सरईटोला को देख लीजिये ।

श्री गजेंद्र यादव :- जी । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको करवा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- सरईटोला उनकी प्राथमिकता है उसको तत्काल बना दीजिये।

श्री गजेंद्र यादव :- जी, सरईटोला का हम बना देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बन जायेगा ।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि श्री कवासी लखमा, सदस्य द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.12.2025 के माध्यम से यह सूचना दी है कि वे वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) तथा ई.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी., छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज किये गये पृथक अपराधों के संबंध में केंद्रीय जेल, रायपुर में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं । ऐसी परिस्थिति में 14 दिसम्बर, 2025 से आयोजित किये जा रहे शीतकालीन सत्र में उनका भाग लिया जाना संभव नहीं है ।

समय :
1.18 बजे

नियम-267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. श्री रोहित साहू
2. श्री रिकेश सेन
3. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते
4. श्री नीलकंठ टेकाम
5. श्री ब्यास कश्यप

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
1.19 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) लोकलेखा समिति का अट्ठाईसवां से साठवां तक कुल 33 प्रतिवेदन

डॉ. चरणदास महंत, सभापति महोदय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोकलेखा समिति का अट्ठाईसवां से साठवां तक कुल 33 प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति महोदय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है -

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक-03)	श्री रिकेश सेन	30 मिनट
(क्रमांक-08)	श्री बघेल लखेश्वर	30 मिनट

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समय

1.20 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री रिकेश सेन
2. श्री ललित चन्द्राकर
3. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
4. श्री धरमलाल कौशिक
5. श्री रोहित साहू

समय

1.21 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025)

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2ब025 (क्रमांक 28 सन् 2025) का पुर: स्थापन करता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री टंकराम वर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन)(संशोधन)विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय(स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 29 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2025(क्रमांक 29 सन् 2025) का पुर: स्थापन करता हूँ।

(3) छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन)(द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025)

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन)(द्वितीय) विधेयक, 2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) का पुर: स्थापन करता हूँ।

समय
1.24 बजे **वित्तीय वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा**

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परम्परानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं, माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि-

दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 79,80,81,82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पैंतीस हजार करोड़ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह चर्चा प्रारंभ करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट । अध्यक्ष महोदय, मुझे विधान सभा सचिवालय से प्रश्न क्रमांक 62 का एक परिशिष्ट मिला है, वह पूरी तरह अंग्रेजी में है। मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता । अंग्रेजी जानता भी हूं तो काम चलाऊ जानता हूं । इसको हिन्दी में दिलवाने के लिए व्यवस्था देने का कष्ट करें, ताकि हम बहस में जानकारी में समृद्ध हो सकें । यह इतना मोटा है, इतनी अंग्रेजी को मैं इस जन्म में नहीं पढ़ सकता ।

श्री रामकुमार यादव :- तै मोर मेर आते त मैं समझा देतेंव । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आपकी दिक्कत समझ में आ रही है और इसका अनुवाद करने के लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (अकलतरा) :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आज अनुपूरक बजट जो नई विधान सभा में यहां पर प्रस्तुत हुआ है, इसके लिए मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को विरोध के साथ बधाई भी देना चाहूंगा । मांग संख्या 1 से 83 में हमारे अनुपूरक बजट में 35 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा मुख्य बजट 1 लाख, 65 हजार करोड़ के आसपास आया था और इतना बड़ा अनपूरक बजट जो मुख्य बजट के बाद लाया गया है । मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वित्त मंत्री जी तो संख्या के खेल को इतना अच्छा समझते हैं तो ऐसे अनुमान में क्या कमी रह गई थी कि आपने लगभग 35 हजार करोड़ का यह अनुपूरक बजट लाया है, जो मुख्य बजट का 22 प्रतिशत के

आसपास है । कुछ खर्च ज्यादा हो गए या नियंत्रण कुछ कमजोर रहा, यह वित्त मंत्री जी ही बेहतर बता पाएंगे । जब मैंने बजट को पढ़ा तो इसमें कुछ नया नहीं दिख रहा है । पिछले बजट की तरह सरकार दावे जरूर कर रही है और छत्तीसगढ़ को कर्ज में डूबाने का काम हो रहा है । जितना कर्ज पुराना लिया गया था, उसके अलावा जिस तरह के खर्च दिखाए जा रहे हैं और कर्ज लिए जा रहे हैं, उसको हम लोग बहुत अच्छी वित्तीय स्थिति या वित्तीय प्रबंधन नहीं कह सकते। जब पिछली सरकार छोड़ी गई थी तो जितना कर्ज था, उससे 1 लाख 25 हजार करोड़ से 30 हजार करोड़ के आसपास यह बढ़ गया है, इन दो सालों में 48 हजार करोड़ के आसपास हम कर्ज ले चुके हैं । हमें यह देखना होगा कि हम आखिर छत्तीसगढ़ को कहां लेकर जा रहे हैं ? पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर 15 साल बीजेपी की सरकार रही, फिर कांग्रेस की सरकार रही । जितना कर्ज जिस अनुपात में लिया जा रहा था, उससे कहीं बढ़कर इन दो सालों में कर्जे पर कर्जे लिये जा रहे हैं । मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बढ़ रहा था। 4.3.2025 को राज्य के ऊपर जो कर्ज था, वह लगभग 1 लाख, 17 हजार के आसपास उसमें दर्शाया गया था, जिसमें प्रति व्यक्ति के ऊपर करीब 42 हजार रूपए के आसपास आ रहा था, जो अभी शायद बढ़ गया है । हो सकता है कि उनकी रिपोर्ट कुछ ऊपर-नीचे हों तो मैं संख्या पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, चूंकि यह समाचार-पत्र की संख्या है इसलिए मैं उनके तथ्य पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कहीं न कहीं हमें यह समझना होगा कि हमारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है । मैंने इस बार प्रश्न भी लगाया था, लेकिन उसका जवाब नहीं आ पाया कि हमने कितना कर्ज लिया है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब मंत्री जी अपना जवाब दें तो इस बात का जरूर उल्लेख करें कि हमने कहां से कर्ज किस ब्याज पर कब लिया है, यह राज्य को जानने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार योजनाएं चला रही हैं । योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं हो रहा है । योजना कही जा रही है, जैसे इसके पहले भी बेरोजगारी भत्ते की बात हो रही थी । जवाब आता है कि अभी यह योजना बंद नहीं की गई है, लेकिन पैसे नहीं दिए जा रहे हैं । गोधन योजना शुरू होती है, लेकिन अब तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है । जब हाईकोर्ट में सड़कों की बात आई तो पता चला कि आपने कितनी सड़कें बनाई हैं तो एक बहुत ही हास्यप्रद आंकड़ा हमारे सामने आया, जो हर जगह की न्यूज पेपर पर था । यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है । मैं यह भी जानता हूं कि सत्ता पक्ष के विधायक यह बात नहीं बोलते हैं, लेकिन सड़कों की हालत बहुत खराब है। हमें लगता है कि बजट में उसको शामिल करना चाहिए था क्योंकि इसकी बहुत बड़ी राशि नहीं है, छोटी-छोटी राशि है, जिसको हम लोग देकर जनता को सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं । कर्ज लेकर हम लोग उत्सव मना रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ रहा है । मैं एक गांव गया था, वहां मैंने महिलाओं से पूछा कि आपको महतारी वंदन की राशि मिल रही है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं उनकी ओर से बड़ा अच्छा जवाब आया, उसने कहा कि बाबू मिलत तो हे, लेकिन एक हाथ ले देत हे तो दूसर हाथ से

बिजली के बिल मा वापिस ले लेवत हे। हम लोग फ्री बिजली की ओर जा रहे हैं, की बात कर रहे हैं। मैंने इस पर एक सवाल लगाया था, उसके आकड़ें कहीं से अगले 10 साल में भी पूरा सोलर पैनल लगा लेंगे, ये आकड़े उसमें रिफलेक्ट नहीं करते हैं। हमारा एक साल का लक्ष्य कितना है और कितने उपभोक्ता हैं, यह बताईये ? आप उसको डिवाइड_करके देख लीजिये, आपको पता लग जायेगा कि हम लोग जिस गति से चल रहे हैं, कितने सालों में भी सोलर पैनल नहीं लगा सकते। आप उसका उल्लेख करिये कि हम लोग कौन से साल में उसको कितना-कितना आगे बढ़ायेंगे। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम सिर्फ यह बात कर रहे हैं कि हम फ्री बिजली की तरफ जा रहे हैं। अगर आप फ्री बिजली की तरफ जा रहे हैं तो आपका टारगेट कितना है ? लेकिन टारगेट के बारे में कोई बात नहीं हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। चाहे बिजली दर में बढ़ोत्तरी हो, यह बहुत अच्छा हो गया है कि सौ रूपया बढ़ाओ और उसके बाद 20 रूपया कम कर दो और यह गिनाया जाये कि हमने 20 रूपया कम करके कितनी सारी चीजें, कितनी अच्छी प्रक्रिया अपना रहे हैं, जिससे आप लोगों को फायदा हो रहा है। मंत्री जी, मैं बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स देख रहा था। अध्यक्ष महोदय, उस बिलबोर्ड में लिखा था कि आपको ट्रैक्टर पर इतनी बचत हो रही है, आपको इतनी बचत इस चीज पर हो रही है। मतलब आप मान रहे हैं कि आप इतने सालों तक आप एक्सट्रा टैक्स ले रहे थे। यह बात शुरू से कही जा रही थी कि हमें इसे रिवाइज करने की आवश्यकता है। जब हमें समस्याएं समझ में आती है तो हमें रिवीजन की आवश्यकता है और हमेशा बनती रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन रजिस्ट्री हेतु गाईडलाईन की दरों में बढ़ोत्तरी बहुत ज्यादा हो रही है। हमने देखा कि गाईड लाईन दरों में इतनी ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई तो हर तरफ हा-हा कार था। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हम 31 दिसम्बर उसमें सुझाव भी ले सकते हैं और आपत्तियां भी ले सकते हैं। आपको बिलकुल लेना चाहिए। आपको उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए, व्यापारियों को शामिल करना चाहिए, ताकि हम लोगों के सामने एक सही पिक्चर सामने आ जाये। जमीन की गाईडलाईन दर के बाद जी.एस.टी. की बात करें तो मैं जी.एस.टी. में मानता हूं कि आप जी.एस.टी. ले रहे हैं और उसकी हर समाचार-पत्र में चर्चा हो रही थी कि छत्तीसगढ़ जी.एस.टी. में टॉप पर है। लेकिन उसके पीछे टैक्स टेरेरिजम भी हो रहा है और यह बात मंत्री जी को संभालनी पड़ेगी। जब उन्होंने एक अनरियलस्टिक फिगर बताया था कि हम जी.एस.टी. वसूली को इतना बढ़ा देंगे, जो नेशनल एवरेज के काफी ऊपर था। मैंने उस समय भी कहा था कि कहीं न कहीं ये छापे, रेड और व्यापारियों को परेशान करने का काम होगा, हम लोगों ने जो अनरियलस्टिक फिगर रखा है, उसकी वजह से यह सब होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में एक एक्ट्रेस आईं थीं। वहां के जो आयोजनकर्ता थें, उन्हीं के यहां दूसरे दिन जी.एस.टी. विभाग ने छापा मार दिया। यहां पर टैक्स टेरेरिजम_का काम हो रहा है।

यह सरकार इवेन्ट मैनेजमेंट कर रही है। हर चीज में इवेन्ट मैनेजमेंट हो रहा है।_कुछ जगहों पर ही सारी चीजों को कानसनट्रेट कर दिया गया है। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनका बिलकुल विकास होना चाहिए, उनका ज्यादा विकास होना चाहिए, हम लोग इस बात से सहमत हैं। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर विकास ही ना हो, हम लोग यह बात नहीं कर सकते हैं। हमें इसमें कहीं न कहीं बैलेंस लाना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी अनुपूरक को देख रहा था तो जी.एस.टी. उत्सव मनाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। अगर उत्सव मनाना है तो जनता को मनाने दीजिये, आप क्यों मनवा रहे हैं कि जी.एस.टी. का उत्सव मन रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, ए मन ऐसनहा हे अपने बिहाव मा अपने नाचने वाला हे।

श्री सुशांत शुक्ला :- तोर तो होत भी नइ पात हे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, विजन डाक्यमेंट के लिए भी प्रावधान किया गया है। एटलिस्ट मैं तो यह सोच रहा था कि जैसा कि हमारे आदरणीय वित्तमंत्री जी ने पहला बजट बड़ी खूबसूरत handwriting में लिखा था, तो उनको सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक अच्छा विजन तैयार करना था। लेकिन वह तो निबंध लिखो प्रतियोगिता की तरह हम लोगों ने देखा। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों ने आदेशानुसार कम से कम उस चर्चा में भाग नहीं लिया। क्योंकि उसमें विजन था ही नहीं, उसमें कोई विजन नहीं था। जैसे इस अनुपूरक में कोई विजन नहीं है। जैसे हम एक सुन्दर घर बनायेंगे, कब तक बनायेंगे समय नहीं बतायेंगे। क्या काम करेंगे, हम कब नींव डालेंगे, कब छत डालेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं है। बस, घर बनाना है और हम लोग इसी हिसाब से चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए भी एक लंबी राशि का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि मंत्रीगणों का नया बंगला भी बन गया है, लेकिन कई जगह ऐसे आवास हैं, जहां मंत्री और अधिकारीगण दोनों जगह हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि घर बनायेंगे और तारीख नहीं बतायेंगे। जब हम तारीख पर चर्चा कर रहे थे तब तो यह गायब थे। नवा अंजोर 2047 पर चर्चा थी तो संपूर्ण विपक्ष एक गलत विषय को लेकर दिल्ली गया हुआ था, जब छत्तीसगढ़ का नया घर बन रहा था।

श्री रामकुमार यादव :- गायब नहीं थे। ओ 15 लाख ला मांगे ला गे रहन।

श्री सुशांत शुक्ला :- तब ये कहां थे, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- 15 लाख रूपया देबो कहे रहौ तेला मांगे ला गे रहन।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप 2047 की बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इतना नीचे जा चुके हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- जब घर बनाने की बात आयी तब आप लोग कहां थे? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- शिक्षा के क्षेत्र में इतना नीचे जा चुके हैं। आज तक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- जब सदन में नया घर बनाने की चर्चा हो रही थी, तब मेरे विपक्ष के साथी कहां थे, यही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं आपका जवाब दे रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, दो मिनट। अमेरिका में एक बात आयी थी कि एक लेडी प्रेग्नेंट थी, उसको डायरेक्ट कार कंप्यूटर से वहां पर हॉस्पिटल में ले गया। आप 2047 की बात करते हैं, लेकिन धरातल में आपका कुछ नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप इतना नीचे गिर चुके हैं कि पुस्तक तक अभी तक नहीं बंटा है और आप 2047 में पहुंच गए।

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछली सरकार में कितना स्तर गिरा था, उस पर भी चर्चा कर लीजिए, ऐसी बात गलत है न। यह गलत बात है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी सरकार की बात मत कीजिए। हमने आत्मानंद स्कूल खोला था, आपने सब बंद करवा दिया।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने घर बनाने की बात कही तब मैं बोला। मैंने अध्यक्ष जी से अनुमति लेकर कहा कि अगर घर बनाने की बात हो रही थी, तो घर के निर्माण के संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब सदन में चर्चा हो रही थी तो मेरे विपक्ष के साथी कहां थे, मैं यही तो पूछ रहा हूं ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं आपका जवाब दे देता हूं कि हम कहां थे।

अध्यक्ष महोदय :- राघवेन्द्र जी, आप कंटिन्यू कीजिए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप पूरी बात सुने बिना ही पहले ही उत्तेजित हो जाते हैं। मैंने यह कहा कि जिस तरह का विजन डॉक्यूमेंट आपका विजन-लेस था, वैसे ही यह बजट भी आपका विजन-लेस है और बजट ऐसी चीज है कि यह विपक्ष का अधिकार है कि हम उस पर चर्चा भी करेंगे, उसका विरोध भी करेंगे, आपको सुझाव भी देंगे और इसलिए मैं खड़े होकर यहां पर बोल रहा हूं। विजन डॉक्यूमेंट का जो विरोध करना था, वह टी.वी. पर हमने देखा है कि कितना सुंदर हुआ था, तो इस पर आप ज्यादा बात न करें। ओपन माइंड के साथ हुआ था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में युवाओं के लिए अगर मैं बात करूं, तो कुछ भी नहीं है। जो हमने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की थी, कुछ भी नहीं है। अनियमित कर्मचारियों की बात की थी, कुछ नहीं है। नए पदों पर भर्ती की बात थी, कुछ नहीं है। अगर यह सब आदरणीय वित्त मंत्री जी इसमें इंक्लूड करें, हम लोग क्यों नहीं स्वागत करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जहां से मेरा जिला है, वहां सबसे ज्यादा उपेक्षित हम लोग जांजगीर जिले वाले हैं। मैंने अभी एक प्रश्न लगाया था जिसमें एक बात सामने आई, राजस्व आपदा विभाग से लगभग 77

करोड़ रुपए जो जारी हुए...।

श्री अजय चन्द्राकर :- राघवेंद्र जी, बजट छत्तीसगढ़ का है न, जांजगीर ज़िला का नहीं है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मैं कुछ उल्लेख ही कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, तो जांजगीर...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- जांजगीर भी छत्तीसगढ़ में ही आता है।

श्री उमेश पटेल :- पहले पूरा सुन तो लो भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले ही शुरू हो जाते हो।

श्री रामकुमार यादव :- एला मंत्री बने के बहुत चाहत हे। बार-बार खड़ा हो जाथे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात इन सदस्य को भी बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम यही है। इस वाले बजट में तो आपके क्षेत्र में खूब पैसा गया है, चूंकि दूसरे क्षेत्रों में नहीं जा रहा है। मैं यही बात कह रहा हूं कि इसको हमें एक साथ सारे क्षेत्रों में देना पड़ेगा, तभी इसकी बात हो सकती है। जांजगीर-चांपा को शून्य, कोरबा को शून्य, सुकमा, बीजापुर, वहां भी कुछ नहीं गया। मंत्री जी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, वहां पर आज तक मैं हमेशा इनसे रिक्वेस्ट करता हूं और आपके माध्यम से भी करूंगा दो साल में एक बैठक नहीं हुई, कम से कम एक बैठक तो कर लें, क्योंकि वह आते हैं, बैठक जब होती है तो उसमें हम लोग कोई नहीं बैठ पाते हैं। अधिकारी उनको यह बताते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस बात से संतुष्ट होकर मंत्री जी चले जाते हैं, लेकिन मंत्री जी वहां पर बहुत बुरा काम हो रहा है। आप हम लोगों को कभी बुलाइए, हम अच्छे ही सुझाव आपको देंगे। वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. के टेंडर्स का जो हाल है, सड़कों का जो हाल है, पूरे प्रदेश में सड़कों का जो हाल है, हम लोगों को कहीं न कहीं इस प्रावधान में लाने चाहिए और जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड उस काम को शुरू कराना है और यह पूरे छत्तीसगढ़ का हाल है, जहां सड़कों की बहुत बुरा हाल है। पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों का भी वही हाल है, वहां पर लगातार ट्रक्स, हाइवा और यह सब के क्षेत्र में हम लोगों को देखने को मिलता है। जब मेन बजट आया तो उसमें तो उसका प्रावधान आया नहीं, लेकिन मोदी की गारंटी के तहत् इस बार सब इंतजार कर रहे थे कि जैसा कि मोदी जी की गारंटी थी कि हर सोसाइटी में पैसे का वितरण हो जाएगा। सब इस बार पैसे खोज रहे थे कि कहीं न कहीं बैंक की एक डेस्क लगी होगी, जहां से हमें पैसा मिलेगा, लेकिन उसकी बात तो छोड़िए, पंजीयन तक नहीं हुआ। 5 प्रतिशत किसानों का आज तक पंजीयन नहीं हुआ है। तीन भुइयां, आपका एग्री स्टेट और इसके बीच में हम लोग भाग रहे हैं। जब यह सवाल हमारे सामने है तो मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर कोई न कोई व्यवस्था दीजिए क्योंकि आपको भी पता है कि यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है, लेकिन हम लोग परेशान हैं और सारा किसान परेशान हैं। चूंकि इसकी व्यापक चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जो गिरदावरी हुई, उसमें गांव के नये लड़को को पैसे देकर गिरदावरी करा ली गई। किसी का रकबा कटा हुआ है, किसी का रकबा जुड़ा ही नहीं हुआ है। इन सब चीजों के लिए एक संशोधन दे

दीजिये कि कम से कम इसमें समय आ जाये, जिससे किसान अपना धान बेच सकता है। क्योंकि इसके पहले गुरूजी लोगों को गिरदावरी के लिए लगाई जाती थी। लेकिन अभी फिलहार वह सांप, बिच्छू ..।

श्री रामकुमार यादव :- कुकुर, बिलई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ओ मन कुकुर गिने बर लगे हे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बैग ग्रास स्टेट की बात कर रहा था। आपका लगभग 12 प्रतिशत के आसपास ग्रोथ का अनुमान दिया हुआ था। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमें ग्रोथ करनी चाहिए। लेकिन आप ऐसा ग्रोथ का Figure मत दीजिये, जिसकी वजह से हमारे छोटे व्यापारी परेशान हो। हमें Prioritize करना पड़ेगा। चाहे वह गाईडलाईन की बात हो। मैं जी.एस.टी. की Goods Figure देख रहा था। नवम्बर में -2 प्रतिशत था, अक्टूबर में -2 प्रतिशत था, सितम्बर में 13 प्रतिशत की वृद्धि थी। यह पिछले साल का अनुमानित Figure है। अगस्त में जी.एस.टी. में 8 प्रतिशत की वृद्धि थी। जुलाई में थोड़ा नीचे गया। लेकिन यह बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास जी.एस.टी. में अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन उसको टैक्स टेरेरिज्म में कन्वर्ट करना गलत हो जाएगा क्योंकि कहीं न कहीं आज हमारा व्यापारी इससे परेशान हो रहा है। अगर हम Recieves की बात करें तो वर्ष 2024-25 की अनुमानित ग्रोथ के अनुसार Increase of 16% आपके बजट के हिसाब से Predic हुआ था। हमें Figure वही रखनें हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में हम लोग इसको जितने भी टारगेट सेट करेंगे, वह टारगेट Realistic हो। मैं स्टाम्प ड्युटी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। यह बजट में इसलिए रिलेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। मैं मंत्री जी को सुन रहा था। मंत्री जी ने कहा कि हमने बढ़ाया है और जितना अधिग्रहण हो रहा है, उस अधिग्रहण में किसानों को अग्रिम फायदा होगा। लेकिन इसका यह भी प्रभाव पड़ेगा कि जितने सारे भूमि अधिग्रहण के प्रोजेक्ट्स पी.डब्ल्यू.डी. और बाकी विभागों में है, वह सारी फाईलें वापिस जायेंगी। क्योंकि जो अधिग्रहण का मामला है, अब वह पैसा बढ़ जाएगा। मैं अपने यहां का ही उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिये कि आप 132 करोड़ में 32 करोड़ अधिग्रहण कर रहे थे तो तीन गुना minimum हो गया है। यह सारी फाईलें वापिस जायेंगी और इसका social impact बहुत बड़ा होगा। हमको इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जितनी फाईलें यह बीच साल में बढ़ा दिया गया, जितना बजट में आया हुआ था, सबका डी.पी.आर. बनकर कार्यालयों में पड़ा हुआ है। सारे अधिकारी अब इस बात पर कंफ्यूज है कि जितना भूमि अधिग्रहण का पैसा है, वह वापस जाना पड़ेगा। हमें चाहिए कि यह सारी फाईलें रिव्यू हो। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इसमें बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि कई सड़कें ऐसी हो रही है, जिसमें अब भूमि अधिग्रहण का पैसा रोड कंस्ट्रक्शन से 60 से 70 प्रतिशत के रेसियों पर जा रहा है। जो पहले 70:30 होता था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि पैसा सड़क से ज्यादा कहीं-कहीं अधिग्रहण में Equal आ जा रहा है। जैसे मेरे यहां ही क्या, सभी जगहों में यह समस्या दिखाई पड़ रही है। आपने वाले समय

में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमें सड़कों पर, धान पर, किसान पर, आदिवासी पर फोकस करना पड़ेगा। आपने यह जो बजट लेकर आया है। हम सबको उम्मीद थी कि हमने 6-7 महीनों में जो जितने दंश झेला है, जितनी दिक्कते झेली है, चाहे वह किसान की बात हो, चाहे पेमेंट की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, जब अनुपूरक बजट आएगा तो इस पर कुछ न कुछ हमको राहत मिलेगा। मैं बहुत दु:ख के साथ कहता हूं कि हमको यह राहत नहीं मिला है और सिर्फ ईवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट में उन चीजों को डाला जाये, उसके बाद ही इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी ।

श्री रामकुमार यादव :- तोर हाथ जोड़थव, सही-सही बोलबे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा तोरे ले शुरू करथंव मेहा ।

श्री रामकुमार यादव :- मोर ले झन शुरू कर गा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक बात बतावव आप। रामकुमार जी ।

श्री रामकुमार यादव :- बताईये जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहला बजट आया, उसके बीच में भी, बजट पर तो मैं बोलूँगा, लेकिन विनियोग में सब तरह की बात होती है । राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमको नाचने वाले घोड़े नहीं चाहिये, रेस के घोड़े चाहिये । छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नाचने वाले हैं कि रेस वाले हैं ? आप कौन से घोड़े हो ? बताओ, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी कौन से घोड़े हैं ? बारात में नाचने वाले हो कि रेस वाले हो कि जीपीएस गलत लग गया ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सब रेस वाले हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- हमन इंसान अन गा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जीपीएस सिस्टम ही खराब है । ऊपर में रेस का घोड़ा बोलता है ना, जीपीएस लगाकर देख लो, नाचने वाला निकलेगा । यह सब रेस वाले हैं । तांगा वाले, इसलिये इधर-उधर बात न करना । समझे रामकुमार जी ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- रेस के घोड़े हैं, उधर खच्चर हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बताने के लिये उमेश जी आ गये ।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर स्थिति और मोर मे कोई अंतर नई ए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले स्पष्ट करो कि रेस के घोड़े हो या नाचने वाले घोड़े हो ? तब राहुल गांधी जी की नजर में आओगे ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक आया है और मैं सोचता हूँ कि किन्हीं भी कारणों से प्रथम अनुपूरक नहीं आया है । यदि इसको

प्रथम अनुपूरक मान लें तो सबसे बड़ा अनुपूरक आया है । माननीय मंत्री जी, एक विषय है मैं इसे पढ़ रहा था, आप इसे देख लीजिएगा । यह पृष्ठ क्रमांक (2) में 41 नंबर के जोड़ को देख लीजिए, अलग-अलग है । यदि वह त्रुटि है तो आपको ठीक करना पड़ेगा । जो मतदेय है, उसमें संख्या दूसरी है और योग की संख्या दूसरी है । आप पेज 2 के 41 को देख लीजिएगा और है तो अभी घोषणा करनी पड़ेगी कि योग ऐसा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 15 साल तक इस प्रदेश को सार्थक नेतृत्व प्रदान किया, आज छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन दिखते हैं, आपका योगदान और आपका नेतृत्व ऐतिहासिक है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता । हमको कुछ चीजों में चिंता करनी चाहिये, नेता प्रतिपक्ष जी दुर्भाग्य से सदन में नहीं है । इस 33 हजार समथिंग के बजट में, 33 हजार 63.28 करोड़ के बजट में 5.53 प्रतिशत ही पूँजीगत व्यय है, बाकी 94 परशेंट बजट राजस्व व्यय है । अब राजस्व व्यय बढ़ क्यों रहा है, इस राजस्व व्यय को बढ़ाने की शुरूआत भूपेश बघेल जी ने की है, इधर जो बैठे हैं, इन लोगों ने की है । मेरा हाई कोर्ट में एक पीआईएल है, हालांकि वह अभी तक सूचीबद्ध नहीं हुआ है और कब होगा मैं नहीं जानता । आपके कारनामों के दो विषय हैं । आपने जैसे शेष लगाया था ना तो 55 करोड़ रूपये का तो पैरा ढुलवाया है ।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, यह जो महतारी वंदन योजना चल रही है, वह राजस्व व्यय है कि पूँजीगत व्यय है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसमें आ रहा हूँ, सुनिये तो । जैसा कि आपने मुझसे सुनने का आग्रह किया है ना..।

श्री उमेश पटेल :- सुनिये तो, यह किसने चालू किया था ? हर महीने 700 करोड़ रूपया लग रहा है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी कट भी रहा है ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब छत्तीसगढ़ बना, हमने 5 क्विंटल से शुरू किया था। यदि छत्तीसगढ़ में धान नहीं खरीदेंगे तो कैसे होगा ? एक इतिहास बना, जिसका मैंने उस दिन उल्लेख किया था कि धान खरीदी के लिये स्थगन भी प्रस्ताव में हुआ कि दिल्ली सरकार को इसे प्रस्ताव के रूप में भेजा जाये । यह इस सदन की गरिमा थी । कांग्रेस के पास क्षमता तो थी नहीं, 15 साल में वह हंफर गये थे । क्या करना है, पिटारा खोल दो । धान खरीदी को राजनीतिक इश्यू बना दिया कि हम एम.आर.पी. से ऊपर बोनस देंगे और यह भी बोलते थे कि एम.आर.पी. से ऊपर हम धान खरीद रहे हैं । डॉक्टर साहब ने क्या शुरूआत की थी, मैंने उनकी बात कही कि शून्य प्रतिशत में ब्याज देंगे । 14 परशेंट, 16 परशेंट को घटाकर शुन्य प्रतिशत में ब्याज देंगे ।

श्री उमेश पटेल :- बोनस तो आपकी सरकारों ने नहीं दिया ना ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इसी में बड़ी अपेक्षा के साथ बोलँगा ना पटेल साहब।

श्री उमेश पटेल :- आप जिस चीज को बोल रहे हैं, जरा पीछे भी घूमकर देख लीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- खाके डकार घलो नइ लेवथे ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप पहले स्पष्ट करिए कि रेस के घोड़े हो या नाचने वाले घोड़े हो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- रेस के घोड़े हैं।

श्री रामकुमार यादव :- मैं इंसान हूं। (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम सभी रेस के घोड़े हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- राहुल गांधी जी को जाकर बताईए कि हम लोग इंसान हैं, घोड़े फोड़े नहीं हैं, गलत तुलना मत करिए।

श्री उमेश पटेल :- आप अमित शाह जी को जाकर बोलिए कि आपकी जगह यहां है लेकिन आपको वहां बैठाकर रखे हैं। आप बोलिए, आप रेस के घोड़े हैं। आपको खच्चर बनाकर रखा गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी तो घोड़े की बात चल रही है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप जितना परेशान हैं न, वह हमेशा झलकता है। आप चिल्लाते रहते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए फकीर।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम तो यह बोल रहे हैं कि आप 15 लोगों को लेकर इधर आ जाईए हम आपको मंत्री बनाएंगे। महोदय जी, आप आ जाईए हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। (हंसी)

श्री दिलीप लहरिया :- लेकिन एक दिन का बनाएंगे। आपके बयान के अनुसार आप एक दिन का बनेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- आपको 2047 में बनाएंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- संगीता जी, क्या आपको कांग्रेस में नहीं रहना है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, हम आपका दर्द समझते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 50 हजार बिजली पंप को 5 लाख तक ले जाने की कोशिश की। हम छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद ऐसे करें। आपने कृषि अभियांत्रिकी की बजट को बढ़ाकर उसकी शुरूआत की। हम कृषि अभियांत्रिकी शुरू करके उसकी लागत को कम करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भांचा जी, दो साल के अंदर अभी स्थाई कनेक्शन कितना लंबित है यह बता दीजिए ?

श्री अजय चंद्राकर :- देख ममा, मोला धीरे-धीरे आवन देना, आज तो में बहुत शांति से बोलहूं ते हा देखत रहा ना। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, आप 15 सालों की बात बोल रहे हैं। आप इन दो सालों का बताईए न।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष जी, ये कौन से ममा भांचा हरे ?

श्री अजय चंद्राकर :- अइसे तैं असत्य बोलबे न तो चंडी मंदिर के भालू तोर डाहन आ जाही। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ओ भालू आए, वहां तक के ठीक हे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में किसानों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, वह समर्थ बने उसकी एक बुनियाद आपने डाली पर कांग्रेस पार्टी...।

श्री दिलीप लहरिया :- अध्यक्ष महोदय, ये तो गलत है न, पूरे प्रदेश में रकबा कट गया और आदरणीय आप समर्थ बनाने जा रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी नहीं हो रही है और आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- पूरा रकबा कट गया है, जहां 10 एकड़ है, उसका 8 एकड़ कट गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- दिलीप लहरिया जी, मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम बजट में 33 हजार करोड़ और 1 लाख 65 हजार करोड़ को जोड़ दें तो हम 1 लाख 95 हजार करोड़ से उपर जा रहे हैं। अब 1 लाख 95 हजार करोड़ से बढ़ रहे हैं तो इसकी दो दृष्टि होती है या तो हमारा कर राजस्व बढ़ा है या हम उसको ऋण के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। कर राजस्व बढ़ा है तो भी हम 5.53 प्रतिशत पूंजीगत व्यय कर रहे हैं और यदि हम ऋण से इसकी साईज को बढ़ा रहे हैं तो भूपेश बघेल जी जैसे नेता को यह सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आगे चलकर धान खरीदी के लिए क्या करना है ? इसलिए हमारी पीढ़ी के बाकी काम और होंगे या नहीं होंगे कि पीढ़ी को सिर्फ एक बात की जरूरत है क्या यह सदन समवेत् रूप से इस पर हल के लिए कोशिश करेगा, खुले मन से चर्चा करेगा। इसका हल क्या हो ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार तो किसान के धान के लिए सोच रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है ? पूरी खनिज संपदा अडाणी को बेच रही है, उसको देखिए, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी ?

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसा है, 5 साल में आपने टोटल कितने पेड़ कांटे और अभी दो साल में कितने पेड़ कटे हैं, एक सूचना का अधिकार लगा लीजिए। अटल जी, समझ रहे हो। ये वैसा ही है, जो मैंने आपको कहा था कि भगवान राम को आप रोज देखते हैं, रतनपुर की टेकरी में अजानबाहू भगवान राम की प्रतिमा है और आपने चंदखुरी में किसको लगाई ? आप पर्यटन मंडल के अध्यक्ष थे। हर चीज में संभावना खोजने का काम किसका था, कांग्रेस पार्टी का था। हर चीज में संभावना खोजने के कारण पी.आई.एल. में यही है कि भूपेश बघेल जी के राज में 5 साल में धान खरीदी में कितना घाटा हुआ ? तब भी आंख नहीं खुली, वह तब भी राजनीतिक मुद्दा बना रहा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अभी आपकी सरकार ने पिछला धान नहीं खरीदा है, जो अप्रैल में खरीदने वाले हैं जिसके लिए आपने 12 हजार करोड़ रूपए का अनुपूरक में प्रावधान लाया है, ये गलती किसकी है कि आपने राईस मिलर से धान नहीं खरीदी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चिंता इस सदन की और प्रदेश की यही है और आप जैसे चिंतक जिन्होंने एक स्थाई कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए माननीय मोदी जी की इच्छा के अनुरूप इनकम दुगुना हो, मछली पालन में आत्मनिर्भरता बढ़े। आप आए और एलाईड सेक्टर के पहले बिजली कांटी, इसलिए कांटी की उस समय के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी वहीं से चुनकर आते हैं, उनको कैसे परेशान किया जाए। आपका यह दृष्टिकोण था कि एलाइड सेक्टर को मजबूत नहीं करना था, बल्कि आपने उसमें भी राजनीति की। भोलाराम जी, यह सही है या गलत है?

श्री भोलाराम साहू :- गलत है।

श्री अजय चंद्राकर :- क्यों गलत है? आप जाइये और ए.बी.सी. से पूछिये कि आपका बिजली कटी या नहीं कटी? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- बिजली भर नहीं कटी, बल्कि प्रदूषण से पूरा राजनांदगांव अब तक मर रहा है।

श्री भोलाराम साहू :- आप यह भी देखिये कि उससे कितने लोग बीमार पड़े। आप जरा कंपनी वाले से पूछिये कि क्या कभी वह किसी सुरक्षा की बात करते हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सुनिये, अजय चंद्राकर जी बहुत तीखा जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए दो शब्द बोल देता हूं।

बेशक हमारी बोली में जहर हो सकता है।

लेकिन हम गंगाजल बोलकर जहर नहीं पिलाते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री भोलाराम साहू :- महाराज, अभी तो गली-गली में पीयत हे। ओमा कोन से जल मिले हे? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- गंगाजल तो नहीं बोलते हैं न।

श्री अजय चंद्राकर :- अब आप देख लीजिए। राघवेन्द्र सिंह जी नहीं हैं। उमेश जी, जिस बात को मैंने बार-बार कहा। बजट को आप शुरू करते थे। 9 हजार 612 करोड़ रूपये धान खरीदी के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को दिये गये। यह कहां तक जाकर रूकेगा? इस पर इस सदन को सर्वसम्मति से चर्चा करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में इसके विकल्प क्या हो सकते हैं? यह संकल्प व्यक्त होना चाहिए कि इसको राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाएगा, तब उसकी कीमत है, तब आपकी विश्वसनीयता है और तब आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ के प्रति आपकी चिंता है, अन्यथा पीढ़ी में भूल जाइये। हर्षिता बहन जी सड़क मांग रही थी।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, क्या यह चिंता कांग्रेस पार्टी की है?

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने सर्वसम्मत कहा। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आप सर्वसम्मत कह रहे हैं, लेकिन आपका आरोप इधर ही है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मेरा आरोप इसलिए इधर है कि बोनस और देंगे, यह आपने शुरू की। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- बोनस देने की सबसे पहले आपने शुरू की। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आपने 100 बार कहा 2 साल का बोनस कहां है? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- 3100 रूपये का घोषणा पत्र हमने रखा था। हम आगे भी किसानों को पैसे देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- कल तो हमने चर्चा के लिए बोला था, आपने चर्चा क्यों नहीं करायी? हमने तो कल चर्चा के लिए स्थगन लगाया था, आपने उस पर चर्चा क्यों नहीं करायी? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- 3100 रूपये किसानों के लिए किसने किया था? यदि आप राजनीतिकरण नहीं चाहते हैं तो 3100 रूपये किसने किया था? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- जब आपने शुरू की तो क्या हम सिर्फ देखते रहते और लहर गिनते बैठेंगे। इसीलिए मैंने सर्वसम्मत की बात की। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि यह सर्वसम्मति से होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- वोट के समय याद आथे। अब दे बर तुमन आना-कानी करत हो। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप यह बताइये कि अभी आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे?

श्री उमेश पटेल :- लेकिन राजनीतिकरण आप लोगों ने किया है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पूरे किसान कर्जे में डूबे हुए थे, उसी कर्जे को हमने माफ किया। आप लोग आज फिर से किसान को कर्ज में डूबा रहे हैं। फिर से वही आत्महत्या के दिन शुरू हो गये हैं। फिर से किसान लोग आत्महत्या शुरू कर चुके हैं। आपको पता है कि शुरूआत हो चुकी है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भाचा, यह स्पष्ट हो रहा है कि भविष्य में आप किसानों का धान नहीं खरीदेंगे। आप अपने भाषण में उसी लाइन में मध्य प्रदेश के तर्ज में ले जा रहे हैं। आप किसानों को दाम नहीं देंगे। आप प्रदेश के विकास की आड़ में किसानों के दाम बंद करेंगे। आपका भाषण उसी दिशा में जा रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विष्णुदेव जी की सरकार है। यह मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने मिलेट के लिए समर्थन मूल्य किया, वैकल्पिक स्थितियां पैदा की। नगद फसल के

लिए उद्यानिकी और सब्सिडियों का अध्ययन करिये। किसान आय अन्नदाता योजना भी प्रधानमंत्री जी ने बनाई है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किसान के बारे में बात कर रहे हैं। हम औद्योगिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए आपने पूरा बस्तर खत्म कर दिया। आप बस्तर में पूरे पेड़ की कटिंग कर रहे हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप कानून क्यों नहीं लाते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- संगीता जी, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- संगीता जी, मैंने बोला कि 5 साल में कितने पेड़ काटे गये और 2 साल में कितना पेड़ कटा? उसको आप निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- चलिये निकालिये कि कितना पेड़ कटा। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इसके लिए विधान सभा की कमेटी गठित हो जाये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- तमनार में कितना कटा है, हसदेव में कितना कटा है और बस्तर में कितना कटा है? (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- सुनिये, 3 लाख 28 हजार पेड़ परसा में कटा, 4 लाख 48 हजार पेड़ कटा। यह आंकड़ा आपकी सरकार के समय का है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्रीवास्तव जी, आप बैठिये। अजय जी अपनी बात रख रहे हैं। कृपा आप हस्तक्षेप न करें। सबको अवसर मिलेगा। जिन्होंने भी नाम दिया है, उनको बोलने का अवसर मिलेगा। जब आपको अवसर मिलेगा, तब आप अपनी बात रखें। अजय जी को अपनी बात करने दें। डिस्टर्ब न हो तो ठीक रहेगा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, अजय जी भी कहां छोड़ते हैं। सब जगह डिस्टर्ब करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यही बार-बार नाम लेकर पुकारते हैं। उंगली दिखाते हैं, इसलिए यह हमको बार-बार बोलने के लिए उत्तेजित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, आपसे भी आग्रह है कि आप किसी को उंगली मत दिखाइयेगा। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं उधर नहीं देखता। मैं आपकी ओर देखूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- यदि आप उंगली दिखाएंगे तो हम लोग उंगली करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- कहां पर उंगली करेंगे?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हैं तो मैं अटल श्रीवास्तव जी को कुछ बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब बोल लीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार ने 3 जनवरी, 2019 को यहां से परमिशन क्लियर किया तो भानुप्रतापपुर को ऑयरन ओर माइनिंग मिला। भानुप्रतापपुर को आयरन ओर माइनिंग 23 मार्च, 2020 को आपकी सरकार ने दिया। केलकी अंडरग्राउंड कोल माइनिंग की भी परमिशन 28 जुलाई, 2020 को आपकी सरकार ने दिया। परसाकोल ब्लॉक की भी परमिशन 26 अप्रैल, 2022 को आपकी कांग्रेस सरकार ने दिया। मेरे पास और भी पूरी लिस्ट है। मैं जब इस सदन में बोल रहा था कि झाड़ काटे न जाये तो आपकी सरकार थी और आप सब मंत्री थे। आपने एक भी तथ्यों में जानकारी नहीं दी थी। एक बात और बता दूं कि आपकी सरकार बनने से पहले श्री राहुल गांधी जी मदनपुर के पास जिस सभा में गरीबों को, आदिवासियों को वचन देने आये थे कि आपके क्षेत्र के झाड़ नहीं काटे जायेंगे और वह जिस चबूतरे में बैठे थे, उस चबूतरे की बेदखली का भी नोटिस भी आपकी सरकार ने आदिवासियों को दिया था। जहां वे वायदा किये थे, उसी चबूतरे की बेदखली का नोटिस दिया था। आप ऐसा मत करिये।

श्रीमती संगीता :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने जवाब में बोल लीजियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, उनको बोलने दीजिये। वह भूपेश बघेल गुट की हैं। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप कौन से गुट के हैं ? ओ.पी. साहब के गुट के या साव गुट के ?

श्री उमेश पटेल :- आप कौन से गुट के हैं। उनके या इनके ?

श्री रामकुमार यादव :- ओ हर स्वयं गुट बनात हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हसदेव के जंगल कटे। आपकी सरकार आयी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण नहीं किया था और उधर हसदेव कटना शुरू हो गया था। आपने परमिशन दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- संगीता जी बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय धर्मजीत सिंह जी की बात में एक लाईन जोड़कर विषय में आऊंगा। खनिज की अनुमति तो दी परंतु आपने देश में पहली बार खनिज की ऑनलाईन नीलामी की थी। जहां तक मेरी जानकारी है कि सुबोध सिंह जी आपके संचालक सेक्रेटरी होते थे। कांग्रेस की सरकार आयी तो उसको ऑफलाईन किया गया और ऑफलाईन करने का कारण यह बताया कि इससे इनकम बढ़ रही है। वाह, वाह। मैं उत्तर दिखा दूंगा और आप कहे तो दस्तावेज रख दूंगा। हर चीज में लहर गिन के, बीरबल से ज्यादा अक्लमंद यह लोग थे। हम क्या बताये ? पैरा ढुलाई में 55 करोड़ रूपये खर्च कर दिये। न पैरादान हुआ और न ही कहीं पहुंचा और 55 करोड़ रूपये बुक हो गये। अब हम क्या बतायें ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो चिंता व्यक्त कर रहा था, वह मैं आपके नेतृत्व की बात कर रहा था। यह ठीक है कि उसको राजनीतिक तौर पर लेते हैं। उस दिन हम अभिलेखागार बनाने की बात कर रहे थे और उसमें जब विधान सभा के रिकॉर्ड को और सरकार के दस्तावेज को, यह दस्तावेज रखे जायेंगे तो यह दिखेगा कि आपने कौन-कौन सी कोशिश की कि किसान अपने पैरों में खड़े हो और प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप उनकी इनकम दुगुनी हो। 9,612 करोड़ रूपये सिर्फ धान खरीदी के लिये। चिंता की लकीरे। जो भी छत्तीसगढ़ के हित के बारे में सोचेगा, निश्चित रूप से यह कहेगा कि आगामी आने वाली पीढ़ी। हर्षिता जी चली गईं। वह सड़क की बात कर रही थी। हम 5 साल और रूक जाये फिर स्कूल, कॉलेज, सड़क और अस्पताल की बात करना हमको बंद करना पड़ेगा। इसलिए आज समय रहते हम लोग सर्वसम्मत कदम नहीं उठाये तो छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। एक वित्त मंत्री अकेले क्या कर लेंगे ? वह खोज-खोज के ऋण लायेगा, क्या यही है ? वह हम सब की जिम्मेदारी है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- वह खनिज संपदा बेचेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके वित्त मंत्री थे, वह उसकी जिम्मेदारी है। मैं इस बात को गंभीरता से बोल रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- आप किस गुट के हैं, वह हम लोगों को समझ में आ गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी के लिये, ऋण के ब्याज की अदायगी के लिये 335 करोड़ रूपये, नए उद्योगों के स्थापना हेतु मशीनरी के लिए 130 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय के तौर पर है। उसके बाद भी मैं इस बात को बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि कल उल्लेख हुआ, मैं उमेश अग्रवाल जी को चिढ़ाने के लिये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन 5 साल में बेरोजगारों की परिभाषा तय नहीं हुई।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कह दीजिए कि यह मेरा नाम मत बिगाड़े। यह लगातार जानबूझकर करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, 5 साल में बेरोजगारों की परिभाषा तय नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय :- अब उमेश पटेल जी को सिर्फ उमेश बोला करिये। आगे पीछे का मत बोला करिये। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 05 साल में बेरोजगारों की परिभाषा तय नहीं हुई, रोजगार की परिभाषा तय नहीं हुई, लेकिन 7 लाख से ऊपर पूंजी निवेश और उसके लिये नये सेक्टर को चाहे वह अस्पताल, पर्यटन हो, इनको मान्यता देकर इनके लिये आवश्यक ऋण, आवश्यक मशीन और उनके लिये आवश्यक व्यवस्था करना कि छत्तीसगढ़ में नये क्षेत्रों का सृजन हो, रोजगार के नये अवसरों का सृजन हो। इतनी विपरीत स्थितियों में इनके लिये करना, अब ये हमको देखना है। मैं

माननीय वित्त मंत्री से ये आग्रह करूंगा कि ये देखें कि ये जो सुविधा है, प्राथमिकता में उन लोगों को जाना चाहिए जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों में से बेरोजगारों का चयन करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को अवसर प्रदान करते हैं, ऐसे उद्योगों को उसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी तरह के उद्योग जरूरी हैं। हमको संकीर्णता से बात नहीं करनी चाहिए। नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये 179 करोड़ रुपये की अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। एक उदाहरण बता देता हूं। मेरे क्षेत्र में भी दो औद्योगिक क्षेत्र के लिये पैसे दिये हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कम बोलता हूं। लेकिन मेरे क्षेत्र में भेन्डरा एक गांव था, जब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री होते थे, माननीय अध्यक्ष जी होते थे, उस समय जहां औद्योगिक क्षेत्र के लिये जमीन आरक्षित थी। जब आपकी सरकार आई तो उसमें गोठान बनाकर तालाब खोद दिया गया। अब उसमें जल क्षेत्र लिख दिये। न आज वहां गोठान है, न तालाब है। ये आपकी स्थिति थी। औद्योगीकरण में हमने बजट से पैसे दिये। आप रीपा लाये। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क कांसेप्ट अच्छा है। ठीक है। उसके लिये क्या बजट सपोर्ट था ? क्या लेजिस्लेटिव सपोर्ट था ? कहां के पैसे से कलेक्टर उसको करता था ? वह कहां से पैसे लाता था ? मशीन के क्या रेट तय थे ? सी.एस.आई.डी.सी. ने तय किया था, कहां से खरीदे जाते थे ? महात्मा गांधी के नाम को आपने सामने स्टीकर चिपकाकर खुले तौर पर लूटने की कोशिश की और जब अवसर आयेगा तो उसका प्रमाण दूंगा जो अभी जांच में लंबित है। क्या बोलें अभी उधर बढ़ना नहीं है। कृषि विभाग में 1159 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का है और छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग उसी में निर्भर हैं। जितना मजबूत करें, लेकिन आप इस तरह से मजबूत न करें। तैरना सीखायें, मछली खाना मत सिखायें। तैरकर पकड़ना ऐसा करके उसको सिखायें। लेकिन एक बात आपको कह देता हूं, कृषि क्षेत्र के लिये दिया है। प्रदेश में जितने कृषि विकास केन्द्र है, कृषि अनुसंधान केन्द्र को 25 प्रतिशत राज्य की ओर से दिया जाना है। राज्य की ओर से कृषि अनुसंधान केन्द्रों को पैसा नहीं मिल रहा है जिसके कारण उनको वेतन, भत्ते सबकी तकलीफ हो रही है। आप उसकी चिंता कर लीजियेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास में 1563 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। अब आप इसमें पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से महतारी वंदन है। women empowerment या आर्थिक स्वायत्तता, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता है या नहीं है ? 1 नवंबर 1998 को इस देश में माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने जो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, उनने स्वसहायता समूह की अवधारणा लागू की। इस समूह की अवधारणा के पीछे कारण क्या था ? छत्तीसगढ़ में या देश में ग्रामीण उद्योग, परंपरागत शिल्प, गृह उद्योग, उनके जितने परंपरागत शिल्प हैं, उसके प्रशिक्षण की, उनके बैंकिग की, उनके मार्केटिंग की व्यवस्था की जाये। उनको एक वित्तीय समावेशन दिया जाये। वह आज की तारीख में कितना सफल है, कितना असफल है, ये अलग बहस हो

सकती है। लेकिन वित्तीय समावेशन की दिशा में उनको आर्थिक रूप से empower करने की दिशा में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार ने भी इसको 2500 रुपये बिहार के चुनावों में घोषित किया था। वह एक empowerment है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आप किसानों को बोनस का विरोध कर थे कि हमारी सरकार ने किसानों को बोनस दिया। आप तो वोट लेने के लिये महतारी वंदन योजना लेकर आये और आप उसका महिमामंडित कर रहे हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति के लिये महतारी वंदन योजना को भी आप बंद कर दो। आप इधर किसानों को बोल रहे है कि किसानों की योजना बंद कर दी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- दो साल से जे बंद हे, ते कब खुलही, तेहू ला बता देवा। जेकर बिहाव होय हे, तेहू मन नई पात हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, संदूक में रखे हे, तेमन निकाल-निकाल के देखत हे कि हमर कब जुड़ही कहिके । हमर कब जुड़ही कहिके देखत हें, पोर्टल ला खोल दो ।

श्री अजय चंद्राकर :- तोला चाहिए का ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हओ, दे दूहू ता अच्छी बात हे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, क्या आप महिलाओं को महतारी वंदन में पैसा देने का विरोध कर रही हैं ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- नहीं, जो नये हैं उनको एड करना चाह रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम विरोध नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री नीलकंठ टेकाम :- स्वसहायता समूहों का आप लोगों ने ऋण माफ नहीं किया । ऋण माफी करने की बात नहीं की । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- भोरा में मत जइहा, बहरी-मुठिया धरे हे । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है । अभी तो यह और बढ़ायेंगे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम महतारी वंदन को गलत नहीं बोल रहे हैं, हम यह बोल रहे हैं कि जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनको जोड़ने के लिये आप पोर्टल खोलिये ।

श्री रामकुमार यादव :- दू साल ले महिला मन के पंजीयन नइ होए हे, तुमन जइहा ता ओ बहरी-मुठिया धर के खड़े हे । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- अटल जी, मैंने यह कहा कि छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्वायत्तता की कितनी जरूरत है उन पर एक बहस करिये । स्वसहायता समूह का आंदोलन कितना सफल है, असफल है और इसलिये इसकी जरूरत है या नहीं है, इसकी चिंता करिये लेकिन आज की तारीख में

खासतौर से बीपीएल की महिलाओं के लिये, खासतौर से एस.टी.-एस.सी. की महिलाओं के लिये यह संजीवनी का काम कर रही है जो छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बिजली बिल बढ़ा के आप महतारी वंदन दे रहे हैं, यह गलत है ।

श्री अजय चंद्राकर :- संगीता जी, एक सेकेण्ड । तें हा गंभीर बात ला नइ सुनच न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सुनत हंओं, सुनत हंओं ।

श्री अजय चंद्राकर :- का हे कि तें हा भूपेश बघेल गुट के आदमी हस न, तें महंत गुट के रहिथे ता तोला मौका मिलतिस ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- नहीं, एखर से यह बात भी प्रूफ होती है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, मैं तो आपको कितने दिन से ऑफर दे रही हूं कि आप यहां आईये । हम आपको मुख्यमंत्री बनायेंगे ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय नेता प्रतिपक्ष के स्थगन पर संगीता नइ बोलिस, दूसर विषय ला लइस । सही बात हे कि नहीं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी का गुट आज पता चला है, हम लोग समझ रहे हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- भूपेश बघेल जी जो कागज दे रहिस हे उही ला पढ़त रिहीस हे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी का अध्ययन कीजिये । देश में सबसे ज्यादा लगभग 42 प्रतिशत एस.टी., एस.सी. है । यह डेमोग्राफी पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगी, आपको नॉर्थ ईस्ट में भी इतने प्रतिशत नहीं मिलेगी इसलिये जब हम वित्तीय समावेशन किसी वर्ग के लिये करते हैं तो उसको छत्तीसगढ़ के एंगल से भी सोचिए, सिर्फ बीच के एंगल से मत सोचिए । मैंने धान खरीदी की बात इसलिये कही क्योंकि धान भूपेश बघेल जी भी बोते हैं । धान नंदकुमार पटेल जी भी बोते थे, उमेश पटेल जी भी बोते हैं । धान विद्याचरण जी भी बोते थे और आप भी बोते हैं लेकिन उस 42 प्रतिशत की विकर सेक्शन की महिलाओं के लिये क्या है, इसमें आप सोचिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय प्रशासन । 1225 करोड़ रूपये, पूंजीगत व्यय ।

समय :
2.13 बजे **(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, फर्स्ट सप्लीमेंट में मेन बजट के बाद इतना बड़ा आयोजन शहरी निवेश के लिये, नगरीय निवेश के लिये इससे पहले कभी नहीं हुआ, आप इसको रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिये इसलिये राजनीति से उठकर इसका स्वागत करना चाहिए कि ओ.पी.चौधरी जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने, मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के नगर निवेश को बढ़ावा देने के लिये बजट की राशि

उपलब्ध करवाकर एक ईमानदार कोशिश की है । अब पढ़िए, माननीय अंबिका जी, भाभी जी । सावित्री जी, सुनिए । अनुसूचित जनजाति के लिये 1047 करोड़ रूपया । अब आप लाईब्रेरी में चल दीजिये, यदि इसको सेकेण्ड सप्लीमेंट्री मानते हैं तो इसके बजट को निकाल लीजिये और इतना बड़ा आयोजन बजट में कभी छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी हुआ है क्या ? यह देखकर मुझे कल बताईयेगा, एक दिन का सत्र और है । ठीक है । आप तो पढ़ी-लिखी हैं, आप बहस में रहती हैं । हम लोग खूब बहस करते हैं, गलत है कि सही है ? बताईयेगा, अंबिका जी को ले जाईयेगा । उनको 18 स्कूल भर टूटे-फूटे दिखे । मैं क्या-क्या करवाया हूं और हमने सिहावा में क्या-क्या करवाया है, मैं अभी वह बता दूंगा । वह जिस ईलाके में घूमती हैं न, जितने सड़क, पुल-पुलिया, बिजली हैं वह सब मेरे करवाये हैं । अब आप सुन लीजिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- [XX][5] हरवंश जी मेडम ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, हम भी चाहते हैं कि आप मंत्री बनो ।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी आपका उल्लेख करूंगा । हरवंश जी ।

सभापति महोदय :- आपका नाम है, आपके नाम के समय बोलिएगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- उत्तरी जी, सुनिए । कविता प्राणलहरे, चातुरीनंद । [XX] आदरणीय सुतत कइसे हस जी । अनुसूचित जनजाति के लिए 1 हजार 47 करोड़ रूपये, अनुसूचित जाति के लिए 3 हजार 113 करोड़ रूपया, तें हिन्दी में लिख सकथस, अंग्रेजी में लिख सकथस कि अंक में लिख सकथस।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सुनना। ओमन के नाम नहीं हे का ? [XX] क्या है?

श्री अजय चन्द्राकर :- ओला कहात हौं [XX] बबा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ऐसा आप किसी को भी बोलेगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, किसी भी माननीय सदस्य को आप (XX) करके क्यों बोल रहे हैं।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, इस शब्द को विलोपित किया जाये। यहां पर कोई [XX] नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओला आपत्ति नहीं हे।

श्री उमेश पटेल :- यह [XX] क्या शब्द है ?

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यहां सम्माननीय विधायक जी है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- [XX] क्या शब्द है, आप इतने वरिष्ठ हैं।

श्री उमेश पटेल :- आप उनसे माफी मांगिये।

---

5 [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सदस्य आपका माफी मांगनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लिख लेंगे । अनुसूचित जाति के लिए 3 हजार 113 करोड़ रूपया।

श्री उमेश पटेल :- आप पहले माफी मांगिए तब आप बात आगे रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं माफी मांगता हूँ।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने माफी मांग ली। इतना बड़ा 3 हजार 413 करोड़ रूपये ...।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय अजय भईया, आप क्या बोले थे ? वह तो बता दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमर सियान हे, हम ओकर बर दिन भर माफी मांग सकथन। देखना। वही तो कहात हौं। ओमन चिल्लात हे तो कहेंव कि उही में खुश रही। ओहा हमर सियान हे। ओ अभी कविता प्राण लहरे हे, पूछना। अभी ओ खोजत रहिथे कि सियान कर कइसे बईठौ करके। (हंसी) ओकर बबा नाती हे दोनों कोई। अब नतनिन अउ बबा हे तेखरो विधान सभा में उल्लेख मत कर, अइसे कहि दूहू।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ओखर उल्लेख कर सकथस।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति उपयोजना में इतना बड़ा बजट आयोजन हुआ होगा तो मैडम हरवंश जी, आप मुझे कल पढ़कर बता सकती है। माननीय उत्तरी जी, आप भी बता सकती हैं। मुझे चातुरी जी बता सकती हैं, कविता प्राण लहरे जी बता सकती हैं।

श्री उमेश पटेल :- ए बता कि एखर पहिली तैं गुरूजी रहे का ? तैं एला करके लानबे, तैं एला करके लानबे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आगे सुनिये। अब जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूँ। भीगीरथ संकल्प 31 मार्च 2026 को नक्सलरहित होगा। (मेजों की थपथपाहट) कभी आपने ऐसा संकल्प छत्तीसगढ़ के हित के लिए लिया हो तो आप यह बता दीजिए कि हम इसको कर देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, केन्द्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूँ उसके लिए 397 करोड़ रूपये पुनर्वास हो रहे हैं, सरेण्डर हो रहे हैं। मकान बन रहे हैं सारी चीजों के लिए। सिर्फ सजा देना है, एनकाऊंटर करना है नहीं। मल्टीएंगल, बहुआयामी योजना के साथ बस्तर में वह परिवर्तन देखिये। शासन क्या होता है ? कभी इस पर भी स्वतंत्र रूप से बहस होनी चाहिए कि 80 के दशक में किन कारणों से छत्तीसगढ़ में नक्सल आयें। इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- इसमें भी बहस होनी चाहिए कि ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा बैठ जा, मैं जल्दी-जल्दी बोलत हौं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, वह सफाया किसके लिये किया जा रहा है, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं । छत्तीसगढ़ ने नक्सल जैसी विभिषिका को झेला है और हम से ज्यादा तो विपक्ष ने झेला है । मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि यह किसके लिए, किसका नाम जोड़कर, आप किसके लिए बात कर रहे हैं ? आप छत्तीसगढ़ की विभिषिका का हास्यास्पद चेहरा मत प्रस्तुत कीजिये। छत्तीसगढ़ के नेता शहीद हुए हैं, उसके लिए उन्होंने शहादत दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आदरणीय वरिष्ठ सदस्य महोदय दोनों को बता देता हूँ। जनगणना कार्य, उसकी तारीख आ गयी। यह कोरोना के कारण समय में नहीं हो पाया। लेकिन जनगणना और जनगणना के सेंसेक्स के अभाव में विकास कार्य कैसे प्रभावित होते हैं। यह जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं वह सभी जानते हैं कि जनगणना के लिए बजट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं माननीय रामविचार नेताम जी को बधाई दे देता हूँ उन्होंने नई योजना के लिए राशि मांगी है। छत्तीसगढ़ में ए.आई. का इस्तेमाल भी एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा। यहां मौसम कैसे बदलेगा, बाढ़ आएगी क्या ? यहां चक्रवात आएगा क्या ? यहां पर तेज हवा चलेगी क्या ? किसानों को पहले से जानकारी दी जाएगी। Digital integreted agriculture intelligence सिस्टम।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपको मंत्री बनाया जाएगा या नहीं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, agriculture intelligence का यही सिस्टम है। हम ब्यास जी को छोड़ दे तो यहां पर जितने लोग हैं सभी किसान हैं। प्रोजेक्ट टाईगर, आप समाचार पत्र पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। मैं यह नहीं जानता। मैं रामकुमार जी के बारे में विशेष तौर पर नहीं जानता कि वह समाचार पत्र पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते ? लेकिन छत्तीसगढ़ या हिन्दुस्तान में छपा है कि फारेस्ट का जो टूरिज्म है, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बाघ छत्तीसगढ़ में हो गए हैं और टूरिज्म की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ? पर्यटन मंत्री जी बैठे हैं । उसके लायक क्या प्रोजेक्ट टाईगर के अंतर्गत राज्यांश 3.43 करोड़ और केन्द्रांश 5.15 करोड़ ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति महोदय, आदरणीय अजय जी, आप और जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, जंगल पर आप लोगों को हम लोग सुनना पसंद करते हैं कि आप लोगों के पास इतना व्यापक ज्ञान है । आप इस बात से सहमति दीजिए कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों का यह दुर्भाग्य है कि आज भी बांधवगढ़ या कान्हा किसली के स्तर का हमारे पास एक भी पार्क नहीं है और ऐसा कोई भी टूरिज्म उस स्तर का हम लोग डेव्हपल नहीं कर पाये हैं । इसके लिए भी बात होनी चाहिए ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, वो अपना भी एक नुकसान कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आपका भी नाम है, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। हर बार मत खड़े होईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- राघवेन्द्र जी, मैंने अभी स्वीकार किया कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मैं इतना मोटा नहीं पढ़ सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ जाता हूं । जब छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखोगे तो 2018 से 2023 का समय डार्क एज़ होगा, जिसमें लिखने लायक और करने लायक कुछ नहीं है और जो दुर्दशा आप चित्रित कर रहे थे, उसमें इतिहास में सिर्फ करप्शन, करप्शन, करप्शन निकलेगा । (शेम-शेम की आवाज)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप लोगों ने 15 साल में क्या किया है ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- 15 साल में तुमन काए करे हवव ? (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- 15 साल में आपने क्या-क्या काम किया है, उसको बताईए ।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- चन्द्राकर जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं । 15 साल में क्या-क्या काम हुआ है, यह भी बताईए ।

श्री रामकुमार यादव :- कुछ भी बोलत रहिही अउ हमन सुनत रहिबो का ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- दो साल में तो एक भी काम नहीं हुआ है 1

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने धान के बारे में चिन्ता व्यक्त की, दलहन-तिलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अर्थात् रबी की वैकल्पिक फसल में जिसे हम छत्तीसगढ़ी में ओल्हा भी कहिथन । वैकल्पिक फसलों की मजबूतीकरण के लिए पल्सेस योजना में 1.5 करोड़ रूपए का प्रावधान है, मैं बधाई देता हूं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने तो चना का भी समर्थन मूल्य नहीं दिया, हम तो बोलते रह गए, मांग करते रह गए कि चना का में समर्थन मूल्य दीजिए करके ।

श्री रामकुमार यादव :- हमर सरकार में, भूपेश बघेल जी के सरकार के होए रिहीसे ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, बार-बार खड़े मत होईए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, स्टेट कैपिटल ऱीजन एक नई अवधारणा के बारे में सोचा जा रहा है कि एक समन्वित एकीकृत शहरी विकास जो वैश्विक स्तर का शहरी विकास हो सकता है, जिसमें शहरी विकास के जो मानक हैं, चाहे वह पेय जल हो, चाहे वह बिजली हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वह लॉ एण्ड आर्डर हो, आप समाचार-पत्रों में पढ़ते होंगे कि कमिश्नरी व्यवस्था के बारे में सोचा जा रहा है । जितने मानक हो सकते हैं, वह सारे मानक विश्व स्तरीय हों, स्टेट कैपिटल रीजन सोचा गया, वह सोचा ही नहीं गया, बल्कि एक प्रकाशन के स्तर में पहुंच गया और तत्काल उनके आवश्यक व्यय करने के लिए मेरे ख्याल से उसकी सेट-अप की भी स्वीकृति हो गई । उसके लिए 10 करोड़ रूपए दिए गए ।

सभापति महोदय, माननीय पर्यटन मंत्री जी, आपने बस्तर पंडूम के लिए 3 करोड़ रूपए मांगे हैं, वह बजट में है । माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बस्तर से आते हैं, माननीय सभापति जी, आप भी बस्तर से आते हैं । आप 3 करोड़ की जगह में 30 करोड़ लीजिए, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि उसको बस्तर में मत करिए, उसको तो दिल्ली में करिए । एम्फीथिएटर बुक कराईए । जितने cultural Minister हैं, उनको बुलाईए, प्रतिदिन एक कार्यक्रम हो । दूतावास के लोगों को बुलाईए, जो छत्तीसगढ़ को और बस्तर को जो बोलते हैं कि नक्सली है, ये है, वह है । ऐसा समृद्ध कल्चर है । Who is Chendru ? बताओ । दंतेवाड़ा के फूलों की होली कितने दिन की होती है, हम सिर्फ बस्तर का दशहरा जानते हैं । दंतेवाड़ा के फूलों की होली कितने दिन चलती है, उसे हम लोग नहीं जानते । केदार जी बता देंगे, अध्यक्ष जी बता दें । वे वहीं के रहने वाले हैं, सुकमा के पुराने जमींदार राजा हैं । आप भोकानाल की प्रतिकृति ही लगा दीजिए, बारसूर के गणेश जी की प्रतिमा लगा दीजिए । एशिया का सबसे चौड़ा जल प्रपात, उसका भी म्यूनरल बनाकर वहां पर लगा दीजिए । सब देखें तो, आंखें फटी रह जाएंगी । छत्तीसगढ़ी में एक कहावत हे, अंते-तंते वाला हे, बोल देवत हंव। गाय-गाय धनाथ हे। तो हमी देखत हन अउ हमी नाचत हन, मतलब का हे ? आप बस्तर पंडुम को दिल्ली ले जाओ, उसके लिए 30 करोड़ रूपया मांगो। मैं सोचता हूं कि आप ऐसा कदम उठायेंगे।

सभापति महोदय, नेशनल फोरेसिंक यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ में हर तरह की यूनिवर्सिटी बन रही हैं। फोरेसिंक यूनिवर्सिटी के भूमि आवंटन के लिए 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपने बनाई थी, मैंने आपको बधाई दिया था। जब पिता जी के नाम यूनिवर्सिटी बनाई थी, बढ़िया किया था। एक ही काम सराहने लायक है कि आपने 2 यूनिवर्सिटी बनाई।

सभापति महोदय, इलेक्ट्रिक वाहनों में सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी 12 लाख रूपये की सब्सिडी की सीमा को कम से कम 20 या 25 लाख करिये। 12 लाख रूपये में कोई भी अच्छा वाहन उपलब्ध नहीं है। भले ही आप सब्सिडी की राशि कम या ज्यादा कर लें, लेकिन वास्तव में सब्सिडी देते हैं तो लोगों को उसका लाभ मिले। आप यहां पर पता कर लीजिये, 12 लाख रूपये में कोई अच्छा वाहन उपलब्ध नहीं है। इलेक्ट्रिक के 20 लाख+ में ही वाहन उपलब्ध हैं। यह अच्छी योजना है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जीरो उपलब्धि के लिए 2070 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधार वर्ष घोषित किया है कि हम जीरो न्यूट्रीलिटी में ले आयेंगे। यह एक संकल्प है। हमको बिलकुल उसमें मदद करनी चाहिए।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप लोग इस नाम से बिदक जाते थे। जब आप लोग प्रधानमंत्री आवास सुनते थे, जैसे गोल्लर ला लाल कपड़ा दिखा दे न त मत देखाव कहय। तो भूपेश बघेल जी की राज में प्रधानमंत्री आवास का नाम लेते थे तो मंत्री विधायक मन ऐसे बिदकय कि जान दे, जैसे कोई पाप करने वाले हे। आपको गरीब की हाय लगी। भगवान ने भी कहा कि गरीब की हाय भर

मत लेना, सब लेना। ममा, कहां चल देय ? कहत रहिस ए कतका बिजली पंप देय हस, 64.60 करोड़ रूपये बिजली कनेक्शन देय बर हे। साहब बता देबे, कतका कन लगवाना हे, तोर इहां के ला पहली लगवा देबो, एप्लीकेशन ला दे देबे।

माननीय सभापति महोदय, खेलो इण्डिया, ट्रायबल गेम्स। मैंने अभी कहा था कि मल्टी एंगल, बहुआयामी, यह आदिवासी की जन्मजात प्रतिभा है। साहब, एकलव्य की संतान हैं।

श्री उमेश पटेल :- आपकी पार्टी की सरकार को 15 और 2, 17 साल हो गए हैं, 17 साल में कितने खेल एकेडमी बने हैं और 5 साल में कितने बने हैं, जानकारी निकालियेगा। कभी जानकारी निकलवाईये कि 17 साल में कितने खेल एकेडमी बने और 5 साल में कितने बने। आप एक बार चेक कराईयेगा।

सभापति महोदय :- उमेश जी, आपका भी नाम है। आपकी बारी आयेगी तो बोल दीजियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- शब्दभेदी बाण, कुकूर भूकीस और एकलव्य हा ओखर मुंह ला बंद कर दीस। ऐसन निशानेबाज अभी बस्तर मा मौजूद हे। ओ मन आज भी अंगूठा से तीर नइ चलाय, ऊंगली से तीर पकड़ के चलाथे।

सभापति महोदय, विवेकानंद एयरपोर्ट माना और रायगढ़ एयरपोर्ट, माननीय वित्त मंत्री जी, बहुत लड़ रहे हैं। बिलासपुर के एयरपोर्ट के बारे में बहुत सारा आर्टिकल छप रहा है। आप अगले मुख्य बजट में जरूर उसको सोचिये। बिलासपुर न्यायधानी है, संतुलित, सम्यक विकास हो।

सभापति महोदय, मैंने प्रमुख-प्रमुख चीजें बताईं। आप कुछ चीजें और सुन लीजिये। प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णु देव साय जी अपने प्रदेश में लोकप्रियता के मामले में पूरे देश में टॉप में दूसरे स्थान पर हैं, आप लोग ताली बजाईये। (मेजों की थपथपाहट) ऐसा नेतृत्व छत्तीसगढ़ में मिला है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- जो पूरे छत्तीसगढ़ की खनिज सम्पदा को बेच रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप इण्डिया टू डे खोलकर देख लीजिये।

अटल श्रीवास्तव :- जो छत्तीसगढ़ की खनिज सम्पदा को बेच रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- रेवंत रेड्डी का नाम है तो आप खुश हो, वह सर्वे अच्छा है। रेवंत रेड्डी जी जीते तो ई.वी.एम. ठीक है। सिद्धरमैय्या जी जीते तो ई.वी.एम. ठीक है। वायनाड से उप चुनाव में जीती तो वहां का ई.वी.एम. ठीक है। बाकी तुम जीते हो तो गलत ई.वी.एम. से जीते हो। यह तो डबल स्टण्डर्ड है।

सभापति महोदय, मैंने महतारी वंदन योजना का उल्लेख किया। देश में पहला वित्तीय समावेशन है। मैंने तो कहा कि डेमोग्राफी के कारण समर्थन कर रहा हूं। सखी वन स्टाप सेन्टर, कहां चली गईं ? छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। क्यों भाभी जी, सही या गलत है ? हम लोगों ने चालू किया था न ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सब काम आप मन करे हव।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सियान मन ला 500 रूपया मिलथे, ओ मन हमन ला अब्बड़ सुनाथे, आप मन 500 रूपया उपरहा दे देवा।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने दीजिये। बीच में टोका-टाकी ना करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यूनिटी मॉल, पौनी पसारी ला जानथस ? कै ठन खुले हे, जा के देख लेबे। पौनी पसारी में ताली बजाओ अइसे। के ठन पौनी पसारी हे। हे का बालोद में एको ठन। अब महिला कोष सक्षम योजना, विधवा महिला परित्यागता, अविवाहित महिला बर, लखपति दीदी योजना, बिहान योजना, मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री सिलाई योजना अउ सबसे ज्यादा महिला मन के रोजगार में छत्तीसगढ़ में प्रतिशत बढ़े हे। 22 प्रतिशत से बढ़ के 40 प्रतिशत।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, प्लीज। अभी आपकी बारी आएगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चंद्राकर जी, एक मिनट, यह बहुत गलत आंकड़ा है, क्योंकि महिलाओं के लिए काम नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय :- चलिए, आपका नाम आएगा, उस समय में अपनी बात रखियेगा।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जो काम कर रहे हैं, उसको भी बंद कर दे रहे हैं तो कहां से आगे बढ़ेगा।

श्री रामकुमार यादव :- 500 रूपया में सिलेंडर देबो कहे रहौ, अभी 1200 मिलत हे। 500 रूपये में देबे कहे रहौ।

श्री अजय चन्द्राकर :- महतारी सदन। महतारी सदन बनवाना है या नहीं तोला? अब बेरोजगारी के बारे में तो उमेश बघेल पटेल जी का कोई दृष्टिकोण नहीं था। (हंसी)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अब आप यहां सिर्फ उमेश बोलिए, उसके आगे मत बोलिएगा। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, चलिए, साहब, आपसे माफी मांग लिया। उमेश पटेल जी ने बेरोजगारों के बारे में क्या किया, क्या नहीं किया, मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- उमेश जी, आपका तो जॉइंट करके डबल इंजन बना दे रहे हैं ना उमेश जी भी और बगल वाले बघेल जी के साथ जॉइंट करके।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या किए, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि कितनी संवेदना बेरोजगारों के लिए थी, पर आज उसको गिनने का, रोजगार उपलब्ध करने का, अपॉइंटमेंट के लिए रोजगार मेला

लगाने का, कैंप लगाने का और ईमानदारी से स्वीकार करने का बताइए कि 5.2 प्रतिशत यह है। यह बेरोजगारी दर को हमने ईमानदारी से स्वीकार किया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अच्छा, इस बात को समझाते हुए बताइए कि कितने लोगों को रोजगार दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- और विजन 2047 में उसको 1 प्रतिशत में लाने का है। ऐसा दस्तावेज आपने कभी देखा पढ़ा होगा तो बताओ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- कभी नहीं देखा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अब लाए हैं तो मेला से कितने लोगों को रोजगार मिला है? बताइए तो मेला से कितने लोगों को रोजगार मिला है?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आगे आइए मामा। रजिस्ट्री में बदलाव। देखे हस कि नहीं देखे हस ते?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- रजिस्ट्री के बदलाव से अंतर्रात्मा से..।

श्री अजय चन्द्राकर :- रजिस्ट्री दर में नहीं बोलत हव, रजिस्ट्री के तौर तरीका में बदलाव।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- वो अंदर से आप जितनी तकलीफ में हो, उतना उस बात से कोई नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब दूसरी बात सुन लो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि असली शासन वह है, जो जनमत का सम्मान करे। खुले दिल से माननीय रजिस्ट्री मंत्री वित्त मंत्री जी ने उन सुझावों को स्वीकार किया कि जो समाज के विभिन्न वर्गों ने रजिस्ट्री के लिए दिया, उसको संशोधित किया और कहा कि दरवाजा आगे भी खुला है और आगे भी संशोधन होगा। जनता का राज है, जनता के मत से ऊपर हम नहीं है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- पहले सुझाव क्यों नहीं लिये थे? पहले ही सुझाव ले लेना था। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन गलती करे रहौ, ए सरकार बइठे हे। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप ही बढ़ा रहे हैं। आप ही कम रहे हैं। आज की डेट में रजिस्ट्री करना आसान नहीं है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बार-बार टोका-टाकी न करें। आपकी भी बारी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- रजिस्ट्री का रेट इतना बढ़ा दिए हैं। आप बढ़ा रहे हैं, उसी का तो विरोध कर रहे हैं, उसी में सब बात कर रहे हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप साल में एक बार बढ़ा दीजिए। तीन बार बढ़ा दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- छत्तीसगढ़ राज्य में अभी रजिस्ट्री पूरा बंद हो चुका है

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य जी बैठिए, बार-बार टोका-टाकी न करें। माननीय को भी अपने विचार रखने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिए, नये विषय नये परिवर्तन से ए.आई. का हब, उसके इंस्टीट्यूशन के लिए 1 हजार करोड़ के डाटा पार की स्थापना। रामकुमार, ए.आई. काला कहथे? बता तो। अब सेमी कंडक्टर, अब आपको ताइवान से नहीं मंगाना पड़ेगा।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़ देगा। हम सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएंगे। उसका सेंटर देश में सबसे पहले बनने की शुरुआत हुई तो छत्तीसगढ़ में हुई। बजाइए ताली चलिए, ठोकिए टेबल चलिए बजाइए। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- एक घंटे होने को है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं खत्म कर रहा हूं। अब लॉजिस्टिक हब, विशाखापट्टनम सड़क कहां है अंबिका मरकाम जी चली गईं, इधर से आ रहा है राजनांदगांव से, उसी में जुड़ेगा और आगे सराईपाली रोड में जुड़ेगा, चातुरी नंद जी को पूछ लो, धनबाद का सेंटर बनना है। छत्तीसगढ़ देश के मध्य में उपस्थित है। जब यह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो लॉजिस्टिक हब सेंटर देश के पूरे जगह के माल सप्लाई होही कहूं ले तो छत्तीसगढ़ से होही।

श्री जनक ध्रुव :- कोयला लोहा मन जाही लगथे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब आप देश की उपलब्धि के लिए बधाई दीजिये। सुधांशु शुक्ला पहले व्यक्ति बने, जो मोदी जी के नेतृत्व में अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे। (मेजों की थपथपाहट) उमेश पटेल जी, अब आप शुरू हो जाईये। मेरे ऊपर नाराज होंगे तो हाईयेगा, उसमें मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मैं शुरू से आपके पक्ष में खड़ा था। जो आपके बाजू में बैठते हैं। यह विनियोग पर चर्चा है। आप ध्यान रखना। पांच साल तक जेब में सबूत लेकर चलने वाले लोग झीरम में क्या किये, अगर पांच साल में एक भी बात की होगी तो जब आप लोग बोलन के लिए खड़े होंगे, तब यह बताईयेगा। उस नौजवान के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया।

श्री उमेश पटेल :- चन्द्राकर जी, आप गृह मंत्री थे। मैंने आपको धन्यवाद दिया था। आपको याद है?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उस बात को मान लिया। मैं उसको धन्यवाद लेने के लिए नहीं किया था। हमारी ड्युटी थी, इसलिए मैंने किया था। पांच साल तक उसका राजनीतिक दुरूपयोग हुआ था। मेरे जेब में वह सबूत है। वह सबूत कहां है? उसको छत्तीसगढ़ की जनता देखना चाहती है। उमेश पटेल जी उसको समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वह नहीं समझते हैं। अब मैं विजय शर्मा जी के बारे कहना चाहूंगा

कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए आलोचना करेंगे। आप लोग यह बताईये कि कांग्रेस पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे हैं, खून करते हैं, तो उसमें विजय शर्मा जी क्या कर लेंगे?

श्री रामकुमार यादव :- मोला अइसे लागत हे कि आप अगर एतके बड़े ज्ञानी हो के अइसनहे बोलत हौ। मतलब आप आय, बाय, साय हो गये हौ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मस्तुरी में दोनों कांग्रसी एक-दूसरे को गोली चला रहे हैं। जांजगीर में एन.एस.यू.आई. का एक पदाधिकारी तस्करी की योजना बनाते-बनाते पकड़ा गया है। यह इतना बड़ा-बड़ा समाचार पेपर में आया है। अब आप यह बताईये कि देश की राजनीति को किधर ले जाना चाहते हैं? सेना में रिजर्वेशन नहीं है, न्यायपालिका में रिवजर्वेशन नहीं है। सेना में रिजर्वेशन की बात कौन उठा रहा है? आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? आप सेना की भी राजनीतिकरण करेंगे? यही आपके राष्ट्र के प्रति प्रेम है? आप एकाध संस्था को तो छोड़ दीजिए। आप लगातार चुनाव हार रहे हैं और आप किसको दोष दे रहे हैं? आप कभी निर्वाचन आयोग को दोष देते हैं, कभी दिल्ली रैली में राष्ट्रपति का नाम लेकर धमका रहे हैं। ज्ञानेश कुमार, हम देख लेंगे, यह चीज हम देख लेंगे। यह आपकी भाषा है? जब आप चुनाव जीतते हैं तो वहां के निर्वाचन आयुक्त को फांसी टांगिये। आप तेलंगाना में चुनाव जीते तो वहां के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है, उसको फांसी में टांगिये कि आपने गलत जीताया है, ई.व्ही.एम. का दुरूपयोग हुआ है। जब वह सर्वोच्च न्यायालय बोलती है कि आप हलफनामा दीजिये, निर्वाचन आयोग बोलता है कि आप हलफनामा दीजिये, यह हमारे प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिये, तब आपको फुर्सत नहीं रहती है, तब उन संस्थाओं के सामने सामना करने के लिए नहीं जाते हैं। आपके लिए प्रेस, पेपर, रैली, इन संस्थओं को बदनाम करने के लिए है? उसके बाद भी आप सेना तक पहुंच गये। न्यायपालिका तक पहुंच गये। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं?

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। अब वह [xx][6] हरवंश मैडम बैठी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार जी, आप बिहार में चुनाव प्रचार करने कहां गये थे?

श्री रामकुमार यादव :- तुमन पैसा बांटत रहा, तेन ला देख रहा कि कहां-कहां बांटत हौ। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- तैं हर तो रेस्ट हाऊस मा गिनत रहे का?

श्री धर्मजीत सिंह :- बिहार चुनाव मा प्रचार करे गे रहे हस ता एकाध एम.एल.ए. जीतिस के नहीं?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बिहार चुनाव में आथौ। माननीय उमेश पटेल जी, वह [xx][7] अकेले रेत माफियाओं से लड़ रही थीं। उनका किसी ने समर्थन नहीं किया। अब क्या सच है, क्या गलत है, वह

---

[6][xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

जानें। लेकिन वह हमारी विधायक साथी हैं, इसलिए हम उनके साथ रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी रेत माफिया के संग सही थी, गलत थी, लेकिन वह अकेले लड़ रही थी। अब सब छूटे तो छूटे, लेकिन आप लोगों की आदत नहीं छूटती है। आप जहां जायेंगे, छाप छोड़ कर आयेंगे। बिहार चुनाव की बात हो रही थी। देवेन्द्र यादव जी ए.आई.सी.सी. के पदाधिकारी हैं। पेपर में बड़ा-बड़ा समाचार छपा। क्या यहां देवेन्द्र यादव जी नहीं है? टिकट लेकर पैसा बांटा? (हंसी) वहां भी जाकर कलाकारी किये। आप छत्तीसगढ़ की इज्जत का तो ध्यान रखते कि बिहार में छत्तीसगढ़िया लोग बदनाम हो गये।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, तुमन झारखण्ड गे रहा। जहां-जहां तुमन गे रहा, ऊंहा-ऊंहा सफ्फा हार गे हौ। ओखर हिसाब कोन करिही?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो कहूं नई गे रहेओ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन ऊंहा के ठेका लेहे रहे हौ। छत्तीसगढ़ के मन ऊंहा जीताय बर ठेका लेहे रहे हौ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चन्द्राकर जी, मान लीजिये कि झारखण्ड में हम हार भी गये तो हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं झारखण्ड गये ही नई हौं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मान लेते हैं कि गये, लेकिन आप लोग जहां-जहां जा रहे हैं, वहां-वहां चुनाव हरा कर आ रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप मन फैसला कर लेवौ कि गये रहे हौ या नई गये रहे हौ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ भई । वृहस्पति सिंह जी बोल रहे हैं कि आप जो बोलते हैं ना कि एसआईआर का विरोध करते हैं तो उदाहरण आपको बता देता हूँ । सरगुजा में जिलाध्यक्ष बन रहे हैं, महाराज की जी-हूज़ूरी चलती है तो कोई फेयर इलेक्शन नहीं होता । यह वृहस्पति सिंह ने कहा है, वह दो बार विधायक थे । अब मनीष तिवारी और शशि थरूर उसने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन के वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाये । उसके वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुआ । हमको मतदाता सूची दी जाये, वह नहीं दिया गया । उन्होंने आरोप लगाया कि पांच सौ फर्जी मत जुड़े हैं, मधुसूदन मिस्त्री जी ने वह भी उपलब्ध नहीं कराया और कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो गया ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, किस विषय पर चर्चा हो रही है, आप चर्चा को कहां से कहां ले जा रहे हैं ? आप उसमें चले गये, आप उसमें रहिये ना, कृपया उनको निर्देश करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह एसआईआर का विरोध करते हैं । एसआईआर को ठीक करना है तो कांग्रेस के मतदाता सूची को, कांग्रेस के निर्वाचन प्रक्रिया को पहले ट्रांसपरेंसी के साथ करो, तब आप देश के संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाना ?

---

[7][xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

सभापति महोदय :- चलिये, आप समाप्त करें । (व्यवधान) हर बार टोकाटाकी न करें । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह अनुपूरक बजट एसआईआर के लिये है क्या ? इसमें बजट है क्या ?

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहली बात तो विनियोग के बारे में नियम पत्रिका में पढ़ लेते हैं । उमेश पटेल जी ला पूछ ले ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इसमें बजट हो तो बता दीजिए कि हम लोग भी यूज़ करेंगे ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल्दी बंद कर रहा हूँ । मैं नहीं बोल रहा हूँ भई, मैं आरोप वगैरह नहीं लगाता, लेकिन 960 करोड़ रूपये दारू का राजीव भवन में पहुंचाया गया, यह पेपर में आया । यदि दारू के पैसे से आपकी पार्टी चलती है तो जीवन में चुनाव नहीं जीतोगे, यह नोट कर लो । यह पेपर में बड़ा-बड़ा छपा है, मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप लोगों का अडानी के पैसे चलता है क्या ? आपकी पार्टी अडानी के पैसे से चलती है ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठे-बैठे नहीं बोलियेगा । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं पेपर कटिंग दे दूँगा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग महिलाओं को फ्री में सटरडे को दारू पीलाते हैं । यह पेपर में आया था, रायपुर की बात है ।

सभापति महोदय :- चलिये, संगीता जी । आपकी बारी आयेगी तो बोलिये ना।

श्री अजय चन्द्राकर :- संगीता जी, बाकी मन नइ जाने । भगवान कसम नइ जाने, लेकिन तैं जानथस के.के.श्रीवास्तव कोने ? ते जानथस । 300 करोड़ रूपया के लेन-देन, वोखरे सती त कहाथंव कि तैं जानथस ।

श्री रामविचार नेताम :- रेखा वगैरह यह भी दिखवाने जाती है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- दारू की बात करते हैं, दारू में विदेशी मदिरा आपके टाईम पास हुआ है । हमारे समय में विदेशी मदिरा पास नहीं हुआ है । सभापति महोदय, जैसे गन्ना रस मिलता है, वैसे जगह-जगह में मिलेगा । 25 लाख आपका टैंडर है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिये । आप 25 लाख में आप कहीं भी दारू बेच सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- दारू के पइसा से कांग्रेस चलथे, यह स्वीकार कर ना। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके राज में हर रेस्टारेंट में दारू मिलेगा । सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राज में एक फैमिली कहीं भी बैठक्र खाना नहीं खा सकती । धमतरी में घटना हुई है । रात को दारू पीये हैं और तीन-तीन मर्डर हुआ है । ढ़ाबा में तीन-तीन मर्डर हुआ है । इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मान लिया, आप सही बोल रही है । मैं यह बोल रहा हूँ कि आप दारू के पैसे से भाजपा चलती है, यह नहीं बोल सकती ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी सरकार अडानी के पैसे से चलती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एकाध पेपर कटिंग दिखा तो । एकाध ठन कोई सबूत दे तो । मैं पेपर कटिंग देथंव । कांग्रेस भवन में कार्टून से 960 करोड़ रूपये पहुंचाये गये ।

श्री रामकुमार यादव :- पेपर वाला तुंहरे ए, टी.वी.वाला तुंहरे ए, सब तुंहरे ए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पेपर तो आपका ही है, मीडिया तो आपका ही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, चलिये अब दो-तीन बात बोलकर बंद करता हूँ ।

सभापति महोदय :- प्लीज बंद करिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, पेरोल दिलवाकर के.के.श्रीवास्तव जी से इनके भाग्य को फिर से मुझे दिखाना पड़ेगा । खासकर संगीता जी को स्पेशली दिखवाना पड़ेगा कि देखो तो महाराज क्या है, इसके हाथ में ऐसा बोलकर । अब राष्ट्र नायकों, राष्ट्रपुरूषों पर आरोप लगाने की स्थिति में यहां तक पहुंच गये कि पेपर पढ़िये साहब कि वीर सावरकर के खिलाफ जब राहुल गांधी जी ने टिप्पणी की तो कोर्ट में उनको माफी मांगनी पड़ी । अभी और एक पेशी बढ़ रही है । अब स्थिति कहां तक पहुंच गई है, राष्ट्रीय राजनीति से लेकर नीचे तक देखें तो जान माल तक पहुंच गई है। साहब, ये देश क्या चलाएंगे ? ये प्रदेश क्या चलाएंगे ? रायपुर नगर निगम में पहले नेता प्रतिपक्ष तो तय कर लें, संदीप है या आकाश तिवारी है, वे एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं हैं और बड़ी-बड़ी बात करते हैं, ये हालत है। सभापति महोदय, मैंने कागज रख दी, मैं अब खत्म कर रहा हूं। आज की तारीख में विपरीत परिस्थितियों में प्रदेश का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट आया है, विकास का पहिया पटरी से मत उतरे, हमने जनता से जो वादा किया है, उस वादे पर खरे उतरें, वह वादा उचित है, अनुचित है, सही है, राजनीतिक है, गैर राजनीतिक है, वह अकेले भाजपा या कांग्रेस का काम नहीं है, यदि उन विषयों पर सहमति बनानी है और राजनीतिक उपयोग दुरूपयोग नहीं करना है तो यह राज्य अपनी संसाधनों की ताकत में और वित्त मंत्री जी ने जिस वित्तीय क्षमता का आंकलन छत्तीसगढ़ से किया है। इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने शपथ लेते वक्त एक लाईन कही, माननीय सभापति जी, उस समय आप भाजपा में थे, आप कांग्रेस में नहीं गए थे, उन्होंने कहा कि इस राज्य को हम टैक्स फ्री राज्य बनाएंगे, इतने संसाधन है, एक हीरा खदान खुल जाएगा, उतना पर्याप्त है। वास्तव में यदि हम जनहित

की ओर बढ़ें और चिंतन करें, सहमति करें तो हमारे संसाधन, हमारे विचार, व्यवहार, हमारे मानव संसाधन, हमारे प्रदेश के लोगों की बनावट मैं कहूंगा कि इससे सीधा आदमी नहीं जो छत्तीसगढ़ में आते हैं और छत्तीसगढ़ छोड़ना ही नहीं चाहता, यहीं का रह जाता है। ऐसी स्थिति में चिंतन करने की जरूरत है। मैं वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और एक आग्रह करूंगा, आप सक्षम हैं, आप विचारवान हैं, राजस्व बढ़ रहा है, ऋण से मत बढ़े, राजस्व व्यय घटे, पूंजीगत व्यय बढ़े, उसके लिए यदि इन महान लोगों से जो सामने बैठे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के असंख्य रिकार्ड पिछले 5 सालों में बनाएं, उनसे भी चर्चा करने की जरूरत है तो चर्चा होनी चाहिए। ये छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, ओ.पी. चौधरी जी के कुशल बजट प्रबंधन में आगे बढ़ेगा। इस भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, वाकई में अनुपूरक बजट का जो साईज है, लगभग 35 हजार करोड़ रूपए का है, इस अनुपूरक बजट में जो बात आई है, अभी अजय चंद्राकर जी और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे मेन बजट में भी और अनुपूरक बजट में भी पूंजीगत व्यय है, इसकी चिंता हम सबको करने की आवश्यकता है। पूंजीगत व्यय और जो राजस्व व्यय हो रहा है, इसमें अंतर जो लगातार आ रही है, ये छत्तीसगढ़ को कहां ले जाएगा, हम किस परिस्थिति में पहुंचेंगे, हमको इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है, ये सच बात है। सभापति महोदय, मैं इसी बात से शुरू करूंगा कि घोषणा पत्र में ये जो सरकार बनी है, 15 साल इनकी सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र बनाई, उसके बाद सत्ता में आई। अभी इन्होंने घोषणा पत्र में जो-जो वादे किए थे, 3100 रूपए में धान खरीदेंगे, महतारी वंदन, हम 50 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे, 5 साल के अंदर हम दो लाख लोगों की भर्ती करेंगे, आपने ये सारी बात कही। लेकिन आज इस बजट में सबसे बड़ा पाठ किस चीज का है ? धान खरीदी का है। लगभग 9 हजार करोड़ रूपये का धान खरीदी के लिए बजट रखा गया है। सभापति महोदय, यह बजट हम किसके लिए दे रहे हैं? हम किसानों के लिए दे रहे हैं। किसानों के लिए आज हम यह बजट पास करेंगे। ठीक है कि उनकी संख्या बल ज्यादा है। हमारे विरोध के बाद भी यह अनुपूरक पास हो जाएगा। यह तो व्यवस्था है और technicality है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि हम किसानों को यह 9 हजार करोड़ रूपये दे रहे हैं तो किसलिए दे रहे हैं? क्या लोगों को परेशान करने के लिए दे रहे हैं? यदि आप अभी जाकर देखेंगे तो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आज लोगों का रकबा कम हो रहा है। यहां पर जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मेरे ख्याल से सबको यह समस्या देखने को मिल रही होगी कि उनके यहां लोगों का रकबा कम हो गया है। पहली बात जो इस सरकार ने की, वह यह थी कि जो पटवारी गिरदावरी करते थे, उनको हटाकर एक प्राइवेट संस्था को लगाया गया। जिसमें गांव के लोगों व लड़कों को लगाया गया और

जिनको अनुभव नहीं है, उनके द्वारा गिरदावरी कराया गया। उसके बाद कौन सा रकबा उसमें जुड़ा है, कौन सा रकबा कटा है, कौन सा रकबा अभी है, यह तय नहीं हुआ है। आज भी हर किसान यही समस्या लेकर सामने आता है कि मेरा इतना रकबा कट गया, मेरा इतना रकबा कट गया। सभापति महोदय, धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन रकबा पूरी तरीके से ठीक नहीं है। धान खरीदी शुरू होने के बाद समस्या कहां पैदा हो रही है तो लोगों को सुबह नोडल अधिकारी का इंतजार करना पड़ रहा है। जब तक उसकी ट्रेक्टर में फोटो नहीं खिंचाएगी, तब तक वह किसान अपने धान को अंदर नहीं ले जा सकता है। वह 10 बजे आये, 11 बजे आये, 12 बजे आये, तब तक ट्रेक्टर की लाइनें लगी हुई हैं। उसके बाद हर सोसायटी में कहीं 3 रूपये, कहीं 5 रूपये, कहीं 7 रूपये, कहीं 4 रूपये इस तरह से किसानों से धान भराई का पैसा लिया जा रहा है। यदि आप इसका अनुमान लगाएंगे तो यह 120 करोड़ रूपये का होता है। यह किसानों से धान भराई के नाम से 120 करोड़ रूपये की वसूली कर रहे हैं। सभापति महोदय, ये सब तो किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन किसानों और छत्तीसगढ़ के आम लोगों की जेब में आप [xx] कैसे डाल रहे हैं? सभापति महोदय, सबसे पहले [xx] खाद से शुरू हुई। सबसे पहले हमको डी.ए.पी. खाद नहीं मिली। जो डी.ए.पी. खाद हमको 1400, 1500, 1600, 1800 रूपये में मिलती थी, वह हमें दुकानों से 2500, 2600 रूपये में लेनी पड़ी। पहली [xx] खाद से शुरू हुई। लोगों ने धरना दिया, परेशान हुए कि कहां से लाये, कैसे लाये? कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद यूरिया के समय में भी यही परेशानी हुई। जो यूरिया 300 रूपये में मिलनी थी, उसको लोग 1000-1000, 1100-1100, 1200-1200 रूपये में लेकर आये हैं। यह आप सब लोग भी जान रहे हैं। चाहे उधर बैठे हैं, चाहे इधर बैठे हैं। यह परेशानी आज किसानों को हुई है। चाहे यूरिया में हो, चाहे डी.ए.पी. में हो। यह समस्या खत्म नहीं हुई थी कि यह रकबा कटने का काम हुआ। रकबा कटने का काम खत्म नहीं हुआ था कि धान खरीदी में समस्या चालू हो गई और हम यह 9 हजार करोड़ रूपये का बजट दे रहे हैं। हम इनको सुविधा के लिए बजट दे रहे हैं। इनको अनाज के दाम देने के लिए बजट दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? किसान परेशान हो गये हैं। मुझे लगता है कि यह जो साल है, इसमें चाहे खाद से लेकर धान खरीदी तक पिछले कई सालों में इस तरह का अनुभव किसानों को कभी नहीं हुआ है, जो इस साल हो रहा है। एक किसान ने मुझे कहा कि जब मैं धान को सोसायटी में बेचकर आ जा रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गंगा नहाकर आ गया। उसको इतनी परेशानी हो रही है और जैसे ही वह धान बेचकर आ रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे सर का जो इतना बड़ा बोझ था, वह उतर गया। क्योंकि उनको लगातार इतना परेशान किया जा रहा है। चाहे नोडल अधिकारी के द्वारा नमी ज्यादा है, करके 17 प्रतिशत में आपको वापस कर दिया जा रहा है, 18 प्रतिशत में आपको वापस कर दिया जा रहा है। नमी कम है तो अभी यह कहा गया है कि जिन किसानों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनको सत्यापन करने के बाद ही धान बेचने दिया जायेगा । यदि अब सत्यापन करना पड़ रहा है तो आपने गिरदावरी किस बात की की है ? अगर उसके

खेत में धान है, उत्पादन है तो फिर अब क्यों करना पड़ रहा है ? और यदि अभी सत्यापन करना पड़ रहा है तो आपने उस समय क्यों किया था ? आप सिर्फ परेशान करने के लिये दोनों समय सत्यापन कर रहे हैं । सभापति महोदय, सबसे बड़ी चीज यह है कि सारे प्रबंधकों को कहा गया है कि आप किसानों से रकबा सर्मपण करवाईये। चाहे जो जितना भी कर सके। जबर्दस्ती कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई पैर पढ़ रहा है, कुछ भी करके आप थोड़ा-सा भी रकबा कम करवाईये। किसानों को लगातार यह सारी परेशानी हो रही है। सभापति महोदय, किसान जब धान बेचने जाता है तो प्रबंधक उसे बोल रहा है कि बोरे का वजन 600 ग्राम है। मैं 40.600 कि.ग्रा. बोरा भरूंगा लेकिन वह 41.500 कि.ग्रा. भर रहा है । वह 41.500 कि.ग्रा. इस नाम से भर रहा है कि सूखत आ जायेगा। यदि सूखत आ जायेगा तो सरकार जो हमसे वसूल गरेगी, वह हम आपसे वसूल कर रहे हैं। 1 कि.ग्रा. का सूखत ? अगर आप नमी ज्यादा ले रहे हैं और 20-21 प्रतिशत ले रहे हैं तब तो समझ में आता है कि इतना सूखत आ गया और 3-4 महीने तक नहीं उठा। यदि आप केलकुलेट करेंगे तो 40 कि.ग्रा. में 1कि.ग्रा. का सूखत आने की संभावना ही नहीं है । लेकिन यह उसको भी कर रहे हैं। सभापति महोदय, आप किसानों को इतना तंग करके धान खरीदी के लिये 9 हजार करोड़ रूपये का बजट मांग रहे हैं। आप बोल रहे थे न कि आपको हाय लगेगी। आपको किसानों की हाय लग चुकी है। आज भी आप किसी सोसायटी में चले जाईये और किसी भी किसान से पूछ लीजिये, भले वह आपकी पार्टी का हो। मेरे क्षेत्र का एक आदमी हैं जो आपकी पार्टी का अच्छा किसान है, बड़ा किसान है, वह मुझसे कह रहा था कि किसानों के लिये आपकी सरकार अच्छी थी। यह उसने मुझसे कहा है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, ये मन गमछा ला ओती लुका के ले गे हे। ओला झोला में भर देत हावय। सोसायटी में ए गमछा ला देखत हन तो भड़क जात हे ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, यह तो किसानों की बात है। किसान तकलीफ में हैं। चाहे खाद को लेकर, चाहे बिजली को लेकर, चाहे 6 घण्टे की बिजली कटौती को लेकर । अजय जी, आप बिजली की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी समस्या बिजली को लेकर है। यदि छत्तीसगढ़ की जनता किसी बात से परेशान हैं तो वह बिजली को लेकर परेशान है। गर्मियों में चाहे घर की बिजली हो, चाहे खेतों की बिजली हो, चाहे ट्रांसफार्मर की बात हो, आप भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। चन्द्राकर जी, मैं आपको सबसे बड़े भ्रष्टाचार के बारे में बता रहा हूं। ट्रांसफार्मर में भ्रष्टाचार हो रहा है। ट्रांसफार्मर एक दिन नहीं चल रहा है। आज बदल रहे हैं और उसमें सुबह फिर से फॉल्ट आ जा रहा है। मैं और बड़े भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं। अभी डेली के केलकुलेशन की डायरी लिखी जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि वह विषय बहुत जल्दी बाहर निकलेगा। मैं अभी बताऊंगा, अभी समय है। डायरी बनाकर केलकुलेशन हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उसको बाद में बता दीजियेगा। आप घर के आदमी हैं। लेकिन आप यह बता दीजिये कि ब्लॉक अध्यक्ष कब तक बनेंगे? आप उसको तो जानते हैं न ? कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कब तक बनेंगे, आप उसको बता दीजिये ?

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- तै हर हमर संगठन के भारी चिंता करत हस।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप मन नाम बता देवव। हमन ऊंही ला बना देवव।

श्री रामकुमार यादव :- अब ओती कोई पूछइयां नई हे तो एती करही नहीं तो का करही।

श्री उमेश पटेल :- आप भ्रष्टाचार की बहुत बात कर रहे थे। मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में बताऊं ? तहसीलदार को यह बोला जा रहा है कि विवादित जमीन को निकालिये और तहसीलदार दोनों पार्टियों को कह रहा है कि आप जमीन फलाना को बेच दीजिये। तहसीलदार दोनों पार्टियों को कह रहा है कि यदि आप फलाना को जमीन बेच देंगे तो आपके पक्ष में कर दूंगा। सभापति महोदय, वह कह रहा है कि 50 लाख रूपये में बेच दीजिए, जबकि वह जमीन 2 करोड़ रूपये की है। इस सरकार का इस लेवल पर भ्रष्टाचार चल रहा है। जहां 10 गाड़ी पास हो रही है, वहां एक गाड़ी का पैसा लिया जा रहा है। उसकी डायरी बन रही है और बहुत जल्द ही वह सामने आयेगी। मैंने उसके पीछे सोर्स लगा रखे हैं। यह भ्रष्टाचार तो चल रहा है। वह अलग विषय है। आपने गाईडलाईन की बात की। आपकी गाईडलाईन को तो सबसे ज्यादा आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने दुर्ग में झेला है। अध्यक्ष जी गये थे, लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया था।

श्री किरण देव :- प्यार से।

श्री उमेश पटेल :- चलिये, प्यार से घेर लिया था। अध्यक्ष जी की गाड़ी को घेर लिया था। गाइडलाइन के लिये इतनी अनियमितता, इतना इस तरह का बिना सोच-समझे निर्णय लिया गया। गाइडलाइन के बारे में बताना चाहता हूं कि जो जमीन खरीदी बिक्री करता है, उसने मुझसे कहा कि मेरी डील हो गई थी, मार्केट रेट 1 करोड़ रुपये का था और गाइडलाइन रेट 50 लाख रुपये का था। अब नई गाइडलाइन बदलने के बाद वह गाइडलाइन रेट 250 करोड़ रुपये का हो गया है और मार्केट प्राईज 1 करोड़ रुपये का है। अब कैसे हो? अब देखिये, अब मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि इस नई गाइडलाइन के साथ आने वाले समय में जमीन की खरीदी बिक्री पूरी तरीके से रूक जायेगी। नहीं होगा, होगा ही नहीं। इसको बदलने की आवश्यकता है, प्रेक्टिकल करने की आवश्यकता है। मार्केट रेट से अगर ज्यादा गाइडलाइन हुई तो कहां से जमीनों की खरीदी बिक्री होगी। आप जाईये, सर्वे करिये, 4 महीने लगाईये, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मार्केट रेट है, उससे अधिक की गाइडलाइन रेट रहेगा तो कहां से चलेगा। माननीय सभापति महोदय, यह गाइडलाइन को लेकर लगातार जो धरना, आंदोलन हो रहा है,

तरह-तरह के मीम्स आ रहे हैं। आप सब लोग सुन रहे हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री मैं आपको ही बोल रहा हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- आपके नेता आपके भाषण का बहिष्कार कर दिये हैं।

श्री उमेश पटेल :- सब लोग सुन रहे हैं, वह अपने कक्ष से सुन रहे हैं। मुझे बोलकर गये हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे बिजली की बात कर रहा था। ऐसी क्या बात हो गई कि हम लोगों की एक दिन में 10 से 20 बार बिजली बंद हो रही है। वही लोग, वही अधिकारी, वही कर्मचारी हैं, लेकिन गर्मियों में बिजली नहीं है। बिजली गावों में 10-10 बार बंद हो रही है। जो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह इस चीज को बता पायेंगे। हम तो 5 साल में भूल गये कि लाइट बंद होती है। कभी-कभी फाल्ट होता था तो लाईट जाती थी।

श्री केदार कश्यप :- आपके समय में भी लाईट नहीं थी।

श्री उमेश पटेल :- ऐसा मत बोलिये। सही में गर्मियों के दिनों में लाइट को लेकर बहुत परेशानी हुई है। आपके जनप्रतिनिधियों से पूछ लीजिए। क्यों ऐसा हुआ? सभापति महोदय, इसलिए हुआ कि गर्मियों में जो मेन्टेनेंस होता था, उसके लिये आपने पैसा नहीं दिया। कहीं पर पेड़ काटना है, कहीं कटिंग करना है, कहीं पर खंबा गिर रहा है, कहीं पर लूज हो गया है। ये जो बिजली विभाग का काम होता है, वह काम तो आपने किया नहीं। चूंकि वह काम आपने किया नहीं तो गर्मी, बरसात के समय में लाईट बंद, 8-9 घंटे लाईटें बंद रहीं, लगातार बंद रहीं। सभापति महोदय, मैं बिजली में ही बोलना चाहूंगा। बिजली में हमारी 400 यूनिट तक छूट थी, उसको खत्म करके 100 यूनिट कर दिया, फिर उसको बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया। मतलब 4 कदम पीछे हटो और 2 कदम आगे बढ़ा लो। क्या माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के लोगों को इतना नासमझ समझे हो। पहले 4 कदम पीछे हटो, फिर 2 कदम आगे बढ़ जाओ। नेता जी, ऐसा हुआ न। 400 यूनिट को आप 200 यूनिट कर दिये। उसमें और ट्विस्ट, अगर आपकी बिजली 400 यूनिट से ऊपर हुई तो कोई छूट नहीं मिलेगी।

श्री रामकुमार यादव :- भैया जी, तू ऐसे आदमी ला हूकारू देवाथन न वो हा अउ न कह सकय।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने उसको एक साल के लिये किया है। उनके आदेश में लिखा है कि एक साल के लिये है। क्यों? क्योंकि हम पी.एम.सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ला रहे हैं। काहे का मुफ्त भैया? उसको लागने में कितने रुपये लग रहा है? 3 किलोवाट का आप सोलर एनर्जी लगवाओगे तो क्या होगा, उसको लगाने में कितने रुपये लग रहा है? ढाई लाख रुपये तो वहां हो गया। 1 लाख रुपये की सब्सिडी है, वह 3 किलोवाट चलाने के लिये डेढ़ लाख रुपये कहां से लायेगा?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, उसमें एक और बड़ी बात है कि उस संयंत्र में केवल और केवल 3-4 कंपनी को दिया गया है । ऐसा नहीं है कि मार्केट में कहीं भी ले लें, उसमें भी अंदर की बात बड़ी है । दूसरी बात, 200 यूनिट तो फ्री किये हैं, यह तो नीति में है लेकिन अघोषित रूप

से बिजली बिल इतना बढ़ाया जा रहा है । अगर आप विभागों में जांच करेंगे तो लाखों की संख्या में जायेगी, जो बिजली बिल ज्यादा आया है करके आवेदन कर रहे हैं और लोक अदालत के माध्यम से बिजली बिल की व्यापक वसूली की जा रही है ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिए ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, मुफ्त बिजली योजना उसको बोल रहे हैं, सौलर एनर्जी लगाओ, 3 किलो वाट का लगाओ, 5 किलो वाट का लगाओ, 10 से ऊपर लगा नहीं सकते हैं । आप एक तरफ तो लोगों को 8 रूपये में बिजली दे रहे हैं और जब वह सौलर से बना लेगा तो आप उसको कितने रूपये में खरीद रहे हैं, ढ़ाई रूपये में । आपकी यह किस तरह की योजना है ? आपको सिर्फ फायदा हो, आपने ऐसी योजना बनायी है ।

माननीय सभापति महोदय, यदि इनकी बात का सम्मान कर कोई सौलर एनर्जी लगवा लेता है और अगर ज्यादा बिजली बना लेता है तो यह उसकी एवज में ढ़ाई रूपये देंगे और जब उसी ग्राहक को बेचेंगे तब 8 रूपये में बेचेंगे । आपके यूनिट के हिसाब से अलग-अलग स्लैब रेट हैं, मैंने आपको आखिरी स्लैब रेट में बताया कि 8 रूपये देंगे तो ऐसे मतलब आप उनको एक-तरफ 8 रूपये में बेच रहे हो और उससे ढ़ाई रूपये में खरीद रहे हो । आपने ऐसी तो योजना बनायी है । आप बतायेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? आप मुफ्त बिजली योजना किसलिए लाये हैं ? ताकि आपको यह जो रिनीवल एनर्जी है, वह मिलता रहे, लोग सब जगह लगायें तो मिलता रहे । आपको खरीदना कम पड़े और आपको ढ़ाई रूपये में मिल जाये । आप यही बिजली जब किसी कंपनी से खरीदते हैं तो कितने रूपये में आपका कांट्रेक्ट हो रहा है? और जब आम आदमी एक लगा लेगा तो उससे ढ़ाई रूपये में ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी, अडानी जी तो 7 रूपये में देते हैं न ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, अगर आप सही में रिनीवल एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो जिस रेट में आप बेच रहे हैं, आप उसी रेट में उससे खरीदिए । मैं व्यापार की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं लेकिन घर में जिसने लगाया है, जिसने व्यापार के हिसाब से लगाया है उसमें तो आपका जो हिसाब लगता है, आपका जो होगा लेकिन घर में किसी ने अगर सौलर एनर्जी लगायी है तो आप यह तय करिये कि आप उससे उसी रेट में खरीदें जिसमें बेच रहे हैं, नहीं तो इस योजना का नाम बदल दीजिये, पी.एम. मुफ्त बिजली योजना । यह पूरी तरीके से भ्रामक है ।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की बात करेंगे । पर्यटन मंत्री जी चले गये क्या ? चलिये, स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, हम उन्हीं की बात कर लेते हैं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने मैकाहारा को, मेरा आपसे निवेदन है । मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे केवल निवेदन कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं । आप मैकाहारा को इस लेवल पर ले जाईये । इतनी स्वच्छता रखिये कि वहां लोगों को आने में परेशानी न हो, मैं आपको बताउं कि वहां परेशानी क्या आ रही है । परेशानी यह हो रही है

कि मैकाहारा में एक वॉर्ड में जितने बिस्तर हैं उससे ज्यादा लोग नीचे रहते हैं तो आपको उस लेवल पर, मैकाहारा लेवल पर या तो किसी प्राईवेट हॉस्पिटल से कांट्रेक्ट करना हो, अपने लोगों को एडमिट कर सकें, वहां डालना है तो वहां डाल दीजिये लेकिन आप मैकाहारा को यह करिये । वन मंत्री जी, आपके लिये बहुत सारी बात हुई । आप फर्जी जनसुनवाई करवा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- 20 मिनट हो गये हैं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, बस 5 मिनट । मैं आखिरी में संसदीय कार्यमंत्री जी से बात करके समाप्त कर दूंगा ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, वह हमारी तरफ से पहले वक्ता हैं ।

श्री उमेश पटेल :- दूसरा ।

श्री रामकुमार यादव :- दूसरा है तो यह हमारा मेन है ।

श्री उमेश पटेल :- मैं दूसरा वक्ता हूं । माननीय सभापति महोदय, यहां लालजीत सिंह जी बैठे हैं, हमारी विधायक विद्यावती सिदार जी हैं । आपको फर्जी जनसुनवाई कराना पड़ रहा है । आज भी 5000 लोग धरने पर बैठे हैं और फर्जी जन-सुनवाई कैसे हुई, मैं आपको यह बताता हूं । जो जगह निर्धारित थी, जिस जगह पर जन सुनवाई होनी थी। वहां 5 हजार लोग अपना विरोध दर्ज करने के लिए बैठे थे। उसमें स्वयं विधायक भी उपस्थित थीं। सुबह 10.00 बजे वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर टेबल, कुर्सी लगा दिया जाता है, जो निर्धारित जगह है। भईया, 15 मिनट की जनसुनवाई होती है। एम्बुलेंस में 18 लोगों को लेकर आया जाता है। वहां 18 लोग आते हैं, समर्थन करते हैं, 15 मिनट के अंदर जन सुनवाई समाप्त होती है और 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस से सब लोग वापस चले जाते हैं। यह स्थिति है। आपको यह जनसुनवाई करने का इतना डर है तो आपको किस चीज का डर है? अगर आपने फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं किया है तो वहां पर 5 हजार लोग क्यों उपस्थित हैं। वहां आज भी बैठे हैं। आज भी वहां उपस्थित हैं। यह तमनार की घटना है। आप यह खुद पता कर लीजिए। तमनार में 5 हजार लोग बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है कि फर्जी जन सुनवाई को निरस्त किया जाये। उनकी सिर्फ एक मांग है और कुछ मांग नहीं है। इस तरह की जनसुनवाई हो रही है। मतलब धर्मजयगढ़ के पुरंगा और उसके आसपास के गांव के लोग ठंड में दिन और रात, 2 दिन तक कलेक्ट्रेड के बाहर बैठे रहे। वहां महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर आयी थीं। वहां दो दिन तक बैठे रहे। वहां पर दो दिन तक बैठने के बाद कलेक्टर मिलने तक नहीं आया। यह आपकी असंवेदनशीलता को दिखाता है। आप संवेदनशील नहीं है। मैं, आप और मजेदार बात बताऊं कि माननीय विष्णु देव साय जी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यह वही लोग है जिन्होंने इनको संसद भेजा है। उनका प्रतिनिधित्व का चुके हैं। उन्हीं लोगों ने इनको वोट देकर सांसद बनाया। आज उन्हीं लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। न कलेक्टर कर रहे हैं न वहां कोई जनप्रितनिधि जा रहा है। आप हिम्मत करिये, उनके बीच जाईये। वहां पर 5 हजार लोग बैठे हैं

क्या होगा ? उनका सामना करिये। उनसे आपकी कुछ बातचीत होगी, वह लोग कुछ बात कहेंगे, आप कुछ कहना। ऐसा हो सकता है कि इस बीच में कुछ रास्ता निकल जाये, लेकिन वहां किसी को नहीं जाना है। वहां पर कोई अधिकारी नहीं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं जाएगा, कोई जनप्रतिनिधि नहीं जाएगा। यह जो सारा बलपूर्वक काम किया जा रहा है हम क्या करें ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक मजाक की बात बताऊंगा। इस लेवल पर राजनीति है। माननीय चन्द्राकर जी राजनीति-राजनीति बोल रहे थे इस लेवल पर राजनीति को ले गये हैं कि किसी गांव में जाते हैं तो कोई दारू बना रहा है तो पहले उससे पूछते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस पार्टी के हो। यदि वह कहता है कि अगर वह कांग्रेस पार्टी का है तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। यदि वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का है तो उसको रहने देते हैं। इस लेवल पर राजनीति को ले गये हैं। यहां पर अभी माननीय चन्द्राकर जी नहीं हैं। वह राजनीति की बात कर रहे थे। इस लेवल पर राजनीति को ले गये हैं कि दारू(शराब) बनाने वाले को भी यह पूछा जा रहा है कि भाई, आप कांग्रेस पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो ? यहां पर यह परिस्थिति बन चुकी है। मैं आपसे यही कहूंगा कि यह जो अनुपूरक बजट लाया गया है। माननीय मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी आ गये हैं। माननीय मंत्री जी आपको बजट में टाईगर रिजर्व मिला है। आप जंगल सफारी की हालत सुधार लीजिये। जंगल सफारी जो इतना बड़ा एरिया में बन गया है उसको सुधारिये। उसके जैसा मत हो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप उधर क्यों बोल रहे हैं, आप इधर बोलिए।

श्री उमेश पटेल :- मंत्री जी आ गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप ईधर आईये।

श्री उमेश पटेल :- अच्छा हां। राजेश जी, मैं माफी चाहूंगा। माननीय मंत्री जी इधर हैं। आप उसको सुधारिये। वह इतना बड़ा रिजर्व बन गया है तो उसको वृहद बनाईए, उसमें काम होगा । आप टाईगर रिजर्व बना रहे हैं । हमारी सबसे बड़ी मांग तो हाथी रिजर्व एरिया को लेकर है । सभापति महोदय, हम इस अनुपूरक बजट का इसलिए विरोध करते हैं कि ये सरकार आदिवासियों के खिलाफ अवंसेदनशील हो गई है, ये सरकार किसानों के प्रति अवंसेदनशील हो चुकी है, ये सरकार महिलाओं को ठगने का काम कर रही हैं । जो बुजुर्ग महिला हैं, जिनको बताया गया कि हम महतारी वंदन योजना के नाम से 1 हजार रूपए आपके एकाउन्ट में डालेंगे, इन्होंने घोषणा-पत्र में बड़ी-बड़ी बात की थी, पर उनको 500 रूपए काटकर दिया जा रहा है । ये उनके प्रति भी असंवेदनशील हैं । ये सरकार नवजवानों के साथ अवंसेदनशील है । क्यों ? इन्होंने 55 हजार नौकरियों की बात की थी, 2 लाख, 55 हजार शिक्षकों के भर्ती की बात की थी, 2 लाख नई नौकरियों की बात की थी और यह इनके ही भाषण हैं । अगर आप चाहेंगे तो इनके भाषण का वह वीडियो मैं प्रस्तुत कर दूंगा । आपने कहा था कि 2 लाख नौकरियां मिलेंगी, 55 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे और आज 5 हजार शिक्षक पर अटक गए। स्कूलों में

युक्तियुक्तकरण करने के नाम पर आप शिक्षकों को 5 हजार पर ले आए । पहले 30 विद्‌यार्थियों के पीछे एक शिक्षक का मापदण्ड था, उसको आपने 60 विद्‌यार्थियों में एक शिक्षक का मापदण्ड कर दिया । 60 विद्‌यार्थियों को एक शिक्षक सम्हाल पाएगा क्या ? आज तो ऐसे स्कूल भी हो गए हैं, जहां सिर्फ हेड मास्टर हैं । क्योंकि वहां एक ही शिक्षक कार्यरत्‌ हैं और हेड मास्टर को काम कहां दिया जाता है? दिन भर में बीईओ और डीईओ का काम ज्यादा रहता है । वह शिक्षक स्कूल में रहता ही नहीं है । इसको भी दूर करने की आवश्यकता है । सभापति जी, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं । मैं अपनी बात को इन बातों के साथ समाप्त करता हूं कि यह सरकार असंवेदनशील है, यह सरकार आदिवासियों के साथ असंवेदनशील है, यह सरकार किसानों के लिए असंवेदनशील है, यह सरकार नौजवानों के साथ असंवेदनशील है, यह सरकार महिलाओं के साथ असंवेदनशील है । इसलिए मैं इस अनुपूरक बजट का पुरजोर विरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपने बहुत ही काबिल वित्त मंत्री जी के द्‌वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं लगातार सुन रहा हूं, हर सत्र में सुनता हूं । जब भी इस विधान सभा का सत्र शुरू होता है तो ये लोग हर जगह सिर्फ गलतियां, खामियां दिलाने का काम करते हैं, कभी कोई सलाह नहीं देते, सिर्फ ऊंगली दिखाने का काम करते हैं और ये बेचैन तब से हो गए हैं, जब से इस प्रदेश की जनता ने जनादेश देकर श्री विष्णु देव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया । श्री विष्णु देव साय एक गरीब परिवार की तकलीफ को जानने वाले मुख्यमंत्री हैं । जिन्होंने आदिवासी अंचल में जन्म लिया, वहां की समस्याओं से पूरी तरह से वाकिफ और भले सीधे-सच्चे और ईमानदार इंसान के रूप में वह अपनी योग्यता से, अपनी सेवा से प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हुए और एक आदिवासी का मुख्यमंत्री बनना और उनका सरकार चलाना कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसीलिए आये दिन वे मुख्यमंत्री की ओर, इस सरकार की ओर ऊंगली उठाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि सीधा होना भी बहुत तकलीफ का काम है । जरूरी नहीं है कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, जरूरी नहीं है कि कोई गलती करने से ही दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और मुख्यमंत्री जी हद से ज्यादा अच्छे हैं, सीधे हैं, सरल हैं । हमारे मंत्रियों में भी सब बहुत सीधे, सरल लोग हैं । इसलिए यह कीमत चुकानी पड़ती है कि आप उनकी आलोचना करते हैं और बिना डर और भय के आलोचना करते हैं । पहले तो आलोचना करने में भी डर और भय लगता था । पहले तो पुलिस के बूटों की धमक से और नोटों की चमक से आपकी सरकार चलती थी । अगर आप कुछ ज्यादा बात करते तो सीधे अंदर । और या फिर मंत्रालय में असंवैधानिक सत्ता के केन्द्र में बैठे हुए लोग, बड़े-बड़े आईएएस आफिसर, बड़े-बड़े नेता करोड़ों की डील करते थे, जिसके कारण आज आप के लोग तकलीफ में हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा है। मैंने अपने 22 वर्ष के विधायकी के राजनीतिक कार्यकाल में 33 हजार करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट नहीं देखा है। यह अनुपूरक बजट, सिर्फ बजट नहीं है। बल्कि उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रतीक है, जिसकी तरफ जनता देख रही है। सिर्फ धान खरीदी करना या सिर्फ सड़क बना देना ही पूरा बजट नहीं होता है। यह बजट का एक हिस्सा है। लेकिन अच्छी एक चिकित्सा शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, अच्छा बिजली संयंत्र चाहिए, सब स्टेशन चाहिए, छोटे-मोटे डेम चाहिए, छोटी-मोटी व्यवस्था चाहिए, गांव में रहने वालों के लिए सुविधा चाहिए, इन सभी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर इस बजट में प्रावधान किया गया है। मैं पूरे बजट और पूरे आकड़ों को नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि मैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी आकड़ें पढकर भाषण नहीं देता हूं। उस बजट से क्या सुकून मिल रहा है, उसकी अनुभूति को व्यक्त करता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों की अनुभूति को यहां प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा।

सभापति महोदय, मैं एक-दो आकड़ें पढ़ देता हूं। मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सिस्टम के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें कहां गलती है ? आप चाहते हैं कि आज से 30-40 साल पहले जैसा ही छत्तीसगढ़ रहे ? अगर यहां रोबोटिक सिस्टम एडाप्ट होगा तो हमारा छत्तीसगढ़ भी अच्छी चिकित्सा सुविधा देने के लिए आगे बढ़ेगा। नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 179 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हम लोग बात-बात में छत्तीसगढ़ में भिलाई, कोरबा बोलते हैं। वहां बड़े उद्योग हैं और वह हमारी एक धरोहर है। लेकिन अगर 179 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है जिससे नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, जहां एक गरीब का बेटा भी उद्योग चलाकर उद्योगपति कहलायेगा और अपने परिवार को जीने के रास्ते में आगे बढ़ायेगा।

सभापति महोदय, महतारी वंदन के लिए 280 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। महतारी वंदन से किसी को क्या तकलीफ है। अगर आप किसी महतारी को पैसा नहीं पाये तो यह आपकी नाकामी थी। लेकिन विष्णु देव साय ने इस प्रदेश की माताओं और बहनों के सम्मान के लिए, उनके आत्म निर्भर होने के लिए महतारी वंदन के माध्यम से 1 हजार रूपया प्रति माह देने का एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है उसके लिए बजट में प्रावधान किया जायेगा। यह महतारी वंदन का कार्यक्रम हमेशा चलते रहेगा। इसको ना तो आपके कहने से रोका जायेगा और ना ही किसी के कहने से रोका जायेगा। आपने महतारी वंदन योजना का एक असर अभी-अभी बिहार में देखा है। महतारी लोगों के मान और सम्मान से टकराने की कोशिश मत करो नहीं तो चूर-चूर हो जाओगे। आप लोगों का बिहार में 6-8 सीट पाने का हाल था, वैसे ही आप लोग यहां दिखाई दोगे और हमको बोरियत लगेगी। क्योंकि यह इतना बड़ा सदन बन गया है।

श्री रामकुमार यादव :- उहां 10 हजार रूपया दे हा, 1 हजार नइ दे हा। ये हा इतिहास मा पहली बार होय हे, ये बात ला पूरा भारत देखे हे अउ पूरा विश्व देखे हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- इहां चुनाव आही तो हम 10 हजार नइ दे दब।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन झांकतेस ह, ये सब ला जान डरिस। छत्तीसगढ़ के जनता होशियार हे।

श्री अनुज शर्मा :- पतियाय के बात होत ए बाबू, तुंहर घोषणा-पत्र ज्यादा के रहिस हे, तभो ले जनता हा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र मा भरोसा करे हे।

श्री रामकुमार यादव :- तू तो बातेच मत करा, तुं हा बात मा फंस गय हा। तू सीधा-साधा हीरो आदमी।

श्री अनुज शर्मा :- ले न, तै हा रेस्ट हाऊस मा गिने कर।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह अनुपूरक बजट सभी वर्ग के सभी जरूरतमंद अच्छे लोगों को सुविधा देने का एक प्रयास है। परम सम्मान प्राप्तकर्ताओं की मासिक सम्मान निधि बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है। परम सम्मान माने समझ रहे हो ? यहां पर परम सम्मान प्राप्त पदम श्री हैं। अनुज शर्मा जी को पदम श्री प्राप्त है। इनके जैसे और सम्मान प्राप्त हमारे कलाकार, साहित्यकार, फिल्म स्टार, इनके सम्मान की निधि को बढ़ाने के लिए भी रूपये का भी प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है। आपने कभी पदम श्री वालों के ऊपर कभी विचार नहीं किया हे। नक्सल प्रभावित जिलों की सहायता प्रदान करने के लिए 379 करोड़ और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 117 का प्रावधान किया गया है। नक्सल की समस्या से ग्रस्त हमारे लोगों को अगर विष्णु देव साय कुछ सहायता देना चाहते हैं तभी तो हम उनकी मदद कर पाएंगे। जो नक्सलियों के प्रकोप से परेशान थे, जो वर्ष 2026 में खत्म हो जाएंगे, तब हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा तो आप उसकी दिशा दशा बदलते हो। बस्तर में नक्सलियों को क्यों खत्म किया जा रहा है? हमको मालूम है कि किसके लिए किया जा रहा है। इस प्रदेश की गरीब जनता की शांति के लिए नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। नक्सलियों का मुहिम खत्म होगा तो प्रदेश विकास करेगा। आपको मालूम है कि केरल प्रदेश से भी ज्यादा बड़ा हमारा बस्तर है और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जितना बड़ा बस्तर है, उसका 110 श्रीलंका का जाफना है, जहां प्रभाकरण जैसे आतंकवादियों ने वहां पर पूरा हाहाकार मचाकर रख दिया था और श्रीलंका की सरकार को उनसे निपटने के लिए थल, जल, नभ सब सेना को उतारना पड़ा और सेना उतार कर वहां पर उस सरकार ने कब्जा किया। हमारे नागरिक रहते हैं। यह सरकार भी सेना उतार सकती थी, लेकिन निर्दोष नागरिकों की रक्षा हो, उसके लिए हमने वैधानिक तरीके से जो पुलिस फोर्स के मनोबल के सहारे और उनको सुविधा दे कर इन नक्सलियों के ऊपर रोक लगाने का हमने प्रयास किया है, इसकी सराहना करनी चाहिए। हमारे बहादुर जवान वहां पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हमारे बहादुर जवान अपंग हो कर वहां से आते हैं और आप सिर्फ आंकड़े पूछते हैं। आपने क्या किया? उंगली दिखाने के पहले जरा तीन उंगली अपनी तरफ देखकर सोचिए कि आपके समय में नक्सलियों का कितना खात्मा हुआ या

कितने सरेंडर किए या कितने की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है कि विष्णु देव साय की सरकार ने क्या किया। विष्णु देव साय की सरकार ने हमारे श्री अमित शाह जी गृह मंत्री के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप माओवादी नक्सली हिंसा से पूरे प्रदेश और पूरे देश को मुक्त कराने का संकल्प लिया है। यह सरकार उसके लिए कटिबद्ध है और उसी के लिए यह बजट का प्रावधान किया गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, कोई मर्डर हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, कोई रेप हो जाए, उसके लिए इतना बड़ा फॉरेंसिक साइंस, कहीं बम ब्लास्ट हो, कौन देखेगा? उसके लिए यूनिवर्सिटी के लिए 21 करोड़ रूपया का प्रावधान कर उसकी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए आपको तारीफ करना चाहिए। 2047 का विजन छत्तीसगढ़ का रखा गया है। सभापति महोदय, उस विजन में हवाई सुविधा के लिए बिलासपुर के एयरपोर्ट के विकास के लिए वहां की जमीन को लेने के लिए मैं पिछले कई वर्षों से जब मैं भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब भी और अभी भी मैं लगातार इस आवाज से चुप होने का मैं कोई समझौता नहीं करता। मैं अपने बिलासपुर की आवाज उठाना चाहता हूं। बिलासपुर के लोगों को भी रायपुर के समान पूरा हक और अधिकार है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी भावना को और वहां हवाई सेवा में बैठे हुए हमारे जो प्रदर्शनकारी हैं, कई साल से प्रदर्शन दे रहे हैं, उस भावना को और वहां के जनप्रतिनिधि माननीय धरमलाल कौशिक जी के विधान सभा क्षेत्र में एयरपोर्ट है, माननीय अमर अग्रवाल जी के विधान सभा क्षेत्र के हम रहने वाले हैं। मोहले जी हमारे जिले के वरिष्ठ नेता हैं। मैं तखतपुर का विधायक हूं। लोरमी का भी विधायक था। पंडरिया का भी विधायक था तो मैंने तीनों जगह के बारे में भी यहां पर बोला हूं। सुशांत शुक्ला जी भी वहां के विधायक हैं। हमारी भावना का सम्मान करते हुए और हमारी भावना को छोड़िए, हमारी भावना का कोई खास महत्व नहीं है। पंडरिया की भावना बोहरा जी हैं और आसपास के कोटा के अटल श्रीवास्तव जी भी हैं, इन सब की भावना के अनुरूप एयरपोर्ट के लिए जन भावना के हिसाब से, वहां की जनता की भावना के हिसाब से 150 करोड़ रूपये का इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है। अब हमारे सारे सपने साकार होने की दिशा में एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं और एक कदम नहीं बहुत आगे बढ़ चुके हैं। रायगढ़ के लिए भी रायगढ़ के एयरपोर्ट के लिए 30 करोड़ रूपये का माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें प्रावधान किया है और रायपुर एयरपोर्ट के लिए भी कार्गो क्या कुछ है, उसके लिए 40 करोड़ रूपये का प्रावधान आपने किया है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं, बिलासपुर की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं, बिलासपुर में हवाई सेवा के लिए आंदोलन करने वालों की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें भी यह सम्मान दिया कि प्लेन से हम अपने शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भैया, मैंने आपके तरफ से मांगा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- चन्द्राकर जी, आपका सहारा हमेशा मिलता है।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन दुनों झन मांगे के सिवाय अऊ काय करिहौ। तुमन दुनों झन पांच साल मांगतेच रइहौ।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, आप लोग पहले तय कर लीजिये कि आप लोग कौन से घोड़े हैं?

श्री रामकुमार यादव :- मैं इंसान हौं, मैं इंसान रहूं। आप हाथी, घोड़ा, चांटी या कोन हौ, तेला बतावौ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अपत्ति लीजिये कि कांग्रेस में रेस के घोड़े हैं। बाराती के घोड़े नहीं चलेंगे, यह राहुल गांधी जी ने किसको बोला? छत्तीसगढ़ के मन का हे? ओ मन रेस वाला घोड़ा हे या बाराती वाला घोड़ा हे?

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, स्टेट केपिटल रीजन के लिए भी आपने 15 करोड़ रूपये रखा। कोई तो शुरूआत करेगा। दिल्ली का एन.सी.आर. कोई एक दिन में थोड़ी बना है। हम लोग विद्याचरण जी के जमाने में जाते थे, उस समय एन.सी.आर. नहीं था। वह योजना वर्षों बाद आया। उस जमाने में ऑटो के धुंआ से आंख चलती रहती थी, आंसू बहते रहता था।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओ एन.सी.आर. मा गौठान भी रही। तैं हर बाद मा मत कइबे कि मैं गरवा चराय हौं, खुम्भरी ओढ़े हौं, पानी भरे हौं। तैं हर कहानी मत सुनाबे।

श्री रामकुमार यादव :- ओ घानी चरात रहे। अभी मैं आदमी चराथौं अऊ मैं समय-समय मा सब चराथौं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सुनिये न, इनके गौठान का एक किस्सा सुना देता हूं। मैंने विधान सभा में पूछा कि कहां-कहां कितने गौठान हैं? मुझे बताया कि लोरमी में इतने गौठान है। मैंने कहा कि आप कोई भी दो गौठान घुमा दीजिये। एक सरकार की मर्जी से और एक मेरी मर्जी से ले गये। सरकार की मर्जी से ले गये, वहां मैंने देखा कि वहां पर आलू लगाये हैं। मैंने पूछा कि कब लगाये हैं तो वह बोले दो दिन पहले लगाये हैं। प्याज लगाये हैं तो दो दिन पहले लगाये हैं। दूसरा, मेरे च्वाइस वाले गौठान में ले-देकर कहां से गाय लाये थे और दस बकरा लाये थे। मैंने पूछा कि दीदी, यह बकरा कब से मिला है तो वह बोलें कि परो दिन तो खाम्ही बाजार ले खरीद के लाय हन। ऐसा वहां का हाल था। शाम को बकरा गायब हो गया। शाम को बकरा शहीद हो गया। आपको मालूम है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने तखतपुर में हार्टिकल्चर कॉलेज का प्रावधान किया है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय धर्मजीत भैया, आप गौधाम के बारे में भी बोल दीजियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- वहां गौठान था ही कहां, भाई?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- गौठान तो था, लेकिन आपने जो गौधाम के बारे में बोला है, उसके बारे में भी बोल दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- हाँ, बिल्कुल बोल देंगे। हार्टिकल्चर कॉलेज तखतपुर में खुला। यह हार्टिकल्चर कॉलेज भर नहीं है। यह किसानों से जुड़ा हुआ कॉलेज है, जहां पर लोग फूल की खेती करेंगे। जहां कलकत्ता से, बैंगलोर से फूल मंगाते हैं, उसको वे सीखेंगे। वे मसाले की खेती करेंगे, फल की खेती करेंगे। वहां हमारे समाज के जो बहुत से किसान हैं, वे इससे लाभान्वित होंगे। सरकार दूरदृष्टि को देखकर कोई कदम उठाती है। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि अगली बजट में प्राइमरी एवं मीडिल स्कूल के भवनों के लिए हर विधान सभा में चाहे पांच-पांच, दस-दस या पन्द्रह-पन्द्रह स्वीकृत कराये। वहां भवन बहुत जर्जर स्थिति में है। उसको सुधारना बहुत जरूरी है। उसके लिए अभी तक बजट प्रावधान नहीं होता है। एक-दो स्कूल का होता है। समग्र रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मीडिल एवं प्राइमरी स्कूल की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए क्रमबद्ध तीन बजट मिलेगा, तो बहुत से स्कूलों की स्थिति सुधर जाएगी। कोई सदस्य अचानकमार टाइगर रिजर्व के बारे में बोल रहे थे। अचानकमार टाइगर रिजर्व को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। अचानकमार टाइगर रिवर्ज 950 km^2 क्षेत्र में फैला हुआ है। जब मैं पिछली बार विपक्ष में बैठकर कांग्रेस की सरकार से बार-बार पूछता था कि आप कितने गांवों को विस्थापित कर रहे हैं तो आपको यह सुनकर बहुत दु:ख होगा कि डॉ. रमन सिंह सरकार के समय में ही वहां से पांच गांव विस्थापित हुए थे और आप पूरे साल में एक गांव व एक घर भी विस्थापित नहीं कर पाये हैं। उसके बाद आप विकास की बात पूछते हैं। जब तक वह गांव विस्थापित नहीं होंगे, तब तक न वहां टाईगर रहेगा, न वहां कुछ रहेगा । लेकिन इस सरकार के द्वारा वहां के 3-4 गांवों को फिर से विस्थापित करने के लिये पैसे की व्यवस्था हो गई है और इनके द्वारा योजना बनाई जा रही है । आप पूछते थे ना, अभी कोयले के बारे में बहुत बात किये । आपकी सरकार में 3494 हेक्टेअर जमीन आपने इन कोयला खदान वालों को दी है, लोहा खदान वालों को दी है । अभी इस सरकार में जनवरी 2024 से लेकर दिसम्बर 2025 तक 5 केस में सिर्फ 1300 हेक्टेअर जमीन ही दिये हैं । आपको पूरा जंगल कटना दिख गया । एक रेंज आफिसर गरीब महिला को बाल पकड़कर मारा तो मैंने इस विधान सभा में प्रश्न उठाया । उस प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने उसे निलंबित किया और 8 दिनों के बाद उसे फिर से रिस्टेट कर दिया और वह रेंजर एक कांग्रेस नेता के घर में सब्जी पहुंचाने का काम करता था । मारपीट और अत्याचार करने की बात करते हैं और आप लोग क्या बात करोगे ? जंगलों की कटाई के लिये मैंने जब मामला उठाया तो मैंने यह कहा था कि श्री राहुल गांधी जी मदनपुर गांव में आकर और जिस चबूतरे में बैठकर गरीबों को आश्वस्त करके गये थे कि हम आपको बचायेंगे । सरकार बनने के बाद उस चबूतरे में और उस गांव में जहां वह गये थे, उनको भी बेदखली का नोटिस कांग्रेस की सरकार ने दिया था । ऐसा मत करिये । समन्वित रूप से विकास हो, इस दिशा में हमको विचार करना ही होगा । माननीय सभापति महोदय, कोपरा रामसर साईट समझते हैं क्या है, पक्षियों में रामसर साईट ईरान का एक गांव है, वहां के नाम पर

समय
3.38 बजे **(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुये)**

यह है । छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला रामसर साईट तखतपुर विधानसभा के कोपरा गांव में स्वीकृत हुआ है । वह पर्यटन के लिये बहुत बड़ा आकर्षण का केन्द्र रहेगा, पक्षी प्रेमी सब वहां जायेंगे, फोटो खींचेंगे, वहां रहेंगे । आज स्वीकृति से उसकी शुरूआत हुई है, अभी वह बहुत आगे बढ़ेगा और देश के कुछ जो रामसर साईट है, उनमें उसका नाम होगा ।

सभापति महोदय, आप बिजली की बहुत बात कर रहे थे । मेरे ही क्वेश्चन में आपकी सरकार ने तेलंगाना को बिजली दिया था, उसका 3000 करोड़ रूपया अभी तक तेलंगाना सरकार ने नहीं दिया है । इसे क्यों नहीं दिया गया । रेवंथ रेड्डी की सरकार है, तेलंगाना हमारे पैसे को क्यों नहीं दिया और आपकी सरकार ने क्यों नहीं वसूला, पहले उसको बताईये, उसके बाद बिजली का हिसाब पूछिये ? माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के रोजगार की बात करते हैं, रेडी टू ईट में हमारी महिलायें खाना बनाती थी । रेडी टू ईट बनाकर गांव के बच्चों को खिलाती थी, उसमें मां की ममता रहती थी । मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह बीज निगम को देने का तुगलकी आदेश आपने क्यों दिया ? बीज निगम ठीक से बीज नहीं बांट पाता है, बीज निगम रेडी टू ईट बनायेगा ? आपने इसे बीज निगम को नहीं दिया है, बल्कि बीज निगम के माध्यम से आपने अपने स्वार्थों की सिद्धि की है । माननीय सभापति महोदय, मैं और ज्यादा बोलने के बजाय दो बात और कहूँगा कि माटी कला बोर्ड के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी इन दोनों मामलों में ध्यान दीजिएगा । माटी कला बोर्ड कुम्हारों के लिये, जो मिट्टी का काम करने वाले हैं, उनके लिये एक बहुत बड़ा मंच है । हमारे प्रदेश में लाखों कुम्हार लोग दिया, चुकिया, बर्तन, मिट्टी का बर्तन और पंजाभट्ठा लगाते हैं । उनको एक छूट दी गई है, इसमें लिखा हुआ है कि उक्त ईंट निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के गौण खनिज निगम के नियम 3 (1) के अंतर्गत आनुवांशिक कुम्हार या उनके सहकारी सोसाइटी द्वारा परंपरागत संसाधनों से बर्तन, कवेलू और ईंट बनाने के लिए (चिमनी भट्ठे छोड़ करके) रायल्टी में छूट का प्रावधान उल्लेखित है। सभापति महोदय, इसमें उनको छूट का प्रावधान है लेकिन उनको छूट नहीं मिल रही है, वह इसलिए नहीं मिलती है कि क्योंकि उनको परमिशन ही नहीं देते तो छूट किस बात की, इसलिए इसकी हाई लेवल मीटिंग होनी चाहिए, हमारे कुम्हारों को दीजिए। "वोकल फॉर लोकल" प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है। इस "वोकल फॉर लोकल" में अगर कोई सरकारी अड़ंगेबाजी के कारण कोई बात रूके और हमारे कुम्हारों को वह छूट न मिले तो हम "वोकल फॉर लोकल" की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, इसमें हाई लेवल मीटिंग कराकर सभी जिला के खनिज अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि कुम्हारों की समस्याओं को ध्यान दें और उन्हें मदद करें, वे गरीब तपके के लोग हैं, आज भी अपने परंपरागत हुनर को, अपनी परंपरागत कामों को वे लोग नहीं

छोड़े हैं तो सरकार का धरम बनता है कि हम अगर नौकरी नहीं दे सकते, कोई बड़े-बड़े औद्योगिक रोजगार नहीं दे सकते तो उनको जो ज्ञान है, उस ज्ञान को सरकार की सुविधा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वन मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। बिलासपुर के पास एक कानन पेंडारी है, कानन पेंडारी में आज ही एक शेर 21 साल की उम्र में दम तोड़ा, उसका शिकार नहीं हुआ, वह 21 साल उम्र पूरी करके मरा है। उस कानन पेंडारी में कई सौ चीतल, शेर, भालू, सांप, बिच्छू, हिरण, सांभर, सब कुछ है, वह तखतपुर विधान सभा में है, जब मैंने उसके सामने सोलर लाईट लगाने के लिए बोला तो फॉरेस्ट की आपत्ति आ गई कि यहां पर लाईट लगाना ठीक नहीं रहेगा। सभापति महोदय, आज मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, वहां पर एक बिल्डर का बड़ा-बड़ा बोर्ड मेरे ख्याल से ये जो बोर्ड दिख रहा है उससे 10-10 गुना बड़ा एक-एक बोर्ड है, ऐसे 10 बोर्ड हैं, वहां पर कानन पेंडारी के दीवार से सटकर लगे हुए हैं, कोई भी आदमी उसमें खड़े होकर गोली मारेगा तो जानवर मरेगा। वह किसके परमिशन से लगा ? किसने उनको परमिशन दी ? कैसे परमिशन दिया ? जब लाईट का परमिशन नहीं मिलता तो बड़े-बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड का परमिशन उसको कैसे दिया गया ? कानन पेंडारी के बाऊंड्रीवाल से लगा हुआ एक धरसा है, उस पर बिल्डर ने अपना होर्डिंग्स बनवा लिया, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है और कानन पेंडारी के धरसे में सड़क बना लिया और कानन पेंडारी के किनारे में बहुत बड़ी कॉलोनी बनाकर उसका परमिशन कैसे ले लिया, आप इसकी जांच जरूर करवाईएगा। मैं ये नहीं चाहता कि कानन पेंडारी के वाईल्फ लाईफ जो हमारे मथुरा प्रसाद दुबे जी, वन मंत्री थे, उस जमाने से आज से 50 साल पहले वह खुला हुआ है, उस कानन पेंडारी की सुरक्षा में, उस कानन पेंडारी की तरक्की में बिल्डर लोगों के द्वारा डिस्टर्ब किया जाए, ये बहुत ही आपत्तिजनक है, बिल्डरों के प्रकोप से कम से कम वन्य प्राणियों को जंगल को बचाने की कृपा करें, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी मैं आपको पहले बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने बिलासपुर में एयरपोर्ट के लिए बहुत अच्छा काम किया। इस सत्र में हम अच्छी उपलब्धि लेकर जा रहे हैं उसके लिए आपको बधाई। अगले सत्र में भी वहां पर कोई और छोटा-मोटा काम होगा, उसका भी बजट प्रावधान कर दीजिएगा, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता लेकिन बिलासपुर से हवाई जहाज उड़ेगा तो कभी-कभी हमारे विजय शर्मा जी बिलासपुर आएंगे तो वहां चढ़ जाएंगे, अरूण साव जी को दिल्ली जाना ही पड़ता है, वहीं से चले जाएंगे और हम लोग भी चले जाएंगे, हम लोगों को रायपुर आना पड़ता है, ढाई-ढाई, तीन-तीन घंटे लगते हैं।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- मेरे रास्ते में भी आएगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बजट दे रहे हो तो आप तो जाओगे ही, मैंने तो आपको पहले भी कहा था, आप वित्त मंत्री हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे कोटे में हैं। हम आपके कारण खुश हो रहे हैं कि आपको भी वह सुविधा मिल जाए। हमारे उप मुख्यमंत्री जी को जाना ही पड़ता है, रायपुर के बजाए वहीं

से चलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वहां का आम आदमी उसमें चढ़ेगा। आपने मेरे क्षेत्र में उद्यानिकी महाविद्यालय का प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रामविचार जी, मेरे लिए बहुत प्रेम करते हैं, उनके प्रेम से ही हम इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी भी हमसे प्रेम करते हैं। हमारे नये पर्यटन मंत्री जी भी प्रेम करते हैं, सभी करते हैं। आप सबका सहयोग है तभी काम हो रहा है। आप हिम्मत से रहिए और आखिरी बात यह कहना चाहता हूं, बघेल जी, हमारे पुराने दोस्त हैं।

थोड़ा हिसाब से रहो, हम सब्र में हैं।

थोड़ा हिसाब से रहो, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं हैं, सब्र में हैं।

इसलिए आप लोग हिसाब से रहिए। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- रामकुमार यादव जी।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- सभापति महोदय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही विद्वान, जो यू.पी.एस.सी. जइसे पेपर ला पास करके कलेक्टर बने रीहिस हे अउ आज विद्वान मंत्री के रूप में जाने जाथे। ओ लगभग 33 हजार करोड़ रूपये के अनुपूरक बजट लाए हे, ओ बजट के चर्चा में बोले बर खड़ा होए हो। हमर ठाकुर साहब जात हे, चंद्राकर जी भी नहीं हे। ए दोनों विद्वान अउ ए मेर कई झन विद्वान हे, ओमन ला देख के मैं समझ ही नहीं पात हो कि ओमन के पहले अलग रूप रहिथे। एक दिन पहले, दो दिन पहले, कुछ दिन पहले इहा पर सत्र में रीहिन तो हमन ओखर मन के अलग रूप देखे रहेन अउ आज इहा पर अलग रूप देखे बर मिलत हे तो अगर शब्द के मायाजाल कहीं पर सीखना हे तो हमर चंद्राकर जी हे, हमर धर्मजीत सिंह जी हे, धरमलाल कौशिक जी हे, ए सब मन से सीखना चाहिए। खैर, ओखर मन के मायाजाल वइसने बन रहे। आज 33 हजार करोड़ रूपये के अनुपूरक बजट अउ मेन बजट लगभग 1 लाख 65 हजार करोड़ रूपये, ए दोनों ला अगर मिला देथन तो हमर लगभग 2 लाख करोड़ रूपये के बजट होथे। छत्तीसगढ़ में एमन के घोषणा पत्र, एमन के भाषण, जा-जा के गांव-गली में गरीब आदिवासी मन करा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग मन करा जाकर अइसे लुभावन भाषण दीन कि छत्तीसगढ़ के जनता मन एखर मन के बात, बोलचाल के भाषा में फंस गीन। ए समझ गे कि एखर मन के डबल इंजन हे। एमन के, भूपेश बघेल जी के, कांग्रेस के तो एक ठन इंजन हे, लेकिन हमर डबल इंजन हे। एमन अइसे-अइसे बात करीन कि हमन दिल्ली से पइसा लानबो अउ छत्तीसगढ़ ला सोने की चिड़िया बना देबो। ए कांग्रेस सरकार तो लोन लेथे, कर्जा लेथे। हमन लोन नहीं लेन। हमन छत्तीसगढ़ ला हरा-भरा कर देबो अउ सोने के चिड़िया बना देबो। लेकिन आज मोला यह कहते हुए अत्यंत दु:ख होथे कि एखर मन के डबल इंजन के सरकार, एमन के ट्रिपल इंजन के सरकार 2 साल में 48 हजार करोड़ रूपये के लोन ले हे। 48 हजार करोड़ रूपये के लोन तो फिर एखर मन के डबल इंजन के का मतलब होइस।

सभापति जी, यही डबल इंजन होथे। मोर छत्तीसगढ़ के जनता ए सब ला देखत हे। हम डबल इंजन तब मानतेन कि आप मन कहथव कि ए कांग्रेस के, भूपेश बघेल जी के सरकार, डॉ. चरणदास महंत जी के सरकार हा लोन लीन। एमन कहिथे कि हमन 2 साल में लोन नहीं लेन तो हमो मन कहतेन कि एमन ठीक कहात हे। चौधरी साहब बहुत बुद्धिमान हे अउ कहां-कहां ले पइसा ले के आत हे। लेकिन आज आप लोन ले डारो, कोई बात नहीं हे। आज मैं आप ला कहना चाहत हो कि आपमन चुनाव के समय कहे रहे हव कि हमन छत्तीसगढ़ ला शिक्षित बनाबो। महोदय जी, मनुष्य के सबसे मेन शिक्षा होथे। सभापति जी, आज आप वहां पर बइठे हो। हमर चौधरी साहब कलेक्टर बनीस। हमर एक झन अउ कलेक्टर साहब बइठे हे। उहु इस्तीफा दे के नेतागिरी के सउख चढ़ीस तो इहा आगे। मैं महोदय जी ला नमस्कार करत हो। लेकिन उहु ला मंत्री बनाना रीहिस हे। जब ओ वित्त मंत्री बन सकथे तो आप ओखर जइसे अउ कुछु न कुछु मंत्री बन सकत रहे हव। आप हा भी तो कलेक्टर रहे हव। आज मैं कहना चाहत हो कि शिक्षा ही मेन होथे। अगर इंसान में शिक्षा नहीं हे तो कहे गेहे। पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। मैं हां सपूत हो। कपूत कौन हन तेला देखव। हमर महाराज, गृहमंत्री जी बैठे हे। आज में हर कहना चाहत हव कि छत्तीसगढ़ ला शिक्षित बना देवव। कहीं से भी हमर छत्तीसगढ़ में धन लाकर के आगे बढ़त सकत हे लेकिन का होत हे ? 10 हजार स्कूल बंद हो गे। जब-जब इतिहास में याद किये जाही तो 10 हजार स्कूल ला बंद करे के तुमन के नाम लिखाही। कौन करिस ? यही डबल इंजन के सरकार हा करिस। हमन नइ कहात हन। आप मन 48 हजार करोड़ रूपये लोन ले हन अउ बढ़ा लेत हन लेकिन स्कूल ला बंद नहीं करना रिहीस हावय। आज गुरूजी मन ला पूछ के देखव कि कहां मेर ले गुरू जी कहां मेर ट्रांसफर होवत हे। घर वाले यनते हे तो ओखर बाबू घर वाले अंते हे। महीना-महीना भर फोन में ही बात होवत हे। ओखर दोष तुमन ला पड़ही। आज में हर बिजली बिल के बात करना चाहत हव। का होत हे, छत्तीसगढ़ ला का कहिथे। यहां पर कोयला हे, एला काला हीरा कहे जात हे। यहां कारखाना हे। जब आप मन अन्य प्रदेश में जाबे अउ कहिबे कि छत्तीसगढ़ के हंव तो उ मन कहिथे अच्छा-अच्छा आप मन के यहां बिजली उत्पन्न होवते हे, कोरबा में। हमन ला ये सुन के कतका अच्छा लगत हे कि हमर यहां बिजली उत्पन्न होवत हे। लेकिन कबीर साहब के एक ठन दोहा हे कि "जल में रख ए मन प्यासी, अउ मोहे सुन-सुन आवय हंसी"। अगर यहां पर कोयला हे, यहां पर बिजली उत्पन्न होत हे, अगर वहीं के इंसान मन ला दो-दो, तीन-तीन दिन ओ मन ला बिजली नइ मिल पात हे, यह दु:ख के बात हे। जैसे मछली हर पानी के भीतर में रहि के कहिथे कि में हर प्यासी हंव तो कतका हंसी लागे। आज बिजली के यह स्थिति हे। जब हमर भूपेश बघेल जी के एक इंजन के सरकार रिहीसे तो 400 यूनिट तक कोई किसान बिजली जलातिस तो बिजली बिल हर हॉफ रिहीस। लेकिन ये मन के डबल इंजन जुड़ गे हे तो ये मन कैसे करत हे। पहले 100 यूनिट करे रिहीसे अब डर के 200 यूनिट कर दिस। 200 तक जाही तो ओकर ले नीचे रिहीन तभी हॉफ होही। आज में हर कहना चाहत हंव कि आप मन

और लोन ले लेवव लेकिन बिजली बिल ला आप मन ला हॉफ करना चाहिए। 48 हजार करोड़ ला 50 हजार करोड़ कर देवव।

सभापति महोदय, में हर ओकर बाद कहना चाहत हव कि ये मन महिला के सम्मान में बहुत बात करे रिहीस कि आज हम 1 हजार रूपये महिला को दे रहे हैं। ऐसा लगत हे कि घर के खेत ला बेच के देथन। हमर छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा हे। ये हमर छत्तीसगढ़ के हे। ये काकरो घर के पैसा नो हे। फिर भी यदि आप मन सरकार में बैठे हव, आप ला जवाबदारी मिले हे तो आप 1 हजार नहीं बल्कि आप ओला पूरा करो। ओ गरीब महिला जेन हर आगी ला फूंक-फूंक कर आंखी हर लाल हो जात हे। ये देश के प्रधानमंत्री कहे रिहीस कि मैं उस मां का बेटा हूं कि मेरी मां जब चूल्हे में आग जलाती थी तो उनकी आंख लाल हो जाती थी, मैंने उसको देखा है। यह बहुत अच्छी बात हे। हम भी गरीब घर के आदमी हन, हमन भी जानत हन कि गरीबी का होवत हे तेला। हमर दाई मन तो पान पतेरा मा रांधवइया हे। वह कोंदा में रांधवइया हे, हमर दाई हर। आप मन भी कहे रिहीन तो हमन ला बहुत अच्छा लगिस कि 500 रूपये में हमन गरीब महिला मन ला गैस सिलेण्डर देबो। बहुत अच्छी बात हे। लेकिन का हुईस ? दो साल बीत गे हे। आज ओ महिला मन, बेचारी मन उ समय कभू ले डारय गैस सिलेण्डर तो 1200 रूपये होये हे तो वो गैस सिलेण्डर ला पट्‌ट मा टांग डारय हवव। ओला अब कब रांधय ? अउ जब भी महिला ओ गैस सिलेण्डर हर देखय तो ओ मन के एड़ी घिस के तरवा में जात हे तुमन ला देख के। इ मन कहे रिहीन तभो ला पारेन। अब ओला 1200-1300 रूपये कर दिस। में हर कहना चाहत हव मोर भाई बंधु, सब ला कहात हन के अउ लोन ले लेवव लेकिन ओ मन ला 500 रूपये में गैस सिलेण्डर देवव। कर्जा में अउ का कर्जा, नहीं सही बढ़ाते जावव। आज में हर गोबर खरीदी के बारे में कहना चाहत हव। अभी हमर चंद्राकर जी नइ हे। 5 साल ओकर दिमाग में गोबर ही भरे रिहीस हावय। यह सही बात हे। जब भी कुछ होवय तो गोबर, गोबर।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, रामकुमार जी समझ ही नहीं पाये कि उनको गोबर कैसे भारी पड़ा। वे जब वहां बैठे हुए थे तो इसी गोबर के कारण आप लोग यहां आ गये। उसके बाद भी आप गोबर, गोबर मत बोलिये। अभी तो यहां सदन में सम्मानजनक हैं और पता नहीं कि आने वाले समय में क्या-क्या होगा ?

श्री रामकुमार यादव :- कौशिक जी, में हर हार-जीत ला कभू नइ डरव। में हर तो गरूवा चराने वाला व्यक्ति हव। में हर ओकर ले नीचे नइ जाउ। अउ ये गरीब के कौन से जन्म ले हव, जेकर दादा हर पंच नइ बने हे ते मोर आलतू-फालतू मन ला चंद्रपुर के जनता हर विधायक बना दिस।

श्री धरमलाल कौशिक :- रामकुमार यादव जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोला कि उसी गोबर के चक्कर में उधर से इधर आ गये।

श्री रामकुमार यादव :- इधर से उधर तो चले गये, लेकिन आप भी इधर हो।

श्री उमेश पटेल :- यहां से वहां भी जायेंगे, आप चिंता करिये। 03 साल ही बचा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- देखिये, छत्तीसगढ़ के जनता ने 02 बार कांग्रेस को टेस्ट किया है। जब पहली बार प्रथम मुख्यमंत्री बने तब और 15 साल के बाद में फिर मौका दिया। लेकिन टेस्ट जनता ने किया, मैं क्या बोलूं उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, आप लोग इतने नाकामी निकले कि 05 साल के अंदर ही आपको यहां से फिर विदा कर दिये। अब भविष्य में सपना छोड़ दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- कौशिक जी, देखा हार, जीत दुनिया में लगे रहथे। अरे ये देश में बड़े-बड़े आदमी मन हारे हे तो का होत हे अगर रामकुमार यादव हा हार जाइस तो घबरायें नही। अगर हार जाइस ता कोई ला घबराना भी नई चाहिए। हां लेकिन इस बात का जरूर होना चाहिए कि जब मोला मौका मिले रहिस हे तब मैं सही मन से काम नई करव, ये जब मन में भावना आथे, तब आदमी ला दु:ख होथे। सभापति महोदय, आज गोबर खरीदी की बात करना चाहथव। ओ गांव के गरीब झौआ ला लेकर के दिन भर किंदरय तो कम से कम 50 रुपये के गोबर बेच डालय। आज उहू ला आम मन बंद देव। ओला कौन आप मन ला बंद करय के कहिस। चन्द्राकर जी, जब देखव ता गोबर, गोबर करत रहत हे, 05 साल ओकर दिमाग में गोबरय भरे रहिस हे। आज भले कर्जा ले लो भले हे, लेकिन गोबर खरीदी ला फिर सो शुरू करव। चूंकि गांव के गरीब मन आप ला सम्मानजनक ढंग से अतके कन वोट देकर विधायक और मंत्री बनाये हे। ओकर बाद मैं कहना चाहत हवं। जब चुनाव आइस तो ये मन कहे रहिन हे। सब ले कमजोर कर्मचारी स्वीपर होथे। ओमन साफ-सफाई करथे और आ जाथे। ओ मन अउ दिन भर कोई पूता कर सकय नई। आज पूरा स्वास्थ्य विभाग मितानिन मन के कंधा में टिके हे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संविदा कर्मचारी ये मन ला आप मन बोले रहव जैसे ही हमारी डबल इंजन की सरकार आयेगी, आप मन पैसा का चिंता मत करना, हम दिल्ली से लायेंगे, सबके वेतन को बढ़ा देंगे। आज दू साल हो गये। आंदोलन करत हे तो जेल भेज देत हव। आप ला पावर मिले हे, आपके इशारा में पुलिस काम करत हे। जेल भेज सकथव, लेकिन ओमन के आत्मा ला आप नई मार सकव, ओमन के आज भी स्वाभिमानी आत्मा जिंदा हे। ये बात ला आप मन याद रखिहव। मैं आज पक्का मकान के बात कहना चाहथवं। सभापति जी, मैं दो-पांच में समाप्त करिहव, मैं आपकी भावना ला समझ गयेन। हमारा गृह मंत्री शर्मा जी बैठे हे। चुनाव के समय आइन तो कहिन, इंदिरा आवास ला, पी.एम. आवास कर दिहिन, ऐसे लागिस कि हम मन उत्पन्न करेहन। अरे वो तो इंदिरा दई के जमाना से मिलत आवत हे। ठीक हे, बजट के रहथे, कभू कमी, कभू ज्यादा हो जाथे। ओ समय के बजट और अभी के बजट में अंतर हे। लेकिन वोही समय के शुरू में आप मन पी.एम. आवास कर दिहा। अउ का कहा कि हम लोग 18 लाख पी.एम.आवास बनायेंगे। हमर पहला पंक्ति के नेता मन चरणदास महंत जी, भूपेश बघेल जी, उमेश पटेल जी मन सवाल करिन तो आप मन कतका कन जवाब दिहा, ये छत्तीसगढ़ के जनता देखत हे।

मानननीय सभापति महोदय, धान खरीदी के बात करना चाहथव। आज धान खरीदी में अइसना हो गये हे, मैं कल भी बोले रहेवं कि किसान ला धान ला लेकर जावत हे, ऐसे लागत हे हमन धान ला लेकर नई जात हन, गांजा, अफीम, चरस लेकर आये हन, ऐसे लागत हे। ओतके कन जांच बैठाय हव। पटवारी, तहसीलदार, एस.डी.एम. जांच करत हे, अतके कन तो कोई गांजा बेचईया के जांच नई होवत हे। आज किसान मन कितना दु:खी हे, ये बात ला सब देखत हे। आप ला 5 साल सरकार मिले हे, लेकिन आप मन बात कहां के कहथव, विजन 2047 की बात करथव। इंग्लिश में विजन कहथे। मैं ज्यादा पढ़े-लिखे नई हवं। हमर महाज्ञानी जी आत होही, ओ ये बात ला जानथे। चन्द्राकर जी महाज्ञानी हे। विजन कब के कहत हे, 2047 के कहते हे। बाप रे, 5 साल बर तोला सरकार मिले हे और 2047 के बात करत हवय। छत्तीसगढ़ी में कहावत हे कब बबा मरिही तो कब बरा चाबबो। 23-24 साल बाद में, ओतके दिन के बात ला कहना, कल के बात नई कहना, आज धान खरीदी में बात नई करना, महिलाओं पर बात नई करना, जंगल कटाई में बात नई करना, दारू के विषय में बात नई करना, कब के बात करना, 24 साल बाद के बात करना हे। हमन एक ठे फिल्म 24 साल बाद देखे रहेन। इस प्रकार से आज यहां पर किये जाते हे।

समय :
4.00 बजे

मानननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा आप ला चूंकि और बहुत सारा बोलईया वक्ता हैं, इही आशा-विश्वास के साथ कि मौर चौधरी साहब जब कलेक्टर रिहीस हे, मोर बहुत अच्छा मित्रता, आज भी मोर मित्र हे। हमन दुनों बॉर्डर के हन । मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करथओं । ठीक है, मैं ओखर मन ला जानत हंओं लेकिन जब ले ओ हा पार्टी में गे हे ता गड़बड़ होए हे, नइ तो आदमी अच्छा हे । (दर्शक दीर्घा से आवाज) माननीय मंत्री जी, हमर आपसे निवेदन हे कि आप ला मौका मिले हे बहुत अच्छी बात हे, सरकार ला मिले हे । आप पक्ष-विपक्ष ला छोड़कर के जइसे मोर क्षेत्र के बात जतका फैक्ट्री हे, मोर इंहां से गाड़ी चलथे । चाहे जिंदल के हो, मोनेट के हो, जतका भी अऊ जतका रोड ला तोड़ देथे अऊ मैं आप ला धन्यवाद भी देथओं कि आप मुख्य रोड ला बनाये भी हा लेकिन अब मुख्य रोड तो बनगिस लेकिन जो गांव-गांव के रोड हे, चूंकि मुख्य मार्ग मा चलत हे । आये दिन, आज ही एक ठन एक्सीडेंट होए हे, अभी सब जानत होंही, मोर क्षेत्र में चक्काजाम होए हे । रोज मुख्यमार्ग मा चलथे ता गाड़ी चलथे तो एक्सीडेंट होथे तो जो गांव-गांव के रोड है, बाईपास टाईप के, ओखर बर जरूर ध्यान दिहा ।

श्री अजय चंद्राकर :- रामकुमार जी, ये चंद्रहासिनी में भैंसा के बलि होथे कि भैंसी के ?

श्री रामकुमार यादव :- ओखर बात, तुंहर-हमर बईठबो तो बताबो, मैं जान डारे हंओं । सुना तो ।

श्री अजय चंद्राकर :- चंद्रपुर के तो विधायक हस गा । बताना, भैंसा के बलि होथे कि भैंसी के ?

श्री रामकुमार यादव :- ये दुनिया में भैंसा-भैंसी, बकरा के बलि होथे । शेर के बलि नइ होए ।

श्री अजय चंद्राकर :- गरवा के बारे में तें हा जानथच कि नइ ? (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर बात अइसनहा हे । माननीय सभापति महोदय, मैं कभू-कभू भैया जी के बारे में सोचथओं था कइसे सोचथओं ।

सभापति महोदय :- अजय जी, बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- तें हा ऐला बताना कि तें हा गरवा के बारे में जानथच कि नइ ?

श्री रामकुमार यादव :- मैं दुनिया के सबके बारे में जानथओं ।

श्री अजय चंद्राकर :- जब गरवा के बारे में जानथस ता ये बताना कि भैंसा के बलि होथे कि भैंसी के ? भैंसा के कि भैंसी के ?

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, ए मन के सरकार में गौ माता के ऊपर वह आप पूरा जानत हओ ।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, चंद्राकर जी बोल दिस ता मैं हा ओखर बारे में सोचथओं । कभू मैं घर में जाथओं ता सुतथओं ता तुंहर बारे में सोचथओं । मैं जब तुंहर बारे में सोचथओं ता मैं कहथओं ये मोर बारे में समस्या होगे हे । जैसे एक आदमी मोला प्रश्न पूछिस कि ये धरती में कुकरी पहिली अइस कि अंडा पहिली अइस । अउ आजतक ओ समस्या के हल मैं नइ सोच पायेंओं कि कुकरी पहिली अइस कि अंडा पहिली अइस । तइसनहे प्रकार के एखर समस्या के हल आज तक नइ होए पाए हे ।

श्री दिलीप लहरिया :- ये समस्या के हल 2047 तक हो जाहए । चिंता मत करओ ।

श्री रामकुमार यादव :- बस । अऊ एखर तड़प ला मैं जानत हंओं लेकिन 2047 तक आपके समस्या हल होही । जइसे कुकरी अइस कि अंडा पहिली अइस तइसनहे ।

श्री अजय चंद्राकर :- तें बता कि चंद्रहासिनी में भैंसा के बलि होथे कि भैंसी के तेला ?

श्री रामकुमार यादव :- ये दुनिया में बोकरा के, छेरी के बलि होथे लेकिन शेर के बलि नइ होवए । तुमन चिंता मत करा, ओला मैं हा तुमन ला 2047 मा बताहां । मैं अंत में पुन: एक-बार चौधरी साहब के पूरा टीम ला इही आशा-विश्वास के साथ कि आप बिना पक्ष के अऊ बिना द्वेष के हमेशा छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा ला अपन विधानसभा समझिहा अऊ अइसे भावना से चलिहा, काकरो कहे मा झन चलिहा । पदा हा बार-बार नइ मिलए साहब हो, मिल गे हे ता बढ़िया चलावओ, दूजा भाव मत करा । माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोले के मौका दे हओ तेखर बर बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि अभी 10 सदस्यों को अपनी बात कहनी है तो 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें, क्षेत्र की बात कहें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री धरमलाल कौशिक जी ।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे वित्तमंत्री सम्माननीय ओ.पी. चौधरी जी के द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, जब अनुपूरक लाते हैं तो उसके पीछे हेतुक होता है और वह हेतुक कि हमारे प्रदेश की जनआकांक्षाओं को पूरा करने का, समस्याओं का निराकरण करने का, हमें नया शुभारंभ करने का और उसके साथ में जनहित में बहुत सारे निर्णय लेने का और हमारे वित्तमंत्री जी के द्वारा इन सारी बातों पर विचार कर जब से हम लोग विधायक हैं तो मुझे लगता है कि 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पहली बार प्रस्तुत हुआ है । मैं उसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यह अनुपूरक लाने के बाद में जो नई व्यवस्थाओं के लिए भी और हमने जो पुराने कार्य किये हैं उन सब का समावेश किया जाये और उसके साथ में नई संरचनाओं का भी विकास किया जाये। जो हमारी सड़कें, अधोसंरचना, पुल-पुलिया, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और Digital connectivity है ऐसी जो हमारी बुनियादी संरचनाएं हैं जिनमें निवेश हो। निश्चित रूप से न केवल तात्कालीक बल्कि आने वाले समय में भी उसका लाभ हम सब को मिलेगा और इस पूरे प्रदेश पर उस क्षमता का प्रभाव पड़ेगा। यदि हम जब राजस्व और पूंजीगत व्यय बात करते हैं तो राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय इस नींव को मजबूत करने के लिए हमारे जो नये उत्पादन लम्बे वर्षों तक चल सकें। उसको दृष्टिगत रखते हुए, इस अनुपूरक बजट में जो प्रावधान किये गये हैं और हम यह देखेंगे कि 25 वर्षों में, हमारे पिछले समय में जो व्यय हुए हैं उन 25 वर्षों में हमारी सरकार आने के बाद जो प्रयास हुए हैं । मुझे यह कहते हुए, इस बात की खुशी है कि हम यदि 25 वर्षों में वृद्धि की बात करेंगे तो पूंजीगत व्यय में लगभग 55 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। जो हमारे लिए स्वयं एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि है।

माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2022-2023 के विषय में बताना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पूंजीगत व्यय 13 हजार 220 करोड़ रूपये था और हमारी सरकार आने के बाद में जब हम वर्ष 2024-2025 की बात करेंगे तो इसको विस्तार देते हुए 20 हजार 55 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय किया गया। हम पिछला बजट वर्ष 2025-2026 की बात करेंगे तो उसमें 26 हजार 341 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया। अभी अनुपूरक में पूंजीगत व्यय में 2000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से हमारा अनुपूरक बजट विकास की नीति को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारी अधोसंरचना, कनेक्टिविटी और सारे चीजों में वृद्धि होने वाली है। यदि हम आंकड़ों में इस पर प्रतिशत की बात करेंगे तो पिछली सरकार में 3.5 प्रतिशत था और इस वर्ष 2025-2026 की बात करेंगे तो हम उसको पर करते हुए, बढ़ाते हुए 4.1 प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना है।

इस प्रकार से जो हमारा उद्देश्य और हमारा ध्येय है कि हमारी सरकार का जो घोषणा पत्र है और यहां पर हमारी सरकार आने के बाद उसका क्रियान्वयन हुआ। हमारे प्रदेश में क्रियान्वयन के पश्चात् उन वायदों को पूरा करने के लिए विभिन्न सेक्टर्स में जो हमारे व्यय किये जा रहे हैं तो आप सकारात्मक दिशा में उसका परिणाम भी देख रहे हैं। यहां के आम लोगों के जीवन में जो परिवर्तन जो दिखायी दे रहा है, वह हम सब के समाने परिलक्षित हो रहा है। यहां पर मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ। काफी समय से हम सब की बिलासपुर एयरपोर्ट को लेकर मांग रही है कि वहां के एयरपोर्ट का विस्तार होना चाहिए। वहां पर रनवे की लम्बाई बढ़नी चाहिए। वहां पर जमीन को लेकर, सेना से लेकर हमारी सरकार, मंत्रिमण्डल और अधिकारियों के द्वारा बीच में बहुत सारी बैठकें हुईं हैं। उसकी बैठक होने के पश्चात् अभी उसके विकास और विस्तार के लिए 150 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से इससे बिलासपुर एयरपोर्ट को लाभ होगा और उसका विस्तार होगा । मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस के लिए 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, लेकिन इसके बाद भी यदि आपको लगता है कि उस एयरपोर्ट में अतिरिक्त बजट की जरूरत है तो उसका प्रावधान मुख्य बजट में करेंगे। वित्तमंत्री जी, धर्मजीत सिंह जी आपके सामने बैठे हैं, मैं यहां पर हूं । वह एयरपोर्ट हमारे विधान सभा में है । जब हमें दिल्ली जाना हो तो हम रायपुर आते हैं और रायपुर के एयरपोर्ट से बैठकर हम दिल्ली जाते हैं और यात्रा करते हैं, जबकि बिलासपुर एयरपोर्ट से फ्लाईट हैं, लेकिन वह छोटे वाले फ्लाईट हैं । उसमें कोई बैठना नहीं चाहते और वह रेग्युलर नहीं है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं, यदि हम रायपुर से अन्य जगहों जाने के लिए पैसेंजर की बात करेंगे तो उसमें जो 40 से 45 प्रतिशत यात्री बिलासपुर रीजन के हैं, जो रायपुर में आकर रायपुर से कोलकाता जाते हैं, रायपुर से हैदराबाद जाते हैं, मुम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं । राज्य का हाईकोर्ट बिलासपुर में है, एसईसीएल का मुख्यालय बिलासपुर में है । एनटीपीसी बिलासपुर में है । कोरबा बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और साथ में वहां जो मार्केट है, इन सबके दृष्टिकोण से वहां पर जो आवश्यकता है । फंड की कमी के कारण उस एयरपोर्ट का विकास न रूके । मैं तो वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने उस एयरपोर्ट के विकास 150 करोड़ रूपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में किये हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि उसमें आवश्यकता पड़ेगी तो मूल बजट में आप अतिरिक्त राशि प्रदान करेंगे, जिससे हमारा एयरपोर्ट बढ़े और हम वहां से बोइंग विमान चला सकें, रेग्युलर फ्लाईट की व्यवस्था हो । केवल वहां के यात्री की बात ही नहीं है, बल्कि बिलासपुर का डेव्हपलमेंट उसके साथ में है । बिलासपुर के विकास का निर्धारण भी उसके साथ में है, इससे हमें लाभ मिलेगा ।

सभापति महोदय, खाद्य उपार्जन के लिए आपने 1220 करोड़ रूपए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 452 करोड़ का प्रावधान है। माननीय वित्त मंत्री जी, यह टोकन एमाउन्ट है और कुछ क्षेत्र को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब डॉ. रमन सिंह

जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय पीडब्ल्यूडी की सड़क, प्रधानमंत्री योजना की सड़क और एक नई सड़क योजना जरनेट की गई थी, उसका नाम मुख्यमंत्री सड़क योजना थी, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर की सड़क थी, लेकिन इसमें बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं । जो गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल नहीं हुए थे, उससे वंचित हो गए थे, ऐसे सारे गांव को मिलाकर मुख्यमंत्री सड़क योजना में जोड़ने का काम किया गया, लेकिन जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हुआ और निर्माण कार्य होने के बाद में पिछले 5 साल में उसमें एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ है, हमारी सरकार आने के बाद भी हमने उसमें खर्च नहीं किया है। आपने उसे प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं । उसके लिए आपने 452 करोड़ रूपए का प्रावधान इस अनुपूरक में किया है । हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी पंचायत मंत्री हैं और पंचायत मंत्री के अंतर्गत ही यह मुख्यमंत्री सड़क योजना है । मैं चाहूंगा कि हमारा मूल बजट आने के पहले एक बार पूरे प्रदेश की प्रधानमंत्री सड़क योजना की हमें अधिकारियों से tentative बजट बनवानी चाहिए कि यदि हमें सड़कों को बनवाना है तो हमें कितने बजट की आवश्यकता पड़ेगी और हम उसको शामिल करने का प्रयास करें क्योंकि यदि हम उसको शामिल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वह कनेक्टिविटी गांव से समाप्त हो जाएगी । पढ़ने वाले बच्चे साईकल से जाते हैं, लोग मार्केट जाते हैं, लेकिन वह सड़क खराब होने के कारण लोग परेशान हैं । मैं केवल अपने विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, कमोबेश पूरे प्रदेश में यह स्थिति है । जब प्रदेश की यह स्थिति है तो पूरे प्रदेश का एक बार आंकलन कराना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए। सर्वे कराने के बाद मूल बजट में मुख्यमंत्री सड़क योजना को विस्तार करना चाहिए। मैं नई सड़क बनाने की बात नहीं करता हूं। लेकिन उस समय जो सड़क बनी थीं, एक बार रिनीवल कराने की आवश्यकता है। अगर सड़कों को रिनीवल करायेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे गांव जो वंचित हो गए हैं, ये उससे जुड़ जायेंगे और इससे उनको लाभ मिलेगा।

मानानीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुफ्त में खाद्यान्न योजना के तहत राशन दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम उसके तहत लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान कर रहे हैं। आपने उसके लिए 680 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। जो हमारे गांवों के लोग हैं, शहरों के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोगों को उस योजना के तहत निरन्तर चावल प्रदान किया जा रहा है और उन्हें उस चावल का लाभ मिल रहा है। आपने उसके लिए अनुपूरक में व्यवस्था की है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी बीच में कई राशन दुकान बंद थे। उस समय कई लोग भूखे रहे हैं उसको सरकार के संज्ञान में दिलवाईये।

श्री धरम लाल कौशिक :- संगीता जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के समय को याद मत करो, उस समय लोग भूखे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के

लोग भूखे नहीं रहेंगे, भरपेट खाकर सोयेंगे, इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, एक महीने पहले की बात है। राशन दुकान बंद हो चुके थे, कहीं पर भी राशन का आवागमन नहीं था। आपके पास राशन रखने का जगह नहीं था, इसलिए आपने 3 महीने का राशन एक साथ दिया था।

सभापति महोदय :- संगीता जी, अब आपका ही नंबर आने वाला है, तब अपनी बात रखियेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- एक नमक और शक्कर को लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर से चलकर हमारी जनता को आना पड़ता था।

सभापति महोदय :- अभी आप बैठिये, आपका नंबर आने वाला है।

श्री धरम लाल कौशिक :- संगीता जी, आप बाद में विधायक बनी हैं। मैं तो उस बात का साक्षी हूं कि जशपुर हाल में टैंट में हमारा विधान सभा शुरू हुआ था। आप नमक की बात कर रही हो न कि उनको 2 किलोमीटर दूर चलकर आना पड़ता है। सभापति महोदय, हमने कांग्रेस की सरकार में देखा है कि चार और चिरौंजी को नमक से तौलकर लिया जाता था। हम बही गांव के ईमली वाली घटना को भूल नहीं सकते। बही गांव में इस नमक को लेकर कितनी बड़ी घटना हुई, धर्मजीत बता रहे हैं कि लाईट बंद करके मारे थे। तो हम यह नहीं भूल सकते। यदि आज उन्हें वनोपज का लाभ मिल रहा है। यदि उनको मुफ्त में नमक देने का काम किया और शोषण से मुक्त दिलाने का काम किया तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो आज उनके लिए सपोर्ट प्राइज घोषित किया गया है। सपोर्ट प्राइज के माध्यम से खरीदी की जा रही है और वनवासी क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, अभी सभी जगह खरीदी बंद है। हमने ही तेन्दू पत्ता का मानक दर बढ़ाया था। आपने तेन्दू पत्ता का मानक दर उतना का उतना ही दर रखा था।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बैठिये। इनके बाद आपका नंबर आने वाला है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धरम भईया, 30 लाख राशन कार्ड कट रहे हैं। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। शायद आप निवेदन करेंगे तो वह राशन कार्ड कटने से बच जायेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- संगीता जी, क्या है कि आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, मुझे हर बात का जवाब देना पड़ेगा। जब उस समय सरकार थी तो आप मंत्री होते तो बोलते या आपसे पूछते रहते। लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। अब आप बाद में बोलना।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- फिर उस समय गोधन न्याय योजना की बात की थी।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, कृषक उन्नत योजना, हमने धान खरीदी की है। मैं बहुत सारी सोसायटियों का दौरा किया हूं। ना केवल बिल्हा विधान सभा क्षेत्र बल्कि रास्ते

चलते बहुत सारे सोसायटियों का दौरा किया हूं। मैं केवल इसलिए गया कि किसान क्या महसूस कर रहे हैं। इस बार की धान खरीदी में किसान कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि अभी तक जितनी धान खरीदी हुई है, यदि सबसे अच्छी व्यवस्था रही है तो विष्णुदेव साय की सरकार में यह व्यवस्था कायम हुई है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, मैं इसका घोर विरोध करती हूं। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं इसका घोर विरोध करती हूं।

श्री धरम लाल कौशिक :- पिछली इनकी सरकार में बार बोरा के लिए लड़ाई लड़ते थे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, आप हमारे साथ चलिये, आप जहां कहेंगे, वहां चलेंगे। आप चलिये, आप जहां बोलेंगे, हम वहां चलते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप सोसाइटी में जाने लायक नहीं हैं। आप सोसाइटी में जाकर दिखाइए। आप कदम नहीं रख सकते। आप धान खरीदी में तो बात न करें तो ज्यादा अच्छा है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप जहां बोलेंगे, वहां चलिए। धरमलाल भैया, आप बालोद जिला में किसी भी धान खरीदी केन्द्र में चलिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कहीं भी धान खरीदी केन्द्र में मैं आपको ले जाउंगी। आप चलिए, विधान सभा खत्म होगा तो। आप परसों मेरे साथ धान खरीदी केन्द्र में चलिए। आप देखेंगे कि वहां की स्थिति क्या है?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कल चलिए, मेरे साथ टीम बनाकर चलिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- टोकन जारी नहीं हो रहा है। ऑफलाइन नहीं चल रहा है। गोल गोल घूमथे साए साए।

सभापति महोदय :- आप बैठिए, आप अपनी बात रखिएगा।

श्री दिलीप लहरिया :- पूरा सर्वर डाउन है। आपकी पार्टी का सर्वर डाउन है।

सभापति महोदय :- आपको कितना समय लगेगा?

श्री धरमलाल कौशिक :- पूरा समय तो इन्हीं लोगों ने ले लिया। माननीय सभापति महोदय, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि किसान इस बार धान बेचने में जितना सुखी है, उतना कभी नहीं रहा है। (मेजों की थपथपाहट) मैंने सोसाइटियों में जाकर देखा है। एक महीने आप धान खरीदी करेंगे, किसी सोसाइटी में बोरे की कमी नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हमारी सरकार ने दिया है। हम इनकी सरकार में बोरा की लड़ाई लड़ते थे। इनके मंत्री कहते थे कि बोरा केंद्र सरकार भेजे, तब धान की खरीदी होगी और हमने प्रश्न लगा दिया कि बोरे की जवाबदारी किसकी है? तो मंत्री जी ने स्वयं जवाब दिया कि राज्य सरकार की जवाबदारी है। यह तो इनकी सरकार चली है। आप सबेरे 10,11 बजे धान बेचे हैं और

धान बेचने के बाद में आप जब घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के पहले आपके खाता में धान का पैसा खाता में जा रहा है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैंने नक्सलियों का सरेंडर सुना था, लेकिन किसानों को सरेंडर कराया जा रहा है। जितना धान बेच दिया गया, हो गया। इस सरकार में रकबा काटा जा रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह पहले कभी नहीं हुआ है कि सेम डे में आप धान बेचे और धान का पैसा आपके खाता में आ जाए, मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, आपका सर्वर इतना डाउन है, इतना डाउन है कि आप लोग रजिस्टर में नोट करके रखते हो, दूसरे दिन एंट्री होता है और आप बोल रहे हैं कि पैसा तुरंत आ रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- तुरंत-तुरंत। चलिए, आप मेरे यहां चलिए। किसी सोसाइटी में आप चले जाएं और पूछें और सेम डे। यह असत्य बोलने की आदत आप लोगों की नहीं जाएगी। यह भूपेश बघेल की सरकार नहीं है। यही अंतर है भूपेश बघेल की सरकार में और यह विष्णु देव साय की सरकार है, जो पैसा सेम डे में भिजवाने का काम कर रहे हैं। यही अंतर है और जनता ने इस बात को परखा है, जाना है, तब आप लोगों को विदा किया है। माननीय सभापति महोदय, 5 एच.पी. के पंप कनेक्शन, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो हमारे किसान हैं, उनको नि:शुल्क पंप में बिजली का बिल नहीं आ रहा है। पंप चला रहे हैं और बाकी हमारे किसानों के लिए जो 750 यूनिट है, उसके लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किए हैं ताकि अबाध गति से हमारे किसानों का पंप चलता रहे और जो अनुदान की राशि है, वह अनुदान की राशि विभाग को चला जाए, इसके लिए हमारे इस अनुपूरक में प्रावधान रखा गया है। साथ ही हमारी जो महत्वपूर्ण योजना थी, जिन-जिन बातों को लेकर हमने चुनाव के पहले घोषणा की, उसमें एक हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना, दूसरा हमारी महतारी वंदन योजना, तीसरा धान की खरीदी के लिए हमारे जो रेट तय किए गए, चौथा हमारे भूमिहीन मजदूर किसान, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 13 दिसंबर को आदरणीय विष्णु देव साय जी ने शपथ लिया और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 दिसंबर को शपथ लिए और 25 दिसंबर को 3,716 करोड़ दो साल का बोनस देने का काम हमारी सरकार के द्वारा की गई और हमारे किसानों के खाता में पैसा डालने का काम किया गया। हम लोगों ने कहा कि 3100 रूपये की दर से खरीदेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वह हमारी सरकार के कारण ही आप 3100 रूपये दे रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- सरकार में तो तीन लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई।

श्री अनुज शर्मा :- नहीं, वह सही बोल रही हैं, उनकी सरकार जाती नहीं और हम 3100 रूपये दे नहीं पाते तो उन्हीं की सरकार की वजह से है। उनकी सरकार चली गई तभी तो हम 3100 रूपये दे पाये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मुझे याद है। धमतरी में किसान लोगों ने आंदोलन किया था। आपने इतना मारा था, इतना मारा था, उसकी भरपाई हमारी सरकार आने के बाद 5-5 लाख रुपया हमारे किसान भाइयों को दिए। हम लोग दिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- अच्छा, प्रदेश के वे किसान किसके साथ हैं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वे हमारे साथ ही थे। पता नहीं, क्या गड़बड़ किये, बटन गड़बड़ कर दिए, क्या हो गया?

श्री दिलीप लहरिया :- किसान हमारे साथ हैं, आप बटन के साथ हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने बटन के साथ क्या किया है, आप जानो।

श्री धरमलाल कौशिक :- किसान किसके साथ हैं?

सभापति महोदय :- कृपया आपस में बात न करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- ऐसा है, आप बटन को तो इसलिए भूल जाओ कि हमने वह भी करके दिखाया है कि नगर निगम में हमने बटन से चुनाव लड़ा तो जनपद चुनाव, जिला पंचायत चुनाव और सरपंच चुनाव में हमने सील मुहर से चुनाव लड़े हैं और दोनों में जीते हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- कितने जनपद सदस्य को हाइजेक करके रखा था, वह भी हमने देखा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अभी तक जिला पंचायत की गिनती की लिस्ट नहीं आयी है। आप सब लोगों ने धांधली कर दिया, सब बंद कर दिया। अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप लोगों ने पिछले जनपद सदस्य को हाईजैक करके रखा था, यह भी हमने देखा है।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- संगीता जी, बटन गड़बड़ था तो आप लोग कैसे जीत गये?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वोटिंग वाले भूल गये थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, अभी पार्लियामेंट में एस.आई.आर. को लेकर चर्चा हुई। जब चर्चा हो रही थी तो सब लोगों ने आरोप लगाया, तब हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एस.आई.आर. को लेकर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वे जिस ई.व्ही.एम. की बात कर रहे हैं, उस ई.व्ही.एम. मशीन को लॉन्च करने वाले इनके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। तब से ई.व्ही.एम. मशीन चली आ रही है। आप लोग विरोध करते हैं तो कम से कम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान रखिये, जिन्होंने ई.व्ही.एम. मशीन को लेकर आया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप भूल रहे हैं। उन्होंने कम्प्यूटर लाया था और आप नई तकनीक की बात करते हैं। वह बैल गाड़ी में संसद जाकर विरोध किये थे। उन्होंने कम्प्यूटर लाया था, उसका आप लोगों ने विरोध किया था और आप नये तकनीक की बात करते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोग आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। यह जनता देख रही है। (व्यवधान) यह देश की जनता एवं छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। माननीय सभापति महोदय, आज मैं प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहा था। हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देंगे। जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला था, लेकिन जब भूपेश बघेल जी की सरकार आ गई, तब उनका आवास छीन लिया गया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नगरीय क्षेत्र में कितने लागों को प्रधानमंत्री आवास मिला है?

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापित महोदय, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा में ऐसे प्रधानमंत्री आवास बना है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। वह अभी भी आधा-अधूरा पड़ा हुआ है। वहां सभी अधिकारी-कर्मचारी निलंबित हुए। यह कैसे प्रधानमंत्री आवास है?

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, गरियाबंद में आवास का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन वह पूरा-पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। यह समाचार पेपर में आया है। यह पूरा प्रदेश में दिख रहा है कि वहां उद्घाटन भी हुआ है और वह अपूर्ण है। यह गरियाबंद जिले की घटना है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- खाली सजा के चाबी ल दे देहे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, उनकी सरकार में पूरे पांच साल में प्रधानमंत्री आवास को बंद कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार ने इसलिए प्रधानमंत्री आवास को देना बंद कर दिया क्योंकि प्रधानमंत्री आवास बनेगा तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ेगा और नरेन्द्र मोदी जी का जय-जयकार होगा। नरेन्द्र जी का जय-जयकार मत हो। चलिये कि आपका सोच ठीक है कि उनको श्रेय मत मिले, लेकिन आपने तो गरीबों का हक छीनने का काम किया है। इसलिए आपने प्रधानमंत्री आवास बनने नहीं दिया। लेकिन हम लोगों ने चुनाव के पहले कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनायेंगे और इस बात का मुझे खुशी है कि जब मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं होगी, तब तक मैं अपने आवास में नहीं जाऊंगा। प्रथम कैबिनेट में जब प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल गई, तब हमारे मुख्यमंत्री गये। यह विष्णुदेव साय की सरकार है, जो कहती है, वह करती है। (मेजों की थपथपाहट) आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, वहां पर लोगों को काम मिल रहा है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ सदस्य से जानना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले का पांडुका का एक मामाला मेरे संज्ञान में आया है। उसको प्रधानमंत्री आवास मिला है, लेकिन उसको आवास बनाने नहीं दिया जा रहा है। उसको पुराने घर से बेदखल कर दिया गया है। मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य से जानना चाहूंगा कि यह कैसे प्रधानमंत्री आवास है? जिसका हक है, उसको आवास मिल रहा है, लेकिन उसको आवास बनाने नहीं दिया जा रहा है और उसको प्रधानमंत्री आवास दिये जाने का नाम हो रहा है। यह पांडुका का मामला है।

सभापति महोदय :- बैठिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, उनको लिख कर देना चाहिए। मौखिक याद कहां रहेगा? यदि वह मंत्री जी को लिख कर देंगे तो वह उसमें स्वयं विचार कर लेंगे। आप हमारे वित्त मंत्री जी को लिख कर दे दीजिये, नहीं तो आई बात और गई बात हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना में हमने 70 लाख महिलाओं को फार्म भरवाया है। इसके बाद इस योजना के प्रभाव से हमारी सरकार भी बनी, हमें उनका आशीर्वाद भी मिला। केवल विधान सभा में ही नहीं, बिल्क आज भी महतारी वंदन का जो लाभ है, जो महतारियों का सम्मान हुआ है, वह केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं हुआ है। आप उड़ीसा का चुनाव जाकर भी देखिये। उड़ीसा की जनता ने उड़ीसा में भा.ज.पा. की सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, मध्यप्रदेश की जनता ने मध्यप्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस को घोषणा करना भी नहीं आता है ? हमने 1000 रूपये देने की बात की थी, हम 12000 रूपये देने की बात किये, इन लोगों ने 1,00,000 रूपये देने की बात की । जनता को यह मालूम है कि 1,00,000 रूपये देने वाले नहीं हैं । यह भूपेश बघेल की सरकार नहीं है, यह [xx] की सरकार है । [xx] कर वापस आये हैं और फिर हमको [xx] वाले हैं, इसलिये इनके 1,00,000 रूपये को जनता ने ठुकराया और हमारे 1000 रूपये को जनता ने स्वीकार किया । भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से जनता का आर्शीवाद मिला, तब इन्होंने कहा कि लोक सभा तक देंगे और लोक सभा चुनाव के बाद इसको बंद कर देंगे । यह प्रोपेगेंडा फैलाने का काम इनके द्वारा शुरू किया गया । प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद हम लोगों ने जनता से कई बात कही है । विष्णु देव साय की सरकार है, एक आदिवासी का बेटा है, आदिवासी एक बार जो बोल दिये तो वही उनका सब कुछ है । विष्णु देव साय की सरकार ने जो कहा है, वह बात हमारे आगे रहेगी । आज महतारी वंदन के तहत 22 वां किश्त मारा मिल चुका है तथा लगातार उनके किश्त जारी है । सभापति महोदय, हम लोग जब गांव में जाते हैं तो पूछते हैं कि इस पैसे का आप लोग क्या उपयोग कर रहे हैं, जो उपयोग महतारी कर रही है, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी गांव में चले जायेंगे, महतारी का चेहरा आपको प्रफुल्लित दिखाई देगा, उनके बीच में खुशियाली दिखाई देगी । महतारियों के खाते में अभी तक 14,318 करोड़ रूपया अंतरित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया गया है । माननीय

सभापति महोदय, इस अनुपूरक में भी 2500 करोड़ रूपये का प्रावधान आने वाले समय के लिये किया गया है । महतारियों को रेडी टू ईट के लिये काम करने का अवसर मिला था, कांग्रेस की सरकार ने उसे बंद कर दिया और उसे बीज निगम के एक प्रायवेट ठेकेदार को सप्लाई करने के दे दिया, तब हमने कहा कि जब हमारी सरकार आयेगी तो इसे महतारियों को पुन: लौटायेंगे । हमारी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है और उसको पुन: प्रारंभ करने की दिशा में अग्रसर हुये हैं । मैं इसके लिये विष्णु देव साय की सरकार ...।(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपने गरम भोजन भी बंद कर दिया । दो साल हो गया है...।(व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने महिलाओं से रेडी टू ईट छीन लिया था । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय आप सीनियर हैं, एक गांव में भी गरम भोजन मिल रहा है, आप बतायेंगे । आप सीनियर हैं, यह बतायेंगे कि कहां पर गरम भोजन मिल रहा है । जब से आपकी सरकार आई है, यह गरम भोजन बंद पड़ा हुआ है । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- इनकी सरकार ने रेडी टू ईट का काम महिलाओं से छीन लिया था..। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अभी आपकी सरकार क्या कर रही है ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उसके बाद बड़ी-बड़ी बातें हो रही है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बच्चे कूपोषित हो रहे हैं, पता नहीं बजट को कहां करते हैं ?

श्री सुशांत शुक्ला :- यह पता नहीं कि कूपोषित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप जरूर हो रहे हैं । यह मुझे समझ में आ गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ । उस दिन जब चर्चा चल रही थी कि हमारे विजन 2047 अंजोर इस पर न्यूयार्क की बात आई । अमेरिका की बात करते हैं तो न्यूयार्क की बात आई कि वहां का डीजीपी क्या है और शेयर क्या है ? उसके बाद में हमारे दिल्ली के एनसीआर की जो बात आई, ऐसे अनेक हमारे कैपिटल की बात आई है, इस दिशा में कोई सोचा नहीं गया । मैं हमारे वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बधाई इसलिये देना चाहता हूँ कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिये उन्होंने एक प्रस्ताव लाया और प्रस्ताव लाने के बाद में आज उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तथा इस बजट में प्रावधान है कि हम स्टेट कैपिटल रीजन बनायेंगे । यह बहुत सुंदर बनेगा। आज हमारे नई राजधानी में अटल नगर को लोग देखने के लिये आते हैं । मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की हमारी पहचान और हमारी शान और हमारी आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षमता, हमारे स्टेट केपिटल रिजन के माध्यम से छत्तीसगढ़ बनने वाले हैं, मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, उसको इस बजट में शामिल किया गया है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आदर्श गांव, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा गांवों को चिन्हांकित करते हैं, वहां की मूलभूत समस्या, उस समस्या के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निराकरण के लिए, वहां पर कैसे काम किया जा सके, वहां पानी, सड़कें, बिजली हैं, वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसके लिए अलग-अलग पंचायतों में केन्द्र सरकार के द्वारा राशि दी जाती है, इस बजट में उसकी प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री आदर्श गांव को हम मुख्यधारा में शामिल कर सकें, हम उस गांव के विकास को बढ़ा सकें, उसके लिए भी यहां पर प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आज के समय में हम डिजिटल तकनीक की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को यहां पर रखा कि हमारा पूरा देश डिजिटल में कैसे आगे बढ़ सकता है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार से हम पूरे विश्व की बात करेंगे, हमारी जो लेनदेन है, डीबीटी है, पूरे विश्व में 49 प्रतिशत हमारी डीबीटी में अकेले हिन्दुस्तान का नाम है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, इसी डिजिटल का विरोध, इसी कम्प्यूटराईज का विरोध आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने सदन का घेराव करके किया था। आपने आधार कार्ड का भी विरोध किया था। अब आप लागू कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हम उसका फायदा देख रहे हैं। महतारी वंदन योजना, महतारी वंदन योजना में आज जितना पैसा हमको महतारियों के खाते में भेजना है, एक प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने कहा कि हम दिल्ली से 1 हजार रूपए भेज रहे हैं तो वहां पर 15 प्रतिशत पहुंचता था, भारतीय जनता पार्टी एन.डी.ए. की सरकार है, जब मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी उस पैसे को महतारियों के खाते में भेजते हैं तो 15 पैसा नहीं, 100 का 100 प्रतिशत पहुंचता है। उसका बहुत बड़ा कारण डिजिटल है। पारदर्शिता, गुड गवर्नेंस...।

श्री उमेश पटेल :- भैया, आप कब की बात कर रहे हैं ? राजीव जी के समय की बात कर रहे हैं। उस समय डिजिटल की क्या स्थिति थी ? ऑनलाईन की क्या स्थिति थी ? कैसे ट्रांसफर होता था ? वही तो बोल रहा हूं, बहुत पुरानी बात है। आप कहां का आंकड़ा कहां बता रहे हो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी की बात कर रहा हूं। उसका 15 प्रतिशत था, तब की बात कर रहा हूं, बहुत दिन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी को बहुत दिन थोड़ी हुआ है, ये 1984 के बाद की बात है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, 10 महीने से पंचायतों में एक रूपया नहीं पहुंचा है, आप सौ प्रतिशत की बात कर रहे हैं पता नहीं आपके पास कहां से 100 प्रतिशत का आंकड़ा है। 1 रूपया पहुंच रहा है तो बता दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, 15वें वित्त का पैसा कहीं नहीं गया है, गुंडरदेही में सरपंच लोग सब हड़ताल में बैठे हैं। उसको तो बजट से दिला दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपस में बात न करें।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, सरपंच भाई लोगों को 15 वें वित्त का पैसा कब जारी करेंगे यह बता दीजिए। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी से घोषणा करवाईए। पंचायतों की मूलभूत सुविधाएं पूरी अधूरी पड़ी हुई हैं। पंचायत के सरंपच हड़ताल में बैठे हैं। आप बड़ी-बड़ी भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, डीबीटी का सिर्फ उतना ही नहीं है, आज आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे हैं, हमारी ई-ऑफिस प्रणाली, ये जो फाईल की बात आती है, फाईल वहां रूका हुआ है, फाईल यहां रूका हुआ है, ये फाईल कहीं रूकने वाला नहीं है, अब सब ऑनलाईन होने वाली है, आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ई-ऑफिस प्रणाली को सभी स्तरों पर लागू किया गया है। हमारी सारी निर्णय, प्रक्रिया पेपरलेस और डिजिटल हो गई है। इसलिए मैंने पहले कहा कि पहले लोग फाईल को ढूंढवाते थे कि कहां धूल में दबा हुआ है, झाड़ते थे, निकालते थे, उसके बाद मिलता नहीं था, आज जो स्थिति है, हम लोग इस नये युग में जो बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं, हमारे वित्तीय प्रबंधन में भी ई-बाउचर, ई-एकाउंट प्रणाली की शुरूआत की गई है, हमको इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। इसके साथ ही हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं, हमारे नियमित कर्मचारियों का ई-केवाइसी सत्यापन पूर्ण कर लिया है। हम लोग लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हमको आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाभ दिखेगा। अभी आपने देखा कि हमें रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है। उसमें आपका नामांतरण हो रहा है। आपको पटवारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया को धीरे-धीरे उस दिशा में ले जाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और बड़ा कदम है। हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर विष्णु देव साय जी की सरकार है, हमारे सब मंत्री बैठे हुए हैं और वह अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं। उनकी जो कुशलता है, उनकी जो प्रबंध क्षमता है, आज हम इस बात को देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जब इस बार चुनाव में हम लोगों को वोट दिया और वोट देने के बाद हमारी सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद जो 2 बजट प्रस्तुत किये गये-गति और शक्ति और उसके बाद जिस प्रकार से हम अनुपूरक लेकर आये और इस अनुपूरक के माध्यम से हमारे जो जन हितैषी निर्णय लिये गये। चाहे हमारे युवाओं के लिए हो, चाहे हमारी महिलाओं के लिए हो, हमारे किसानों के लिए हो, हमारे वृद्धों के लिए हो और उसके साथ में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं। यह बड़ी-बड़ी बात करते हैं। इनके राज में खेल अलंकरण समारोह समाप्त कर दिया गया था। जब हमारी सरकार आई है तो खेलो इंडिया खेलो को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अभी सांसद खेल महोत्सव करा रहे हैं कि गांव से बच्चे निकलकर हमारे ब्लॉक स्तर तक आये, ब्लॉक स्तर से जिला तक आये, जिला से लोक सभा तक आये, राज्य तक जाये और राज्य से

होकर राष्ट्रीय स्तर पर जाये। इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। सभापति महोदय, कमाल की बात तो यह है कि बस्तर जैसी जगह, जहां गोलियों की आवाज आती थी, वहां हमारे यही वित्तीय प्रबंधन, यही अनुशासन और यही निर्णय से आज वहां बंदूकों की आवाज नहीं है। पिछले साल हमारे डेढ़ लाख लोगों ने पंजीयन करवाया था और खेल खेला था। आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि 3 लाख 91 हजार लोगों ने बस्तर में जो पंजीयन करवाया है, जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, यह हमारा कुशल राजनीतिक प्रबंधन है।

श्री उमेश पटेल :- भैया, आप ही वह आदमी थे, जो छत्तीसगढ़ ओलम्पिक का विरोध करते थे। क्या आप भूल गये? अभी उसमें जो पंजीयन हो रहा है, उसके लिए आपका सीना चौड़ा हो गया।

धरमलाल कौशिक :- हमने बस्तर ओलम्पिक का विरोध कहां किया?

श्री उमेश पटेल :- आपका जो सांसद खेल हो रहा है, क्या उसमें अलंकरण समारोह होगा? उसमें जो जीतकर आएगा, क्या उसके लिए उसमें नौकरी का प्रावधान है?

श्री धरमलाल कौशिक :- अलंकरण समारोह आप लोगों ने नहीं कराया। नौकरी का प्रावधान नहीं, लेकिन नौकरी लग गई। मैं उस दिन गया था।

श्री उमेश पटेल :- आप लोगों ने उसमें नौकरी का प्रावधान क्यों नहीं किया है?

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें सब प्रावधान हैं। आपने तो उसको बंद कर दिया। आपने उसको ऐसे पलट कर रखा कि आपने 5 साल तक बच्चों की तरफ से मुख मोड़ लिया था। आपको 5 साल तक जो अवसर मिला तो उसका आपने सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरूपयोग किया।

श्री उमेश पटेल :- आप छत्तीसगढ़ ओलम्पिक का विरोध क्यों करते थे? यह आप लोगों का [xx] है। जब हमने किया तो आप उसका विरोध करते थे और आज उसी खेल को आप सीना चौड़ा करके बता रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- जहां खेल अलंकरण समारोह करना चाहिए, उस पैसे को अपने कार्यकर्ताओं को बांटने का काम कांग्रेसियों ने किया। आप क्या सोचते थे कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों के खेल का पैसा देकर उनको चुनावी एजेंट बना लूंगा और चुनावी एजेंट बनाकर पार्टी का काम करा लूंगा। लेकिन आपने पूरे 5 साल तक जिनको पैसे दिए, वह भी आपका काम नहीं किए। आज हम खेल अलंकरण समारोह तैयार कर रहे हैं। हमारा खेल अलंकरण समारोह हम पहले कर रहे थे, आज करने जा रहे हैं और हमारे ऐसे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आ रहे हैं तो उनको सम्मानित करने का काम यदि किसी ने किया है तो विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है और डॉ. रमन सिंह जी ने किया है।

श्री दिलीप लहरिया :- इस बार वह लोग आपका काम नहीं करेंगे।

श्री उमेश पटेल :- छत्तीसगढ़ ओलम्पिक में सबसे बुजुर्ग महिला फुगड़ी में जीतकर आई थी, उसका आप विरोध करते थे। भैया, यह आपका दो रंग है। आप वही आदमी है, जो छत्तीसगढ़ ओलम्पिक का विरोध करते थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति जी, हम इसका विस्तार कर रहे हैं और मुझे एक बात और कहना है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धरम भैया, मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं। आप एक मिनट सुन लीजिए। आप दल की बाध्यता के चलते मुख्यमंत्री साय जी की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अगर इस सरकार में सर्वाधिक अन्याय हुआ है तो वह आपके साथ हुआ है। आप सच बोलने की स्थिति में नहीं है। आप जितनी भी बातें बोल रहे हैं, वह केवल और केवल दल की बाध्यता में बोल रहे हैं। इस सरकार से आप कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं, वह सब जान रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आप लोग यह जो सांसद खेल महोत्सव करा रहे हैं, उसमें कुछ अलंकरण का प्रावधान है या नहीं ? क्या कोई नौकरी का प्रावधान है या ऐसे ही है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैंने बस्तर ओलंपिक का जिक्र इसलिए भी किया कि 3 लाख 91 हजार लोगों का पंजीयन हुआ और इससे बड़ी बात जो नक्सली थे, जिनके कारण लोग भयभीत थे और गोलियां गूंजती थी। उन 771 लोगों ने इस बस्तर ओलंपिक में खेला है। यह उनकी सहभागिता रही है। आज लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि जहां नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जहां विष्णु देव साय जी की सरकार है, वहां पर आम लोग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 51 दिनों तक वहां पर खेल हो और शांति के साथ उसका समापन हो, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मैं उसके लिए इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, विष्णु देव साय जी की सरकार, हमारे मंत्री और साथ ही वित्तमंत्री जी ने जिस प्रकार से अनुपूरक लाया है, जो हमारे जनहितैषी निर्णय लिये जा रहे हैं, जो यहां पर लोगों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं और जो कुछ अभी तक नहीं हुआ है, वह नए उपक्रम करने जा रहे हैं, इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में परिवर्तन आयेगा। छत्तीसगढ़ का मान बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के विकास की गति में और तेजी आयेगी। सभापति महोदय, मैं उसके साथ में बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर 35 हजार करोड़ रूपये की अनुपूरक राशि के विरोध में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं अभी विरोध करती हूं और बाद में जो समर्थन है, वह आपको बताऊंगी। मैं इस बात से

शुरूआत करती हूं कि “जब समुंदर में उतर ही गये तो किनारा भी आयेगा और वक्त का क्या है आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आयेगा” (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारा तो आ गया लेकिन अब सिन्हा जी का नंबर कभी नहीं आयेगा। वह गोल हो गये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आयेगा। हम उम्मीद रखेंगे, उनका नंबर आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- बेचारे सिन्हा जी का नंबर कभी नहीं आयेगा।

श्री दिलीप लहरिया :- आयेगा भी और छायेगा भी।

श्री अजय चन्द्राकर :- आ जाही ? सबका नंबर आ जायेगा लेकिन सिन्हा जी का नंबर कभी नहीं आयेगा।

श्री उमेश पटेल :- आप यह तो बताईये कि आप सांसद खेल महोत्सव करवा रहे हैं, उसमें अलंकरण करा रहे हैं कि नहीं ? आपने 5 साल तक यह प्रश्न पूछा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पुन्नू जी, जब संगीता सिन्हा जी के पति सिन्हा जी विधान सभा में आये थे तब आप विधान सभा थे या संसद में थे ?

श्री उमेश पटेल :- वह आ गये थे। वह खाद्य मंत्री थे। आप भूल गये हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, 35 हजार करोड़ रूपये का बजट है। यह अनुपूरक बजट है। जबकि आज अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं या पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं तो वहां पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि बजट कहां पर खर्च हुआ है ? क्योंकि आपका जो मुख्य बजट है, वह कहां पर खर्च हुआ है ? न वह मेरे क्षेत्र में दिखता है, न छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पर भी कोई भी नया काम ऐसा नहीं दिखता है और फिर से अनुपूरक बजट आ गया। यदि उस बजट का पैसा खर्च हो चुका है, तब अनुपूरक बजट आता है। जब वह बजट खर्च हुआ ही नहीं है तो सरकार को फिर से अनुपूरक बजट की क्या आवश्यकता पड़ गई ? वह फिर से कर्जा क्यों ले रही है ? वह सभी विभाग के लिये क्यों मांग कर रही हैं ? शिक्षा के लिये, स्वास्थ्य के लिये, सड़क के लिये, पुलिस प्रशासन के लिये, सभी के लिये फिर से मांग आयी है। सभापति महोदय, इस सरकार को बने हुए दो साल हो गये, दो साल में एक नई रोड नहीं बनी है। मैं पूछ लेती हूं यदि किसी के पास नई रोड आयी होगी ? हम जितने भी लोकार्पण कर रहे हैं, भूमिपूजन कर रहे हैं, वह सब माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में हमने जितने स्कूल बनाये, उसका लोकार्पण कर रहे हैं। एक भी ऐसा काम नहीं है, जिसका हम लोकार्पण या भूमिपूजन करें। सभापति महोदय, मैं गुण्डरदेही विधान सभा की बात कर रही हूं। सरपंच रोड पर बैठे हैं। वे हमारे पास आवेदन देने आये थे, उनके पास 15वें वित्त का पैसा नहीं आया। वे लोग जब चुनाव लड़े हैं, सरपंच के चुनाव में 2-3 लाख रुपये खर्च किये हैं, छोटे से चुनाव में 3 से 5 लाख रुपये खर्च हुआ है। सभापति महोदय, सरपंच लोग चुनाव लड़ने के लिये 5-5 लाख रुपये खर्च किये हैं। आज उनके पास एक

रुपया नहीं है। वह सभी विधायक के यहां चक्कर लगा रहे हैं कि उनको विधायक राशि मिले तो वह कुछ काम करें। सरपंच लोग रोड पर आ गये हैं। ये सरकार की स्थिति है। सभी लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। अभी बड़ी-बड़ी उपलब्धि बता रहे थे। महोदय जी ने धान खरीदी की बात की। वह बोले कि विष्णु देव साय की सरकार में यह पहली बार है कि बहुत जोरदार धान खरीदी हो रही है। सभापति महोदय, यह लोकतंत्र का मंदिर है। हम सभी अपने क्षेत्र की बात यहां रखने आते हैं। जनता हमसे उम्मीद रखती है। वह यह सोचते हैं कि हमने जिनको जनप्रतिनिधि बनाया है वह हमारी आवाज को ऊपर तक उठायें और वह इंतजार करते हैं कि हमारी आवाज को हमारे विधायक इस लोकतंत्र के मंदिर उठायें और हम अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाते हैं। आप जब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा धान खरीदी कर रहे हैं तो मैं उसका घोर विरोध करती हूं। उसके लिये अनुपूरक बजट में बहुत सारी राशि निकाले हैं। वहां राशि खर्च कहां हो रही है। हम पहले दिन गये थे। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरूआत हुई थी। हम पहले दिन जब दौरे में गये तो वहां पर बोरा रखा हुआ था, बोरे में इतना बड़ा-बड़ा छेद था कि हाथ घुस जाता था। जब हम बोरे का विरोध किये तब नया बोरा वहां पर आया है। सभापति जी, वह जो नया बोरा आया है, मैं आपको बताऊंगी कि नया बोरे का वजन 500 ग्राम था। पहले बोरे का वजन 700 ग्राम था, नये बोरे का वजन 500 ग्राम का था। इतना वेट कम करने की आवश्यकता क्या है? इसकी मार किसानों को पड़ रही है। सबसे पहली बात कहना चाहती हूं कि आप बड़ी-बड़ी योजना बनाते हैं। कोई भी चीज के लिये योजना बनती है। मैं तो कहती हूं कि विष्णु देव साय जी की सरकार ने उस योजना को बनाया कि उनको धान न खरीदना पड़े। आपने शुरू से किसानों को तंग करके रखा। सबसे पहले शुरूआत हुई, आपने डी.ए.पी. की कमी किया। ये सरकार वह सरकार है जो डी.ए.पी., यूरिया सबके लिये शार्टेज कर दी और वही डी.ए.पी., यूरिया दुकान में 2 हजार, ढाई हजार रुपये में मिल रही थी। आपने नैनो खाद पकड़ा दी ताकि उत्पादन कम हो। उत्पादन कम हुआ। आज उत्पादन का रेशियो कम हो चुका है। अगर धान का उत्पादन देखा जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको मालूम है कि मैं उस दिन बालोद गया था। आपको बता देता हूं कि एस.आई.आर. की बैठक लेने गया था। मैं सिन्हा जी से पूछा कि उत्पादन कैसा है, खेती कैसी है तो वह बोले कि बहुत अच्छा है। आप फोन करके पूछ लीजिए। यहां आप बता रहीं हैं कि उत्पादन कम है। सिन्हा जी से पूछ लीजिए न कि इस साल उनकी कितनी धान की फसल हुई है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- सुन ना फील्ड में ये रहिथे, वो नई रहय।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पूछ लीजिए न। ओकर घर में कतका उत्पादन हे, तेला पूछ ले। यहां उत्पादन कम के बात करत हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, यही चन्द्राकर वो चन्द्राकर हे जो बोलले हे सिन्हा जी हा का सब्जी बनाये हे।

श्री उमेश पटेल :- एक्चुअली का हाईस जानत हस। जब ले गाइडलाइन के रेट चेंज होईस हे न, तब ले ओकर दिमाग काम नई करत हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहली बात उत्पादन कम हुआ। उसके बाद आपने जिनके पास 5 एकड़ खेत है, उनका 2 ही एकड़ का धान खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो इतने लोग इधर वाले बैठे हैं, यहां पर सब अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस एरिया के बाहर जब हम बाहर बैठते हैं न, सभी परेशान हैं। सभी अपना दर्द बताते हैं। कहीं पर टोकन नहीं मिल रहा है। आपका 8.00 बजे टोकन मिलना शुरू होता है और 8 बजकर 3 मिनट में टोकन खत्म हो जाता है और 8 बजकर 3 मिनट तक किसका टोकन कटता है, कहीं किसी को पता नहीं है। वह सांय-सांय, गोल-गोल घूमते रहता है। सभापति महोदय, ऑफलाइन टोकन मिलना शुरू हुआ, ऑफलाइन भी कटता नहीं है। हम आवाज उठाते रहते हैं। उस दिन हम बात में इस चीज को रखे हैं। ऑफलाइन सिर्फ कुछ-कुछ लोगों का कट रहा है, वह भी स्पेशल लोगों का कट रहा है। मैं यहां कहना नहीं चाहती कि किनका-कितना कट रहा है। मेरा निवेदन है कि जब ऑफलाइन है, जो 01 एकड़, 02 एकड़ वाले हैं, जो बुजुर्ग, बीमार हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है। यहां पर सबके पास मोबाइल नहीं है। यहां पर रोजी-रोटी कमाने वाले हैं जिनके पास वह टिक-टाक वाला मोबाइल है। एक-एक डिसमिल की जो एक-एक धान है, वह लोग दूसरे के यहां अपने धान को रखते हैं, उनका इतना छोटा सा घर रहता है, उनके पास धान रखने की जगह नहीं है, वह दूसरे के प्रसार में रखे हैं और दूसरे के यहां रखे हैं तो 55 डिसमिल का धान रखे हैं, वह तो चूहा ही काटकर खा गया । आधा तो सूख गया, अब बताईये कि वह धान कैसे बेचेगा? आपका धान 15 दिन...।

श्री अनुज शर्मा :- तुंहर इंहा के मूसवा बहुत पोठ हे का ? तुंहर इंहां के मूसवा बहुत पोठ हे लागत हे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं, अब कइसे करबे । आप मन के इंहां मूसवा नइ हे, हमर तनी मूसवा हे । माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि जो लोकल नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनका तो ऑफलाईन में धान खरीदीये, वह ऑनलाईन में नंबर नहीं लगा सकते तो उनका भी धान नहीं खरीदा जा रहा है । मैंने तो कल इस बात को बताया है कि जब मैं दौरे में गयी थी तो 19 के बाद 45 का टोकन कटता है, 45 नंबर के टोकन वाले का धान खरीद लिया जाता है। क्या आपको ऐसी गिनती आती है ? लेकिन यहां पर ऐसी गिनती है, आप मेरे विधानसभा में चलिये, मैं आपको बता दूंगी कि 19 टोकन कटे हैं ।

श्री दिलीप लहरिया :- लगता है कि आपकी तरफ छुछवा हे, आपकी तरफ छुछवा होगा । (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, 20वें नंबर पर जिसका 45 नंबर पर टोकन है उसका टोकन कटा है, उसका धान बिक गया । कैसे बिकेगा ? सरकार यहां पर जवाब दे कि कैसे 45

नंबर पहले आयेगा, इनको गिनती तो सही आती होगी न । यह हो रहा है । सूखत में निकाल रहे हैं, 40-500 लेने का है, 40-700, 800, 41-500 ले रहे हैं, मैंने धान को छूकर देखा । 1 नवंबर से पहले लुआ गया है, पूरा सूख चुका है और क्या सूखत निकाल लेंगे ? आप कितना राजस्व बटोर लेंगे ? आज तो राजस्व विभाग में मेरा प्रश्न लगा था मतलब संग्रहण केंद्र में लगा था, इत्तिफाक से मेरा नंबर नहीं आया । महोदय जी से घोटाले की बात की थी, महोदय जी बैठे हैं । आज उनका प्रश्न था । महोदय जी, आप याद करिये । मैंने प्रश्न लगाया था, मेरे यहां धान के 2 संग्रहण केंद्र हैं और 2 संग्रहण केंद्र में घोटाला था, 10 करोड़ राशि का गबन था । उस समय जब मैंने उठाया तो आपने कहा कि कहीं पर गबन नहीं हुआ है और फिर से मैंने प्रश्न लगाया कि इतना धान कहां गया।

माननीय सभापति महोदय, मैंने आपसे 18 जुलाई को प्रश्न किया था । मेरा प्रश्न 11 तारीख को लगा है और 13 तारीख को कार्रवाई हुई है मतलब मेरा प्रश्न लगने के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई कर दी उससे पहले क्यों नहीं किये ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि आज जब मैंने 2 संग्रहण केंद्रों की बात की, वह भी बालौद विधानसभा का तो 10 करोड़ की राशि और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि उससे कई गुना ज्यादा का वहां पर घोटाला-गबन हुआ है । मैं तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा जांच कराना चाहती थी लेकिन जब एक विधानसभा में 2 संग्रहण केंद्र हैं और वहां 10 करोड़ राशि का गबन होता है तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति सोचिए कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कितना गबन हो रहा होगा, हमने तो जांच ही नहीं करायी । यह बात सोचने लायक है । इसमें हमारा कुछ नहीं, सरकार की हानि है । सरकार को कहां से राजस्व आयेगा ? आपके पास पैसा नहीं है, पूरा पैसा तो इन लोग गबन कर रहे हैं तो सरकार को राजस्व की हानि तो हो रही है न । माननीय सभापति महोदय, किसान को अलग लूटने का कार्य किया जा रहा है । बोरे में सूखत निकाल रहे हैं, उसको लाइट करके बोरे का वेट बढ़ा हुआ है । यदि आप पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का धान खरीद रहे हैं, अगर सभी को इकट्ठा करें तो बहुत सारा धान होता है । खैर इस धान खरीदी में बहुत चर्चा हुई । मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सरकार किसानों के साथ बहुत अन्याय कर रही है, उसके लिये और राशि निकालना, पता नहीं किसमें वह पैसा देगी, वह किसमें बजट देगी ?

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात बिजली के बारे में कहना चाहती हूं। इसमें भी आपने बहुत सारी मांग की है, वित्तमंत्री जी ने मांग की है । महतारी वंदन योजना की बहुत बात हुई और हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं कि महतारी वंदन ला रख ले लेकिन बिजली बिल के रेट ला कम कर दे । चिल्ला रहे हैं और सबसे ज्यादा मेरे भाई के क्षेत्र में चिल्ला रहे हैं कि ये पैसा ला रख ले भाई अऊ मोला महतारी वंदन ला मत दे भले लेकिन बिजली बिल के रेट ला कम कर दे । माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार में हम बिजली बिल हाफ योजना लाये थे और मुझे इस बात की खुशी है कि इस सरकार ने सभी योजनाओं को बंद किया, लेकिन बिजली बिल हाफ योजना को जारी रखा। जब इन्होंने इस योजना को

जारी रखा तो हमने आपको बधाई भी दी कि आपको बहुत-बहुत बधाई हो। सरकार, आपने हमारी बात सुनी, गरीबों की बातें सुनी और इस प्रदेश में आपने बिजली बिल हाफ योजना चालू रखी। यहां पर बिजली बिल हाफ योजना चालू थी, लेकिन अचानक से 400 यूनिट कम कर दिया गया, भाई यह क्यों किया गया ? जब 400 यूनिट कम कर दिया गया फिर उसमें मैंने प्रश्न लगाया और उस दिन प्रश्न आया था उससे पहले फिर से 100 यूनिट, 200 यूनिट कर दिया गया। यहां पर बिजली बिल 200 यूनिट कर दिया गया। मुझे यह बात समझ में नहीं आयी कि पूरे रायपुर, भिलाई, दुर्ग और मेरे बालोद विधान सभा में बड़ा-बड़ा पोस्टर लग गया। अब बिजली बिल 200 यूनिट कर दिया गया। आप किस बात की बधाई ले रहे हैं? अगर आप 400 यूनिट के बदले 500 यूनिट हाफ करते तो यह सरकार बधाई की पात्र थी। यह आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आपने 200 यूनिट क्यों किया? अगर आपको जनता से बधाई लेना है तो आप 500 यूनिट हाफ कीजिये। हम आपको बधाई देंगे। हम इस सदन से बधाई देंगे, हम जनता की ओर से पोस्टर लगवायेंगे और पूरे प्रदेश में धन्यवाद् देते हुए, हम लोग आपके बड़े-बड़े पोस्टर लगवायेंगे। हमारे क्षेत्र में एक दिन में 20-30 बार लाईट गुल होती है। मैं तो यह भी बताना चाहती हूँ कि सभी जनप्रतिनिधियों के पास रात को 12.00 बजे फोन आता है काखरो घर छट्ठी के सगा आ गे हे। मुझे यह बात बताने में भी बड़ा मजा आ रहा है कि मुझे एक दिन अरमरीकला गांव से किसी ने फोन किया । उन्होंने कहा- भाभी जी, मोर घर छट्ठी के सगा आए हे अउ सबो मन बढ़िया शहर के हरे। वहां पर इस लाईट की व्यवस्था को ठीक करें। छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली का उत्पादन है फिर यहां के लोग क्यों तरस रहे हैं ? अगर हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं तो आप हमें ढाई रूपये देते हैं तो आप अडानी बिजली उत्पादन करता है और आपको देता है तो उसको 7 रूपये क्यों देते हैं ? यह तो भेदभाव है। आप एक को मां और एक को मौसी क्यों कर रहे हैं ? आपके बिजली की यह व्यवस्था है।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बात करना चाहूंगी। आज मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई क्योंकि यहां पर हम लोगों ने स्थगन लाया था और मैं एक चर्चा करना चाह रही थी। आपने पुलिस प्रशासन को एकदम हाई स्टैण्डर्ड बनाने के लिए बजट मांगा है। आज यहां स्थिति इतनी खराब है अगर आप कहीं एफ.आई.आर. दर्ज कराने जाते हैं तो कहीं पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो रहा है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, अपनी सरकार में तबादला उद्योग चलाकर, पुलिस का मनोबल गिराने वाले लोग आज यहां पर प्रश्न कर रहे हैं। यह बड़ा अच्छा विषय है। इनकी सरकार में एक थाने में कोई थानेदार 6 महीने तक नहीं चला। जिला तो दूर की बात है, जिला का एक एस.पी. उदाहरण नहीं दे सकता कि जिसने 1 वर्ष पूर्ण किया हो। आज यह मनोबल की बात कर रहे हैं और उसकी उन्नति की बात कर रहे हैं तो यह बात समझ से परे है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, पुलिस प्रशासन के बारे में बताना चाहूंगी। यह आरंग के कुरूद गांव का मामला है । वहां 15 साल की बच्ची जो नाबालिक है, उसको एक बदमाश युवक 4 चक्के की गाड़ी में उठाकर ले जाता है और जब उसके पिताजी को खबर आती है कि उसको एक बदमाश युवक ले गया है तब तुरंत उसको लाकर छोड़ता है। जब उसके पिता जो प्रार्थी हैं । मुझे दो मिनट का समय दें। जब उसके पिता थाने में रिपोर्ट करने जाते हैं एक, दो, तीन नहीं चार बार जाते हैं उसके बाद भी उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है।

श्री सुशान्त शुक्ला :- माननीय सभापति महोदय, सूरजपुर में पुलिस के साथ किस कांग्रेस के पदाधिकारी ने क्या किया था ? उस समय क्या घटना घटित हुई थी, कांग्रेस के साथियों की तरफ से उस पर भी बयान आना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, जब उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है तब वह कोर्ट में जाते हैं उनको यह पता है कि यह पुलिस प्रशासन एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करेगा और उसके बाद वह कोर्ट की शरण लेते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि मेरी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो रही है। जब कोर्ट से एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए आदेश आता है तब उनकी एफ.आई.आर. दर्ज होती है। यह कितनी लज्जा की बात है। एक पिता अपनी बेटी की आत्मा रहता है। एक पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए दर-दर ठोंकरें खा रहा है, लेकिन उसकी एक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो रही है। यहां ऐसा पुलिस प्रशासन है। क्या इनके अलग नियम आ गये हैं कि किसी पीड़ित का एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होना है। मैं तो चाहती हूँ कि अगर यहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी बैठे हों तो उस टी.आई. के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जाये । मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जो कुरूद में आरंग के थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए । जब कोर्ट से आदेश लेटर लाया, उसके बाद थाना प्रभारी ने पीड़ित को बुलाया तो उसने फिर से डराया, धमकाया कि तुम्हारी बेटी की बेईज्जती होगी, जबकि वह अपने बेटी की बेईज्जती के लिए तैयार था । मेरे विधान सभा में यह घटना हुई है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगातार एक बेटी को शोषित किया जा रहा था । मैं भी एस.पी. के पास गई थी कि इसमें कार्रवाई एवं एफ.आई.आर. दर्ज होना चाहिए । वह व्यक्ति दो महीने से घूमता रहा, उसके बाद उस पिता ने आत्महत्या कर ली । यह घटना 15 दिनों पहले की बात है, वह बाप अपनी बेटी के सामने डायरेक्ट आत्महत्या कर लिया। यह पुलिस प्रशासन है । ऐसी सरकार को लज्जा आना चाहिए, जो बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकता । नवरात्रि के समय में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप होता है । गृहमंत्री के क्षेत्र में एक युवा बेटी के साथ नवरात्रि के 6वें दिन रेप होता है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । आज अनुपूरक पर चर्चा हो रही है । अगर इतिहास की बात करेंगे तो अपराध और अपराधियों को संरक्षण पिछले 5 साल के कार्यकाल में किसने दिया, कैसे किया, इस पर बात आनी चाहिए ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी आपको अनुपूरक याद आ गया ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आपकी सरकार कैसे-कैसे काम कर रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आपकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो क्यों पैसा ले रही है, हम अनुपूरक में पैसा क्यों देंगे ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओं योजना थी, उसमें क्या हुआ (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोग चाहते हैं कि बेटियों के साथ अन्याय होता ही रहे ।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप लोगों ने 5 साल में क्या किया, उस पर कभी जवाब दीजिए । आपने अपराध और अपराधियों को संरक्षण दिया । आपके समय में थाने नीलामी पर थे, भू माफियाओं को संरक्षण था । आप क्या बात करते हैं ?

श्री दिलीप लहरिया :- आपकी सरकार ने क्या किया ?

श्री सुशांत शुक्ला :- आपके पदाधिकारी क्रिमिनल लिस्ट की सूची में थे ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- आप खुद चाह रहे हैं कि यहां के बेटियों के साथ अन्याय हो । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- पिछले 5 साल के कार्यकाल में अपराध और अपराधियों का संरक्षण करना कांग्रेस का एक मात्र उद्देश्य रहा । यह बात आज होनी चाहिए, लेकिन मैंने प्वाइंट आफ आर्डर चाहा है । अगर अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है तो उसी विषय पर केन्द्रित रहें, यह आपसे मेरा आग्रह है ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- संगीता जी महिलाओं के लिए किए गए अनुपूरक प्रावधान पर बोल रही हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, आपने खूब सारी बातें की, आपने खेलकूद की बात की, क्या वह अनुपूरक में आ सकता है ? जब हम अपनी बात रख रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- एक मिनट । आप सभापति जी की ओर देखकर बोलिएगा, इधर डायरेक्ट बात मत करिए । सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्यगण यहां पर जो अपनी बात रख रहे हैं, वह विभागीय डिमांड मांग के अनुसार अपनी बात रख रहे हैं । आप अपनी बात अनुपूरक बजट पर रखिए । सभापति जी, आपसे भी आग्रह है कि सदस्यगण समय-सीमा में अपनी बात रखें । अगर राजनीतिक भाषण है तो राजनीतिक दृष्टि से सबको समय दिया जाये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, आप बहुत बढ़िया बोल रही हैं, इसमें दो मत नहीं है (हंसी) मैं पीछे बैठे-बैठे सुन रहा था कि आपने बिजली की समस्या के बारे में बताया कि आपके घर में मेहमान आये थे.

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मेहमान मेरे क्षेत्र में आये थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप सबकी समस्या का निराकरण कोर्सेवाड़ा जी कर चुके हैं । कोर्सेवाड़ा जी का टेप सुन लेना, रात को कोई तकलीफ नहीं होगी । आपने टेप सुना है या नहीं ? सुना है न । कहां समस्या में उलझ रही हैं । सभी समस्याओं का हल कोर्सेवाड़ा का टेप है । (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की बहुत सारी बातें हैं, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं । मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इतने कम दिनों का सत्र होता है, तीन दिनों का सत्र है । हम बोलें तो बोलें किसमें ? हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं।

श्री केदार कश्यप :- आपको बोलने के लिए प्रथम दिन ही आमंत्रित किया था कि आप प्रथम दिन आकर फ्री स्टाइल में बोलिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, ने उसके लिए व्यवस्था दी थी। आप उस दिन नहीं आये। क्योंकि आप लोगों का छत्तीसगढ़ के प्रति विजन नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप भाषण तो अचछा दे रही हैं, परन्तु एक टेक्नीकल फाल्ट है। आप सुशांत की तरफ देखकर बोल रही हैं तो वह बार-बार उठ रहा है। आप उधर देखिये न, सुशांत की तरफ देखोगे तो वह इधर-उधर दौड़ने भी लगेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भईया, सुशांत को भी बोलिये कि इधर मत देखें।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बोलिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मेरा कहने का मतलब यही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या है कि सुशांत के आंख के सामने हैं तो वह क्यों नहीं देखेंगे। लेकिन इनको उधर देखना है। अब वह उल्टा दिशा में देख रही हैं तब तो झंझट, बखेड़ा खड़ा होगा ही।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मोहले जी की तरफ देखने के लिए कह दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मेरा बस एक ही निवेदन है कि हमारे क्षेत्र की जनता पुलिस प्रशासन से बहुत परेशान है। क्योंकि हम दर-दर भटकते हैं।

श्री अनुज शर्मा :- अनुपूरक बजट मा पुलिस ला काबर लावत हव भाई, बजट के बात ला करव तेन हा सोलह आना ए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- क्योंकि पुलिस प्रशासन को आधुनिकीकरण करने के लिए बहुत सारा बजट दिया है, यह आपके अनुपूरक में है।

श्री सुशांत शुक्ला :- यानि आप पुलिस के आधुनिकीकरण करने का विरोधी हैं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने पर विरोध करती हूं। आप बेटी को नहीं बचा पाये।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ साथी बतायें कि क्या पुलिस का आधुनिकीकरण नहीं करना चाहिए ?

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बैठिये। कृपया समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं चाहती हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में व्यवस्था हो, ताकि हम महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित रख सकें। मैं इस बात के लिए आवाज उठाना चाहती हूं। आपका ही नारा है " बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" लेकिन अगर मैं आज के परिवेश में देखूं तो यहां पर बेटियां सुरक्षित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि इस अनुपूरक में मेरे यहां के लिए भी बजट है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अम्बेडकर हास्पिटल के लिए बजट आया है तो आप उसको जरूर बजट दीजिये। हमारे पास पेशेन्ट आते हैं और जब भी हम अम्बेडकर हास्पिटल में फोन करते हैं तो वहां बेड ही नहीं रहता है। मेकाहारा में भी यही स्थिति रहती है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मेरा एक आग्रह है। माननीय नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी भी हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय में सुपरस्पेशयालिटी हास्पिटल बिलासपुर में दिया था। वह सन् 2017 में बनते-बनते रह गया था। यह 5 साल तक पूरा नहीं कर पाये। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो एम्स की मांग कर रहे हैं। एम्स किसने दिया ? भारत सरकार ने दिया। सुषमा स्वराज के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि किसने दिया था ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नेहरू जी ने दिया था।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप 5 साल तक प्रधानमंत्री जी को गेस्ट्रोलॉजी पद के लिए एक पत्र नहीं लिख पाये। मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी एम्स बनवाया था।

श्री अनुज शर्मा :- सभापति महोदय, मैडम छत्तीसगढ़ के एम्स के बात चलत हे।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं छत्तीसगढ़ रायपुर के एम्स की बात कर रहा हूं। 5 साल तक गेस्ट्रोलॉजी पद के लिए आग्रह नहीं कर पाये और यह बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- हां, चलिये बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, मेकाहारा है, जहां हम गरीबों का ईलाज करवाने के लिए भेजते हैं। वहां पर उचित डाक्टर, उचित व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो। आप अम्बेडकर हास्पिटल जाकर देखिये, आप वहां पर कदम नहीं रख पायेंगे। वहां तो बीच में पत्रकारों को मारा-पीटा गया था। (शेम-शेम की आवाजें) यह बहुत लज्जा की बात है। अंदर की बात को उजागर करने का काम हमारे देश का जो चौथा स्तम्भ मीडिया है, करता है। उन लोगों के साथ मारपीट किया गया था। क्योंकि वहां की व्यवस्था को उजागर करने काम मीडिया के लोग कर रहे थे। सभापति महोदय, जो आवाज उठाता है उसको यह सरकार दबाने का काम करती है।

आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहना चाहूंगी कि आपने ऐसा कोई सरकार देखा है जो स्कूल बंद कर दें। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार है, जिसने बहुत सी स्कूलों को बंद किया है। यहां पर युक्तियुक्तकरण किया है। यहां पर शिक्षा विभाग को अनुपूरक में बजट दिया गया है। वित्त मंत्री जी सामने बैठे हैं, सहायक शिक्षक लोग मेरे पास आवेदन देने आये थे। सहायक शिक्षक लोग सभी मंत्री और विधायकों को वेतन विसंगति दूर करने के लिए आवेदन देने आये थे। वित्त मंत्री जी, आप कृपा करके इनका उद्धार कर दीजिये ताकि ये लोग भी थोड़ा संभल जाये।

सभापति महोदय :- समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, दो मिनट लूंगी। ज्यादा समय नहीं लूंगी, दो मिनट में अपनी बात खत्म करती हूं। शिक्षा के क्षेत्र में गुरू को भगवान मानते हैं। हम भगवान से बढ़कर गुरू को मानते हैं। भगवान से बढ़कर हम गुरु को मानते हैं और आजकल गुरुओं की स्थिति आप देखे हैं, कुकुर गिन रहे हैं। कुकुर गिनती कर रहे हैं। यह मैं नहीं कह रही, यह आपके प्रोटोकॉल में आया। सब जगह आदेश आया है कि आपके यहां कितने कुकुर हैं। सभापति महोदय जी, ये क्या है? आप शिक्षक को कुकुर को (हंसी) मतलब उसके बाद..।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिपालन की व्यवस्था है, अगर उस पर भी चर्चा होती है तो इसमें मैं आपत्ति ले रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, गुरुओं का सम्मान करना सीखिए। आप गुरुओं का सम्मान करना सीखिएं। वे शिक्षा के मंदिर हैं। (व्यवधान) हम 2047 की बात करते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं आपत्ति ले रहा हूं। यह बिल्कुल गलत बात है। शासन उच्चतम न्यायालय के आदेश का परिपालन कर रह है। उस पर चर्चा न की जाये। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- क्या शिक्षक गिनेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, ये मेरे समय को ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह आदेश है क्या कि शिक्षक गिनेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारे साथी 2047 की बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है। स्कूल में दो टीचर हैं। एक टीचर एस.आई.आर. कर रहा है और एक टीचर पूरा फाइल तैयार कर रहा है। बच्चे क्या करेंगे? दो टीचर हैं दो। उसमें आप एक एस.आई.आर. में लगा दिए हो आप और एक टीचर को किसमें लगाए हो, पूरा फाइल बनाने में। सभापति महोदय, पढ़ाएगा कौन? ये 2047 की बता कर रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, जैसे पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में खुद पढ़ाए हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं दो मिनट में बात रखूंगी।

श्री आशाराम नेताम :- सुनिए, शिक्षा को गांव से शहर की ओर लायें, उस दिन चिंता नहीं हुआ क्या?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमने आत्मानंद लाया था। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- आपने आत्मानंद लाया, लेकिन आपने सेटअप नहीं दिया। आपने वित्त का प्रावधान नहीं किया और आपने आत्मानंद स्कूल लाये थे। इधर की ईट, इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमने आत्मानंद स्कूल लाया था ताकि गरीब के बच्चे उसमें पढ़ें। (व्यवधान) हमने गरीब के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा दी थी। (व्यवधान) आप महिला सुरक्षा की बात करते हो। हमने महिलाओं को स्वालंबन बनाने का काम हमने किया। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- संगीता जी, ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। (व्यवधान) सभापति महोदय, ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में ठगा नहीं। आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं को स्वालंबी बनाये हैं। बताउं क्या किसको-किसको स्वालंबी बनाये हैं। सिर्फ माता दरबार को स्वालंबी बनाये हैं। एक वंशीय परिवार की चरण वंदना में 5 साल तक पूरा संसाधन आपने समर्पित कर दिया था।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, बैठिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, ये सरकार जो है, वह किसान विरोधी सरकार है। यह सरकार महिला विरोधी सरकार है। यह सरकार युवा साथी विरोधी सरकार है। ऐसी सरकार को मैं नहीं चाहती कि इतना सारा बजट दिया जाये, इसका घोर से घोर, घोर, घोर विरोध करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। सभापति महोदय जी, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा जी।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- धन्यवाद, सभापति महोदय जी, मैं अपनी बात की शुरुआत इसी से करूंगी कि जो अनुपूरक बजट है, वह इतिहास का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट के रूप में शामिल किया गया है। विषय बहुत सारे थे, लेकिन कुछ विषय जो हमारी माननीय सदस्या ने या अन्य सदस्यों के माध्यम से आये, विशेषकर जो सामने बैठे हैं, उन विषयों पर दोषारोपण तो नहीं करूंगी, लेकिन कुछ इतिहास की बातें मुझे लगता है कि आज के विषय को सुनकर एक बार चर्चा करना जरूरी है। सभापति महोदय जी, जब बात आती है महतारी वंदन योजना की, जब भी पिछले दो बजटों में जब हमने देखा कि लगातार महतारी वंदन को लेकर विपक्ष ने कभी उसकी सराहना नहीं की। आज हम किसी भी सभा में जाएं, वोटर्स चाहे किसी के भी हों, किसी को भी वोट दें, लेकिन महतारी वंदन योजना का लाभ जिन भी महिलाओं को मिल रहा है, हर भरी सभा में उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है, मुझे लगता है कि

विष्णु देव साय जी की सरकार के लिए वह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनको इस बात की संतुष्टि है कि महीने के हजार रुपए हमारे खाते में आ गए। (मेजों की थपथपाहट) विपक्ष ने कभी भी इस बात की सराहना नहीं की, जो बहुत आश्चर्य की बात है। सभापति महोदय, दूसरा विषय महिला सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। महिला सुरक्षा पर मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे सरकार किसी की भी हो, निश्चित ही महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। चाहे महिला के साथ एक कोई घटना हो या 100 घटना हो, हम सब उसको एक ही चश्मे से देखते हैं जो कि यह घटना गलत है, लेकिन महोदय, चूंकि छींटाकशी हो रही है तो अगर एक उंगली यहां दिखाएंगे तो तीन उंगली विपक्ष में भी जरूर उठेगी। मैं थोड़ा सा इतिहास दोहराना चाहूंगी, जिस समय हमारी विधवा बहनें अनुकंपा नियुक्ति की मांग करके रायपुर के ही एक ग्राउंड पर एक मैदान पर लगातार एक डेढ़ महीने तक जब बैठीं, उन्होंने अपना बाल मुंडन करवाया तो उस समय जिसकी सरकार थी, जिन्होंने जरा भी उस विषय पर संज्ञान नहीं लिया मुझे लगता है मेरी सदस्या बहनें हैं, खासकर उनको इस विषय की चिंता होनी चाहिए कि अगर इस सरकार का आप आंकड़ा उठाएं और अपनी सरकार का आप आंकड़ा देखें तो जिस तरीके से महिलाओं पर उस समय अत्याचार हुआ, शायद उसकी गिनती मैं यहां करना भी नहीं चाहूंगी क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि चाहे एक महिला के साथ अत्याचार हो, चाहे सारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो, वह पूर्णत: गलत है। दूसरा विषय यह आया कि स्कूल में टीचर्स कुकुर गिन रहे हैं। इस बात से मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगी। शिक्षकों की स्थिति यह थी कि एक समय में बच्चियां क्लास रूम में नहीं मिलती थी। हम लोग उस समय विपक्ष में थे। जब हम दौरे पर जाते थे तब देखते थे कि स्कूल में कितनी बच्चियां आई हैं और टीचर्स अपना सिर पकड़ कर बोलते थे कि चूंकि गोबर खरीदी चल रही है तो गांवों की बच्चियां गांव की पुस्तक-कापी अपनी क्लास में छोड़ कर गोबर बिनने गयी हैं। उनके माता-पिता को गोबर से कमाई हो रही थी। बच्चों की शिक्षा पर तब फर्क पड़ा था। यह विषय ध्यान रहना चाहिए। बहुत खुशी एवं वर्ग की बात है कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं, वह कलेक्टर रह चुके हैं। जब वे कलेक्टर थे, तब उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े-बड़े माईल स्टोन सेट किया था और उसी का परिणाम है और उसी का दर्पण है कि कहीं न कहीं हमें अपुनूरक बजट में 35 हजार करोड़ रूपये देखने को मिल रहा है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, मैं फिर से इतिहास की बात करूं तो जिस समय गोबर खरीदी होती थी, उस समय स्थिति यह थी कि कलेक्टर और जिला पंचायत सी.ई.ओ. को गोबर कलेक्शन का टारगेट दिया जाता था। वे टेंशन में रहते थे कि हमारा आज के दिन का, आज के महीने का गोबर कलेक्शन पूरा नहीं हुआ तो हम सरकार को क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है कि जब चर्चा हो तो उन विषयों में भी चर्चा होनी चाहिए कि जब आरोप-प्रत्यारोप होते हैं तो दोनों साईड में छींटाकशी आती है। अब बहुत सारे ऐसे विषय हैं, लेकिन मैं एक बात बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूं कि अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जिनकी नीति और नीयत, दोनों साफ है। नीयत में कहीं कोई

खोंट नहीं है। नीति में अगर कोई 19-20 का विषय आता है तो विपक्ष उस पर चर्चा के लिए आमंत्रित था। जिस दिन शीतकालीन सत्र की शुरूआत हुई, उस समय चर्चा के लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे विधान सभा अध्यक्ष जी ने एक दिवस का विशेष सत्र बुलाया था, उसमें पूरे विपक्ष के सदस्यों को शामिल होना चाहिए था। पता नहीं कि जो परंपरा है, उसको निभाने के लिए उनको क्या तकलीफ है। जिस तरीके से जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, पहले दिन जब लोक सभा का सत्र हुआ था, उस दिन विपक्ष नदारत थी। जब यहां पर नये विधान सभा में सत्र की शुरूआत हुई, जब विज़न 2047 पर चर्चा होनी थी, उस दिन भी विपक्ष नदारत थी। जब परंपरा ऊपर से नीचे तक चलती आ रही है तो कहीं न कहीं वह शायद इनके अंदर बस चुका है, जिससे वह बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इतनी सारी विषयों में इतने सारे अनुपूरक बजट में इन्हें दिखी है तो सिर्फ कमियां दिखी है। क्योंकि लगातार सदस्य बोल रहे थे, तब हमें विश्वास था कि वे कहीं न कहीं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे कि आपका यह विषय का बजट अच्छा है। अब चार गिनती गलत हो सकती है, लेकिन कोई एक सदस्य बोलते कि आपने अच्छा काम किया है। हम महतारी वंदन योजना की बात कर रहे थे। 280 करोड़ रूपये सिर्फ महतारी वंदन योजना के लिए दिया गया है, जोकि सरकार के बजट का बहुत बड़ा हित्सा है, जो सिर्फ महिलाओं को समर्पित है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वह योजना सिर्फ कागज में नहीं रह जाती है। रेडी टू ईट का काम नहीं छीना जाता है, बल्कि उसको जिलेवार डिस्ट्रीब्युट किया जाता है। कागज की जो योजनाएं हैं, चाहे मैं महतारी वंदन योजना के माध्यम से बात करूं, चाहे मैं रेडी टू ईट के जरिये बात करूं, आज महिलाओं के घर के चौखट तक यह योजनाएं पहुंच चुकी हैं। मुझे लगता है कि कम से कम इस विषय पर हमारे मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और सरकार को विपक्ष के साईड से पीठ थपथपानी चाहिए थी, जिसका उम्मीद हम नहीं करते हैं। चूंकि हम साथ बैठते हैं तो एक उम्मीद रहता है कि कभी तो प्रशंसा होगी। सभापति महोदय, उसके अलावा अगर हम नई उद्योग नीति की बात करें तो लगभग 79 करोड़ 65 लाख रूपये नई उद्योग नीति के लिए खुला है। कल भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो रही थी कि रोजागर का कितना पंजीयत हुआ? बेरोजगारी भत्ता कितना दिये? जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बेरोजगारी भत्ता के नाम पर जिस तरीके से कभी कांग्रेस युवा कमेटी को, कभी और कमेटी का भरण-पोषण होता था, वह सब बात हमसे छिपी नहीं है। जिस तरीके से हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने नीति के लिए इतना बड़ा बजट उद्योग रखा है तो निश्चित ही एक सराहनीय है। हर जगह उद्योग पार्क की स्थापना लगातार हो रही है। उद्योग क्षेत्र लगातार बढ़ाये जा रहे हैं, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। अब हमारे युवा नौकरी मांगने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि नौकरी देने की डेव्हलपमेंट की जो परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थिति में हमारे युवा आने वाले हैं। अगर नक्सली प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो 397 करोड़ 76 लाख रूपये नक्सली प्रभावित क्षेत्रों को मिला है। कहीं न कहीं जब हम 31.03.2026 की बात करते हैं,

जहां हम सोचते हैं कि नक्सली पूरे समाप्त हो जायेंगे, उस स्थिति में आने के बाद आप सरकार की योजना एवं दूरदर्शिता को सोचिए कि इतना बड़ा बजट का पैकेज हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को जा रहा है। चूंकि वहां पहले रोड बनते थे तो नक्सलियों को द्वारा रोड को ध्वस्त कर दिया जाता था, स्कूल बनते थे तो स्कूल को बर्बाद कर दिया जाता था, हॉस्पिटल बनते थे तो हॉस्पिटल को भी बर्बाद कर दिया जाता था। उसके विकास के लिए बहुत बड़ा बजट स्कूल से लेकर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से लेकर शिक्षा जैसी बहुत सारी चीजों में यह आगे गति देने वाला है । हम कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य की बात करते हैं, अभी एम्स और मेकाहारा की बहुत चर्चा हो रही थी । हमें ध्यान है कि एम्स और आई.आई.टी. जैसे इंस्टिट्यूट्स हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में ही छत्तीसगढ़ में आये हैं । कोविड का समय हम सब लोगों ने देखा है, हमारे विपक्ष के साथियों ने निश्चित रूप से वहां स्वास्थ्य लाभ लिया होगा । उसमें थोड़ा प्रोत्साहन होता तो हमें लगता कि चलिये ठीक है, उस समय सरकार थी तो आज की नहीं तो उस समय की तो कम से कम सराहना करते ? सभापति महोदय, यह उम्मीद भी बेकार थी, यहां बहुत सारे विषय मुझसे पहले भी माननीय सदस्यों ने लिया है, लेकिन कुछ विषय है कि मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते ध्यानाकर्षण कराना चाहिये । सभापति महोदय, महतारी वंदन योजना का लाभ निश्चित ही बहुत दूरगामी परिणाम देगा । यदि हम इसको वित्तीय साक्षरता से जोड़ देते हैं, पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर उसकी कार्यशाला हम लगाते तो कहीं न कहीं ग्रामीण महिलायें उसमे अपने आने वाले भविष्य को, चाहे बचत के रूप में, चाहे बीमा के रूप में, एक सिस्टम उनके अंदर डेवलप होगा कि ऐसे में कुछ बचत करके बहुत सारी बीमा पालिसी आती है, जो सौ-दो सौ-तीन सौ रूपये से चालू हो जाती है, उनको उसका लाभ मिल सके । सभापति महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह था कि औद्योगिक नीतियां बहुत अच्छी है, नई औद्योगिक नीतियॉ निश्चित ही बहुत सराहनीय है, लेकिन कुछ जो वंचित क्षेत्र अभी हैं, जब औद्योगिक क्षेत्र हम तय करते हैं, अगर रायपुर के आसपास की हम बात करें तो तिल्दा, उरला, सिलतरा, जहां जमीन बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है । यहां निश्चित रूप से नये उद्योग लगने वाले हैं, यदि हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहां जो 90 विधान सभा है, अगर 10 विधान सभा आपके अर्बन में आते हैं तो 80 आपके रूरल में भी आते हैं। उन औद्योगिक क्षेत्रों के लिये भी ब्लॉक स्तर पर जमीन उपलब्ध कराना, इसके साथ ही एप्रोच रोड, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कराना, इस पर भी ध्यान देना चाहिये। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट में फोकस है, रोजगारमूलक जो मेले लगते हैं, उनको भी और नई उद्योग नीति को भी लघु उद्योग तक पहुंचाना मुझे लगता है कि अवेयरनेस के लिये बहुत जरूरी है । सभापति महोदय, जब हम विजन 2047 पर चर्चा कर रहे थे तो यह कहा था कि निश्चित रूप से 5 नये मेडिकल कॉलेजों को स्वीकृति मिली है, लेकिन जहां मेडिकल कॉलेज है उसके आसपास नर्सिंग कालेजों की स्वीकृति मिले । मुझे लगता है कि जरूर इसको शामिल करना

चाहिये । इसके अलावा जो हम पीएससी और सीएससी की बात करते हैं, आज भी वहां प्राथमिक चीजों की, चाहे वह डिलिवरी के समय गरम पानी के व्यवस्था की बात हो, सोनोग्राफी मशीन की बात करें, एक्सरे मशीन की बात करें, आज भी उसकी कमी है । मुझे लगता है कि इसकी जानकारी उपलब्ध कराके, प्रमुखता से इस विषय पर चर्चा हो तो काफी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा ।

सदन की सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्यवाही की सूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूँ कि सभा इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्रीमती भावना बोहरा :- सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा से आती हूँ, वहां की कुछ मांगे हैं जिसमें प्रमुखता से हर बार मैंने चर्चा की है और उन विषयों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगी । हम जिस पंडरिया क्षेत्र से आते हैं, उसकी आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा वनांचल क्षेत्र, ट्राईबल बेल्ट है, जहां हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, बैगा समुदाय है, वे आज भी बिजली और पानी की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जहां तक हम विजन 2047 या 2030 की बात करें तो वह क्षेत्र अछूता न रह जाये । मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि उसका सर्वे कराकर उन तक पानी और लाईट की व्यवस्था हो जाये तो उचित होगा । ऐसे 30 से 40 गांव आते हैं, जहां इन सुविधाओं का अभाव है । पंडरिया जहां से हम आते हैं, मैकाल पर्वत है । मेरी इस बात से धर्मजीत भईया भी सहमत होंगे, यह बहुत खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है । सरकार जिस तरह से पर्यटन को, लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने की बात कर रही है तो यह क्षेत्र भी उस ओर अग्रसर हो सकता है । मैंने पहले भी निवेदन किया था कि भैंसाओदार और दीवान पटपर इन दो जगहों को पर्यटन की दृष्टि से, लॉजिस्टिक के हिसाब से यहां पर डेवलपमेंट हो । दीवान पटपर का सर्वे दिल्ली से भी कई बार हो चुका है, मीडिया ने बहुत कव्हरेज भी किया है, जैसे हम मैनपाट में उल्टापानी की बात कर रहे थे, उसी तरह से वह एक मैदान है, वहां पर आप बिना ब्रेक लगाये गाड़ी या गाड़ी बंद भी करेंगे तो वह सीधा ऊपर चढ़ती है । आपको न एक्सीलेटर देना है या कुछ भी नहीं, गाड़ी डायरेक्ट ऊपर जाती है, पता नहीं वहां पर ऐसा क्या नीचे है, उसकी भी जांच भी लगातार हो रही है, ऐसे स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है कि वहां के स्थानीय लोगों को भी बहुत बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। सभापति महोदय, इसके अलावा एक मांग

और है, मैंने पांडातराई और बाजारचारभांठा में आई.टी.आई. के लिए पहले भी विषय रखा था, मैं आज भी वही निवेदन करूंगी, क्योंकि ये क्षेत्र युवाओं से घिरा हुआ क्षेत्र हैं, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं, हम स्कील डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, उस दृष्टि से वहां पर अभी तक आई.टी.आई. नहीं खुला है, मैं उसकी एक मांग करती हूं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित अन्य विभाग का धन्यवाद करूंगी कि कुगदुर कॉलेज की स्वीकृति इस अनुपूरक बजट में दी गई है, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करती हूं, ये बहुत पुरानी मांग थी। सभापति महोदय, जब हम पंडरिया जाते हैं तो मुझे बहुत से सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से बोला है कि आपके पंडरिया के सड़कों की हालत बहुत खराब है, कई वीडियो भी बने हैं, मैं उसके लिए हमारी सरकार की अभिनंदन करूंगी कि बिसेसरा पुल से लेकर हरिनाला तक लगभग ढाई किलोमीटर की सड़क को फोरलेन बनाने की स्वीकृति इस अनुपूरक बजट में मिली है, उसके लिए भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूं। यह अनुपूरक बजट हमारी सरकार लेकर आई है, बहुत अच्छा विज़न के साथ लेकर आई है, निश्चित ही यह बहुत सराहनीय बजट है, हम सब इसकी प्रशंसा करते हैं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। कुंवर सिंह जी, अपनी बात जल्दी रखिएगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुंडरदेही) :- सभापति महोदय, सभी लोगों ने बोला है। माननीय वित्त मंत्री जी ने 35 हजार करोड़ रूपए का जो अनुपूरक बजट लाया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं विरोध में बोलने के लिए इसलिए खड़ा हूं, क्योंकि इस बजट में दिख कुछ नहीं रहा है, केवल मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिख रहे हैं और दिखाया जा रहा है। सभापति महोदय, इसमें बड़ी-बड़ी बात, बड़ी-बड़ी योजनाएं दिख रही है, मैं यही कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से यह सरकार नशामुक्ति की बात कर रही है, इस बजट में नशामुक्ति के लिए 9 करोड़ 35 लाख का प्रावधान किया गया है और होलोग्राम के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। आप शराब दुकानों में अनलिमिटेड बिक्री कर रहे हैं, ये डबल पॉलिसी क्यों है ? आप एक तरफ नशामुक्ति की बात करते हैं, उसके बाद अनलिमिटेड शराब बिक्री की बात कर रहे हैं। ये दो-दो पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। अब तो नशे का कारोबार अड्डा बन गया है, अमूमन लगभग हर गांव में अवैध शराब की बिक्री हो रही है और घर-घर पहुंच सेवा है। शराब की बात आती है तो मैं एक विषय ध्यान में लाना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम अर्जुन्दा में मेरे घर से 100 मीटर दूर, मेरा घर, उसके बाद एक घर, उसके बाद ब्यारा है, मेन रोड में साढ़े आठ से पौने 9 बजे के बीच दरमियान रात को एक युवक दुर्गेश देवांगन की हत्या हो जाती है, सी.सी.टी.वी फूटेज में दिख रहा है, उसने 8 दोस्तों के साथ बैठकर बाहर में शराब पी, ये शराब के नशे के कारण अपराध का गढ़ बन रहा है, इसे रोकना चाहिए। इसके होलोग्राम के लिए न ही पैसा दी जाए। नशामुक्ति की बात कर रहे हैं तो नशामुक्ति की तरफ चलना चाहिए। आप लगातार शराब दुकान खोल रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, डोंगरगढ़ में नकली शराब और नकली होलोग्राम का जखीरा पकड़ाया, अभी गुंडरदेही में मिलावटी शराब पकड़ाया। वहां दुर्ग की टीम जाकर छापा मारी, 12 बोतल अंग्रेजी शराब मिलावटी पाई गई, उसके बाद तुरंत उसके सुपरवाईजर को हटा दिया गया, खानापूर्ति कर दी गई, उसे तत्काल सेवा से हटा दिया गया, अवैध शराब की बिक्री लगातार चल रही है। अभी आपका विभाग पकड़कर केवल खानापूर्ति कर रहा है। पुलिस भी पकड़कर खानापूर्ति करती है। केवल एक औपचारिकता निभा रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा यदि किसी में हिम्मत हैं तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि कहां-कहां पर खुले रूप में अवैध शराब की बिक्री चल रही है। सबसे बड़ी बात, हल्दी में जहां नया शराब दुकान खुला है, वहां पर पंच, सरपंच ने विरोध किया, मैं प्रस्ताव नहीं दूंगा तो उस सरपंच को अपने पद से हाथ धोना पड़ा, उस सरपंच को पद से हटना पड़ा। ये स्थिति है, सरकार सरपंचों के उपर कितना दबाव डाल रही है, यहां शराब दुकान खुलेगी, आप प्रस्ताव दीजिए, जब उन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया तो दबाव डाला गया, इसका उदाहरण ग्राम हल्दी के सरपंच को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और शराब के कारण वे पदच्युत हो जाते हैं। ये स्थितियां निर्मित हैं जो शराब के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- निषाद जी, यह जो आप कागज रखे हैं, उसमें सुन-सुन कर लिखे हो या तैयारी करके आये हो?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं अभी सुन-सुन के लिखत रहे हव।

श्री अजय चंद्राकर :- ये लोग बोल रहे थे, उसको यही सुन-सुन कर लिखे हो?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी। सबो डहार के ला सुन-सुन के लिखे हो। आप ओ के ला घलो सुने हो।

श्री अजय चंद्राकर :- मोर ला छोड़ या तैयारी करके आये हो?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, मैं सुनत हो अउ इही करा लिखत जात हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अउ जो तैयारी करके लाए रीहिस हे, ओला तो तेहा बोल डाले हस। बीच में टोका-टिप्पणी होइस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, मैं इहीच करा बोलहूं करके अपन लिखे हो। सभापति महोदय, कृषक उन्नति योजना की बात हुई तो आपने बहुत बड़ी बात की कि धान खरीदी पर लगभग 12 हजार 2 सौ करोड़ रूपये की राशि आप धान उपार्जन में हुई क्षतिपूर्ति के लिए ले रहे हैं। आपका धान उपार्जन केन्द्र में सड़ रहा था, इसके लिए नेता प्रतिपक्ष जी ने लगातार 1 साल तक पत्र व्यवहार किया। वह राज्यपाल जी को आपके पत्र के माध्यम से अवगत कराते रहे, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया और सदन में बोलते हैं कि कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। मंत्री जी का भी बयान आता है कि कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वित्त मंत्री जी अपने भाषण में इसको जरूर बताएं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि नुकसान

नहीं हुआ है। मंत्री जी सदन में स्वीकार कर रहे हैं कि नुकसान नहीं हुआ है, फिर आप इतनी राशि की मांग क्यों कर रहे हैं? उसका उदाहरण माननीय संगीता जी ने भी बताया।

श्री अजय चंद्राकर :- ते कहिबे अउ स्वीकार कर लीही। ते बोलत हस, तेन सच हे। ते जे बात करत हस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं बिल्कुल सही बात बतात हो। बिल्कुल करेल लगही। अगर गलत है तो स्वीकार करेल पड़ही।

श्री अजय चंद्राकर :- अइसे स्थिति नहीं हे कि ते कहिबे अउ ओ स्वीकार कर लीही। मंत्री जी स्वीकार करे, मंत्री जी स्वीकार करे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बिल्कुल वही स्थिति है क्योंकि बालोद की बात आई है। मैं आपको धोबनपुर और जगतारा का बता देता हूं कि 9 करोड़ 97 लाख।

श्री अजय चंद्राकर :- ते लिख के दे दे कि मंत्री जी हा का-का ला स्वीकार करही। हटा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- नहीं, लिख के काबर दुहूं। मैं बोलिहो, तब तो पता चलही कि का होवत हे।

श्री अजय चंद्राकर :- ते लिख के दे दे कि का-का स्वीकार करना हे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, 43 हजार 235 क्विंटल धान का शॉर्टेज आया है। अभी फुण्डर, मालिखोरी का और बचा है। उसमें भी जांच चल रही है। उसमें भी बड़ी हेरा-फेरी का मामला अभी सामने आने वाला है। फिर यह इतनी बड़ी राशि की मांग क्यों कर रहे हैं? साथ ही अप्रैल, 2026 तक केन्द्रीय पूल में चावल जमा की अनुमति की अवधि बढ़ाई गई है। एफ.सी.आई. में जगह नहीं है। यह जो विलंब हो रहा है तो हमने जो धान खरीदी के लिए हजारों-करोड़ों रूपये का लोन लिया है, उसके ब्याज का भार कब तक हमारे ऊपर आएगा? आपने जो लोन लिया है, उसकी अप्रैल तक आपने अवधि बढ़ाई तो उसके पूरे ब्याज का भार हमारे ऊपर आएगा। गलती आपकी और भुगते प्रदेश की जनता। यह उचित नहीं है। इन्हीं सब कारणों से स्टेट बजट का भार बढ़ते जा रहा है। आप अपनी इज्जत छिपाने के लिए कर्ज पर कर्ज लिये जा रहे हैं और हमारे प्रदेश की जनता पर सीधा भार आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 लाख मीट्रिक टन की नीलामी से 3500 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है और केन्द्रीय पूल में चावल जमा नहीं लेने के कारण हमको अतिशेष धान आधे दाम पर नीलामी के द्वारा बेचना पड़ा है। इस पर आप बात नहीं करेंगे। पंजाब में तो डबल इंजन की सरकार नहीं है। वहां तो आपकी सरकार है उसके बाद भी 143 लाख टन पूरा चावल केन्द्रीय पूल में लिया गया है। वहां तो आपकी सरकार है। यहां तो डबल इंजन की सरकार है उसके बाद भी यहां वाले चावल को केन्द्रीय पूल में नहीं लिया जा रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? माननीय अजय चंद्राकर जी, वर्ष 2003 से 2018 तक कुल कितने पेड़ कटे? पूर्व में जो पेड़ कटे हैं, उसका लैण्ड डायवर्सन आपकी सरकार के समय हुआ था। वर्ष 2003 से 2018 तक

कितने हजार, कितने लाख पेड़ कटे हैं, यदि हम उसकी बात करे तो उसका लैण्ड डायवर्सन भी आपकी सरकार के समय हुआ था। हमने तो उसको रोक दिया था। हसदेव अरण्य की बात आई। माननीय धर्मजीत भैया ने अशासकीय संकल्प लाया था, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था। मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने शपथ नहीं ली थी और 11 तारीख को चुपके से उसे काटने की अनुमति दे दी जाती है और हसदेव अरण्य की कटाई प्रारंभ कर दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी 17 तारीख को शपथ लेते हैं, लेकिन आदेश 11 तारीख को निकल जाता है। यह अच्छी बात नहीं है। आप 5 साल का बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अब मैं प्रदेश की अन्य बातें करूं तो पंचायत की बात पर आऊं तो आज मनरेगा का कार्य पूरी तरह से ठप्प हुआ है। साल भर से मनरेगा के काम बंद हैं, लोग बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, मैं आप से यह कहना चाहूँगा कि जो पंचायत आज 15वें वित्त की राशि के लिए आंख देख रहा है, बांट जो रहा है कि कब हमारे 15वें वित्त की राशि आयेगी तो हम विकास का काम करेंगे लेकिन आपने बढ़िया सुशासन तिहार मनाया और ये आयोजन सरकार का था, लेकिन आपने राशि पंचायत से ली। आपने एक-एक पंचायत से 10 हजार, 15 हजार रुपए की राशि ली और आपने वह सुशासन तिहार मनाया। आज भी पंचायतों के पास एक रुपए नहीं है। हमारे यहां गुंडरदेही ब्लॉक में तीन दिन पहले पूरे सरपंच संघ के लोग 15वें वित्त की राशि, मानदेय और अन्य चीजों को लेकर धरना दिये थे। यह स्थिति चल रही।

माननीय सभापति महोदय, दिव्यांगजनों पर बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी और मैंने पिछले सत्र में भी आवाज उठाई थी। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। चाहे अनिकेत का मामला हो या अन्य दो दिव्यांग का मामला हो। ऐसा पेंच है कि वह बच्चा साल भर से भटक रहा है। उसे 1 लाख रूपये तक का लोन नहीं मिल रहा है। उसके लिये शासकीय गारंटर मांगा जा रहा है। वह दिव्यांग कहां से गारंटर लाकर देगा ? लेकिन फिर भी वह काम कर रहा है। उसे ट्रायसायकल मिला है और वह उसी ट्रायसायकल में घूम-घूम कर चूड़ी बेचता है, सामान बेचता है, तब अपना पेट चलाता है। एक दिव्यांग है, मैं जिसकी बात करना चाहूंगा और इस सदन के माध्यम से उसे बधाई भी देना चाहूंगा कि राजेन्द्र देशमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका खेलने गया लेकिन सहयोग के नाम पर उसे कलेक्टर के माध्यम से केवल 15 हजार रूपये दिया जाता है और जब वह खेलकर आता है तो उसके पिताजी पूरा पैसा लगाते हैं, तब पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उसे 20 हजार रूपये दिया जाता है। वह लड़का, राजेन्द्र देशमुख अभी फिर खेलने जायेगा। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक हाथ से पूरा मैच खेलता है। उसके लिए भी ऐसी कार्ययोजना बननी चाहिए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए तब हम सही में मानेंगे कि आपकी यह योजना फलीभूत होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं खैरागढ़, छुईखदान की घटना के बारे में बताना चाहूंगा। वहां 45 गांवों के लोग श्री सीमेंट के विरोध में सड़क पर आये। सैकड़ों ट्रैक्टर और हजारों महिलाएं छोटे-छोटे बच्चों

को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रही थी। उनके साथ दमनपूर्वक कार्य किया गया है। आप यदि वीडियो फुटेज देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि उन्हें दीवार में टीकाकर इतनी बेदर्दी से मारा गया। वे केवल यह मांग करते हुए विरोध कर रहे थे कि यहां पर श्री सीमेंट का प्लांट नहीं लगना चाहिए क्योंकि यह जो धरती है, यह बंजर नहीं है। वहां के लोग धान बोते हैं, धान के साथ गेहूं चना बोते हैं और गेहूं चना के बाद गर्मी में मूंग की भी फसल बोते हैं। इस तरह से उस जगह के लोग तीन-तीन फसल लेते हैं। लेकिन उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गयी है, मैं उसके बारे में भी बोलना चाहूंगा कि आप अपने पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को खुश करने के लिये किसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर बहुत-सी बातें आयी हैं। चाहे वह PWD विभाग की बातें हो या PMGSY की बातें हो या RES की बातें हो या NHM की बातें हो। जो सड़क पूर्व में स्वीकृत है, जो बजट है, जो प्रावधान है, वह अब प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में अब बजट से बाहर हो रही है। जब आपने मूल बजट में लिया था, वह प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में काम नहीं हो पाये तो जो मूल बजट में उसके लिए प्रावधान रखा था, वह राशि कहां है ? उसके बाद भी आप अनुपूरक बजट में यह प्रावधान रख रहे हैं। यह समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात आ रही है। गुंडरदेही विधान सभा के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरा सेटअप उठाकर खैरागढ़ में डाल दिया गया। क्या गुंडरदेही विधान सभा में सड़कों की जरूरत नहीं है ? वहां लोग किधर से जायेंगे ? आपको पता है कि अभी वहां चक्काजाम, धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुआ था। आश्वासन भी मिला था लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं हो पायी है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। यहां माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के लिए पूर्व की सरकार द्वारा जो राशि जारी हुई थी, उसमें बहुत से भवन बन गये हैं और कुछ भवन अधूरे हैं लेकिन अभी तक उस भवन की राशि उस विभाग को नहीं दी गयी है, जिसके कारण ठेकेदार काम करना बंद दिये हैं। उस पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी में आयुष्मान योजना के 40-45 लाख रूपये का जो घोटाला हुआ था, अभी तक उसकी जांच नहीं हो पायी है। मैं जहां निवास करता हूं, मेरे घर के समीप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्जुंदा में भी अभी 15 दिन पहले आयुष्मान योजना में घोटाला सामने आया है। वहां जो डॉक्टर पदस्थ नहीं हैं और जिसका साल भर पहले से ट्रांसफर हो गया है, अभी-भी DBT के माध्यम से उसके खाते में पैसा जा रहा है। जब इसकी जांच हुई, कमेटी बैठी तो यह पाया गया और उसके खाते से वापस उस पैसे को ट्रांसफर किया गया तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। केवल लीपापोती का काम किया जा रहा है।

सभापति महोदय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बात करना चाहता हूं। भगवान ही मालिक है। सड़कें, गांव की गलियों में इतने गड्ढे हो चुके हैं कि चलना मुश्किल हो गया है। टंकी तो बनी है, लेकिन बोर नहीं हुआ है। पानी कहां से जायेगा। धोखा से कभी टेस्टिंग हो जाती है तो पाईप फट जाती

है। अब पता नहीं किस हिसाब से आपने उसका मानक तय किया है। जी.आई. पाईप होती है तो कम से कम मजबूत होती है, उसमें ब्लास्ट नहीं होता, वह फटती नहीं है। आप एक, डेढ़ किलोमीटर की लंबी पाईप बिछा दिये हैं और जब प्रेशर के साथ पानी जाता है तो वह वैसे ही फट जाती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- निषाद जी, ये बताईये कि बोर है, पानी नहीं है, किसके कारण है ?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वह आपके कारण है। सरकार आपकी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुन लीजिये। जितने काम घोषित हुए, आप समझ रहे हैं। एक बार सेन्ट्रल टेंडर हुआ, सबके लिये एक रेट। फिर कांग्रेसी लोग मुख्यमंत्री जी के पास गये कि हम बेरोजगार हो जायेंगे, कौन खायेगा, कौन पीयेगा। पैसा कहां से आयेगा ? फिर वह टेंडर निरस्त हुआ, फिर कौन लोगों को ठेका दिया, कैसे दिया गया, तोहू ला मिलिस या नई मिलिस एला तय जान। उसके बाद जिसकी जो मर्जी आई, कोई नियम कानून नहीं, तौर तरीका नहीं, खोदो, बनाओ, देखो, खाओ, पीओ, चलो। जल जीवन मिशन में तो आपको भाषण ही नहीं देना चाहिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी दो साल तो आपकी सरकार हो गई।

श्री अजय चन्द्राकर :- जल जीवन मिशन भूपेश बघेल सरकार का जेब खर्चा था।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धरातल में क्या काम हुआ, अभी वह बतात हवं। अभी आपकी सरकार को दो साल हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां पानी नहीं है गिना रहो हैं, कहां से आकर।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- बिल्कुल, आपकी सरकार को दो साल हो गया। धरातल में आपने क्या काम किया है, यह बतायें।।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप चिंता मत करिये, ये पानी दे देंगे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- क्या काम हुआ है, आप यह तो बता दें। अगर एकात कोई काम हुआ है तो बता दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, माननीय तोर काय चलत रहिस, तेला मैं जानत हवं। जब मछुआरा नीति बतिस तो तोला पूछिस तक नहीं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं उहां बैठे रहेंव। वो बोर्ड में बैठे रहेव। मोर दस्तखत हे, देख लेबे।

श्री अजय चन्द्राकर :- गिनात भर में कोतरी धरत हवं, मोगरी धरत हवं कहकर। आप ला पूछिस तक नई। अउ पूछतिस तो आप ला रहत ले निजी क्षेत्र बर डेम ला कैसे खोल दीहिस। आप ला निजी क्षेत्र बर डेल ला कैसे खुलवा दिहेस। बता न तैंहा जब तोर चलिस तो। तैं खुद तोर समाज से अन्याय करेस। इहां भाषण देत हस कि पानी नई हय।

सभापति महोदय :- कृपया आपस में बात न करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं स्वयं कमेटी में बैठे रहेव। बहुत सारी पालिसी बने हे। आपकी सरकार में का करव।

श्री अजय चन्द्राकर :- निजी क्षेत्र बर खोलिस या नई खोलिस? बांध ला निजी क्षेत्र बार खोलिस या नई खोलिस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- निजी क्षेत्र में अगर कोई मिले हे तो भूपेश बघेल के सरकार मा मिले हे। ..(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- बांध ला निजी क्षेत्र बार खोलिस या नई खोलिस, तेला बता।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी आप का करव हव जेन प्रति व्यक्ति ला एक हेक्टेयर करव, तेन आप आधा कर देव हव। हम तो 01 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति देत रहेन, आप ओला आधा हेक्टेयर कर देव। आप मन मछुआरा मन के साथ ये अन्याय करत हव। ये अन्याय आपकी सरकार करथे।

श्री अजय चन्द्राकर :- भूपेश बघेल जी हा निजी क्षेत्र बर खोल कर के मछुआरा मन के हक मारिस, निषाद मन के हक मारिस। बात करत हस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हक नहीं मारिस, हमन कृषि के समान दर्जा देन। सारा सप्लाई करन। अभी एक साल से आपके विभाग के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा कोई योजना नई चलत हे। बडे-बड़े बात होथे। शिक्षा मंत्री जी बैठे हे, मैं यही कहना चाहूं कि पूर्व के सरकार में स्कूल जतन के माध्यम से हर विधान सभा में चाहे प्राथमिक स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो, हायर सेकेण्डरी के भवन, जीर्णोद्धार सब चलत रहिन।

श्री आशाराम नेताम :- निषाद जी, स्कूल जतन योजना के तहत कौन काम करिस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पी.डब्ल्यू.डी., आर.ई.एस. दोनों विभाग काम करत रहिस।

श्री आशाराम नेताम :- गलत बात हे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- चल मोर विधान सभा में चल।

श्री आशाराम नेताम :- अभी भी मोर क्षेत्र कांकेर जिला में स्कूल जतन योजना के काम अभी भी अधूरा है। पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने काम किया है। अभी भी अधूरा है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- चल मोर विधान सभा में चल, दूसर के बात नई बोलव। अतका ला जानथव कि पी.डब्ल्यू.डी., आर.ई.एस. ने काम किया है। मोर विधान सभा में चल, मैं पूरा आप ला दिखा देहूं। मैं दूसरा के बात नई करत हवं।

श्री आशाराम नेताम :- मैं विधान सभा कांकेर जिला की बात कर रहा हूं। स्कूल जतन योजना में इतना घोटाला हुआ है। आपके कार्यकर्ता ने काम किया है, वह अभी भी अधूरा है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- क्या किया है, कौन किया है, वह मैं नहीं जानता। मैं यह जानता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी., आर.ई.एस. विभाग ने काम किया है। वह हो सकता है कि आपके यहां काम किया हो तो

अलग बात है। पशु विकास परियोजना के बात होथ। इसी सदन में याचिका के माध्यम से बात आती है। लेकिन दो साल हो गया है, अभी तक न पशु औषधालय बन पाये हैं, न पशु चिकित्सालय का उन्नयन हो पाया है और न ही नये पशु औषधालाय का बजट में प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, छात्रावास की भी मांग लगातार सदन में हुई, लेकिन अभी तक किसी भी छात्रावास के लिये इस बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । विकास की अवधारणा की बातें करते हैं, किसान-मजदूर की बात करते हैं लेकिन जब बजट में उस हिसाब से प्रावधान नहीं हो पाता तो निश्चित ही मन में एक पीड़ा होती है और मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो मीठी और लच्छेदार भाषण कर रहे हैं, वह कभी मेल नहीं कर पाते लेकिन उनकी इतनी मजबूरी है कि कम से कम सरकार का भाषण दें और अपने मंत्री के समर्थन में बात करें तो हो सकता है कि उन्हें मंत्री बना दें तो ऐसा नहीं हो पायेगा । मैं उनके लिये तो यही कहना चाहूंगा कि - मतलब पड़ा तो सारे अनुबंध हो गये, मतलब पड़ा तो सारे अनुबंध हो गये और नेवले के भी सांपों से संबंध हो गये । माननीय सभापति महोदय, बस इतना कहकर, इसके विरोध में अपनी बात कहते हुए, आपने मुझे बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रामकुमार यादव :- महाज्ञानी जी आप ला बधाई हो ।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस अनुपूरक बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । चूंकि मैं बस्तर से आता हूं इसलिये सबसे पहले तो मैं इस बात के लिये धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि पिछले 40 साल से जिस कैंसर से बस्तर ग्रसित था, नक्सलवाद के नाम से आज उस कैंसर का संपूर्ण ईलाज होने का अवसर आया है और यह हमारे लिये बड़ा ही गौरव का क्षण है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- ओ 40 साल में 15 साल तुंहरो रिहिस हावय ।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, नक्सलवाद ने बस्तर को 40 साल पीछे किया और पीछे करने वाले सामने बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी विजन को महत्व नहीं दिया । हमारी सरकार ने हर काम एक विजन के साथ किया और उसका नतीजा भी हमको दिखायी देता है । जैसे महतारी वंदन योजना की बुराई की जा रही है, सामने वाले लोगों को उसकी आलोचना करने का मौका मिल रहा है । मैं यह कहता हूं कि आज महतारी वंदन योजना 70 लाख परिवार की माताओं को एक सम्मान देने का सबसे बड़ा विषय हो गया है, 1 से 3 तारीख तक हमारी यह 70 लाख महिलायें अपने एकाउंट में 1000 रूपये आने का रास्ता देखती रहती हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट यह होता है कि आज बैंक महिलाओं को बुलाकर के बिना गारंटी के 25,000 रूपये तक का लोन देने के लिये तैयार हैं । यह उसका रिजल्ट है, उसके स्वावलंबन का एक परिणाम है । हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए । इसमें जो मांग रखी गयी है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में

हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, औद्योगिकीकरण, आई.टी. के क्षेत्र में हो यह सारी मांगें हमारे विकसित राष्ट्र के साथ विकसित छत्तीसगढ़ और हर विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने का इसमें एक नया रास्ता दिखाई दे रहा है इसलिये मैं चाहूंगा कि जो अच्छी बातें हैं उसका समर्थन सामने वाले मित्रों को भी करना चाहिए लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि केवल एक विरोधी स्वर हमें इधर से सुनाई देता है । मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बजट के माध्यम से हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, आने वाले दिनों में इसके जो परिणाम आने वाले हैं उन परिणामों को देखकर हमें यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक ऐसे विचारवान वित्तमंत्री और हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से संपूर्ण कल्याण करने की बात कही है । 27 लाख किसान परिवार और निश्चित तौर पर यह कहने की बात जरूर हो रही है कि इस बार सरकार बहुत ज्यादा धान खरीदी में फेलियर हो रही है लेकिन हमको यह समझना पड़ेगा कि इससे पारदर्शिता कितनी बढ़ी है । हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं तो सिस्टम में भी रहा हूं इसलिये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि पहले जो धान की खरीदी होती थी उसमें 30 प्रतिशत तक घोटाला हुआ करता था लेकिन अब यह जो धान खरीदी हो रही है इसके लिये जो व्यवस्था बनायी जा रही है । इस व्यवस्था से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो लिंकेजस हैं, जो भ्रष्टाचार करने के रास्ते हैं उनको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका परिणाम आने वाले 2-3 सालों में देखने को मिलेगा। सरकार के माध्यम से धान के बदले हम दूसरे उत्पादों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसमें भी काम हो रहा है। यहां पर Allied agriculture सेक्टर्स में भी काम हो रहे हैं, मिलेट्स उत्पादन में काम हो रहे हैं, उद्यानिकी के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। हम जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तब हमें आम जनता, हमारे मतदाताओं के साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी तभी जाकर उनकी समझ विकसित होगी और धान के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है वह धीरे-धीरे कम होकर, हमारे जो मिलेट्स उत्पाद हैं और उद्यानिकी का क्षेत्र है, मछली पालन, पशुपालन की तरफ लोग बढेंगे तब जाकर आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के रूप में अपना स्थान बना पायेगा। चूंकि इस पर समय बहुत कम रखा गया है। मैं बस्तर क्षेत्र से आता हूँ इसलिए मैं बस्तर की वकालत करना चाहता हूँ। अभी मैं देख रहा था कि हमारे बिलासपुर संभाग के सभी नेतागण बड़े प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे क्योंकि उनके लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे रायपुर से जगदलपुर की जो विमान सेवा है उसको भी तत्काल बहाल करने की आवश्यकता है क्योंकि वह आगावमन का बहुत ही आवश्यक साधन है । हम रायपुर से जगदलपुर पहुंचकर और जगदलपुर से रायपुर आने की जो सुविधा है अगर यह विमान सेवा शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ हो जाती है तो उस क्षेत्र की जनता पर बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। मैं आज सुबह हमारे प्रांताध्यक्ष और जगदलपुर के माननीय विधायक जी का जो प्रश्न लगा था, उस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जो जवाब आया था उसको भी स्मरण करना चाहूंगा कि हमें हर मामूली ईलाज के लिए या तो विशाखापट्टनम् जाना पड़ रहा है या

फिर रायपुर आना पड़ रहा है। इसमें हमारा बहुत ज्यादा समय और धन भी अपव्यय होता है। ऐसी स्थिति में बस्तर मुख्यालय और इसके अलावा हमारे कोण्डागांव जिले में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, मैं यहां पर इसे भी एक विषय के रूप में लाना चाहता हूँ ताकि वहां के लोगों को सही प्रकार से ईलाज मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर का फायदा लेते हुए, एक और मांग रखना चाहता हूँ। आप सभी यह जानते हैं और जो भी बस्तर जा रहा है, केशकाल घाट और केशकाल शहर की जो सड़क है उससे हर आदमी परेशान है। मैं हमारी केन्द्र सरकार को धन्यवाद् देना चाहूंगा । माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव जी को भी धन्यवाद् देना चाहूंगा कि उन्होंने जो जनता से वायदा किया था कि हम बारिश के तुरंत बाद इस सड़क का पुनर्निर्माण करेंगे और उसके लिए 8 करोड़ रूपये का प्रावधान करके, उस सड़क का निर्माण का कार्य चालू हो गया है। मैं इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके निर्माण के लिए केवल 8 करोड़ रूपये की राशि से काम नहीं बनेगा, हमें अतिरिक्त 16 करोड़ रूपये की और जरूरत है ताकि हम उस सड़क को पूरे 60 फीट चौड़ी सड़क बना सकें, उसमें डिवाईडर लगा सकें, उसमें नाली की व्यवस्था हो सके। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भी ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि उस सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आने वाले समय में वह सड़क भारत माला से जुड़ेगी जो कि हमें व्यावसायिक सड़क के रूप में सामने दिखायी देगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसमें हमें मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के अंतर्गत 16 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि प्रदान कर दी जाये तो हम केशकाल शहर के अंदर एक बहुत ही मजबूत सड़क बना सकेंगे और इससे वहां का जो अतिक्रमण है, वहां से उस अतिक्रमण को भी हटाने का काम हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा जो केशकाल विधान सभा क्षेत्र है इसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां पर हमारे वन मंत्री जी, पयर्टन और संस्कृति मंत्री जी भी मौजूद हैं। मांझिनगढ़, टाटामारी, कुएमारी, चर्रेमर्रे का जलप्रपात, धार्मिक पर्यटन स्थल भोंगापाल और 5 वीं, 6 वीं शताब्दी के गोबराईन के शिव मंदिर है, वहां पर अनेक ऐसे स्थान हैं जिसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिनको विकसित करने की आवश्यकता है । मैं इस अवसर का फायदा उठाते हुए, यह मांग रखता हूँ।

समय :-
06:00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में बड़े डोंगर की पहाड़ी है । यह बड़े डोंगर की पहाड़ी वही पहाड़ी है, जहां पर आज से 13 सौ साल पहले जब अन्नम डे वहां से आये थे और वहां पर अपनी पहली राजधानी बड़े डोंगर में बनाई थी, जिसमें आज भी दंतेश्वरी माता के दर्शन के लिए लाखों

की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का बहुत अच्छे तरीके से विकास नहीं हो पाया है । यहां पर पर्यटन मंत्री बैठे हुए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्राचीन विरासत को संरक्षित करने के लिए, विकसित करने के लिए बजट प्रावधान का शामिल करने का प्रयास करेंगे । इसका प्लान ऑलरेडी बनाकर सब्मिट कर दिया गया है । इतना ही कहकर 35 हजार करोड़ रूपए की अनुपूरक मांग है, उसका समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- धन्यवाद सभापति जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा, क्या है कि आप यह बोल दीजिए कि परम्परागत रूप से हम लोगों को विरोध करने के लिए जनादेश मिला है इसलिए हमारे साथियों ने पूर्व में जो विरोध किया, उसका समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

समय :-
6.02 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भांचा जी, आपके साथ वैसे ही अन्याय हो रहा है, जैसे भगवान राम के साथ हुआ था । मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री राम चन्द्र जी राजा बनने से वंचित हुए थे, वे 14 वर्ष वनवास गए थे और वापस आये तो भगवान श्री राम चन्द्र के रूप में आये । वैसे ही जब आपकी वापसी हो तो उसी तर्ज पर हो, यही कहना चाहता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी विद्वान हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और यही हकीकत है । माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा 35 हजार करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है । मुझसे पहले जो भी सम्माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, उन्होंने निश्चित रूप से यह कहा है कि अभी तक जितने भी अनुपूरक बजट प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें से यह सबसे बड़े अनुपूरक बजट का आकार है, 35 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट है । मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं । वित्त मंत्री जी, आपने बजट के आकार बढ़ाने में कहीं न कहीं अपनी विद्वता दिखाई है, पर योजनाओं में अपनी विद्वता नहीं दिखाई । इस बजट में कर्ज के ब्याज में धनराशि जा रही है तो बहुत सारा हिस्सा केन्द्रीय योजनाओं के लिए आपने प्रावधान किया है, लेकिन मुझसे पहले हमारे भांचा जी ने ही कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने यह बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में इतनी वन एवं खनिज सम्पदा है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला टैक्स मुक्त राज्य हो सकता है और पिछले सत्र में मैंने भी इस बात को नाम लेकर नहीं कहा था, जब वे पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की यात्रा कर रहे थे तो भी इन्होंने इस बात को कहा था कि छत्तीसगढ़ देश का पहला टैक्स मुक्त राज्य हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के इतने वर्षों बाद धरातल की स्थिति यह है कि देश के 5-6 राज्य जितने ज्यादा

कर्ज में होंगे, उनमें से छत्तीसगढ़ राज्य है । जब आप वित्त मंत्री बने तो मुझे खुशी थी कि आप कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की परिस्थिति कुछ अलग होगी ।

अध्यक्ष महोदय, अब किसान के धान खरीदी की बात है तो मंत्री जी, आप जितनी धनराशि दे रहे हैं । एक तरफ डबल इंजन के सरकार की बात होती है और डबल इंजन की सरकार है भी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ को लाभ देने की बात आती है तो डबल इंजन की सरकार नहीं दिखती । धान खरीदी में आपने जितनी भी धान की नीलामी की है और केन्द्रीय पुल में कुछ चावल बढ़ाएं और आपने जितना धान खरीदा, लेकिन पंजाब की तर्ज पर यहां डबल इंजन की सरकार, आपकी दिल्ली की सरकार छत्तीसगढ़ के साथ न्याय करती तो छत्तीसगढ़ का 5 हजार करोड़ रूपये का नुकसान बच सकता था। आप किसानों को 10 हजार करोड़ रूपये दिए, लेकिन नुकसान हुआ। आपकी नीति और दिल्ली सरकार की मदद नहीं होने की वजह से 5 हजार करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा, ये बता धान खरीदी मा पूरा 5 साल मा तुंहर कै हजार करोड़ रूपया के घाटा होइस।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हमारे समय में एक बार हुआ था।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक बार नहीं, एक बार कहकर मुड़-कान ला मत झुला ममा। सही-सही बता दे कि कतका के होइस ए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :-देखो, दलगत राजनीति थी। दिल्ली सरकार मदद नहीं की थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुन तो। अपन ला स्वीकार करना हे गा कि भूपेश बघेल के समय मा अतका के घाटा हाइस अउ अतका रूपया के धान सड़ीस, अतका-अतका होइस, ऐसे बता न।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उसको बताने के लिए तो आप पर्याप्त हैं। उसको मेरी तरफ मत लाईये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- वाह, ऐसन मा तो फिर आधा-अधूरा हे ममा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मेरा बोलना है कि आपका दल..।

श्री अजय चन्द्राकर :- कैसे ममा ? बता न तो ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उसको तो कई बार बता चुके हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै हा भूपेश बघेल गुट के अस का ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मेरी जानकारी में 5 हजार करोड़ हुआ है। विश्वास करव न।

श्री अजय चन्द्राकर :- भूपेश बघेल गुट के अस का ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक साल हमारी सरकार में भी 5 हजार करोड़ का हुआ है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- ये अजय चन्द्राकर जी के गुट के हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै हा भूपेश बघेल गुट के अस का ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भाई, मैं संगठन का हूं।

एक माननीय सदस्य :- जोगी जी वाला रहिस ए।

श्री अजय चन्द्राकर :- घोषित तौर पर सब जानते हैं कि श्री अटल जी, भूपेश बघेल गुट के हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मैं अजय चन्द्राकर जी के गुट का हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब को सब कोई जानते हैं कि टी.एस. सिंहदेव गुट के हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मैं सदन में अजय चन्द्राकर गुट का हूं।

श्री रामकुमार यादव :- ये तो भाचा हा न, ना ऐती ना ओती के, अंडा बटे पराठा ए।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसलिए उसकी आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कितना धान सड़ा, कितना बेचे, कितना घाटा हुआ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- एक ही बार हुआ। लेकिन उसका वास्तविक कारण दिल्ली की सरकार थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसे हे मामा श्री, तै हा कंस मत बन।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भाचा जी, आपकी सरकार और हमारी सरकार में अंतर है।

श्री रामकुमार यादव :- बहुत अंतर है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जब अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, आपकी एक मांग को, आपकी दशमलव की मांग को नहीं काटे थे, आप स्वयं अपने भाषण में बोले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं हा अर्जुन सिंह भी ला बलाय हव, मनमोहन सिंह जी ला बलाय हव, समझ गय न ? नहीं जानत हस तो बता देवत हंव। 5 साल मा तुमन कतेक भा.ज.पा. के प्रधानमंत्री अउ मंत्री ला बलाय हव ? एकाध ठन बता दे ?

श्री रामकुमार यादव :- तुमन नइ बलाय जी, हमर डाक्टर साहब हा बलाय हे। हमर डाक्टर साहब हा बलाय रहिस हावय।

श्री अजय चन्द्राकर :- तै हा एक झन ला भी बलाय नहीं हस, जेला बलाय हस, तेखर सेतीर बाबा जी के ठुल्लू हे, सुनत हस नहीं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में वरिष्ठ सदस्य आदरणीय धरम लाल कौशिक जी बोल रहे थे कि पहली बार किसान खुश हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यादव जी, आप एक बात बताओ कि आप बिहार में चुनाव प्रचार के लिए गये थे या नहीं ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं तो 3 ही दिन गया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- गये थे न ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हां।

श्री अनुज शर्मा :- उड़ीसा भी गये थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप बिहार नहीं जीते हैं। लोकतन्त्र में जब से चुनाव हो रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है और 10 हजार नकद देने की योजना ..।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। जैसे ए साल फिर 10 हजार दे दब तो तुमन का कर लेहव ? (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप पहले दीजिये न।

श्री धर्मजीत सिंह :- चुनाव के एक महीना पहली 10 हजार का 15 हजार दे देबव, का करहिव ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप पहले दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- जनता हा एक घव ठगाथे, अब 10 हजार का एक लाख कर दिया तभी तुंहला वोट नहीं देवय। तुंहर पैसा ला खा दिही, लेकिन वोट ला ऐती दीही, ये दारी चिंता मत करव।

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा, जैसे तै हा बिहार गय रेहेस, एक झन यादव के पैसा ले के टिकट बाटिस कहके छपे रहिस ए। तोहरो संग ऐसे तो नहीं होय हे न।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, वह छपा नहीं है। साजिश के तहत छपवाया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा छपे हे भैय्या।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भाचा, कई तरह से छपता है।

श्री सुशांत शुक्ला :- छपवाय हे, बोलिस हे। भैय्या कौन छपवाय हे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ममा, पैसा-वैसा खाय मा तोर नाम तो नहीं हे न ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, द्वारिकाधीश जी, समाप्त करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सिर्फ 2 मिनट बोला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य धरम लाल कौशिक ने अभी धान खरीदी के विषय में कहा कि अभी तक की सर्वाधिक अच्छी व्यवस्था धान खरीदी की हैं, इस बात अपने भाषण में शामिल किया है। मैं इस सदन में बोलना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जब से सरकार धान खरीद रही है, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक किसान टोकन के नाम से अपने गले को काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे अनुपूरक बजट भाषण में कांग्रेस के सारे वक्ता टोकन से ऊपर नहीं उठ पाये हैं। इनका भी टोकन काट देते हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, मैं दूसरे बिन्दु पर आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, सदन चल रहा है, कोई भी समय यहां पर बस लगा दें, धर्मजीत भैया के स्टाइल में बोल रहा हूं और कोई भी खरीदी केंद्र में सभी विधायक चलें, अगर किसान संतुष्ट होंगे तो हम उस बात को स्वीकारने में भी नहीं हिचकेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी, दूसरा महत्वपूर्ण विषय

यह है कि आपके विभाग में जो अभी रजिस्ट्री की दर लागू हुई और जो बातें लाए हैं, माननीय वित्त मंत्री जी, स्थिति यह है कि आपने गाइडलाइन बढ़ाया है, सही है, लेकिन गाइडलाइन का जो आंकलन है, केवल और केवल बड़े लोगों की बात नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि गांव की जो जमीन पहले 15 लाख या 10 लाख थी, वह एक करोड़ जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी, उसमें दो बातें हो रही हैं, एक करोड़ अगर वह जा रहा है तो केवल बड़े के लिए और छोटे के लिए अलग नीति के लिए आप विचार कीजिए। कोई भी जरूरतमंद और किसान का अब जमीन नहीं बिकेगा, उसका कारण मैं जो समझा हूं, आपको बताना चाहता हूं, 15 लाख की जमीन है। आपकी वास्तविक दर और सरकार में वह एक करोड़ हो गया है। अगर कोई व्यक्ति एक करोड़ में खरीदता है तो 12 लाख रुपया रजिस्ट्री खर्च आएगी और एक करोड़ में पहले 30 लाख रुपया, वह इनकम टैक्स विभाग को देगा तो 42 लाख रुपया जब सरकार को देगा तो कौन ऐसे खरीददार होगा कि 15 लाख की जमीन में 42 लाख रुपया सरकार को देने के बाद स्थिति यह बनेगी..।

श्री रामकुमार यादव :- एला छत्तीसगढ़ी में सरल भाषा में कहथे चार रहगे घाघर और 15 रहगे पुतगौनी। एला सरल भाषा में कहे जाथे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय वित्त मंत्री जी, स्थिति यह बनेगी कि जरूरतमंद लोग नहीं बेच पाएंगे। व्यापार करने वाले के लिए आपकी नीति सही है, लेकिन जरूरतमंद लोगों की जमीन नहीं बिकेगी जिससे कि जरूरतमंद लोगों को नुकसान होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15वां वित्त आयोग में अभी तक एक भी सरपंच को, कोई भी पंचायत को धन राशि नहीं मिली है और इस सरकार में महतारी सदन या कोई भी योजना में एकाध विधान सभा में दो चार पंचायत में स्वीकृत भी हुई तो उसकी एजेंसी आर.ई.एस. को बना दी जा रही है । आज पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायत राज से ही इस सदन तक पहुंचेंगे। अगर उनके पास वित्तीय प्रबंधन नहीं होगा, पावर नहीं होगा तो लीडर कैसे आएंगे? पहले छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश करके लोकसभा विधान सभा तक आते थे, लेकिन आज त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय से आ रहे हैं, लेकिन उनको पावर लेस किया जा रहा है और अगर पावर लेस होंगे तो लीडर कैसे सदन में आएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो चिंता का विषय है। दूसरी बात, इस बजट में नगरीय निकाय के लिए पर्याप्त धनराशि की माननीय मंत्री जी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- ए ममा। अतेक देर ले बोलत हस गा, अभी दो ही के गिनती में पहुंचे हस गा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं। मुझे बोलने दीजिए न। देखिए, आप बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूं।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मामा भांचा ऐसी झगड़ रहे हैं कि यह सदन न होकर इनका ननिहाल हो गया है। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकाय के लिए एक तरफ जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी के आंदोलन किए तो वे चाहते थे कि रायपुर शहर में ही डामर की सड़क न हो, रायपुर शहर में ही विश्वविद्यालय न हो, रायपुर शहर में ही बड़े अस्पताल न हो, गांव में भी हो। लेकिन यह जो अभी बजट आया है, वह केवल और केवल शहर के लिए हो गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में भी धनराशि की व्यवस्था हो। दूसरी एक और बात कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी, हमारी सरकार की कई बातें उधर से आती हैं कि यह गलत था, वह गलत था। लेकिन जो सड़क स्वीकृत है, सामाजिक भवन स्वीकृत है, उसकी धनराशि भी कलेक्ट्रेट में जा चुकी है। लेकिन आज तक उसके आगे की टेंडर की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है? उस गांव की, उस जनता की गलती सिर्फ यह थोड़ी है कि वह कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत हुई थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में जो स्वीकृत कार्य हैं, उसको आप स्वीकृति प्रदान करेंगे। महतारी वंदन योजना की बात बहुत हो रही है। महतारी वंदन योजना ठीक है, लेकिन महतारी वंदन याजना में पिछले दो साल में अगर एक गांव में 10 लोग को औसत लेते हैं तो उनके साथ कितना अन्याय हो रहा ह। प्रदेश में उनकी मात्रा बड़ी संख्या में है। महतारी वंदन योजना में आपकी घोषणा थी कि कलेक्टर की पत्नी को लाभ देंगे, मुख्यमंत्री की पत्नी को लाभ देंगे, लेकिन दो साल से छत्तीसगढ़ की जो बहनें शादी होकर गई हैं, उसके लिए सरकार आज तक एक पोर्टल नहीं खोल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस अनुपूरक अनुदान मांग का विरोध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अनुज शर्मा।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। चूंकि समय का अभाव है। मैं अनुपूरक अनुमान में समर्थन करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता की बात कहूंगा कि उन्होंने भविष्य को देखते हुए पूंजी और राजस्व के व्यय में जो संतुलन बनाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। मैं विषयांतर नहीं करूंगा। मेरी कुछ मांगें हैं, मैं उसको सीधा रखता हूं क्योंकि दोनों पक्षों से काफी विस्तार में बातों को रखा जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम का निर्माण हुआ और आपने इसकी घोषणा की थी। फिल्म विकास निगम की पॉलिसी बनने में थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन वह धरातल में नहीं उतर पाई है। उसमें फिल्मों के सब्सिडी का नियम है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को राष्ट्रीय स्तर के सम्मान मिलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में बनने वाली फिल्मों एवं छत्तीसगढ़ी फिल्मों को सब्सिडी मिले, उसके लिए जो पॉलिसी है, उसको धरातल में उतारने का समय आ गया है। उनकी सब्सिडी के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि का समावेश किया जाये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग सभी कलाकरों का फोन आता है, जिसमें सभी कलाकार परेशान हैं। उसको वाजिब पेमेंट भी नहीं होता है। मैं दोनों पक्ष के विधायकों की बात कर रहा हूं कि वह हर पर्व में 10-12 अनुशंसा करते हैं। उसका पेमेंट दो साल, डेढ़ साल में किया जाता है। इसको भी सुनिश्तिच किया जाये कि एक-डेढ़ महीने में ही उनका पेमेंट हो जाये। इस ओर मैं माननीय वित्त एंव संस्कृति मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और आग्रह करूंगा कि हमारी पुरानी विधान सभा के बाजू में ग्राम बरौदा में शासकीय हाई स्कूल है। शाला परिसर से गुजरने वाली मांढर शाखा नहर के वितरण शाखा क्रमांक 14 को भूमिगत करने हेतु वर्ष 2025-2026 में जल संसाधन विभाग के बजट में इस कार्य के लिए 3 करोड़ रूपये की स्वीकृत हुई थी। मेरा आग्रह है कि उसकी जल्दी स्वीकृति प्रदान की जाये। इसी स्कूल में शाला भवन के अहाता निर्माण के लिए मैंने याचिका प्रस्तुत की थी और इस पर मैंने और भी मांग की थी। माननीय वित्त मंत्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कि इसे जल्द से जल्द पूरा करने का कष्ट करेंगे। धरसींवा विधान सभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहां क्रिटिकल ड्राई जोन है। यहां हर गर्मी के मौसम में पानी की समस्या होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करता हूं कि क्रिटिकल ड्राई जोन के लिए पानी की व्यवस्था के लिए हमको कोई विशेष प्रावधान करना पड़ेगा, कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूं क्योंकि हमारा विधान सभा क्षेत्र देश के क्रिटिकल ड्राई जोन में आता है। आप वहां पानी की व्यवस्था के लिए कोई स्पेशल स्कीम को लेकर आये। सिलतरा में इंडस्ट्रीयल एरिया है। सिलयारी में पॉलिटेक्निक और आई.टी.आई. कॉलेज की स्थापना हो सकें, ताकि वहां के जो स्थानीय प्रतिभाएं हैं, उनको वहां की इंस्ट्रीज में काम करने का अवसर मिल सकें और वह अपने कुशलता के आधार पर नौकरी हासिल कर सकें। यह मेरा आग्रह है। माननीय वन मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह है कि जैसे कि आपने राजनांदगांव के पूरे जंगल को इतना सुव्यवस्थित करवा दिया कि वह अपने आप में एक अद्भूत उदाहरण है। वहां ढेर सारे रिसॉर्ट खुल रहे हैं, वह बहुत बड़ा बिजनेस का सेंटर बना है और वह लोगों की छुट्टी मनाने का केन्द्र बना है। ऐसा स्कोप हमारे मोहेरंगा जंगल में है। मैं दोनों माननीय मंत्री जी आग्रह करता हूं कि इस पर विशेष कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री पुन्नूलाल मोहिले :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मेरा एक ही मांग है, पिछले विधान सभा में एक अशासकीय संकल्प रखा था कि मुंगेली में मेडिकल कॉलेज खोला जाये, वह सर्वसम्मति से पास हुआ था । आप इस पर जरूर ध्यान देंगे, मैं ऐसी मांग करता हूँ ।

राष्ट्रगीत वन्देमातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा की तिथि में परिवर्तन

श्री केदार कश्यप (संसदीय कार्यमंत्री) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में सदन की सहमति द्वारा सत्रावधि में एक दिन की वृद्धि की गई थी तथा 19 दिसम्बर को वंदे मातरम पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया था । इस पर प्रस्ताव है कि वंदे मातरम की चर्चा दिनांक 17-12-2025 को की जाये । कल अशासकीय कार्य दिवस का दिन है, यह सबसे अंत में आता है । मेरा आपसे निवेदन है कि जब अशासकीय कार्य पूर्ण हो जाये तो वंदे मातरम पर चर्चा हो । कृपया नियम को शिथिल करके अशासकीय कार्य के पश्चात् उसकी सदन पर चर्चा कराई जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 19 दिसम्बर 2025 को होने वाली सभा की बैठक में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर की जाने वाली चर्चा दिनांक 17 दिसम्बर 2025 को अशासकीय कार्य को संपादित होने के बाद किया जाये । क्या सभा इस प्रस्ताव से सहमत है । सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई । प्रस्ताव अनुसार कल दिनांक 17 दिसम्बर 2025 को अशासकीय कार्य संपादित होने के पश्चात् राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा होगी । मैं चर्चा के लिये दो घण्टे का समय निर्धारित करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- वित्त मंत्री जी ।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी.चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस अनुपूरक के विनियोग के अवसर पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । आज की इस चर्चा में हमारे पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सम्माननीय सदस्यों ने जो भाग लिया है, मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । इसमें से राघवेन्द्र सिंह जी, आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय रामकुमार यादव जी, आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, संगीता जायसवाल जी, भावना बोहरा जी, कुंवर निषाद जी, नीलकंठ टेकाम जी, द्वारिकाधीश यादव जी, अनुज शर्मा जी, । आप सभी ने पक्ष और विपक्ष के साथियों ने भी जो चर्चा में भाग लिया है, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सफलतम दो वर्ष पूर्ण किये हैं और हमारी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को 25 साल का समय भी पूरा हुआ है । 25 साल की इस विकास यात्रा में विधान सभा का भवन जो राजकुमार कालेज के जशपुर हाल से चलते हुये इस भव्य इमारत तक पहुंची है, उसके लिये सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों को और पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य का विषय है कि कल इस नये बने भवन में छत्तीसगढ़ के विजन की चर्चा हो रही थी, विजन 2047 की चर्चा हो रही थी, हमारे विपक्ष के साथी यहां से नदारद थे । ऐसा ही प्रकरण हुआ था, जब सेंट्रल विष्टा का केस हुआ था,

जब सेंट्रल विस्टा में प्रथम सत्र हुआ था । आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने भारत के विकास के लिये लाल किले की प्राचीर से 5 प्रणों की बात कही है और उसमें महत्वपूर्ण प्रण है कि देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाई जाये । यह महत्वपूर्ण प्रण है । संसद भवन जो देश की सबसे बड़ी पंचायत का भवन है, वह अंग्रेजों के बनाये हुये भवन पर चलता था, अत: तय हुआ कि हमारे संसद की कार्यवाही है, हम संसद भवन खुद बनायेंगे और सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ, सेंट्रल विस्टा पर भी जो पहला सत्र का पहला दिन था, उसे भी कांग्रेस ने बहिष्कार करने का काम किया था। हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर यहां पर प्रथम दिवस पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी, उसको भी कांग्रेस ने बहिष्कृत करने का काम किया। इस तरह के सकारात्मक विषयों का बहिष्कार करना एक अत्यंत ही निंदनीय है, मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह से सेंट्रल विस्टा का बहिष्कार किया, जिस तरह से हमारे इस भव्य मंदिर में प्रथम दिवस का बहिष्कार किया, यही कारण है कि पूरे देश में जनता इनको बहिष्कृत करने का काम कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राघवेन्द्र भाई ने आज चर्चा की शुरूआत की थी और उन्होंने कहा था कि हम घर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, उन्होंने ये लब्ज इस्तेमाल किया था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी हमारी विचारधारा से संघर्ष करते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा को पूरी की है, हमारे सभी सीनियर लोग इस यात्रा को पूरा किए हैं, इसी तरह की बात राम मंदिर को लेकर होती थी, जब हमारे आदरणीय पुराने वरिष्ठ लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे तो विपक्ष के साथी उस समय भी उपहास करते हुए कहते थे कि मंदिर यहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उपहास करने का काम विपक्ष के लोग करते थे। लेकिन राम मंदिर भारत की सांस्कृतिक प्रतिबद्धता थी, 500 वर्ष पुराना एक कलंक था, जिसे आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने समाप्त करने का काम किया और विशुद्ध रूप से पूर्ण रूप से डंके की चोट पर हमें अपना मेनिफेस्टो का हिस्सा बनाकर घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हां ये हमारा राजनीतिक एजेंडा है और उस राजनीतिक एजेंडा को डंके की चोट पर पूरा करने का काम किया। इस तरह की जो बातें होती है कि हम तारीख नहीं बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पार्टी नहीं है, मैं इस बात को सदन में आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ की पीड़ा को समझा और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इस स्थिति में किया कि राज्य के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में भी और मध्यप्रदेश में भी दोनों में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, उसके बाद भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए राजनीति से उपर उठते हुए सरकार बनाने की पार्टीगत विषमताओं से उपर उठते हुए निर्णय लिया, छत्तीसगढ़ के हित में निर्णय लिया, 5 दशकों तक कांग्रेस को ये मौका मिला था लेकिन कांग्रेस ने इस काम को कभी नहीं किया, छत्तीसगढ़ की इस पीड़ा को कभी महसूस नहीं किया, मैं आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और आज हम 25 वर्ष

पूर्ण करके रजत जयंती वर्ष पर पहुंचे हैं। इस 25 वर्ष की यात्रा में हमारे विधान सभा की दृष्टि से 14 दिसंबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण थी, हमारी विधान सभा की यात्रा को भी 25 साल पूरे हो रहे थे, उस दिन आपने छत्तीसगढ़ के विजन 2047 पर चर्चा के लिए समय निर्धारित की थी, उसका विपक्ष ने बहिष्कार किया, जो कि लोकतांत्रिक दृष्टि से, छत्तीसगढ़ के भविष्य की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ के हितों की दृष्टि से अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। अध्यक्ष महोदय, जब हम इस बजट की साईज पर बात करते हैं तो अनुपूरक बजट का आकार 35 हजार करोड़ रूपए का दिखाई देता है, इसमें पूंजीगत व्यय, 1937 करोड़ रूपए और राजस्व व्यय 33 हजार 63 करोड़ रूपए है। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से इस चीज को स्वीकार करूंगा कि अगर इतना बड़ा अनुपूरक बजट आ रहा है तो मैं ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानता हूं, ये कोई बहुत वीरता का विषय नहीं है, क्योंकि हम अनुपूरक बजट में कोई अतिरिक्त आय का प्रावधान नहीं बताते हैं, उसके बाद भी हमको 35 हजार करोड़ रूपए की व्यवस्था करनी पड़ रही है तो आखिर ये क्यों करनी पड़ रही है ? मैं इसको आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसमें लगभग दो हजार करोड़ रूपए का पूंजीगत व्यय हैं। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय भी हैं, इसमें बहुत सारे जनता के हित के विषय भी हैं, उससे प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन जो इतना बड़ा बजट 35 हजार करोड़ रूपए का प्रस्तुत किया गया है, उसके माध्यम से पुरानी समस्याओं को, पुराने वित्तीय समस्याओं को हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हमको करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि ऋण की बात होती है, Financial stability की बात होती है। उस पर हम निश्चित रूप से ध्यान दे रहे हैं। मैं उसके बारे में आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि कांग्रेस ऋण की किन दशाओं में प्रदेश को छोड़कर गई थी। वह एक विषय है और उसके बारे में हमने अनेक बार चर्चा की है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पिछली सरकार प्रदेश पर अनेक लंबे दायित्व छोड़कर गई थी। जिसे उन्होंने वित्तीय रूप से ठीक-ठाक मैनेंज नहीं किया और अलग-अलग संस्थानों पर अलग-अलग उधारी छोड़कर गये थे। जिसको हमको पूरा करने में पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष करना पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मार्कफेड का धान खरीदी में जो ऋण था, वह 22 हजार करोड़ रूपये का पेन्डिंग अमाउंट कांग्रेस की सरकार छोड़कर गई थी, जो ऋण की गणना में कहीं नहीं आती है। मार्कफेड के ऊपर 22 हजार करोड़ रूपये की राशि पेन्डिंग थी। नागरिक आपूर्ति निगम के ऊपर 5 हजार करोड़ रूपये की राशि पेन्डिंग थी। आयुष्मान योजना के ऊपर 2 हजार करोड़ रूपये की राशि पेन्डिंग थी। दवाई, रिएजेंट पर लगभग 1 हजार करोड़ रूपये की राशि पेन्डिंग थी। 5 एच.पी. तक कृषि पंपों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय करने के लिए जो सुविधा दी जाती है, उस पर पिछली सरकार 2 हजार करोड़ रूपये की राशि पेन्डिंग छोड़कर गई थी। आप बजट ऋण जो बजट में प्रस्तुत नहीं किये जाते, जो अलग-अलग संस्थानों पर थे, वह 7 हजार करोड़ रूपये की ऋण की राशि पेन्डिंग छोड़कर गये थे। जल जीवन मिशन की 3 हजार करोड़ रूपये से

भी अधिक की राशि पेन्डिंग थी। कांग्रेस इस तरह की टोटल 42 हजार करोड़ रूपये की पेन्डिंग राशि छोड़कर गई थी। जिसको हमको आज अलग-अलग समय में adjust करके वित्तीय रूप से मैनेंज करना पड़ रहा है। जिसके कारण हमको अनेक प्रकार के फाइनेंशियल पेन भी झेलने पड़ते हैं। उसको भी हम बखूबी मैनेंज करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमें जो गंभीर वित्तीय विरासत मिली थी, उसमें यह ऊपर में बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते थे, बड़ी-बड़ी बातें करते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि धान खरीदी का पैसा मार्कफेड के ऊपर ऋण के रूप में छोड़ दो। पी.डी.एस. में जो वितरण हो रहा है, उसको नॉन पर पेन्डिंग अमाउंट के रूप में उधारी के रूप में छोड़ दो। आयुष्मान योजना के पैसे मत दो। दवाई के पैसे मत दो। बिजली में जो सब्सिडी दी जा रही है, उसके पैसे मत दो। इस तरह से पिछली सरकार लगभग 42 हजार करोड़ रूपये की राशि पेन्डिंग छोड़कर गई थी।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2018 में आपकी सरकार थी, तब भी आपने 42 हजार करोड़ रूपये का ऋण हमारे ऊपर छोड़ा था। उसके बाद 2 साल का कोरोनाकाल गुजरा, जब आर्थिक स्थितियां बहुत मंद हो चुकी थीं। उसके बाद भी हमने कर्जों को नहीं बढ़ाया, परंतु आप ऐसा गुणगान कर रहे हैं कि जैसे हम आपको बहुत सारा कर्ज देकर गये हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यही बात बताना चाहता हूं कि जो ऋण की राशि की गणना की जाती है, उसमें 42 हजार करोड़ रूपये कहीं भी गणना में नहीं होता है। इसलिए मैं वित्तीय तकनीकी को स्पष्ट करते हुए आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आप जो भी गणना करते हैं, उसमें इस 42 हजार करोड़ रूपये को एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा कि किस तरह से पिछली कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति को छोड़कर गई थी। यह मैं आपके समक्ष तथ्य के रूप में रख रहा हूं। इस तरह के जो पेन्डिंग अमाउंट थे, उसके कारण विभिन्न संस्थाएं मृतप्राय स्थिति में थीं और वह आगे कुछ करने की स्थिति में नहीं थीं। मैं आपको छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन का एक उदाहरण देना चाहता हूं। उसके ऊपर जी.ए.डी. के जो क्वार्टर बनाने के लिए उसके नाम से स्टेट गारंटी पर हाउसिंग बोर्ड को लोन लिवाया गया और हाउसिंग बोर्ड के लोन को पटाने के लिए 5 साल तक कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। उसके कारण से हाउसिंग बोर्ड कर्ज के जाल में फंसा रहा और एक मृतप्राय संस्था बनती चली गई। उस तरह की चीजों को ठीक करने के लिए हम पिछले अनुपूरक बजट में बजटीय व्यवस्था लेकर आये और उस पैसे को एकमुश्त हाउसिंग बोर्ड को देने का काम किया और स्टेट गारंटी को वापस लिया और इससे ब्याज की राशि की भी बचत हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह वित्तीय प्रबंधन है। जब हम वित्तीय प्रबंधन करते हैं तो वह केवल accounting नहीं है। financial management is not only accounting. हम कहां से क्या बेहतर कर सकते हैं, हमको उस पर भी बुद्धि, दिमाग लगाना

पड़ता है। उस दिशा में ईमानदार नीयत के साथ प्रयास करने होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने उस तरह के जो रि-पेमेंट करके व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया, उसके कारण आने वाले 8-10 वर्षों में हमने जो ब्याज की राशि को रिलोन ले-लेकर कम किया, उससे 1 हजार करोड़ रूपये से अधिक की बचत होगी। यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। मंत्री जी, माफ करियेगा मैं टोकना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप विद्वान हैं और आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आपने पूरा लोन का मामला हमारी सरकार के ऊपर मढ़ दिया। आप इसमें दो बातों के ऊपर और प्रकाश डाल दें कि जब GST लागू हुआ तो कैसे जो छत्तीसगढ़ का शेयर था, वह हमें नहीं दिया जाता था या लेट आता था, वह भी आंकड़े आपके पास हैं। दूसरा, जब कोविड था तो किस तरह लोन Independent agencies से लिया गया था और उस समय जो स्थिति थी, GST के टाईम पर भी वह लोन आया और उसके बाद भी लोन लिये गये। उस समय जो स्थिति थी, आप उसको आज की तारीख में Equate नहीं कर सकते हैं। वह एक बड़ी संकट की स्थिति थी तो यह कहना कि हमने जो किया वह पूरी तरह गलत किया। आपको हमें एक सकारात्मक रूप से देखना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- राघवेन्द सिंह जी, आपकी सरकार कहां थी ? आप तो प्रताड़ित समूह में थे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- हमारी सरकार ही थी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो स्थिति बता रहा हूं और जो 42 हजार करोड़ की देनदारी शेष थी, उसमें कांग्रेस के समय जो लोन था, उस राशि में वह नहीं जुड़ा था। मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से संस्थाओं को लोन लेकर और कर्ज में छोड़ देना, उनके ऋण के अकाउण्ट को NPA कर देना, यह प्रदेश की संस्थाओं के साथ न्याय नहीं था। जैसे केपिटल सिटी बनाने के लिये NRDA है तो NRDA के अकाउण्ट को NPA कर दिया गया था और यह जो स्थिति है, वह मैं कोरोना के समय की स्थिति को नहीं बता रहा हूं। उसके बाद आपको 2-3 साल का समय मिला था, जिसमें आप चीजों को व्यवस्थित कर सकते थे और संस्थाओं को मृतप्राय होने से बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह वित्तीय प्रबंधन नहीं किया गया। यह तथ्य निश्चित रूप से प्रदेश में और सदन को ज्ञात होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी पर अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। बिना फैक्ट के कोई आरोप-प्रत्यारोप अलग-अलग तरह से लगाये जा रहे थे मैं आपके माध्यम से उससे इतर कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जो उपार्जित धान की Quantity थी, वह कांग्रेस के पहले कार्यकाल के पहले वर्ष 2018-19 में 80 लाख मीट्रिक टन थी, वर्ष 2019-20 में 83 लाख मीट्रिक टन थी, वर्ष 2020-21 में 92 लाख मीट्रिक टन थी, वर्ष 2021-22 में 97 लाख मीट्रिक टन थी और वर्ष 2022-23 में 107

लाख मीट्रिक टन थी। हमारे कार्यकाल में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने जो दो बार धान खरीदी की है, उसमें पहले वर्ष 2023-24 में 144 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड था, यह एक तरह से 40-50 प्रतिशत का सीधा जंप था और वर्ष 2024-25 में 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है जो कि इनके कार्यकाल के समय से 40-50 प्रतिशत अधिक धान की खरीदी हुई है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- और क्या जान ले लेंगे ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है। जब हमारी सरकार में 2500 रूपये प्रति क्विंटल का दाम हुआ तो किसान युवा खेती की ओर लौटे तो निश्चित रूप से जब उपज हो रही है तो धान खरीदी तो ज्यादा होगी ही। अभी आप सोसायटियों में जो लिमिट दे रहे हैं, आप आज की तारीख में आंकड़ा निकलवा लीजिए कि 25 प्रतिशत धान खरीदी कम हो रही है और यदि आप आखिरी में डेट बढ़ायेंगे तो किसान की सूखती 1 क्विंटल में 5-7 किलो हो जायेगी। जब और डेट बढ़ायेंगे तो धान सूखेगा और कम्प्लीट धान पर आप औसत निकालिये तो किसान कितने नुकसान में जायेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- कका उहु ला बता देवव कि पिछले समय से कम किसान के पंजीयन होये हे, अभी किसान मन के पंजीयन बचे हे। पिछले समय ज्यादा किसान मन के पंजीयन होये रिहीसे अउ अभी कम हो गे हे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वही-वही बातें आ रही है। मैं यही तथ्य आपके समक्ष और आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि इनके समय में जो अधिकतम धान खरीदी हुई थी वह 107 लाख मीट्रिक टन हुई थी और यदि उस वर्ष 2022-23 को छोड़ दिया जाये तो 80-90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के बाद एक बार 144 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और उसके अगले बार 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। किसानों की संख्या भी बढ़ी है। धान खरीदी में भी 30-40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री लखेश्वर बघेल :- मंत्री जी, मंत्री जी।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी, आपको इस तथ्य में कोई आपत्ति है तो बताईये। अनावश्यक सदन को Divert मत करिये।

श्री लखेश्वर बघेल :- यह अनावश्यक नहीं है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, यदि इस तथ्य में किसी को कोई आपत्ति है तो बताएं। (व्यवधान)

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये, आप बजट में चर्चा मत करिये, न मांग करिये। माननीय अध्यक्ष जी के प्रयत्नों से और मुख्यमंत्री जी के प्रयत्नों से हम बस्तर को विकसित बना देंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम 2030 तक बस्तर को विकसित बना देंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- मंत्री जी यह बता देंगे कि अभी तक कितना धान नहीं उठा है और कितना नुकसान हुआ है थोड़ा उसको भी बता दीजिये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बजट के चक्कर में मत पड़िए। सब कर देंगे। आप जो बोलेंगे बस हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ये लोग किसानों के बड़े हिमायती होने की बात करते थे, आपके माध्यम से कुछ तथ्य मैं फिर से रखना चाहता हूं। बोनस की राशि जिसको राजीव किसान न्याय योजना के नाम से चार बार में किसानों को तरसा-तरसाकर देते थे। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये कितनी राशि देते थे और अंतर की राशि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कितना देती है। अध्यक्ष महोदय, ये लोग जो बोनस की राशि दिये थे वह वर्ष 2018-19 में 5979 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 5596 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 5521 करोड़ रुपये, वर्ष 2021-22 में 7000 करोड़ रुपये, 2022-23 में 5563 करोड़ रुपये दिये थे। अध्यक्ष महोदय, साढ़े 5 हजार करोड़ रुपये से 7 हजार करोड़ रुपये के बीच में ये बोनस की राशि किसानों को देते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में वर्ष 2023-24 में 13289 करोड़ रुपये बोनस की राशि दी गई है। (मेजों की थपथपाहट) वह भी एकमुश्त, एक हफ्ते के अंदर, चार बार में नहीं, एक साथ अंतर की राशि को स्थानांतरित किया गया है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- माननीय अध्यक्ष जी, उसमें जो बोनस था, क्या वह भी शामिल था। आपका जो एक पुराना बोनस पिछले 2017-18 का छूट गया था, वह उसमें शामिल था या नहीं था?

श्री धर्मजीत सिंह :- चौधरी साहब, ये लोग हलाली में ज्यादा विश्वास करते हैं। चार बार हलाल कर-करके दिये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय चौधरी साहब, यदि हलाल में विश्वास रखते हैं तो भाभी जी के लिये खास तौर पर कड़कनाथ को एस.जी.एस.टी. से फ्री कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप जारी रखिये।

श्री दिलीप लहरिया :- आप लोग 2047 में भरोसा रख रहे हैं न। इसी विजन को हम लोगों को सुनना पड़ रहा है। 14 तारीख को नहीं आये। हम लोग क्यों नहीं आये ? आप लोग 2028, 2023 का विजन रखते, 2047 का विजन रख रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तो आप उम्मीद मत पालिये। हम फिर महतारी वंदन योजना में 15 हजार रुपये देंगे, आप क्या कर लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जुबिन गर्ग को जानते हैं, वह मर गये। वह असम के सिंगर थे, सिंगापुर में डूबकर मरे हैं, वह बड़े कलाकार थे। आप भी कलाकार हैं। पानी से बचकर रहना।

श्री दिलीप लहरिया :- मैं कहना नहीं चाहता कि मैं मारता हूं, हम लोग 2047 तक रहेंगे, बाकी कई लोगों का भरोसा नहीं है, इसलिए 2047 के विजन को काटा जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, ये जो कलाकार सामने हैं न, ये एक ही चीज में पूरा चुनाव जीत गये। इनकी टीम में डांसर थी तो वह गाना गाते थे कि कटनी का चूना, सोच-समझकर छूना।

श्री दिलीप लहरिया :- इतना ही गा-गाकर हमारे पक्ष में थे, विपक्ष में लड़ रहे थे, मैं दो बार गाना गा-गाकर जीता हूं। लेकिन सही गाना गाया हूं, मैं 2047 का विजन नहीं किया हूं। मैं बोला कि इस विजन में 2028 तक खत्म हो जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपके आपके गाने की कला बता रहा हूं कटनी का चूना सोच-समझकर छूना।

श्री दिलीप लहरिया :- गिर जाबे मूड़भरसा, सड़क पाबे न धरसा, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के सड़क हे, ओला मैं गाना मा जोडे रहेव। गिर जाबे मूड़भरसा, सड़क पाबे न धरसा, बिजली अस करेंट हे कई गुना, कटनी के चूना देख ताक के छूना।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप जारी रखिये।

श्री ओ.पो.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय अटल जी बोनस के बारे में बोल रहे थे। एक बोनस की मैं और चर्चा करना चाहूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अटल जी जब बोले न तो आप एक बात को चेक करवाईये। राम वन गमन पथ 1 अरब 16 करोड़ रुपये का कम से कम था। आप उसको चेक करवाईये। वह छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। उन लोगों ने भूपेश बघेल जी के साथ में मिलकर बड़ा प्रोजेक्ट किया।

श्री रामकुमार यादव :- अयोध्या में चंदा बनाकर जमीन घोटाला करे हे, आप काबर बात करथव।

कृषि विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अरे भैया, आप लोग बंद रखो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राम भगवान को पहचानने में मेहनत करनी पड़ रही है। चंदखुरी में राम भगवान है, करके तखती लगाये हैं। ये मूर्ति राम भगवान की है, ऐसी तखती लगी हुई है। यह कांग्रेस शासन में ही हुआ।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप सबको प्रताड़ित करिये। इनको व्यवस्थित करिये, इनका भाषण होने दिया जाये। आप लोग बीच-बीच में खड़े हो जा रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने कहीं देखा है कि मैं राम भगवान हूं करके । भूपेश बघेल जी ने वह कारनामा किया है, राम भगवान हूं करके । चंद्रखुरी की मूर्ति में तख्ती लगी थी ।

अध्यक्ष महोदय :- रामविचार जी, भविष्य में इन दोनों की सीट को थोड़ा अलग-अलग किया जाये । चलिये । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोलेंगे लेकिन अलग मत करिये । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप जारी रखिये ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम पहले 2 साल का बोनस नहीं दे पाये थे उसको इन्होंने अपने जन घोषणा-पत्र 2018 में कहा था कि हम देंगे लेकिन 5 साल तक नहीं दिये और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने शपथ लेने के 12 दिन के अंदर 12 लाख किसानों को 3716 करोड़ रूपये दिये । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धान खरीदी होती है उसमें मार्कफेड को जो भी मायनस होता है वह पैसा राज्य को लगातार देना चाहिए तभी धान खरीदी Sustainable तरीके से चल सकती है । इन्होंने 5 वर्षों में मार्कफेड को मात्र 5000 करोड़ रूपये रिलीज किये थे, मैं पूरे 5 सालों का डेटा बता रहा हूं और माननीय विपक्ष के सदस्य भी सुनें कि पिछली सरकार ने मार्कफेड के साथ क्या करतूत की थी । मार्कफेड को 5 वर्षों में केवल 5000 करोड़ रूपये इन्होंने रिलीज किये, हम 2 साल के अंदर मार्कफेड को राज्य शासन से 17,000 करोड़ रूपये का प्रावधान कर चुके हैं । (मेजों की थपथपाहट) आप लोग मार्कफेड के ऊपर जो 22,000 करोड़ रूपये का मायनस छोड़कर गये थे उसी को हम पूरा कर रहे हैं इसीलिये आज 35,000 करोड़ रूपये हमको इन सब चीजों के लिये ही खर्च करना पड़ रहा है ताकि मार्कफेड अच्छे तरीके से चले और धान खरीदी अच्छी तरीके से चल सके । इसी तरह से पी.डी.एस. संचालन के लिये, जो नागरिक आपूर्ति निगम है उसमें इन्होंने 5 साल में, कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों में लगभग 16 से 17,000 करोड़ रूपये रिलीज किया था । हमारी सरकार मात्र 2 सालों में 21,000 करोड़ रूपया नागरिक आपूर्ति निगम को दे चुकी है तब जाकर पी.डी.एस. व्यवस्था संचालित हो पा रही है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन सी बात करें ? चना, गुड़, शक्कर का, सबका पेमेंट पेण्डिंग छोड़कर गये थे । इस तरह से इन्होंने जो स्थिति निर्मित की थी तो आज केवल मैं यह बताना चाहूंगा कि इस बजट में 19,224 करोड़ रूपया केवल जो धान खरीदी और पी.डी.एस. व्यवस्था अच्छे से संचालित हो । भविष्य में Sustainable तरीके से चले उसके लिये 19,224 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, यह इस अनुपूरक बजट की आवश्यकतानुसार एक बड़ा काम है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संदर्भ में आपके माध्यम से महतारी वंदन योजना का जिक्र करना चाहूंगा । हमारे विपक्ष के साथी महतारी वंतन योजना के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि यह हो गया, वह हो

गया । जो जन घोषणा-पत्र 2018 कांग्रेस ने लाया था उसमें साफ तौर पर इन्होंने लिखित में लिखा हुआ है कि माता-बहनों को हर माह 500 रूपये देंगे । कांग्रेस को सदन में यह बताना चाहिए कि इन्होंने 5 साल में एक भी माता-बहन को 5 रूपया भी नहीं दिया, इस बात को बताना चाहिए । (शेम-शेम की आवाज)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आते ही तीसरे महीने से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी महिला बाल विकास मंत्री जी के विभाग के द्वारा महतारी वंदन योजना लायी गयी और 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ बिना रूके हर माह 22 महीनों से लगातार 22 किस्तों में दिया गया है । (मेजों की थपथपाहट) और जो 22 किस्तों में दिया गया है इसके माध्यम से, 22 किस्तों के माध्यम से 14,318 करोड़ रूपये का भुगतान पिछले 2 सालों में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों के सशक्तीकरण के लिये किया है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महतारी वंदन योजना 70 लाख का केवल डेटा नहीं है, 70 लाख आशीर्वाद है, 70 लाख परिवारों का आशीर्वाद है, जो इस सरकार के साथ है उसी कारण से उतनी माताओं का, उन माताओं के परिवारों का आशीर्वाद है जो इस सरकार के साथ है । जो महतारी वंदन योजना है, उसे हमारी सरकार ने केवल महतारी वंदन योजना तक सीमित नहीं रखा है बल्कि अनेक प्रोफेशनल बैंकों के माध्यम से हमने ऋण देने की भी योजना बनायी है । महतारी शक्ति ऋण योजना भी है जो ग्रामीण बैंक और अनेक बैंक इस तरह की योजना संचालित कर रहे हैं । अगर महतारी वंदन की हितग्राही कोई माता है या बहन है तो 25,000 रूपये का माडगेज फ्री लोन किसी भी समय ले सकती है और अपनी कोई भी आर्थिक गतिविधि चालू कर सकती है, अपने पैर पर खड़े होने का कार्य चालू कर सकती है । यह केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं है, परिवार के अंदर एक माता को, एक बहन को संबल प्रदान करने वाला विषय है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला विषय है, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने वाला विषय है। यह केवल आथिक सशक्तिकरण का नहीं, आथिक सशक्तिकरण के माध्यम से राजनीतिक और समाजिक सशक्तिकरण की भी योजना है जो प्रदेश की आधी आबादी को सशक्तीकृत करने का काम कर रही है। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा से और हमारे सरकार के ऊपर आर्शीवाद के रूप से स्थापित है। माताएं, बहनें अपने संबल से किस-किस तरह के सांस्कृतिक कामों को कर पा रही हैं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दानसरा गांव में इसका बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला है। दानसरा गांव की माताओं-बहनों ने महतारी वंदन के पैसे को इकट्ठा करके राममंदिर बनाने का काम किया है। हमें इस तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी लखपति दीदी की योजना भी चला रहे हैं सुपोषण के लिए भी अनेक काम कर रहे हैं। इस अनुपूरक बजट में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण हेतु 700 करोड़ रूपये के अतिरिक्त, अनुपूरक में 277 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जो निश्चित रूप से आंगनबाड़ियों के लिए है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अगर महिलाओं के लिए है तो उधर भाभी जी ही सुपोषित हैं बाकी की तरफ उधर ध्यान दीजिए। उधर कुपोषण मुक्त करना जरूरी है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में महतारी वंदन योजना 22 महीनों से चल रही है। लोकसभा, पंचायत चुनाव के समय कई बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भ्रम फैलाने की कोशिश भी की गयी कि चुनाव के बाद यह योजना बंद हो जाएगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस हमेशा अफवाह फैलने की राजनीति करती आयी है। उन्होंने इस योजना पर भी कुत्सित प्रयास किया था। मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक यह योजना अनवरत चलती रहेगी और बिना एक भी महीने रूके, यह योजना चलती रहेगी।(मेजों की थपथपाहट) यह योजना आगे लगातार बिना बाधा के चले। इस अनुपूरक बजट में इसके लिए 2500 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है इससे माताओं बहनों के सशक्तिकरण को नया आयाम मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल्य राज्य है और हमारी जनजातिय संस्कृति का संरक्षण, हमारी सरकार का, हमारी विचारधारा का प्रमुख ध्येय है । इनके समय में इन्होंने उनकी संस्कृति को भी संरक्षण देने का काम नहीं किया । इनके समय में न उनकी पहचान को सम्मान मिला, न उनकी समृद्ध संस्कृति को कोई संरक्षण मिला। हमारे मॉडल में आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय है, अंत्योदय के कारण अनुसूचित जनजाति हमारे विकास मॉडल केन्द्र में है। हमारे लिए जनजातिय समाज, समाज का पहला तबका है, सर्वोच्च प्राथमिकता का तबका है और हमारे जनजातिय समाज के जो नायक शहीद वीर नारायण जी, शहीद गुण्डाधूर जी हैं, ऐसे जो हमारे महानायक हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था। उनके महत्व को रेखांकित करना, राज्य में स्थापित करना, हमारा आदिवासी बेटा जो मुख्यमंत्री बना है उनके प्रमुख एजेंडे का हिस्सा है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने वाले भारत देश को नेतृत्व प्रदान करने वाले श्री नरेन्द्र मोदी जी पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रहे हैं कि आजादी के आन्दोलन में हमारे जनजातिय समाज का देश भर में जो योगदान रहा, उस योगदान को रेखांकित करते हुए, उसको प्रमुखता के साथ स्थापित किया जाये। 15 नवम्बर की तारीख को, भगवान बिरसा मुण्डा जी की जयंती को जनजातिय गौरव दिवस के रूप में मानने का निर्णय लिया है। उन्होंने डिजिटल जनजातिय संग्रहालय विभिन्न राज्यों में बनाने का निर्णय लिया है। हमारे जनजातिय विभाग के काम को देख रहे, यहां हमारे वरिष्ठ आदरणीय रामविचार नेताम जी बैठे हैं वह उस विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस सदन में आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ 2 म्यूजियम जनजातिय समाज के आजादी के आन्दोलन को रेखांकित करने के लिए, उनके संघर्ष को रेखांकित करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई को लड़ते हुए दिखाने के लिए जो कांग्रेस मानती थी कि आजादी के आन्दोलन को चन्द लोगों को बीच में इन्होंने

सीमित करके रख दिया था, एक परिवार की बफौती आजादी के आन्दोलन को बनाने का कुत्सित प्रयास किया था, लेकिन आज हमारे आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे जनजातिय समाज का योगदान हो या किसी अन्य व्यक्ति का योगदान हो उसे रेखांकित करने का काम किया जा रहा है। आदरणीय रामविचार नेताम जी ने यहां पर बहुत अच्छे तरीके से जो म्यूजियम बनाने का काम आगे बढ़ाया है और नवा रायपुर में बहुत जबरदस्त फुटफॉल हो रहा है। इन चन्द महीनों में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इस म्यूजिमय का अवलोकन किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद पर आज अनेक बातें आईं और मुझे लगता है कि आपने भी 15 साल तक सबसे ज्यादा संघर्ष अपने कार्यकाल में किया, सरकार ने किया, वह नक्सलवाद के खिलाफ था । हमारे छत्तीसगढ़ में कैंसर की तरह नक्सलवाद फैला हुआ था और पूरे देश के लिए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की लड़ाई को एक केन्द्रीय रूप से लड़ता रहा, दशकों तक लड़ता रहा । माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर किस तरह की परिस्थितियों को झेला है, यह आपने और हमारे वरिष्ठ साथियों ने बहुत गहराई के साथ देखा है । जब मैं दंतेवाड़ा में प्रशासन में काम करता था और वह नक्सलिज़म का पीक था, उस समय भी मैंने बहुत करीब से देखा कि किस तरह की स्थितियां और किस तरह की परिस्थितयां थीं । 1960 के दशक में कांग्रेस की जो नीतियां थीं, कांग्रेस सरकार की जो सोच थी, उस अबूझमाड़ को दशकों तक भारत देश का अनसर्वे पार्ट ऑफ इंडिया बनाकर रखा गया, अबूझमाड़ का कोई सर्वे ही नहीं हुआ । 4000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जिसमें कोई सर्वे ही नहीं हुआ, ऐसा क्षेत्र कांग्रेस ने बनाकर रखा था । अध्यक्ष महोदय, अबूझमाड़ के अंदर किसी व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए कलेक्टर का परमिशन लगता था, किसी कलेक्टर के परमिशन के बाद ही वहां जा सकते थे । इस तरह की मानसिकता, एक संस्कृति को किस तरह से बंद करके रख दिया गया, इसका एक उदाहरण है । अबूझमाड़ के क्षेत्र में सड़क बनने से रोके गए । हजारों लोग हैजा और मलेरिया से मरते रहे और कांग्रेस सांस्कृतिक संरक्षण के नाम पर इस तरह की नीतियां बनाकर रखीं और पूरे बस्तर के साथ अन्याय करने का काम किया गया । जब मैं दंतेवाड़ा में कलेक्टर बनकर गया था तो मैं एक दिन बीजापुर की ओर जा रहा था, मुझे बीजापुर जाना था तो लोगों ने बताया कि शाम 5 बजे के बाद नहीं जा सकते, 5 बजे तक जाना है तो चले जाईए। उसके बाद कोई चांस नहीं है । इस तरह की स्थिति थी । वहां पर नेशनल हाईवे में दिन के 10:30 बजे ब्लास्ट होते थे । जिला मुख्यालय के पुलिस हेड क्वाटर पर अर्दली को गोली मारकर चले गए । 26 जनवरी की तारीख को कोई चेक इन कर रहा है, कई ऐसे प्वाइंट्स थे, जहां पर नक्सली अपना नाका लगाकर रखते थे । कोई हैल्थ वर्कर जाता था तो उससे पूछताछ करते थे, तब उसको अंदर जाने देते थे । इस तरह से क्षेत्रों का निर्माण कांग्रेस के समय की जो नीतियां थीं, उसके कारण हुए हैं । देश में एक मात्र ऐसा उदाहरण होगा, जिसमें एक बड़ा नेशनल हाईवे जो जगदलपुर से गीदम तक जाता था, गीदम के बाद वह भैरमगढ़ तक जाता था, भैरमगढ़ के बाद बीजापुर तक जाता था,

बीजापुर के बाद भोपालपट्टनम तक जाता था और भोपालपट्टनम से आगे तिमेढ़ में जाकर देश के अंदर एक नेशनल हाईवे खतम हो जाता था । आजादी के 50 सालों तक कांग्रेस ने इंद्रावती नदी पर पुल बनाने का काम नहीं किया । अगर वह पुल बन जाता तो पूरा बस्तर नागपुर क्षेत्र से और पूरा बस्तर हैदराबाद क्षेत्र से सीधा जुड़ जाता और वहां की आर्थिक गतिविधियों को, वहां की सांस्कृतिक गतिविधियों को एक नई ऊंचाई मिलती ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, 17 साल आपका राज रहा है, आपने पुल क्यों नहीं बनाया ? छत्तीसगढ़ बनने के बाद 25 सालों में 17 साल आप शासन में रहे हैं, तब आपने इंद्रावती नदी पर पुल क्यों नहीं बनाया ?

श्री रामकुमार यादव :- जे स्कूल मा चन्द्राकर जी पढ़े हे, ओला कांग्रेस ह बनाए हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अटल जी, मैंने भाषण दिया था तो एक लाईन कही थी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कैसे आया, इसमें एक बहस करवाईए, फिर उसमें वह उत्तर आ जाएगा । कितने तरह के प्रयत्न माननीय डॉ. साहब ने किये और कितने तरह से प्रयत्न माननीय विष्णु देव साय जी ने किये, वह स्पष्ट हो जाएगा । सबसे लाख टके का सवाल है कि नक्सलवाद बस्तर में घूसा कैसे, क्यों घूसा, इसमें चर्चा कीजिए ? सबूत जेब में लेके घूमथे, वो सबूत ह कहां हे ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, इस तरह का हाल नेशनल हाईवे का था। जगरगुण्डा दक्षिण बस्तर का सबसे बड़ा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक केन्द्र था । 1990 के दशक में जब वहां पर नक्सलवाद नहीं आया था तो वहां पर विभिन्न तरह के आफिस हुआ करते थे । 1990 के दशक के वहां पर बैंक की बिल्डिंग थी, वहां पर ग्रामीण विकास बैंक की शाखा थी, पूरा बैंक चलता था । दक्षिण बस्तर का सबसे बड़ा हाट बाजार जगरगुण्डा में लगता था । वहां पर नक्सलवाद जब पांव पसारता गया, इस तरह की स्थितियां बनीं कि वह पूरी तरीके से टापू बन गया, किसी को जगरगुण्डा जाना होता था तो हेलीकाप्टर से जाया जा सकता था । अध्यक्ष महोदय, जब आपने मुझे वहां पर कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया तो मैं दूसरे-तीसरे दिन पालनार, फूलपार झरना चला गया था । मुझे आधे घण्टे के अंदर एस.पी. का फोन आ गया कि फूलपार झरना के पास हो क्या कलेक्टर साहब, तो मैं बोला हां। तब एस.पी. ने पूछा कि वहां पर नक्सली मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं या नहीं ? इस तरह की स्थिति पालनार में थी। दिन में नक्सली घूमते थे, इस तरह के हालात पालनार जैसे जगह में थी। उस पालनार में जहां दिन में नक्सली घूमते थे, वहां से 9 किलोमीटर आगे समेली होता था, उसके 9 किलोमीटर आगे अरनपुर होता था, उसके 6 किलोमीटर आगे कोण्डा सांवली होता था। उस कोण्डा सांवली से 10-12 किलोमीटर बाद जगरगुण्डा आता था। अध्यक्ष महोदय, वह पूरा रोड खत्म हो गया था। वह नक्सलियों की राजधानी जैसा बन गया था। वहां नाका लगा रहता था, यदि वहां से कोई एन्ट्री करना चाहता था तो

उसकी चेकिंग होती थी। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई मितानीन जाना चाह रही है तो वहां पर चेकिंग होती थी। वहां पर उनको घेरा जाता था, वहां उनसे एक-एक चीज को पूछा जाता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय आपके नेतृत्व में प्रदेश चल रहा था। आपके संबल से वहां पर रोड बनाने का काम चालू हुआ। अभी भी याद आता है कि वहां पर कैसे रोड बनता था। रोड बनाने के लिए दो-तीन सौ सी.आर.पी.एफ. और लोकल पुलिस के जवान, सब मिलकर रेडी मिक्स की गाड़ियों को, सीमेन्ट की गाड़ियों को घेरते थे, मजदूरों को घेरते थे और 3 सौ लोगों को सड़क बनाने के लिए ले जाते थे। चारो ओर से ए.के.-47 से घेरे रहते थे। बीच में 3-4 घण्टे रोड बनाने का काम चलता था और 3-4 बजे के बाद वापस आना पड़ता था। इस तरह से रोड बनता था। वहां पर रोड बनाने के लिए अनेक जवानों की शहादत हुई है। बीजापुर में गंगालूर की तरफ से जगरगुण्डा जाये तो उस रोड को बनाने के लिए अनेक लोगों की शहादत हुई। सुकमा तरफ से दोरनापाल-चिंतलनार गुफा होते हुए जगरगुण्डा जाये, उसमें अनेक जवानों की शहादत हुई। आज जब नक्सलवाद सब तरफ से अपनी सांसें गिन रहा है तो मैं उन जवानों की शहादत को सलाम करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं। उन जवानों ने अपने प्राणों तक को त्यागा, भारत देश के अंदर एक क्षेत्र ऐसा ना हो, जिसमें भारत राष्ट्र की संप्रभुता ना चले। संविधान में, किसी भी राज्य की परिकल्पना में जब concept principle of state पढ़ते हैं तो संप्रभुता सबसे बड़ी चींज होती है। किसी राज्य की sovereignty, उसके अंदर राज्य सुप्रीम होता है, सर्वोच्च होता है। लेकिन भारत देश के अंदर एक ऐसा क्षेत्र बन गया था, जिसमें राज्य की sovereignty, राज्य की संप्रभुता सर्वोच्च नहीं थी। वहां इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए थे। बड़ी-बड़ी नक्सली घटनाएं होती थीं। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता था, जिसमें प्रशासन को लाश उठानी नहीं पड़ती हो। काफी बड़ी-बड़ी घटनाएं होती थीं। अध्यक्ष महोदय, ताड़मेटला की 6 अप्रैल, 2010 की तारीख याद है जब एक साथ 76 जवानों की शहादत हो गई। आजाद भारत के इतिहास में यदि टेररिजम को भी जोड़ लें, पूरा जम्मू कश्मीर को भी जोड़ लें, Insurgency in Northeast India को भी जोड़ ले तो भी इससे बड़ी घटना घटित नहीं हुई, इतने दुर्भाग्यजनक हालात हमारे छत्तीसगढ़ में थे। अध्यक्ष महोदय, झीरम की दुर्भाग्यजनक घटना हुई। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की शहादत हुई। इस तरह की स्थितियां नक्सलवाद में बनती थीं। कहीं 20 जवानों की शहातद हुई, कहीं 26 जवानों की शहादत हुई, कहीं 30 जवानों की शहादत हुई। हर दिन ऐसी घटनाएं घटित होती थीं। उन परिस्थितियों से बस्तर जूझ रहा था। हमारा छत्तीसगढ़ उन परिस्थितियों से जूझ रहा था।

अध्यक्ष महोदय, आज आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नक्सलवाद पर पिछले 2 सालों से किस प्रकार से प्रहार हुआ, सब देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने भी अपने 15 सालों के कार्यकाल में बहुत संघर्ष किया है। ऐसा कोई सप्ताह नहीं जाता था, जब आप बस्तर नहीं आते थे। उस समय की

परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। उस समय सेन्ट्रल का उस तरह से सहयोग नहीं मिल पाता था। उस तरह का फोर्स नहीं मिल पाता था। फिर भी आपने संघर्ष किया। लोग डबल इंजन की सरकार का मजाक उड़ाते हैं। डबल इंजन की सरकार में यह हो गया, वह हो गया, बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कैंसर को इस डबल इंजन की सरकार ने दूर करने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ के कोई भी विकास की परिकल्पना, छत्तीसगढ़ का कोई भी विजन, छत्तीसगढ़ का कोई भी मिशन इस नासूर को, इस कैंसर को समाप्त किए बिना सम्पन्न नहीं हो सकता था। यह डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है। यह डबल इंजन सरकार की करामात है कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पिछले 2 सालों में जिस तरह से नक्सलवाद को सफाया करने का काम किया गया, जिस तरह से नक्सलवादियों को सरेण्डर कराने का काम किया गया, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार बस्तर में सक्रिय रहकर जिस तरह से फौज का हौसला अफ़ज़ाई करते रहे, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी जिस तरह से संघर्ष करते रहे, इन 2 वर्षों की इससे बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ की दृष्टि से कोई हो ही नहीं सकती है।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अमित शाह जी, जब महीने में 3 बार छत्तीसगढ़ आये तो मैं अनेक लोगों को देख रहा था कि उस पर भी मजाक उड़ा रहे हैं। अगर देश का गृह मंत्री छत्तीसगढ़ की धरती पर आते हैं, अगर देश का गृह मंत्री छतीसगढ़ की धरती पर तीन बार आता है, अगर देश का गृह मंत्री बस्तर की जमीन पर साल में अनेकों बार जाता है और नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष करता है तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार किए जाते हैं। (शेम-शेम की आवाज) यह कुत्सित मानसिकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष में जरा भी सकारात्मकता होती, जरा भी रचनात्मकता होती तो आदरणीय अमित शाह जी का, पक्ष-विपक्ष दोनों को मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से नागरिक अभिनंदन करना चाहिए था। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ जनों को खोया है। उनकी शहादत हुई है। उनके परिवार हैं। आज उन लोगों के दिल को राहत मिलती होगी। अध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे वरिष्ठ शहीद हुए हैं, कांग्रेस के भी जो वरिष्ठ शहीद हुए हैं, हमारे भीमा मंडावी जी जैसा नेतृत्व शहीद हुआ है, जिस दिन भीमा मंडावी जी की शहादत हुई, महेंद्र कर्मा जी की शहादत हुई, नंद कुमार जी की शहादत हुई, विद्याचरण शुक्ला जी की शहादत हुई, कांग्रेस के और अनेक नेताओं की शहादत हुई, आज भी मैं उस घटना को भूल नहीं पाता हूं। जिस भीमा मंडावी जी की जिस दिन शहादत हुई, ठीक 24 घंटा पहले मैं उनके साथ सात घंटे तक पॉलिटिकल कैंपेनिंग किया था और उसी के जस्ट 24 घंटे बाद भीमा मंडावी जी को हमने खो दिया। आज चाहे वह नंद कुमार पटेल जी की आत्मा हो, चाहे वह महेंद्र कर्मा जी की आत्मा हो, चाहे वी.सी. शुक्ला जी की आत्मा हो, चाहे भीमा मंडावी जी की आत्मा हो, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयत्न को, इस राजनीतिक इच्छा शक्ति को, इस क्रियान्वयन को, हमारे मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास को, अमित शाह जी के संकल्प को निश्चित रूप से वह आत्मा आशीर्वाद दे रही है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, अगर राजनीतिक नैतिकता कुछ भी विपक्ष में अगर बची

हुई है तो ऐसे विषयों पर कम से कम विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, नक्सल मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है। लगातार हम बस्तर जा रहे हैं। हमारे सभी मंत्रियों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लगातार बस्तर जाइए। वहां अपने-अपने विभागों के कामों को आगे बढ़ाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं जगरगुंडा की बात कर रहा था, पालनार से उतना दूर तक कभी हम सपने में नहीं सोच पाते थे कलेक्टर रहते हुए कि कभी सड़क से पहुंच पाएंगे। उस समय कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि नक्सलवाद क्या कभी खत्म हो पाएगा ? ऐसी हिम्मत नहीं होती थी। आज अमित शाह जी के कारण खत्म हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, वह पूरी रोड बन गई। मेरे को पता चला कि फोर्स को मैंने पूछा, एस.पी. को पूछा, आई.जी. को पूछा कि जगरगुंडा बाय रोड जा सकते हैं क्या? तो बोले हां जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं जगरगुंडा जाने के लिए इसलिए निकल रहा था, क्योंकि सन् 2000 में जिस ग्रामीण बैंक को नक्सलियों ने उड़ा दिया था, जिसको लूट लिया था, उसी बिल्डिंग को हमने रिनोवेट किया और वहां पर इंडियन ओवरसीज बैंक का बैंक ब्रांच खोले। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, उस जगरगुंडा में बैंक ब्रांच खोला और उस बैंक ब्रांच में मुझे जाना था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन जुड़कर उसका हमको इनॉगरेशन करना था। मेरे को जब पता चला कि जगरगुंडा हम बाय रोड जा सकते हैं तो मैं रायपुर से बाय रोड निकला और 500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जगरगुंडा तक सीधा बाय रोड गए। अध्यक्ष महोदय, आज हम जगरगुंडा के अंदर जाने की अगर परिकल्पना कर पा रहे हैं, उस दर्द को हम भूल नहीं सकते कि हम नक्सलवाद के उन परिस्थितियों से हमारी सरकार वापस लाने में सफल हुई है। अध्यक्ष महोदय, आज बस्तर पंडुम हो, बस्तर ओलंपिक हो, किस तरह से बस्तर के लोगों का विश्वास जुड़ रहा है, किस तरह से बस्तर में पर्यटन की संभावनाओं को विकास मिल रहा है। हम अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, पर्यटन नहीं आया। इस तरह की चर्चाएं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या थी तो परसेप्शन की समस्या थी। अगर छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति चाहे वह कोरबा का हो, चाहे वह रायगढ़ का हो, चाहे वह रायपुर का हो, दिल्ली में बॉम्बे में बैठा हो और अगर बोलता था कि मैं छत्तीसगढ़ का हूं तो उसके लिए बोला जाता था, अच्छा, आप लोग सुरक्षित तो रहते हैं? मान लीजिए रायगढ़ दंतेवाड़ा से 600 किलोमीटर दूर है। हमारा रायपुर दंतेवाड़ा से 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन सबके लिए लोग ऐसे सोचते थे। अभी मेरे को याद आता है एक बड़े इंटरप्रेन्योर हैं, एक दिन आए, रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे और मेरे साथ वी.आई.पी. रोड पर चलने लगे तो वी.आई.पी. रोड में हमारी अच्छी हरियाली है तो उन्होंने धीरे से पूछा बहुत पेड़ पौधे जंगल टाइप लग रहा है, यह सुरक्षित तो है ना ? गोली तो नहीं चल जाएगी? अध्यक्ष महोदय, इस तरह का परसेप्शन था। कैसे इन्वेस्टमेंट आता ? कैसे पर्यटन आता ? इस कैंसर को समाप्त करने का काम आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। (मेजों की

थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, पुलिस व्यवस्था के लिए इस बजट में इस अनुपूरक बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। 452 करोड़ रुपए का प्रावधान पुलिस अपग्रेडेशन और अन्य मदों में किया गया है। इस अनुपूरक बजट में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 117 करोड़ रूपये, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एवं राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर के लिए 22 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए प्रावधान हुआ है तो मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में सन् 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तब हम लोग 12वीं पास होकर निकले थे। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर का स्थान नहीं था। मेडिकल कॉलेज की 100 सीटें थीं। उस समय केवल एक मेडिकल कॉलेज था। आज छत्तीसगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज से 14 से अधिक मेडिकल कॉलेज हो गये हैं। यह 20 संख्या की संख्या को बहुत जल्द पार करने वाली है। एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। आपके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में आई.आई.टी. बना, आई.आई.आई. बना, एच.एन.एल.यू. बना, आई.आई.एम. बना, एम्स बना, नीट बना, एन.आई.टी. बना, सिपेड बना आदि इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान आये। (मेजों की थपथपाहट) पिछले पांच साल में कांग्रेस सरकार के समय एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं आया। कांग्रेस पार्टी को इस बात का आत्ममंथन करना चाहिए। जनता ने उनको भी पांच साल का अवसर दिया था। पांच साल में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, इन दो सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में तीन नये राष्ट्रीय स्तर के संस्थान नवा रायपुर में आने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। दो साल के अंदर उनकी पूरी तरह से स्थापना हो जाएगी। NIFT (National Institute of Fashion Technology) की स्थापना हो जाएगी, The National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) की स्थाना हो जाएगी, National Forensic Sciences University (NFSU) की स्थापना हो जाएगी। (मेजों की थपथपाहट) सतही आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर डिलेव्हरी पर बात करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उद्योगों की बात होती है। सबसे बड़ा चीज मैं बस्तर के संदर्भ में एक और तथ्य रखना चाहूंगा। आपने ही उस दिन बस्तर से अवगत कराया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया। अभी कुछ दिन पहले ही आदरणीय अमित शाही जी आये थे, उन्होंने सार्वजनिक मंच से ऐलान किया कि वर्ष 2030 तक बस्तर देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग होगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- लखेश्वर जी, आप इसको नोट कर लीजिये। आप चाहेंगे तो पेन-कागज रख लीजिये।

श्री बघेल लखेश्वर :- 2030 में नोट करेंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- 31 मार्च को भी देखियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- 31 मार्च, 2026 को नोट कर लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- नोट करे के काम ला तूं हर करा। तूं हर आगे मा रहे रहौ। आप बस दोनों के ला नोट करत रइहौ। ओइच तो तुंहर काम हे।

श्री सुशांत शुक्ला :- तैं हर रेस्ट हाऊस मा नोट गिने के काम करे रहे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आगे पढ़ेंगे तो यह सब ऐतिहासिक दिवस रहेगा। आप 31 मार्च, 2026 और वर्ष 2030 को नोट कर लीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- आने वाला समय बताही कि कोन नोट वाला हे अऊ कोन वोट वाला हे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप काफी हैं। हम लोग सुन लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- वित्त मंत्री जी हर बोल देहे कि तोर कड़कनाथ हर एस.जी.एस.टी. से फ्री रिही। (हंसी)

श्री अनुज शर्मा :- आप लोग दिल से तो सचमुच खुश होते होंगे। आप लोगों को लगता होगा कि क्या करें?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वक जगरगुंडा गये हैं। जब मेरे भी परिवार के लोग थे तब मैं भी जगरगुंडा जाकर आ गई हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुपोषण मा भी तोर छोड़, बाकी ओहर सबके ख्याल रखही।

श्री रामकुमार यादव :- शुक्ला जी, बिलासपुर मा स्क्वेयर फीट मा का हे? (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ओ डहर ज्यादा कुपोषण दिखत हे। आप मन पहिली अपन कुपोषण ला ठीक कर लेओ, तब फिर आगे बात करिहौ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2030 का देश का सर्वाधिक विकसित जनजातीय संभाग बस्तर होगा। यह भी डेडलाईन आदरणीय अमित शाह जी ने दे दिया है। जब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तब उन्होंने पहले ही अपने visit में कहा था कि दिनांक 31.03.2026 तक पूरा देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। (मेजों की थपथपाहट) जब उन्होंने सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति का डेट दिया तो भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाने का दु:साहस किया। अमित शाह जी की प्रतिबद्धता को, उनके कमिटमेंट को पूरा देश जानता है। वह शख्स जो धारा 370 को समाप्त कर सकता है। (मेजों की थपथपाहट) अब तो लोगों को लगने लग गया कि 31.03.2026 से पहले ही नक्सलवाद खत्म न हो जाये। सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो जायेगा। उनको निश्चित से पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों को यह बताना चाहिए, यह स्पष्ट करना चाहिए कि हिड़मा को न्यूट्रलाईज करने की सफलता पर कांग्रेस का क्या रूख है?

श्री रामकुमार यादव :- गोडसे ला तुमन काय मानथौ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अतेक ऊँचा बात तोला समझ में आय नइ रामकुमार ? ज्यादा ऊँचा बात तैं मत बोले कर । हल्का बात में बोले कर ।

श्री रामकुमार यादव :- तैं अपने आप ला समझे कर ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि बस्तर के विकास के लिये आगामी वर्षों में 1 लाख 30 हजार करोड़ रूपये खर्च किया जायेगा, ताकि बस्तर सर्वाधिक विकसित संभाग हो सके । इस अनुपूरक बजट में उद्योग पर भी अनेक प्रावधान किये गये हैं, मैं बताना चाहूँगा कि उद्योग के संदर्भ में हमारी सरकार के आते ही वर्ष 2024 से वर्ष 2030 तक नई औद्योगिक नीति की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिससे सबसे काम्पिटिटिव औद्योगिक नीति हमारी बने, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है । आज गुजरात की सरकार में बैठे लोग, मध्यप्रदेश सरकार में बैठे लोग, छत्तीसगढ़ के लोगों को फोन करके बोलते हैं कि हम आपस में काम्पिटिशन न करें । तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हम आपस में काम्पिटिशन कर लेते हैं, इसलिये इन्वेस्टर्स का ज्यादा भाव बढ़ रहा है । इन राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ के विभागों को फोन कर बोलते हैं । अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य को राज्य बनने के पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता था, अगर गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग बोलते हैं कि हम आपस में कांपिटिशन कर रहे हैं, यह 25 सालों में छत्तीसगढ़ के लिये बहुत बड़ा अचीवमेंट है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 से 2030 तक के लिये जो औद्योगिक नीति आदरणीय विष्णु देव साय जी ने लाया है, उसका मूल उद्येश्य रोजगार सृजन है । फिलासफी में पूरी तरह चेंज किया गया । पहले जो औद्योगिक नीति की फिलासफी थी कि 1000 करोड़ का निवेश आयेगा तो यह छूट दी जायेगी, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो यह छूट दी जायेगी, इस तरह का प्रावधान किया जाता था । आदरणीय विष्णु देव साय जी के बाद हमारी सरकार ने कहा है कि 1000 हमारे छत्तीसगढ़िया भाई-बहनों को रोजगार दोगे तो यह छूट देंगे । 2000 को रोजगार दोगे यह यह छूट मिलेगी । औद्योगिक नीति के फिलासफी को चेंज किया गया । अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा कि हमारी जो छत्तीसगढ़ की जीडीपी है, उसमें सर्विस सेक्टर का और लेबर इंटेसिव मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का, कम रोल रहा है । सर्विस सेक्टर लेबर इंटेसिव मैनुफैक्चरिंग में ज्यादा रोजगार पैदा होगा । हमारा जो इकॉनामी है वह दशकों से कोर सेक्टर पर आधारित रहा है । यदि स्टील में निवेश होता है तो 1 करोड़ के निवेश पर आधा से भी कम रोजगार पैदा होता है । टेक्सटाईल्स है, आई.टी. है, बीपीओ है, गारमेंट सेक्टर हैं, इस तरह के जो सेक्टर हैं, उसमें 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 20, 30, 40, 50 तक के रोजगार पैदा होते हैं । अध्यक्ष महोदय, जो नई औद्योगिक नीति है, नये रोजगारपरक सेक्टर को ज्यादा प्राथमिकता प्रदान करती है । (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाईल्स सेक्टर में निवेश हेतु 800 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव नई औद्योगिक नीति के तहत प्राप्त हुये हैं, जिससे 10 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा । छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति से आकर्षित होकर आई.टी.सेक्टर में 100 करोड़ से अधिक के निवेश प्रोत्साहन प्राप्त हुये हैं । सेमी कंडक्टर क्षेत्र में नया रायपुर में 11,000 करोड़ के प्रस्ताव उद्योग विभाग

को प्राप्त हुआ है । इस तरह से बहुत ही ऐतिहासिक रूप से चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, बाम्बे हॉस्पीटल का आना हो, सेमी कंडक्टर का आना हो, एआई डाटा सेंटर का आना हो, टेक्सटाईल्स सेक्टर की दिशा में कुछ अच्छे प्रयास हो रहे हों, यह छत्तीसगढ़ की इकॉनामी को बदलने के लिये, छत्तीसगढ़ की इकॉनामी में क्रय क्षमता बढ़ाने के लिये, छत्तीसगढ़ के युवा भाई-बहनों के लिये अधिकाधिक रोजगार सृजन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बहुत फोकस करते हैं, बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लॉन पर बहुत फोकस करते हैं और उनका ध्येय रहता है कि प्रोसेस सिंपलीफाई हो, इससे औद्योगिक निवेश ज्यादा अच्छे तरीके से हो गये हैं । जैसे आज राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है, वैसे ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिये विभिन्न देशों के बीच भी कांपिटिशन चल रहे हैं । नरेन्द्र मोदी जी एक विजनरी लीडर होने के कारण इन बातों को समझते हैं और उन्होंने कहा है कि यह जो पूरा कानून है, उसको सिंपलीफाई करने का काम किया जाये । अंग्रेजो के जमाने का कानून है, जिनका माईंडसेट था रूल करना । एक औपनिवेशिक देश को कंट्रोल करना । इस माइंडसेट के साथ उन्होंने जो रूल बनाये थे, जो कानून बनाये थे, उसको सिंपलीफाई किया जाये । अध्यक्ष महोदय, इसके तहत जन विश्वास बिल लाने का काम पिछले मानसून सत्र में उद्योग विभाग ने, हमारे उद्योग मंत्री जी ने किया था और सदन से जन विश्वास बिल का पहना चरण पास हुआ । इस सत्र में भी जन विश्वास बिल का दूसरा चरण पटल पर रखा जा चुका है, उस पर कल चर्चा होगी । जन विश्वास बिल का दूसरा चरण प्रस्तुत करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है । (मेजों की थपथपाहट) जिसमें 1167 जटिल अनुपालनों की पहचान कर सुधारात्मक कार्रवाई इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत् की जा रही है। 231 प्रावधानों को अपराधमुक्त करना, 369 प्रक्रियाओं को डिजिटल करना, 194 प्रावधानों को सरलीकृत करना, 14 प्रावधानों में अनावश्यकता समाप्त करना, इस तरह के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नागरिक केन्द्र सुधार किए गए हैं। उद्योग विभाग की दृष्टि से इस अनुपूरक बजट में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 200 करोड, औद्योगिक ईकाइयों को लागत पूंजी अनुदान देने के लिए 130 करोड़ और उद्योगों में ब्याज अनुदान देने के लिए 25 करोड़, टोटल 355 करोड़ रूपए का अनुपूरक में बजटीय प्रावधान किया गया है, इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी के बारे में भी बहुत चर्चा होती है। जी.एस.टी. के बारे में सब बोलते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी बोला करते थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, गब्बर सिंह टैक्स जी.एस.टी. के पहले का टैक्स था जो गब्बर सिंह टैक्स था, राज्यों और केन्द्र के लगभग 17 प्रकार के अलग-अलग टैक्स थे, 13 प्रकार के सेस थे, अलग राज्य अपनी मर्जी से अलग चीजें आरोपित करता था, कभी भी मन करे रेट को बढ़ा लेता था, कभी भी मन करे रेट को घटा लेता था, हर राज्य को पार करने के लिए एंट्री टैक्स देना पड़ता था, उस राज्य के बॉर्डर पर गाड़ियां लाईनों में खड़ी रहती थी, चुंगी जैसे चीजें होती थी, इस

तरह से बिजनेस को असंभव सा बना दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने इस रिफॉर्म की दिशा में कभी दशकों तक नहीं सोचा, दशकों तक काम नहीं किया।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अगर आप जी.एस.टी. की बात कर रहे हैं, जैसा मुझे याद है, आपके नेताओं का बयान है कि ऑल ओवर इंडिया में जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इसकी बात हुई तो उन बड़े नेताओं का बयान था कि ये लागू नहीं किया जा सकता, आदरणीय राहुल जी ने जो बोला चूंकि संदर्भ आना नहीं चाहिए लेकिन आया है तो उन्होंने इस बात को कहा था, जी.एस.टी. जिस रूप में लागू हुई थी, वे उसके खिलाफ थे और उन्होंने कम भी किया है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, यू.पी.ए. के समय में 2004 से 2014 तक केवल बात ही होती थी। अभी हमारे कोई साथी बोल रहे थे कि आधार की बात हमने की थी, अब जी.एस.टी. की बात हमने की थी बोला जा रहा है, जो आधार सीडिंग है, उसकी बात हमने की थी बोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बात तो सारी की गई थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी वित्तीय व्यवस्थाओं के अच्छे समझदार व्यक्ति भी थे, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक सुधारों के लिए कितना जरूरी होता है। अध्यक्ष महोदय, मनमोहन सिंह जी, 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे लेकिन देश की अर्थव्यवस्था 10वें से 10वें नंबर की ही अर्थव्यवस्था बनी रही, उनको कोई काम करने ही नहीं दिया गया, रिमोट कंट्रोल से चलाया गया, उनको [xx] बनाकर रखा गया, उनको नेशनल एडवायजरी काउंसिल बनाकर कंट्रोल करने का काम किया जाता था। उस सरकार द्वारा बनाए गए अध्यादेश को मीडिया के सामने फाड़ा जाता था।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक **Honourable Prime Minister** जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनको [xx] बोलना, ये Objectionable है। **This is objectionable to the point.**

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, उनको दूसरे बनाकर रखे थे, मैं थे नहीं बोलता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को फाड़कर फेंके न, उसी कानून के तहत् ही वे अयोग्य घोषित हुए।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- उसमें वे अयोग्य कैसे घोषित हुए **?**

श्री अजय चंद्राकर :- अयोग्य इसलिए घोषित हुए कि मनमोहन सिंह जी सुधार ला रहे थे उसको फाड़कर फेंक दिया। पुराना कानून था जिसके तहत् वे अयोग्य हुए। अब बहरहाल राहुल गांधी जी तो आपको पहचानते नहीं, वे छत्तीसगढ़ में सिर्फ देवेन्द्र यादव जी भर को पहचानते हैं। ये ध्यान रखिए और क्यों पहचानते हैं उसको समझ लीजिए। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपसे विनम्र आग्रह है कि शीघ्र ही छत्तीसगढ़ का दौरा भी कराएं, राहुल जी का दौरा भी बनवा लीजिए। अभी आप लगातार दो तीन साल दौरा करा लीजिए तो हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। (हंसी)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उनके एक दौरे में आप 15 सीट में आ गए थे। धोखा खा जाएंगे, जब उन्होंने पिछली बार संकल्प लिया था, किसानों का कर्ज माफ, 2500 दाम तो आप लोग 15 सीट में आ गए थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक बार आईसक्रीम के धोखे में जनता चूना चांट ली है, बार-बार नहीं चांटने वाली।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ये बात हमारे उपर ही लागू नहीं होता, आपकी तरफ भी हो सकता है।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004 से 2014 तक देश में जो पॉलिसी पैरालिसिस था, वह सबको पता है। मनमोहन सिंह जी बैंकिंग सेक्टर को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। 2008 से 2014 तक जो स्थिति उत्पन्न हुई थी। वर्ष 1947 से 2008 तक 61 सालों में देश की बैंकिंग व्यवस्था ने टोटल 18 लाख करोड़ रूपये का लोन दिया था और वही वर्ष 2008 से 2014 तक यू.पी.ए. के भ्रष्टतम समय में 8 सालों में 16 लाख करोड़ रूपये के लोन बांट दिये गये। पूरी बैंकिंग सिस्टम को instable करने का कृत्य यू.पी.ए. की सरकार ने किया था। मनमोहन सिंह जी अपने मन से कभी ऐसा नहीं करते, जब तक उन पर दबाव नहीं होता। वही समय था, जिसमें यश बैंक के व्यक्ति ने 2 करोड़ रूपये की पेंटिंग खरीद ली थी। यह उस तरह का बैंकिंग का समय था। इस तरह से देश की व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया गया। वही मनमोहन सिंह जी वर्ष 1991 से 1996 के बीच में वित्त मंत्री के रूप में अच्छा काम किए। प्रधानमंत्री के रूप में नहीं कर पाये, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में कर पाये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- नीरव मोदी कैसे भागा? माल्या किसके कहने पर भागा? उस समय किसकी सरकार थी?

श्री ओ.पी. चौधरी :- नीरव मोदी और माल्या को किसने लोन दिया था?

श्री अटल श्रीवास्तव :- और उनको भगाया किसने था? वह विदेश जाकर बोल रहा है कि आप लोगों ने उसको भगाया। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उसको भगाने का काम आपकी सरकार ने किया। नीरव मोदी को आपने भगाने का काम किया। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप कलाकार हैं न। जो माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, उसको सुनिये।

श्री रामकुमार यादव :- ओ कलाकार ए अउ आप विलन हो। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कि प्रियंका जी चित्र बनाती हैं? प्रियंका जी की चित्र को यश बैंक के सी.ओ. राणा कपूर को साढ़े 3 सौ करोड़ रूपये में बेचा और फरार हो गया। आप पता कर लो कि उसकी पेंटिंग को साढ़े 3 सौ करोड़ रूपये में खरीदा है या नहीं खरीदा है? क्या आप कोई

कांग्रेसी यह जानते हो कि प्रियंका गांधी जी फोटो बनाती है? (व्यवधान) जाते हो एक नंबर, दो नंबर करने के लिए।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्य बार-बार बोल रहे हैं, इसपर कंट्रोल किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, दिल्ली की बहस नहीं हो रही है। आप अपनी बात जारी रखें। आप बैठिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991 से 1996 के बीच में मनमोहन सिंह जी ने अच्छा काम किया। उसमें पीछे में पी.वी. नरसिम्हा राव जी का सपोर्ट था। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि पी.वी. नरसिम्हा राव जी के साथ कांग्रेस ने क्या किया। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। (शेम-शेम की आवाज) इन्होंने दिल्ली में उनका शांति स्थल भी बनने नहीं दिया। इंदिरा जी का बनाया गया, जवाहर जी का बनाया गया, सबका बनाया गया, परंतु पी.वी. नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया गया। कांग्रेस के हेड क्वार्टर में श्रद्धांजली के लिए उनके पार्थिव शरीर को नहीं रखने दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस भवन नहीं ले गये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, हम राज्य की बात सुनना चाह रहे हैं। आप केन्द्र की बात लेकर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। मंत्री जी, आप राज्य की बात कीजिये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जी। अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. में जो सुधार हुए, वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जी.एस.टी. में आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने बड़े reforms किए। जी.एस.टी. के पहले लगभग साढ़े 12 प्रतिशत सेन्ट्रल एक्साइज अलग लगता था, लगभग 5 प्रतिशत वैट अलग लगता था, 1 प्रतिशत के लगभग एन्ट्री टैक्स अलग लगता था। उस समय tax terrorism था। साढ़े 18 प्रतिशत से 20-22-25 प्रतिशत तक टैक्स हो जाते थे। जब आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 1 जुलाई, 2017 को जी.एस.टी. लेकर आये तो सीधे इनकी दरों में बहुत तेजी से कमी आई। जब जी.एस.टी. की व्यवस्था stabilized हो गई। देश की इकोनॉमी reforms के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगी। देश में न केवल indirect taxes, बल्कि direct taxes में भी अच्छा ग्रोथ आने लगा। वर्ष 2017 में हमारे देश में जो direct tax था, वह लगभग 10 लाख करोड़ था और वर्ष 2025 के आते-आते तक वह 20 लाख करोड़ से ऊपर तक हो गया। direct taxes में income tax, personal income tax और corporate tax दोनों शामिल थे। जैसे-जैसे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो direct taxes बढ़ने चाहिए और indirect taxes का रेट कम होना चाहिए। वही नरेन्द्र मोदी जी ने करके दिखाया है, क्योंकि indirect taxes से सीधा गरीब प्रभावित होता है और direct tax अमीर लोग pay करते हैं। यह नरेन्द्र मोदी जी का विजन है। यह डेव्हलपिंग इंडिया को डेव्हलप्ड इकोनॉमी

बनाने का विजन है। नरेन्द्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है। नरेन्द्र मोदी जी जैसा विजन है, जो इंकम टैक्स में एक साथ 12 लाख रूपये तक की छूट देने की क्षमता रखता है। एक साथ जी.एस.टी. में इतने सारे सुधारों को, रेट को कम करने की क्षमता रखता है।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप स्टेट में बोलिये न। आप तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हम मोदी जी को सुनने नहीं आये हैं।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. पूर्णरूपेण स्टेट का विषय है। यह स्टेट का बराबर का विषय है। जी.एस.टी. के reforms पर आपने भी बात कही थी, इसलिए मैं इस विषय को रख रहा हूं। जी.एस.टी. में उन्होंने सीधे 5 में से 2 स्लैब को हटाकर 3 स्लैब में ला दिया। आयकर की सीमा को 12 लाख तक बढ़ाने का काम किया। यही नरेन्द्र मोदी जी की reforms की ताकत है, इसलिए वह कर पाते हैं। इसके अलावा खेल की दृष्टि से भी अनेक बजटीय प्रावधान किये गये हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केबिनेट ने खेल की दृष्टि से हमारे शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम को राज्य के क्रिकेट संघ को देने का एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और इसी का परिणाम है कि अब हमारे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स कल्चर डेव्हलप हो रहा है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ। सारे कांग्रेस के लोग भी देखने आये।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, ओ मा टिकट नइ मिलय। विधायक मन ला टिकट नइ मिलय। ए ला तुमन बेचे हव तो हे। ओला देय हव तो अतका में हमर में तो टिकट मिलय। यह पहली बार होये हे कि टिकट नइ मिले हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है कि हमको एक भी टिकट नहीं मिला है।

श्री रामकुमार यादव :- वो टिकट हर ब्लैक में बेचे हवय।

श्री धर्मजीत सिंह :- सिर्फ तुमन भर ला नइ मिले हे, ऐसा नइ हे। हमू मन ला नइ मिले हे। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- अब तुहर दशा ला सोच लेवव कि कैसे हे तेला।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि अगली बार हमारे साथ इनके लिए भी टिकट की व्यवस्था कर दीजिएगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, आप मन ये बता देवव कि मैच देखे ला छोड़ के आप मन बैला ला दुहे कैसे सीख गे हस ? (हंसी) गाय ला तो सब दुहथे, आप तो बैला ला दुह देथस। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- अब आप हर मोर कलाकारी ला समझ गय हव न ? अब आप मन मोर कलाकारी ला समझ गे हवव तो हिसाब से रहिबे। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हमको थोड़ा परिपक्व होना पड़ेगा। हम यदि बोलेंगे कि हमको टिकट की व्यवस्था हो तो यह उचित नहीं है। हमको टिकट खुद खरीदने की दिशा में सोचना पड़ेगा। आज वह समय है। अध्यक्ष महोदय, इंडिया और अफ्रीका का इंटरनेशनल मैच हुआ तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला वन-डे इंटरनेशनल मैच हुआ है। हमको टिकट मिला कि नहीं मिला से ऊपर उठने का समय है। छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल वन-डे मैच हो रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है कि टिकट ब्लैक में बिका है। यदि हम ब्लैक के टिकट को आपके सामने उजागर करें तो बहुत बड़ी बात होगी।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, 50 रूपये के टिकट हर 2 हजार रूपये में बिके हे। तुमन ला जोहार हे गा।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, यह ब्लैक वाले लोग ब्लैक ही ब्लैक सोचते हैं, यह बड़ी दिक्कत का विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, क्या आप मन जानत हव कि संगीता सिन्हा जी कोन्दा, लेड़गा बनाये के जादू जानत हे ? (हंसी) नहीं तो पूछ ले ओकर से।

श्री अनुज शर्मा :- वह तो गनीमत हे नहीं तो दारू से ये मन दूध, मिश्री बना देथे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अउ ओ बता देवव खड़े होकर कि कौन ला कोन्दा, लेड़गा बनाये हे तेला। पूछ लेवव।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार जी, आप 3 साऊथ अफ्रीकन खिलाड़ियों का नाम बतायेंगे तो आपको बॉक्स का टिकट दिया जायेगा। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यख महोदय, स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाने के लिये हम लगातार प्रयत्नशील है। इंडिया, न्यूजीलैंड का टी-20 इंटरनेशनल मैच भी 23 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है। यहां लगातार मैच होंगे। जब इंटरनेशनल मैच होते हैं तो 50 से ज्यादा देशों में हमारे रायपुर के नाम को सुना जाता है, पढ़ा जाता है और देखा जाता है। पूरा छत्तीसगढ़ राज्य और राजधानी नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मैप पर आता है। हमको उस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें क्रिकेट अकादमी की भी स्थापना की जा रही है। ट्रेनिंग अकादमी की भी स्थापना की जा रही है और हमारे छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रतिभाओं को भी नया मंच मिलेगा। महिला क्रिकेटरों ने विश्व कप जीता है और उसी तरह का एक टर्निंग प्वाईंट महिला क्रिकेट के इतिहास में हुआ है जो 1983 में कपिल देव जी के नेतृत्व में हुआ था। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में उसी दिशा में भारत की महिला क्रिकेट तेजी से आगे बढ़ी है और हमारे छत्तीसगढ़ की कवर्धा की प्रतिभा इस पूरे मुकाम को हासिल करने में बहुत बड़ी

भूमिका निभाई है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, IPL में RCB से शशांक सिंह क्रिकेट खेल रहे थे। आदरणीय अजय चन्द्राकर जी याद दिला रहे हैं।

श्री अटल श्रीवास्तव :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की कबड्डी टीम की संजू देवी यादव का भी नाम ले लीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- निश्चित रूप से।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, वह विश्व कप जीती है। मान लीजिए कि जो कबड्डी खेल है, वह हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे मेन खेल है। खेल में राजा खेल कबड्डी है। क्रिकेट वाला मन ला करोड़ो रूपये के ईनाम मिलत हे, DSP बनाये जात हे। मोर आपसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े खेल कबड्डी हे तो संजू देवी यादव ला आप DSP बनाये के घोषणा कर देवव तो तुंहर जय-जयकार हो जाही।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बछिया संग कबड्डी खेलत हस कि बछुआ संग, तेला बता दे ? (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, हमारी क्रिकेट प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा और अभी अजय चन्द्राकर जी शशांक सिंह जैसी प्रतिभा का जिक्र कर रहे थे जिसने IPL के फाईनल में हेजलवुड को 1 ओव्हर में 26 रन मारे थे। ऐसी प्रतिभाओं को बल मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- क्रिकेट से थोड़ा आगे बढ़िये।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, जी। हमारे यहां ट्रेनिंग अकादमी की भी स्थापना हो रही है और हमारी राजधानी को एक बड़े स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में डेव्हलप करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ते हा सोझबाए गोठयाए नइ सकस का ? उल्टा सीधा गोठियाथस। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- रात भर चली तो अइसने नई बैठबे तो कैसे बैठबे। विधान सभा दो बार रात भर चले हे।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना योजना हेतु इस अनुपूरक बजट में 453 करोड़ रुपये का, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 152 करोड़ रुपये का, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। सबके लिये आवास योजना नगरीय के अंतर्गत मुख्य बजट में 875 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। उक्त योजना के लिये अभी 1250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है ताकि नगरीय क्षेत्रों में भी आवास बनाने के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, पिछले कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों में 18 लाख गरीबों के छत को छीनने का

पाप किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार आते ही आवास के प्रावधान को आगे बढ़ाया है और 25 हजार करोड़ रुपये से 30 हजार करोड़ रुपये के आवास छत्तीसगढ़ के गरीबों को डबल इंजन की सरकार के कारण मिलेंगे। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के द्वारा, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 60 प्रतिशत की राशि प्रदान की जा रही है और 40 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार के द्वारा, आदरणीय विष्णु देव साय जी के द्वारा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जो गरीब आवासविहीन रह गये थे, 18 लाख से अधिक गरीबों को आवास देने के महायज्ञ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन की सरकार का ये फायदा होता है। डबल इंजन की सरकार का मजाक उड़ाने वाले लोगों को समझना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क और अन्य प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये भी कुछ प्रावधान इसमें किये गये हैं। मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा कि इसमें से अधिकांश प्रावधान आदरणीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर किये गये हैं। इसमें सारंगढ़ में उच्च स्तरीय विश्राम गृह, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर में आडिटोरियम भवन निर्माण, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद, कन्या छात्रावास भवन निर्माण ग्राम जोबी में, ऐसे अनेक प्रावधान किये गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इतना बड़ा दिये हैं, हम लोगों के लिये तो कुछ न कुछ है। मुंगेली के लिये कुछ है तो बता दीजिए। मुंगेली का स्पेशल उल्लेख कर दीजिए।

श्री ओ.पी.चौधरी :- सर, वह सबसे आदरणीय हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से हवाईजहाज का उल्लेख चाहूंगा। आदरणीय धर्मजीत सिंह जी जिक्र कर रहे हैं। रायपुर के एयरपोर्ट में जो भी विषय हैं, उसके लिये 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर के एयरपोर्ट के लिये 150 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा रायगढ़ के एयरपोर्ट का एम.ओ.यू. आपके समय में एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया से होकर रखा हुआ है। उसका land acquisition भी प्रारंभ हो गया था जो बीच में जटिलताओं में उलझ गया था। अभी उसके land acquisition की प्रकिया को आगे बढ़ाने के लिये भी 30 करोड़ रुपये का प्रावधान उसमें रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा रेल नेटवर्क की दृष्टि से सरगुजा अंचल के लोगों की दृष्टि से चिरमिरी-नागपुर हाल्ट रेल लाइन परियोजना हेतु 84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। जो आग लग जाती है, इस तरह की स्थिति आने के बाद उत्पन्न होती है, उससे निपटने के लिये 154 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिये ई-ट्रैक जो आधुनिक तकनीकी से बनते हैं, उसके लिये भी इसमें बजटीय प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में एवियेशन सेक्टर में स्किल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था को भी तेजी से

आगे बढ़ाया जा रहा है। एवियेशन डिपार्टमेंट द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विभाग को देखते हैं, वह पायलेट पालिसी बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ के युवाओं को फ्लाईंग ट्रेनिंग एकेडमी के माध्यम से प्रशिक्षण कर वाणिज्यिक और निजी पायलेट बनने का अवसर प्रदान किया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किये गये हैं। मैं एक और विशेष जवाब देना चाहूंगा कि आज बहुत चर्चा हो रही भी कि भर्ती के संदर्भ में क्या किया जा रहा है? मैं पहली चीज तो स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पिछले 05 सालों में जितनी भर्तियां की हैं, उससे ज्यादा भर्ती हम अपने 05 साल में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेंगे। 02 वर्षों में 15 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। 4 हजार से 5 हजार के लगभग शिक्षक, कालेज के लिये लगभग 800 पद, बस्तर फाइटर्स के लिये 2000 पद, इसके अलावा 20 अनेक विभागों में इसकी भर्ती की अनुमति दी गयी है और लगभग 17,000 पद नये सृजित करने का काम अपने 2 सालों में हुआ है । इसके संदर्भ में...।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति चाहिए । माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2024 में आपने ही घोषणा की थी, अभी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं, 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी । मैं आपके माध्यम से वित्तमंत्री जी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तक वर्ष 2026 आ गया, अभी तक उसकी भर्ती नहीं हो पायी है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो भर्ती में पी.एस.सी. में क्या करते थे, पूरे प्रदेश की जनता जानती है । (शेम-शेम की आवाज)

श्री रामकुमार यादव :- अभी पुलिस के भर्ती ला देखओ, पुलिस के भर्ती के का होत हे ? (व्यवधान)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी पी.एस.सी. का रिजल्ट देखा होगा, कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बेटा सलेक्ट हो रहा है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- रायपुर पी.एस.सी. के का होइस हे ? (व्यवधान) इंजीनियर भर्ती के का होइस हे ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की भर्ती में राजनांदगांव में धांधली हुई । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय रामकुमार जी, यह बता सकते हो कि 18 लाख में कितने शून्य होते हैं ?

श्री रामकुमार यादव :- मैं सब ला जानथओं । (व्यवधान)

श्री अनुज शर्मा :- आज फॉर्म में बेटिंग चंद्राकर जी करत हे, आज ओखर आघू में कांग्रेस के कोनो बालर नइ टिक सकय ।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी, तें पढ़े-लिखे के बात मत करा । मैं हा पढ़े-लिखे मा तुंहर गुरू बबा हंओ ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- सुनिये न, आप लोग बार-बार उनकी अशिक्षा पर क्यों बात उठाते हैं, यह अच्छी बात है क्या ? हर बार उनकी शिक्षा के बारे में बोलते रहते हो । यह गलत बात है न ।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी, जे दिन तुंहर-हमर बहस होही ओ दिन देखबे कि कोन ज्यादा ज्ञानी तेला ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं कहां शिक्षा में काहीं पूछे हओं ?

श्री रामकुमार यादव :- नहीं-नहीं, मैं जान डारेओं कि तुमन ज्ञानी हओ, धरती ला बोह के किंदरत हावा तेन ला जान डारे हओं ।

श्री अजय चंद्राकर :- तें जबरदस्ती लमात हस ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- नहीं, लमात के का बात हे । ऐसे ही दादी बैठते थे, उनको आप शिक्षा के बारे में बोलते थे ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपके यहां भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी शिक्षा हमको मालूम है लेकिन उस बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा चुनाव प्रचार में जा रहा था । एक महापल्ली गांव है, वहां बीच में एक माता ने सड़क पर आकर मेरी गाड़ी को रोका और रोते हुए बोली कि कांग्रेस सरकार के पी.एस.सी. में भ्रष्टाचार के कारण मेरे बेटे का चयन नहीं हो पाया । तुम लोगों की सरकार बनेगी और तुम लोग उनको जेल भेजना, उन्होंने यह बोला, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं और अभी इस साल जो पी.एस.सी. का रिजल्ट आया है उसका बेटा सलेक्ट हुआ है । (मेजों की थपथपाहट) और वही माता आकर बोली कि आप लोगों की सरकार आयी, सही परीक्षा हुई तो मेरे बेट का चयन हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ते का बहुत विषय उठा रहे थे । कल हमारे विधानसभा में प्रश्न लगा था तो तरह-तरह की बातें कर रहे थे । इन्होंने बेरोजगारी भत्ता के नाम पर क्या किया है, इन्हें पहले अपना आत्मावलोकन करना चाहिए । 10 लाख लोगों को 2500 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था उस हिसाब से एक साल का इनका ढ़ाई हजार करोड़ रूपया बैठता था। हर साल इनको 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये ढ़ाई हजार करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान करना था । वर्ष 2020-21 में इन्होंने कितना बजटीय प्रावधान किया, शून्य । वर्ष 2020-21 में इन्होंने

बेरोजगारी भत्ता के लिये शून्य बजटीय प्रावधान किया । (शेम-शेम की आवाज) वर्ष 2021-22 में इन्होंने शून्य बजटीय प्रावधान किया । वर्ष 2022-23 में इन्होंने क्या बजटीय प्रावधान किया, शून्य। वर्ष 2023-24 में चुनावी वर्ष में अगर उस साल भी इनको पूरा देना था तो ढ़ाई हजार करोड़ रूपये का प्रावधान करना था लेकिन इन्होंने 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया । पूरे कार्यकाल में इन्होंने जो वायदा किया था उसके हिसाब से इनको साढ़े 12,000 करोड़ रूपये देना था और इन्होंने पूरे कार्यकाल में मात्र ढ़ाई सौ करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान किया था और अपने घोषणा-पत्र में बोलने के बाद ये बेरोजगारी भत्ता पर सवाल उठाते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय स्थिति पर बहुत सारी बातें हुईं । आदरणीय राघवेंद्र जी ने भी अनेक विषय उठाये थे । मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूंगा कि मैंने जो 42,000 करोड़ की देनदारी गिनायी, छोटी-छोटी चीजों को छोड़कर के गिनायी । उनको बैलेंस करने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है । निश्चित रूप से वह हमारी सरकार के लिये, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिये, हमारे वित्त विभाग के लिये चुनौती है । उस चुनौती का सामना करते हुए हम सब कर रहे हैं । किस तरीके से हम राजस्व बढ़ा रहे हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है । इन सारी चुनौतियों के बीच में हम राजस्व भी बढ़ा रहे हैं, हम पूंजीगत व्यय भी बढ़ा रहे हैं । मैं राजस्व की दृष्टि से आपके सामने रखना चाहूंगा कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां लगभग 93,000 करोड़ थी। वर्ष 2023-2024 में 1 करोड़ 3 लाख करोड़ हुई, वर्ष 2024-2025 में 1 करोड़ 20 लाख, 120 लाख करोड़ हुई, 1 लाख 20 हजार करोड़ हुई। वर्ष 2022-2023 में 93 हजार करोड़ हुई और वर्ष 2023-2024 में 1 लाख 3 हजार करोड़ रूपये हुई और वर्ष 2024-2025 में 1 लाख 20 हजार करोड़ हुई। वर्ष 2022-2023 में पूंजीगत व्यय 13 हजार 300 करोड़ रूपये थी, वर्ष 2023-2024 में 15 हजार 400 करोड़ रूपये हुई, वर्ष 2024-2025 में 20 हजार करोड़ रूपये हुआ। हम पुरानी जो वित्तीय देयतायें थीं या पुरानी जो वेलफेयर स्किम्स के जो वित्तीय बातें थीं उसके अलावा 8 हजार करोड़ रूपये लगभग प्रतिमाह का अतिरिक्त महतारी वंदन दे रहे हैं। इन्होंने जो 18 लाख आवास छोड़ दिया था उसको हम 40 प्रतिशत राज्यांश देते हुए पूरा कर रहे हैं। धान में 3100 रूपये के भाव से 15 क्विंटल की जगह 21 क्विंटल के भाव से दे रहे हैं। दो साल के बोनस के रूप में 3 हजार 716 करोड़ रूपये, 20-25 हजार करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय दायित्व राज्य पर हुआ है उसके बाद भी हम पूंजीगत व्यय को बढ़ा रहे हैं और जो हम राजस्व वृद्धि कर रहे हैं यह उससे संभव हो पा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) मैं इसके बाद भी आपको बताना चाहूंगा कि हम वित्तीय स्थिरता के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। Consolidated sinking fund होता है, यह आर.बी.आई. का प्रावधान है, आर.बी.आई. के नियम हैं कोई भी राज्य जितना लोन लिया हो, उसका 5 प्रतिशत लोन, लोन का एमाऊंट Consolidated sinking fund में जमा करके रखना है ताकि कभी 19-20 हो तो राज्य में वित्तीय स्थिरता बनी रहे। इसके लिए

दिसम्बर 2023 तक 4 हजार 100 करोड़ रूपये जो Consolidated sinking fund में जमा किये गये थे आज हमने 8 हजार 684 करोड़ रूपये जमा किया हे। कोई Compulsion नहीं होता। लेकिन हम राज्य की वित्तीय स्थिरता के लिए हम कर रहे हैं। आर.बी.आई. के नियम में जी.आर.एफ. फण्ड होता है, Garanty rendemtion fund होता है, स्टेट गारण्टी जो देती है उसके एवज में। दिसम्बर 2023 तक इन्होंने मात्र 15 करोड़ रूपये जमा किया था। हम उसको 1 हजार 8 करोड़ रूपये तक उसको पहुंचा चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) पेंशन फण्ड पर कहना चाहूंगा कि इन्होंने ओ.पी.एस. लाया। इनकी गिद्ध दृष्टि थी । न्यू पेंशन स्किम में स्टेट शेयर 19 हजार करोड़ रूपये था उसको कैप्चर करने की गिद्ध दृष्टि थी। उसको पेंशन फण्ड, भारत सरकार ने मना कर दिया। वह तो नहीं कर पायें, अब ओ.पी.एस. लाया, ओल्ड पेंशन स्किम, हमारी सरकार ओ.पी.एस. को Continue कर रही है, लेकिन सबको यह पता है कि life expectancy बढ़ रही है, जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। आने वाले समय में पेंशन दायित्व राज्य के ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन उसके भविष्य की इन्होंने कोई चिंता नहीं की। इनको तो केवल यह था कि आज जो न्यू पेंशन स्किम में स्टेट शेयर देना पड़ता है, वह देना नहीं पड़े। इनका यही मतलब था, इनको कर्मचारियों के हितों से कोई लेना-देना नहीं था। भविष्य में पेंशनदेयता की जो आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए राज्य भविष्य के लिए कैसे तैयार होगा, उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। आज केवल 3-4 साल, इस कार्यकाल की चिंता न करके, हम राज्य के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। इसलिए पिछले मानसून सत्र में पेंशन फण्ड का एक्ट लेकर आएं और हमने उसमें 1 हजार 88 करोड़ रूपये जमा किया है। ताकि पेंशनदेयता 10 प्रतिशत से ज्यादा प्रदेश के जिस वर्ष भी बढ़ेगी, उस पैसे को यूस करके राज्य वित्तीय स्थिरता को बनाये रख सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ग्रोथ फण्ड भी बनाया है जिसमें माईनिंग के जो मटेरियल होते हैं जो मिनरल्स होते हैं उनके दाम नेशनल, इंटरनेशनल कारणों से अप-डाऊन होते रहते हैं। इसलिए माईनिंग रेवेन्यू भी प्रतिशत में होने के कारण अप-डाऊन होते रहती है, Absolute rupees में वह नहीं होता है , प्रतिशत में होता है इसलिए जब प्राईस अप-डाऊन होते हैं तो माईनिंग रेवेन्यू इंटरनेशनल नेशनल कारणों से कम ज्यादा हो सकते हैं। हमारा राज्य माईनिंग रेवेन्यू पर आधारित राज्य है। उस पर कभी नेशनल इंटरनेशनल कारणों से अचानक कमी हो जाए, उस स्थिति में राज्य का capital expenditure प्रभावित न हो, इस दृष्टिकोण से growth and stability फण्ड की स्थापना की गई। पिछले मानसून सत्र में एक्ट लाया गया और उस पर भी पैसा जमा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोन की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो अन्य देयताएं होती है अन्य संस्थानों पर। अप बजट जो लोन होता है उसकी भी हमको चर्चा करनी चाहिए। इसके अलावा हमको स्टेट गारण्टी की भी चर्चा करनी चाहिए। जब यह राज्य में छोड़कर गये थे तो उस समय 22 हजार 500 करोड़ रूपये की स्टेट गारण्टी थी, आज हम उसको कम करते हुए 19 हजार स्टेट गारण्टी को घटाने में सफल हुए हैं।

(मेजों की थपथपाहट) अगर हम लोन की बात करते हैं तो अन्य देयताओं की बजट, आम बजट लोन की स्टेट गारण्टी की, पेंशन फण्ड की, ग्रोथ फण्ड की, Consolidated sinking fund की, Garanty rendemtion fund की इन सबको एक साथ एक दृष्टि से उसको देखने की आवश्यकता है। सतही रूप से आलोचना करना, केवल सतही ब्लेम-गेम लगाना उचित नहीं है। यह सब हम जो कर पा रहे हैं उसमें बड़ा Contribution special capiltal assistance का है। भारत सरकार में नरेन्द्र मोदी जी ने स्पेशल केपिटल असिस्टेंस का प्रोवीजन किया । लगभग डेढ़ लाख करोड़ रूपए का प्रावधान उन्होंने किया है । इसमें अलग-अलग प्रकार के रिफार्म्स होते हैं, उन रिफार्म को इंट्रोड्यूस करने पर राज्य को प्रोत्साहन स्वरूप 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है, जो अनुदान की तरह है । 50 साल तक कोई ब्याज नहीं देना है और 50 साल बाद उस राशि को लौटाना है । इस दृष्टिकोण से यह एससीए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए रिफार्म करने पड़ते हैं । 2020-21 में इनको एससीए में 286 करोड़ मिला, यह एक तरह से पुरस्कार है । केवल 286 करोड़ मिला क्योंकि रिफार्म नहीं कर पाए । 2021-22 में 423 करोड़ मिला क्योंकि रिफार्म नहीं कर पाये । वैसे ही 2022-23 में इनको 2900 करोड़ मिला, 2023-24 में 3300 करोड़ मिला, लेकिन 2024-25 में हमको हमारी सरकार आने के बाद 23-24 में हमने इसको 3300 करोड़ तक पहुंचाया और 2024-25 में 6100 करोड़ तक पहुंचाया । इतने सारे रिफार्म हमने करके दिखाएं हैं । (मेजों की थपथपाहट) तब जाकर एससीए का पैसा मिला और राज्य की वित्तीय स्थिरता, इतने सारे वित्तीय दायित्वों के बाद सुनिश्चित हो पाई है ।

अध्यक्ष महोदय, हम जो भी बातें करते हैं, उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वह तेजी से लागू भी हो । अभी एक बहुत अच्छी योजना जो हमने बजट में लेकर आये थे, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे लागू करने का काम किया है । मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना की उन्होंने घोषणा की है । 34 चयनित मार्गों पर बस संचालन का काम चालू हो चुका है और 250 गांव, नक्सल प्रभावित गांव, सरगुजा के दूर गांव इस योजना से जुड़ पाए हैं । इतना बड़ा चीज यहां पर हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि हम लोन की जब भी बात करते हैं तो जीएसडीपी के परसेंटेज टर्म में उसको देखने की जरूरत है । अब सेल्यूट नम्बर को देखना उचित नहीं है क्योंकि एफआरबीएम के जो रूल्स हैं, रिजर्व बैंक के जो नार्म्स हैं, वह जीडीपी के परसेंटेज टर्म में हैं तो जीडीपी के 3 परसेंट के लोन का, 25 परसेंट की जीडीपी का नियम होता है, सभी लोग जानते हैं । जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी तो प्रदेश को ज्यादा कैपिटल उपलब्ध कराने के लिए लोन भी ज्यादा लेना चाहिए और उसका अधिकाधिक बेहतर उपयोग जनता के कल्याण में करना चाहिए । लोन को अब सेल्यूट नम्बर में न देखकर परसेंटेज के रूप में देखा जाए, यही मैं कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो बहुत तरह की बातें हुईं । अब मैं अपनी बातों की चरण के अंतिम बिन्दू पर आता हूं । 2047 के विजन डाक्यूमेंट के नाम पर विपक्ष ने अनेक प्रकार की बातें

कहीं । 2047 की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं । विजन एक बड़ा लक्ष्य होता है, एक सपना होता है । किसी भी सरकार का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी उद्योग का, किसी भी किसान का एक विजन हो सकता है, एक ड्रीम हो सकता है । लोग मंगल में जाने की सोच रहे हैं तो उनकी कोई हंसी उड़ाएगा ? इसी ने सोचा होगा कि हम चंद्रमा में जा सकते हैं । आज लोग सोचते हैं कि मंगल में जाना संभव नहीं है । जब पहले सब लोग सोचते थे कि चंद्रमा में जाना संभव नहीं है, लेकिन किसी ने विजन बनाया, किसी ने सोचा, तब चन्द्रमा तक पहुंच पाए । आज ऐसे निजी लोग भी हैं, जो प्राईवेट स्पेस छोड़ रहे हैं, प्राईवेट तरीके से सेटेलाईट छोड़ रहे हैं । वह भी व्यक्ति कभी विजन देखा होगा, कोई सपना देखा होगा, तब उसको पूरा कर पाये । भारत देश को डेवलपिंग से डेल्वलप्ड एकानॉमी बनाने के लिए, विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अमृत काल में नरेन्द्र मोदी जी एक सपना देखकर, एक विजन देखकर एक कांक्रीट रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहे हैं । उसी तरीके से हमारे राज्य में हम विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक कांक्रीट रोड मैप में आगे बढ़ने के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डाक्यूमेंट 2047 का हमने निर्माण किया है । 2047 की बात न करें तो केवल क्या 3-4 साल तक केवल जैसे तैसे राज्य चले, ऐसा तो नहीं हो सकता । हम कोई दूर का लक्ष्य बनाना पड़ेगा । ठीक है, उसमें कोई 19, कोई 20 होगा, कुछ कमी होगी, कुछ बेशी होगी, कुछ भी हो सकता है । लेकिन विपक्ष उस चर्चा में भाग नहीं लेने आए, यह कितनी दुखद बात है । 2047 का जो लक्ष्य है, उसमें केवल लांग टर्म लक्ष्य, दीर्घकालीक लक्ष्य 2047 का ही नहीं है, बल्कि उसमें 2035 का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है । उसमें 2030 का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है । हर बजट एक साल का लक्ष्य होता है । ठीक है, उसकी प्राप्ति में कुछ 19, कुछ 20 हो सकता है। अनेक लोकतांत्रिक बाध्यताएं होती हैं । अनेक प्रकार के राजनीतिक विषय भी हो सकते हैं । हम डमोक्रेसी में काम करते हैं, कोई डिक्टेटरशिप में हम काम नहीं करते हैं । जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, परिस्थितियों के अनुसार जनता के अभिमत को भी हमको उचित दिशा में ले जाने की दिशा में काम करना है, लेकिन साथ ही साथ जनता के विषय को भी ध्यान में रखते हुए हमें रिफार्म करना है । अध्यक्ष महोदय, इस विजन डाक्यूमेंट पर ये लोग चर्चा करने नहीं आए, यह बहुत ही गलत बात है और इस परित्र सदन में, इस परित्र मंदिर में प्रथम दिवस था, उसको इन्होंने सेन्ट्रल विस्टा की तरह बहिष्कृत करने का काम किया है। यह राजनीतिक रूप से और छत्तीसगढ़ के विजन की दृष्टि से बहुत ही गलत है। हम सब गवाह बन सकते थे कि इस भव्य मन्दिर का पहला दिन हम सब लोगों ने एक साथ बिताया। हम भविष्य में कभी बूढ़े होकर, 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद इस बात को सुना सकते थे। लेकिन इस बात के लिए छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी।

श्री दिलीप लहरिया :- उद्घाटन हुआ, उस दिन का हमारा दायित्व था।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, उस प्रथम दिवस के सत्र में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, जिसमें विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन डाक्यमेंट की प्रथम दिन चर्चा हो रही थी, इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

श्री दिलीप लहरिया :- आप लोग 14 तारीख को मनाये और हम लोग 15 तारीख को याद रखेंगे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊचांईयों को प्राप्त करेगा। लोकतान्त्रिक जरूरतों के बीच में लोकतान्त्रिक दबावों के बीच में, लोकतान्त्रिक दायित्वों के बीच में हमारी सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूर्णत: समर्पित है और समर्पित रहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में काम करती रहेगी। विपक्ष कितना भी अनर्गल आरोप लगाये, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया, very good.

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पैंतीस हजार करोड़ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुमान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय
7.57 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2005 (क्रमांक 31 सन् 2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ओ.पी.चौधरी जी।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2,3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025) पर पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 8.00 बजे विधान सभा बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 26 शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं